



सत्यमेव जयते

नीति आयोग

# वार्षिक रिपोर्ट

2023 - 24

[www.niti.gov.in](http://www.niti.gov.in)







सत्यमेव जयते

नीति आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

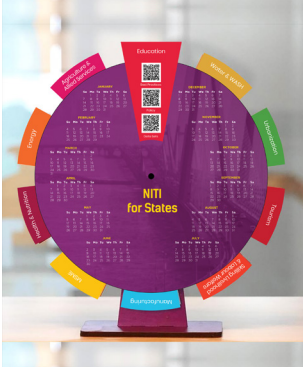
# विषय सूची



## खंड 1:

### नीति आयोग: रूपरेखा

• गठन	02
• उद्देश्य और विशेषताएं	05
• नियुक्तियां	06
• कार्यक्रम/विषय आवंटन	06
• नीति आयोग की शासी परिषद	08
• मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन	10



## खंड 2:

### नीति फॉर स्टेट्स

• भूमिका	15
• आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम	15
• राज्य सहायता मिशन	21
• नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफार्म	23
• नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला	24
• राज्य वित्त और राज्य समन्वय	35
• राज्यों के साथ विविध कार्यकलाप	36



## खंड 3:

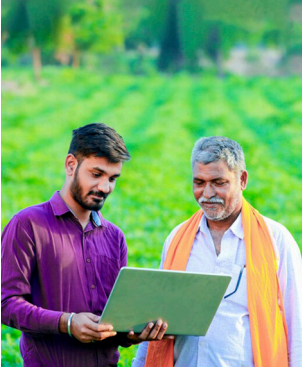
### थिंक-टैंक गतिविधियाँ

• भूमिका	43
• नीति इन-हाउस व्याख्यान श्रृंखला	43
• शिक्षाविदों और थिंक टैंकों के साथ तालमेल	46
• ऊर्जा मॉडलिंग और डेटा प्रबंधन	47
• परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन	48
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग	48
• अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का दौरा	51
• जी 20 थिंक टैंक कार्यशाला श्रृंखला	52



## खंड 4: क्षेत्रवार उपलब्धियाँ

• भूमिका	59
• कृषि	59
• डाटा प्रबंधन और विश्लेषण	62
• अर्थ एवं वित्त -I	63
• अर्थ एवं वित्त -II	64
• शिक्षा	66
• इलेक्ट्रिक मोबिलिटी	69
• हरित परिवर्तन, ऊर्जा, जलवायु और पर्यावरण	72
• शासन और अनुसंधान	77
• परिवार कल्याण, पोषण एवं स्वास्थ्य	81
• उद्योग	90
• सूचना प्रौद्योगिकी (सीमांत प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार सहित)	93
• इंफ्रास्ट्रक्चर-कनेक्टिविटी (परिवहन)	94
• द्वीप विकास	98
• मिशन लाइफ – पर्यावरण के लिए जीवनशैली	99
• उत्तरपूर्वी राज्य	100
• लोक वित्त और नीतिगत विश्लेषण	101
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी	102
• ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाएं	105
• विज्ञान और प्रौद्योगिकी	106
• कौशल विकास और उद्यमिता, श्रम और रोजगार	110
• सामाजिक न्याय और अधिकारिता	113
• सतत विकास लक्ष्य	114
• पर्यटन और संस्कृति	120
• शहरीकरण	121
• स्वैच्छिक कार्य	125
• जल और भूमि संसाधन	126
• महिला और बाल विकास	127



## खंड 5:

### अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

• विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय	133
• आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क	133
• भारत में डेटा गवर्नेंस में परिवर्तन: डीजीक्यूआई पहल	134
• सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक	135
• मूल्यांकन	136
• सेक्टर की समीक्षा	136
• क्षमता निर्माण	136
• राज्यों के साथ परियोजनाएं	138



## खंड 6:

### अटल इनोवेशन मिशन

• भूमिका	141
• अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल)	141
• अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी)	143
• अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (एसीआईसी)	147
• अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी)	148
• एआईएम इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम (एईडीपी)	149



## खंड 7:

### प्रशासन और सहायक इकाइयां

• भूमिका	155
• सामान्य प्रशासन, आरटीआई सहित प्रशासन/मानव संसाधन	155
• संचार कक्ष	163
• शासी परिषद सचिवालय एवं समन्वय, संसद	168



## खंड 8:

### राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (निलडी)

- भूमिका 171
- 2023-24 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम 171



## अनुलग्नक

- अनुलग्नक-1 179
- अनुलग्नक-2 181

## संक्षेपाक्षरों की सूची

एबीपी	आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम
एसीसी	उन्नत रसायन सेल
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीपी	आकांक्षी जिला कार्यक्रम
एआईजीजीपीए	अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान
एआई/एमएल	कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग
एआईआईएमएस	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एआईएम	अटल नवाचार मिशन
एपीआई	सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक
एपीआईएस	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
आशा	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एयू	अफ्रीका संघ
बीईई	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
बीआईएसएजी-एन	भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान
बीएमजीएफ	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
बीएमजेड	संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (जर्मनी)
सीबीसी	क्षमता निर्माण आयोग
सीबीएम	कोल-बेड मीथेन
सीबीएससी	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीईईडब्ल्यू	ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद
सीईपीए	व्यापक आर्थिक साझेदारी करार
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड
सीएम	मुख्यमंत्री
सीपीएसई	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
सीएस	केन्द्रीय क्षेत्र
सीएसओ	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएसओ	सिविल सोसायटी ऑर्गनाइजेशन
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व
सीएसएस	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
सीडब्ल्यूएमआई	समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
सीओसी	चैपियंस ऑफ चेंज



डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
डीईएसी	विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति
डीएफसीसीआईएल	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
डीजीक्यूआई	डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक
डीएचआई	भारती उद्योग विभाग
दीपम	निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
डीएमईओ	विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय
डीओपीटी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
ईसीटीए	आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईजीओएस	सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह
ईपीआई	निर्यात तैयारी सूचकांक
ईवी	इलेक्ट्रिक वाहन
एफआईसीसीआई	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
एफएमसीजी	जल्दी चलने वाले उपभोक्ता समान
एफपीसी	किसान उत्पादक कंपनियां
एफपीओ	किसान उत्पादक संगठन
जीआईआई	वैश्विक नवाचार सूचकांक
जीआईआरजी	सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीआईजैड	जर्मन सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन
जीओआई	भारत सरकार
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु और सेवा कर
जीटीएपी	वैश्विक व्यापार विश्लेषण परियोजना
जीवीसी	वैश्विक मूल्य श्रृंखला
एचएलपीएफ	उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच
एचएमआईएस	स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली
आईए एवं एएस	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा
आईएएफ	भारतीय प्रशासनिक अध्येता
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ

आईसीईडी	भारतीय जलवायु और ऊर्जा डैशबोर्ड
आईसीएफ	इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईडीए	द्वीप विकास एजेंसी
आईईडी	भारत ऊर्जा डैशबोर्ड
आईईएसएस	भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य
आईएफओएस	भारतीय वन सेवा
आईएफपीआरआई	अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान
आईएचबीटी	हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएचसीयूसी	इंडियन हिमालयन सेंद्रल यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
इनक्लेन	अंतर्राष्ट्रीय नैदानिक महामारी विज्ञान नेटवर्क
आईएसबी	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस
आईएसईजी	सततता, आजीविका और विकास के लिए संस्थान
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेसीईआरटी	झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
जेएनपीटी	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्य समूह
केपीआई	प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक
केएसएम/डीआई/ एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एलबीएसएनएए	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी
एलजी	उपराज्यपाल
एलएनजी	तरलीकृत प्राकृतिक गैस
एलओए	प्राधिकार पत्र
एमडीबी	बहुपक्षीय विकास बैंक
एमएंडई	अनुवीक्षण और मूल्यांकन
एमडीओएनईआर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमआईबी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमआईटीआरए	महाराष्ट्र इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन

एमओसी एंड एफ	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओएचएंडएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओएचयूर	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
एमओएमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एमएनआरई	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमपीआई	बहुआयामी गरीबी सूचकांक
एमआरओ	रखरखाव, मरम्मत और संचालन
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
नाबाई	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएएस	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण
एनसीईआर	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीटीई	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
एनडीसी	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एनडीएलडी	नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा
एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनईजीडी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग
एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनएचएसआरसी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र
एनआईईपीए	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
एनआईएलईआरडी	राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईटीआई	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान
एनएलसीआईएल	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
एनएमपी	राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन
एनओटीपी	राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम
एनआरएससी	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र

एनटीपीसी	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन
ओईएम	मूल उपकरण निर्माता
ओओएमएफ	निष्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा
ओओएससी	स्कूल में न पढ़ने वाले बच्चे
ओपेक्स	परिचालन व्यय
पीजीआईएमईआर	पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च
पीएलआई	उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन
पीएमजेवाई	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
पीपीआर	प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट
पीएसएचआईसीएमआई	भारत के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए नीति एवं कार्यनीति
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
आरई	अक्षय ऊर्जा
आरएमआई	रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसएटीएच-ई	मानव पूंजी को बदलने के लिए सतत कार्टवाई - शिक्षा
एससी-एनईसी	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसईसीआई	राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक
एसईक्यूआई	स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
एसईटीयू	उत्तराखंड को सशक्त बनाने और बदलने के लिए राज्य संस्थान
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईटी	परिवर्तन के लिए राज्य संस्थान
एसएमआर	छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रियाएँ
एसओआई	आशय विवरण
एसटीसी	राज्य परिवर्तन आयोग
एसएसएम	राज्य सहायता मिशन
यू-डीआईएसई	शिक्षा प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूएनएफसीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन
यूएनएफपीए	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
यूनिसेफ़	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष

यूएनजीए	संयुक्त राष्ट्र महासभा
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
वीआईएफ	विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन
वाश	पानी, स्वच्छता और सफाई
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
विंग्स	विकास अध्ययन के लिए महिलाओं और शिशुओं के एकीकृत हस्तक्षेप
डब्ल्यूईएफ	विश्व आर्थिक मंच
वीजीएफ	व्यवहार्यता अंतराल निधीयन

“ जब हमारे राज्य प्रगति करेंगे,  
तो भारत भी प्रगति करेगा  
- नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री ”



नीति आयोग

सबकी आकांक्षाएं, सबका विकास

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत

संकल्प सप्ताह

30 सितंबर 2023, भारत मंडपम, नई दिल्ली



नीति आयोग

सबकी आकांक्षाएं, सबका विकास

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत

संकल्प सप्ताह

# सं

# 1

## नीति आयोगः रूपरेखा

### गठन

केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से 01 जनवरी, 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। यह भारत सरकार का नीति से संबंधित प्रमुख 'थिंक टैंक' है, जो निर्देशनात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने के अलावा, नीति आयोग केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त कार्यनीतिक एवं तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय हित में साथ मिलकर कार्य करने के लिए राज्यों को एक मंच पर लाने के लिए नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

## नीति आयोग का गठन (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)



माननीय प्रधानमंत्री  
श्री नरेंद्र मोदी  
अध्यक्ष



श्री सुमन बेरी  
उपाध्यक्ष

### पूर्णकालिक सदस्य



श्री वी के सारस्वत  
सदस्य



प्रो. रमेश चंद  
सदस्य



डॉ. वी के पॉल  
सदस्य



डॉ. अरविंद विरमानी  
सदस्य



श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



## नीति आयोग का गठन (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)

### पदेन सदस्य



श्री राजनाथ सिंह  
माननीय रक्षा मंत्री



श्री अमित शाह  
माननीय गृह मंत्री और  
सहकारिता मंत्री



श्रीमती निर्मला सीतारमण  
माननीय वित्त मंत्री और  
कॉर्पोरेट कार्य मंत्री



श्री अर्जुन मुंडा  
माननीय कृषि एवं किसान  
कल्याण मंत्री

### विशेष आमंत्रितगण



श्री नितिन जयराम गडकरी  
माननीय सड़क परिवहन और  
राजमार्ग मंत्री



श्री पीयूष गोयल  
माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री,  
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं  
सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा  
मंत्री



श्री अश्विनी वैष्णव  
माननीय रेल मंत्री, संचार मंत्री और  
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी  
मंत्री



राव इंद्रजीत सिंह  
माननीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम  
कार्यान्वयन राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार), योजना राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार) और कॉर्पोरेट कार्य  
राज्य मंत्री



डॉ. वीरेंद्र कुमार  
माननीय सामाजिक न्याय  
एवं अधिकारिता मंत्री

## उद्देश्य और विशेषताएं

नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इस नोडल एजेंसी को आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में नीचे से ऊपर वाले दृष्टिकोण का उपयोग करके भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों के एक साझा विजन का विकास करना।
- यह स्वीकार करते हुए कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए क्रियाविधि तैयार करना और इनको उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना।
- यह सुनिश्चित करना कि जो क्षेत्र विशेष रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित किया गया है।
- हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना, जिनको आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो सकता है।
- कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और प्रभाव की निगरानी करना। निगरानी और फीडबैक के माध्यम से सीखे गए सबक का प्रयोग आवश्यक मध्यावधि संशोधन सहित नवोन्मेषी सुधार करने के लिए किया जाएगा।
- महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं को सलाह देना और उनके बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृत्तिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना।
- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर्क्षेत्रिक और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच प्रदान करना।
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र का अनुरक्षण करना, सुशासन पर अनुसंधान तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का भण्डार बनना और साथ ही उसे हितधारकों तक पहुंचाने में भी मदद करना।
- आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ-साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रियता से मूल्यांकन और निगरानी करना ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।
- कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना।
- ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा को लागू करने और उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

नीति आयोग स्वयं को आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है जो इसे तेजी से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीतिक नीति विज्ञान प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में समर्थ बनाएगा। इसे एक संबद्ध कार्यालय यानी विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन संगठन (डीएमईओ), एक महत्वपूर्ण पहल अर्थात् अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और एक स्वायत्त निकाय अर्थात् राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

**नीति आयोग के समस्त अधिदेशों को चार मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है :**

1. ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना
2. नीति फॉर स्टेट्स (सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद)
3. परिवर्तनकारी बदलाव लाना
4. अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

## नियुक्तियां

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2023 के पत्रव्यवहार के माध्यम से कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की मंजूरी के अनुसरण में, श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम (आईएएस, सीजी: 1987) को श्री परमेश्वरन अय्यर के स्थान पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त किया गया था। तदनुसार, श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने 24 फरवरी, 2023 से नीति आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला।

## कार्यक्रम/विषय आवंटन

नीति आयोग के विभिन्न कार्यक्रम, विषय, संबद्ध कार्यालय और स्वायत्त निकाय उपर्युक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं। विशेष पहलों/कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों, विषयों की सूची नीचे दी गई है, जबकि 2023-24 के दौरान उनके कार्य क्षेत्र और प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख खंड-4 में किया गया है।

क्र.सं.	कार्यक्रम/विषय आवंटन
1.	राज्य i) राज्य वित्त और राज्य समन्वय ii) राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) iii) आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) iv) आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) v) राष्ट्रीय मुख्य सचिव समन्वय प्रभाग

2.	शिक्षा
3.	जल और भूमि संसाधन
4.	पेयजल और स्वच्छता
5.	उत्तरपूर्वी राज्य
6.	संचार
7.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता, स्वैच्छिक कार्रवाई
8.	ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाएं
9.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
10.	सामान्य प्रशासन, आरटीआई सहित प्रशासन / मानव संसाधन
11.	शासन और अनुसंधान
12.	शासी परिषद सचिवालय और समन्वय (जीसीएस एंड सी), संसद
13.	सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)
14.	सूचना प्रौद्योगिकी (फ्रंटियर प्रौद्योगिकी और दूरसंचार सहित)
15.	डेटा प्रबंधन और विश्लेषण
16.	शहरीकरण
17.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पोषण
18.	महिला एवं बाल विकास
19.	कृषि प्रौद्योगिकी
20.	कृषि नीति
21.	सार्वजनिक वित्त और नीति विश्लेषण (पूर्व में पीएमएडी)
22.	अर्थ और वित्त I: अर्थ मॉडलिंग, परिदृश्य निर्माण, पूंजी बाजार
23.	अर्थ और वित्त II i. अर्थ और वित्त वर्टीकल के अन्य सभी मामले जिनका जी-20, बहुपक्षीय संस्थानों और विनिवेश सहित ई एंड एफ-1 में उल्लेख नहीं किया गया है; ii. व्यापार और वाणिज्य

24.	कौशल विकास और उद्यमिता, श्रम और रोजगार
25.	हरित परिवर्तन, ऊर्जा, जलवायु और पर्यावरण
26.	अवसंरचना - कनेक्टिविटी (परिवहन)
27.	इलेक्ट्रिक मोबिलिटी
28.	एफडीआई सहित उद्योग और एमएसएमई
29.	पर्यटन और संस्कृति
30.	हाई स्पीड ट्रेन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण सहित सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)
31.	द्वीप विकास
32.	विधि
33.	वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सहित सुरक्षा और विदेश मामले

### अन्य विशेष पहल/कार्यक्रम

1.	परिदृश्य आयोजना और विकसित भारत सहित विजन यूनिट: विजन@2047
2.	ज्ञान सहायता इकाई
3.	आर्थिक आसूचना इकाई
4.	चक्रीय इकोनॉमी प्रकोष्ठ
5.	विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) - संलग्न कार्यालय
6.	अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) - प्रमुख पहल
7.	राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (निलडी) - स्वायत्त निकाय

## नीति आयोग की शासी परिषद

नीति आयोग की शासी परिषद, जिसमें सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल शामिल हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से 16 फरवरी, 2015 को प्रभाव में आई। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा शासी परिषद का पिछला पुनर्गठन दिनांक 19 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया।

शासी परिषद एक प्रमुख निकाय है जिसे विकास की गाथा को आकार देने में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों का एक साझा विज़न विकसित करने का काम सौंपा गया है। शासी परिषद, जो सहकारी संघवाद के उद्देश्यों का प्रतीक है, राष्ट्रीय विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए

अंतर-क्षेत्रक, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रस्तुत करती है।

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों और शासी परिषद के अन्य सदस्यों के साथ अब तक शासी परिषद की आठ बैठकें हो चुकी हैं।

## शासी परिषद की आठवीं बैठक

'विकसित भारत@2047' विषय पर नीति आयोग की शासी परिषद की आठवीं बैठक 27 मई, 2023 को भारत मंडप, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसमें 19 राज्यों तथा 6 संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों और उप राज्यपालों ने भाग लिया। बैठक में पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रितगण के रूप में चुनिंदा केंद्रीय मंत्रियों; नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों; मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव; नीति आयोग के सीईओ; और भारत सरकार के चुनिंदा सचिवों तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और नीति आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

शासी परिषद ने 5 से 7 जनवरी, 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एजेंडा सेट पर विचार-विमर्श किया, जिसमें (i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमडी) पर जोर, (ii) अवसंरचना और निवेश, (iii) अनुपालन को कम करना, (iv) महिला सशक्तिकरण, (v) स्वास्थ्य और पोषण, (vi) कौशल विकास और क्षेत्र विकास और सामाजिक अवसंरचना के लिए गति शक्ति पर अतिरिक्त एजेंडा मद शामिल थी। इसके अलावा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा विकसित भारत@2047 पर एक प्रस्तुति दी गई जिसने बैठक के लिए एक गति निर्धारित की।

बैठक में मुख्यमंत्री/उप राज्यपालों ने विभिन्न विकास प्राथमिकताओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने राज्यों से संबंधित उन विशिष्ट मुद्दों पर प्रकाश डाला जिनके लिए केंद्र-राज्य सहयोग की आवश्यकता है। उनके द्वारा उजागर किए गए कुछ प्रमुख मुद्दों और सर्वोत्तम प्रथाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रीन कार्यनीति को चुनने, क्षेत्रवार योजना बनाने, पर्यटन, शहरी योजना, कृषि, कारीगरी की गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता शामिल है।

माननीय प्रधानमंत्री ने उपर्युक्त सभी मुद्दों के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना एक अन्य क्षेत्र है जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भौतिक और डिजिटल अवसंरचना के अलावा, पर्याप्त निवेश को सामाजिक अवसंरचना की ओर संचालित करने की भी आवश्यकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजीविका के बेहतर अवसर पैदा होंगे। उन्होंने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्थानीय स्तर पर सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से जल संरक्षण और रोजगार सृजन के दोहरे मुद्दों को हल करने का आग्रह किया, जो मनरेगा को अमृत सरोवर कार्यक्रम से जोड़कर किया जा सकता है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों से अनुरोध किया कि वे अपनी वित्तीय स्थिति पर कड़ी नजर रखें और विशेष रूप से अस्थिर वैश्विक स्थिति के संदर्भ में राजकोषीय अनुशासन अपनाएं। उन्होंने राज्यों को आगाह किया कि वे दुनिया के कई देशों की तरह कर्ज के जाल में नहीं फसें, जो अविवेकपूर्ण वित्तीय नीतियों के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने नगरपालिका, जिला और पंचायत स्तरों पर प्रतिस्पर्धा आधारित रणनीतियों को दोहराने के महत्व पर भी जोर दिया, जो अधिकारियों को सामाजिक-आर्थिक मापदंडों में प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

प्रधानमंत्री ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनेक शहरों में आयोजित जी-20 की बैठकों में उत्साहजनक वैश्विक भागीदारी की ओर मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि जी-20 प्रेसीडेंसी ने विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया है, इसने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वैश्विक एकसोजर का अवसर भी प्रदान किया है। उन्होंने विश्व भर में मजबूत उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस अवसर का उपयोग कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से

अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता और इसके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया।

अपने समापन वक्तव्य में, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अमृत काल के 25 वर्ष भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विकसित भारत का विज़न पूरे देश के लिए है न कि किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के लिए। टीम इंडिया के एकजुट और सहयोगात्मक प्रयासों से, भारत को 2047 तक एक समावेशी, विकसित और प्रगतिशील राष्ट्र बनना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि नीति आयोग में हो रही सभी चर्चाएं भारत को विकसित भारत विज़न की ओर ले जाने के लिए हैं।



दिनांक 27 मई, 2023 को आयोजित शासी-परिषद की आठवीं बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/गवर्नरों के साथ माननीय प्रधानमंत्री।

## मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन

माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार, वार्षिक आधार पर मुख्य सचिवों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अब तक इस तरह के तीन सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। तीसरा सम्मेलन 9 महीने से अधिक की तैयारियों के बाद 27-29 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के पदाधिकारियों ने सम्मेलन विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया था। तीसरे सम्मेलन का विषय ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना है। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ, सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए पांच उप-विषय थे: (i) पेयजल: पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता, विद्युत: (ii) गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता, स्वास्थ्य: (iii) पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता; (iv) स्कूली शिक्षा: पहुंच और गुणवत्ता और (v) भूमि और संपत्ति: पहुंच, डिजिटलीकरण, पंजीकरण और उत्परिवर्तन।

इनके अलावा, निम्नलिखित विषयों पर विशेष सत्र भी आयोजित किए गए (i) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर परिप्रेक्ष्य; (ii) साइबर सुरक्षा: उभरती हुई चुनौतियां; (iii) जमीनी कहानियां: आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रम; (iv) राज्यों की भूमिका योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं को युक्तिसंगत बनाना और पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना; और (v) शासन में एआई: चुनौतियां और अवसर।

इनके साथ-साथ, नशा मुक्ति और पुनर्वासि; अमृत सरोवर; पर्यटन संवर्धन, ब्रांडिंग और राज्यों की भूमिका; और पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम स्वनिधि पर भी विचार-विमर्श केंद्रित किया गया। सम्मेलन में प्रत्येक विषय के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को भी प्रस्तुत किया गया ताकि राज्य एक राज्य में प्राप्त सफलता को दोहरा सकें या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर सकें। मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का परिणाम को 9वीं शासी परिषद बैठक के एजेंडा में शामिल किए जाने की उम्मीद है।



# मुख्य सचिवों का तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन Third National Conference of Chief Secretaries

27-29 दिसंबर 2023 | नई दिल्ली

27-29 December 2023 | New Delhi



माननीय प्रधानमंत्री दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य सचिवों के साथ।





# Education



Best Practices



Policy



Data Sets

# Water & WASH

## DECEMBER

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

## NOVEMBER

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

## OCTOBER

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## SEPTEMBER

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

## AUGUST

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

## JULY

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

## JANUARY

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

## FEBRUARY

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	

## MARCH

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

## APRIL

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

## MAY

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## JUNE

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

# NITI for States

# Agriculture & Allied services

# Energy

# Health & Nutrition

# MSME

# Manufacturing

# Skilling Livelihood & Labour Welfare

# Urbanization

# Tourism

खंड

2

नीति फॉर स्टेट्स

## भूमिका

सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हुए, नीति आयोग का मुख्य अधिदेश राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। इसे ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग 'टीम इंडिया' की भावना के साथ कई पहलों का आयोजन करता रहता है। आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अलावा, नीति आयोग ने वर्ष 2047 के लिए, जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्षों का जश्न मना रहा होगा तब परिकल्पित परिवर्तनकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चल रहे जुड़ाव को और अधिक संरचित और संस्थागत तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक पहल के रूप में अपने राज्य सहायता मिशन को जीवंत किया है। इनमें राज्यों में नीति आयोग की तर्ज पर संस्था स्थापित करने के लिए विशेष सहायता प्रदान करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमता निर्माण, ज्ञान और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सूचकांक लॉन्च करना और शिक्षा, निगरानी एवं मूल्यांकन, सतत विकास लक्ष्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट पहल और हिमालयी क्षेत्र, द्वीप विकास, तटीय राज्यों आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए तैयार रणनीतियां सम्मिलित है।

## आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम

### आकांक्षी जिला कार्यक्रम

आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जैसा कि इसने जनवरी 2024 में अपने कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे किए, भारत के अपेक्षाकृत अल्पविकसित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक व्यावहारिक और डेटा-संचालित दृष्टिकोण के प्रमाण के रूप में मौजूद है। यह अग्रणी पहल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है, जो एक ऐसे मॉडल का प्रदर्शन करती है जो राष्ट्रव्यापी समावेशी और सतत विकास में योगदान करने के लिए व्यक्तिगत जिलों के परे जाती है।

कार्यक्रम के मूल में डेटा-संचालित दृष्टिकोण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता निहित है। नीति आयोग, 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) पर मासिक डेटा एकत्र करके 112 जिलों की निगरानी कर्मठतापूर्वक कर रहा है। डेटा पर बल देना एक कार्यनीतिक स्वीकृति है कि सामाजिक-आर्थिक परिणामों में पर्याप्त सुधार कठोर डेटा विश्लेषण के माध्यम से चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने पर निर्भर करती है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निरंतर सफलता का श्रेय केंद्र और राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, गैर-सरकारी संगठनों, निजी भागीदारों, नागरिक समाज और जनता सहित विभिन्न हितधारकों के प्रयासों के कुशल समन्वय को दिया जा सकता है। नीति आयोग ने राज्य सरकारों और सम्बद्ध केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो उन्नयन के एक साझा लक्ष्य को लेकर विभिन्न संस्थाओं को जोड़ने के लिए एक पुल के रूप में कार्य कर रहा है।

इस सहयोगात्मक प्रयास में प्रमुख पक्षकारों में नीति आयोग, केंद्रीय और राज्य प्रभारी अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर (डीएम/डीसी) के नेतृत्व वाली जिला टीम शामिल हैं। नीति आयोग द्वारा आयोजित नियमित बैठकें और कार्यशालाएं इन हितधारकों को एक साथ आने, अंतर्दृष्टि का आदान-प्रदान करने, जमीनी स्तर की चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान की पहचान करने और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए मंच के रूप में कार्य करती हैं। यह सहयोगात्मक भावना न केवल कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मजबूत करती है बल्कि विशेषज्ञता का एक नेटवर्क भी बनाती है जो प्रशासनिक सीमाओं से परे जाती है।

भौतिक रूप में संग्रहण से भी आगे बढ़कर, नीति आयोग ई-मेल, पत्र और सोशल मीडिया जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से सफलता की कहानियों और सर्वोत्तम पद्धतियों का सक्रिय रूप से प्रसार करता है। यह ज्ञान-

साझाकरण पहल उपलब्धियों का जश्न मनाने में महत्वपूर्ण है और समान चुनौतियों का सामना करने वाले जिलों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में भी कार्य करती है। प्रौद्योगिकी और संचार प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि एक क्षेत्र में सीखे गए सबक को दूसरे क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, जिससे निरंतर सुधार और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का प्रभाव किसी एक जिले तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव कई जिलों में हुआ है। यह देश भर में पहल को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत पेश करता है, एक मॉडल का प्रदर्शन करता है जिसे विविध सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में अपनाया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान प्रदान करके, यह कार्यक्रम भारत में समावेशी और सतत विकास के व्यापक लक्ष्य में योगदान देता है।

### आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

7 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता की राह पर चलनेवाली एक परिवर्तनकारी पहल है। 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए, एबीपी का लक्ष्य मौजूदा योजनाओं को अभिसरित करके, परिणामों को परिभाषित करके और प्रगति की निरंतर निगरानी करके शासन और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाना है।

चिन्हित प्रत्येक ब्लॉक में, एबीपी कार्यानीतिक रूप से स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य विकास के लिए एक अनुरूप दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है, जो संदर्भ-आधारित कार्यानीतियों की अनुमति देता है जो प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे निर्णय लेने की क्षमता को जमीनी स्तर के और करीब लाते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण न केवल असमानताओं को लक्षित करता है बल्कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित करते हुए आर्थिक विकास को भी उत्प्रेरित करता है। एबीपी अंतिम-मील सेवा वितरण, जागरूकता बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने और सीखने को साझा करने के लिए ब्लॉक प्रशासन के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करने पर जोर देता है। इसका व्यापक लक्ष्य सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करके और एक समावेशी, स्थानीय रूप से संचालित विकास प्रतिमान को बढ़ावा देकर नागरिकों के लिए जीवन स्तर को बढ़ाना है।

एबीपी का पहला वर्ष सभी चयनित ब्लॉकों में कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने में बहुत उपयोगी रहा है। संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श से 40 संकेतकों वाले एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक ढांचे को अंतिम रूप दिया गया। एडीपी के विपरीत, इन संकेतकों का डेटा सीधे केंद्रीय मंत्रालय के डेटाबेस से प्राप्त किया जाता है, जिससे डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है और क्षेत्र के अधिकारियों पर डेटा प्रविष्टि का बोझ कम होता है। मार्च 2023 को उनकी स्थिति के अनुसार सभी 500 ब्लॉकों को एक बेसलाइन रिपोर्ट प्रदान की गई थी। एबीपी के तहत पहली डेल्टा रैंकिंग मार्च और जून, 2023 के बीच प्राप्त की गई वृद्धिशील प्रगति के आधार पर दिसंबर, 2023 में जारी की गई थी।

एबीपी के तहत प्रमुख पहलों में से एक ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं और ब्लॉक विकास रणनीति (बीडीएस) तैयार करना था। अगस्त और सितंबर 2023 के दौरान देश भर के 10 केंद्रों में 4,500 से अधिक ब्लॉक-स्तरीय पदाधिकारियों ने नेतृत्व प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण का एक प्रमुख परिणाम सभी आकांक्षी ब्लॉकों द्वारा एक मजबूत ब्लॉक विकास रणनीति (बीडीएस) की तैयारी करना रहा है। बीडीएस ब्लॉक के प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकताओं और उन सेवाओं की रूपरेखा तैयार करता है जो पहचाने गए सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए मौजूदा संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग करते हुए नागरिकों को

प्रदान की जाएगी। बीडीएस की तैयारी के लिए, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अनेकों चिंतन शिविर आयोजित किये गये। इन परामर्शों में असंख्य स्थानीय हितधारक जन प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों और आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे फ्रंटलाइन कर्मचारियों से लेकर स्थानीय प्रभावशाली लोगों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों तक शामिल थे। प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक व्यापक विकास रणनीति को आकार देने के लिए उनकी सामूहिक अंतर्दृष्टि और अनुभवों का उपयोग किया गया है। कार्यनीति आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना बनाती है। इस कार्यक्रम के तहत सभी ब्लॉकों ने सफलतापूर्वक अपना ब्लॉक विकास कार्यनीति तैयार कर लिया है और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

30 सितंबर 2023 को, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में एबीपी के तहत 'संकल्प सप्ताह' लॉन्च किया। लॉन्च के अवसर पर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी और ब्लॉक और पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों सहित देश भर से 3,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। संकल्प सप्ताह बुनियादी सेवाओं की संतृप्ति और प्रत्येक नागरिक तक उनकी पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एबीपी के प्रत्येक क्षेत्रीय विषयों के तहत चले विभिन्न गतिविधियों का सात-दिवसीय कार्यक्रम था। लॉन्च के बाद, संकल्प सप्ताह क्रियाकलाप दिनांक 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 2023 के बीच सभी आकांक्षी ब्लॉकों में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किए गए।



माननीय प्रधानमंत्री भारत मंडपम, नई दिल्ली में संकल्प सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर

समावेशी, स्थानीय रूप से संचालित विकास कार्यनीतियों को प्राथमिकता देकर, एबीपी एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हुए सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक बन गया है जहां स्थानीय पहल और सुशासन सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे-जैसे इसका प्रसार होता है, कार्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव और सतत, संदर्भ-आधारित विकास में निहित परिवर्तनकारी क्षमता का उदाहरण देता है।



## प्रदर्शन डैशबोर्ड: चैंपियंस ऑफ़ चेंज

### आकांक्षी जिला कार्यक्रम

वास्तविक समय डेटा संग्रह और निगरानी के लिए चैंपियंस ऑफ़ चेंज (सीओसी) डैशबोर्ड दिनांक 1 अप्रैल 2018 को सामान्य जन के देखने के लिए खोला गया। डैशबोर्ड का नाम जिलों की प्रगति में जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों और उनकी टीमों द्वारा निर्भाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए रखा गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम नियमित रैंकिंग के माध्यम से 112 जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करने पर निर्भर है, जो गतिशील है और हर

महीने किए गए वृद्धिशील (डेल्टा) सुधार को दर्शाता है। डैशबोर्ड पर अद्यतन डेटा दर्ज करने के लिए जिलों को अपने डेटा संग्रह और रखरखाव तंत्र में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

डेटा-संचालित शासन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की दिशा में जिला प्रशासन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल (सीओसी 2.0) को अद्यतन किया गया है। सीओसी 2.0 कई नई सुविधाओं जैसे नागरिक रिपोर्ट, नागरिकों से फीडबैक, उन्नत एनालिटिक्स, परियोजना प्रबंधन, भू-स्थानिक मानचित्र और अन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लैंग्वेज समाधान का आयोजन करता है।



**Projects**  
Implementation and Monitoring of Projects in Aspirational Districts  
[Read More](#)

**Analytics**  
Deeper analytics into administrative data to support Districts Magistrates/Collectors  
[Read More](#)

**Citizen Feedback**  
NITI Aayog looks forward to constructive feedback from citizens to further improve the  
[Feedback](#)

**Alternative Land Use Planning**  
GIS developed by ICAR-NBSS to aid Aspirational Districts in Sustainable Land Use Planning  
[Read More](#)

चैंपियंस ऑफ चेंज डेटा के विश्लेषण के आधार पर नागरिक रिपोर्ट में 3 डैशबोर्ड शामिल किए गए हैं:

- 1) शुरुआत के बाद से आकांक्षी जिलों का प्रदर्शन।
- 2) जिलों की डेल्टा रैंकिंग जो प्रत्येक माह जारी की जाती है।
- 3) सभी जिलों के लिए थीम्स में संकेतक स्तर की प्रगति।

इन रिपोर्टों के अलावा, जिला प्रशासन के पास सीओसी डेटा का उपयोग करके उनके प्रदर्शन विश्लेषण के लिए उन्नत विश्लेषण करने हेतु डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल तक पहुंच है। जिले राज्य के अन्य जिलों या सभी आकांक्षी



जिलों में सर्वश्रेष्ठ के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं, एनएचएफएस, जनगणना और तीसरे पक्ष के सर्वेक्षण डेटा जैसे अन्य डेटा स्रोतों के साथ अपने विश्लेषण को त्रिकोणित कर सकते हैं और विश्लेषण के लिए ब्लॉक स्तर या ग्राम पंचायत स्तर के डेटा को भी अपलोड कर सकते हैं।

इस नए प्लेटफॉर्म में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक डेटा गुणवत्ता और मासिक प्रदर्शन पर स्वचालित सिस्टम जनित मेलर्स हैं। सिस्टम में पूर्व-कॉन्फ़िगर किए गए तर्कों के आधार पर, उनके द्वारा दर्ज किए गए डेटा में किसी भी विसंगति को उजागर करने वाले जिलों को स्वचालित मेलर भेजे जाते हैं। इससे कार्यक्रम की समग्र डेटा गुणवत्ता और उसके बाद जिलों के प्रदर्शन के विश्लेषण को बढ़ाने में मदद मिली है। सिस्टम द्वारा तैयार की गई मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों, केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों/राज्य प्रभारी अधिकारियों और राज्य के मुख्य सचिवों को भी भेजी जाती है, जिसमें विभिन्न संकेतकों में उनका प्रदर्शन का ब्यौरा शामिल रहता है।

### आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

एबीपी पोर्टल जो कि जनता की पहुँच में है, चिन्हित ब्लॉकों में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण जानकारी को कवर करने वाले व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके केंद्र में, पोर्टल 40 केपीआई के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो कार्यक्रम का हिस्सा हैं तथा जो प्रत्येक ब्लॉक की प्रगति का विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। उपयोगकर्ता ब्लॉक प्रोफाइल में जा सकते हैं, उनकी विशिष्ट गतिशीलता, चुनौतियों और विकास के संभावित अवसरों को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह सीखने के संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं का भंडार प्रदान करता है, जिससे हितधारक प्रभावी दृष्टिक्षेप और सहायता के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस हो सकें।

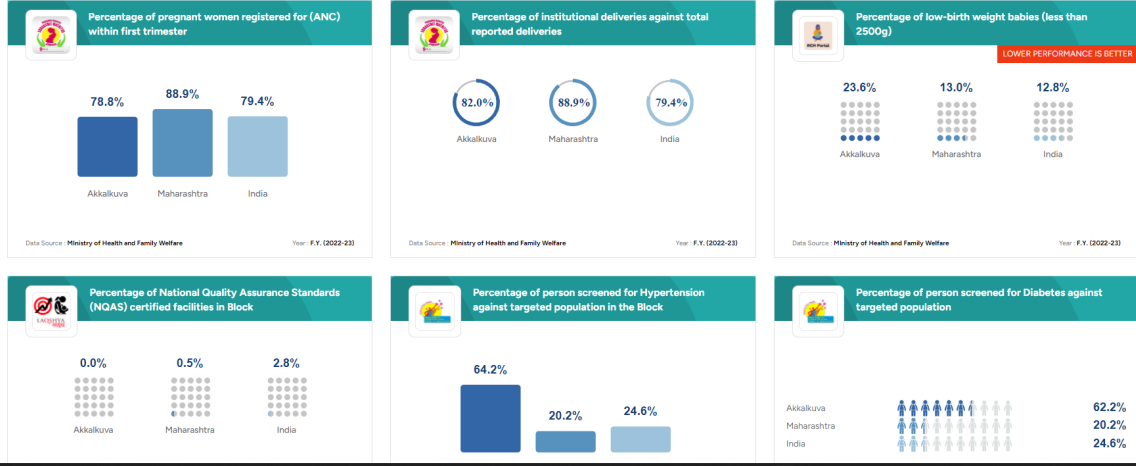
इसके अलावा, त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग जारी करने का काम पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। यह प्रगति पर नज़र रखने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और विकास की दिशा में सक्रिय उपायों को प्रोत्साहित करने को सुकर बनाता है।

विश्लेषण के लिए जानकारी और उपकरणों का खजाना प्रदान करके, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम पोर्टल समग्र विकास की दिशा में सूचित निर्णय लेने और सहयोगी प्रयासों को उत्प्रेरित करता है।

The screenshot shows the website for the Aspirational Blocks Programme. The navigation menu includes: Aspirational Blocks Programme, Key Performance Indicators, Best Practices, CHAMPIONS OF CHANGE, Training, Learning Resources, and Block Development Strategy. The main banner features the text: "Building Strategies. Bridging Gaps. Bolstering Progress." followed by the mission statement: "Improving the quality of life and service delivery, fostering sustainable communities and moving to create circular village economies across India." and a call to action: "Join us on this journey of empowering, uplifting, and transforming lives. Together, we will build brighter, better and progressive futures." with a "Know More" button. The footer contains the "Champions of Change Aspirational Blocks Programme" logo and name.



Health & Nutrition



## राज्य सहायता मिशन

**“जब हमारे राज्य प्रगति करेंगे, तो भारत भी प्रगति करेगा” - माननीय प्रधानमंत्री**

राज्य सहायता मिशन वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में घोषित नीति आयोग की एक व्यापक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नीति आयोग की संरचित और संस्थागत भागीदारी को बढ़ावा देना है। मिशन को कार्यनीतिक रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप विकसित करने और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप उनकी विकास कार्यनीतियों को सुकर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के कोर बल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस मिशन के तहत, नीति आयोग इच्छुक राज्यों को राज्य परिवर्तन संस्था (एसआईटी) स्थापित करने में सहायता कर रहा है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यनीतियों को चलाने के लिए एक बहु-विषयक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों या तो एसआईटी के रूप में एक अलग संस्थान स्थापित कर सकते हैं या योजना विभाग और बोर्ड जैसे अपने मौजूदा संस्थानों की भूमिका की पुनः कल्पना कर सकते हैं। एसआईटी में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी और क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञता वाले पार्श्व प्रवेशकर्ता शामिल हो सकते हैं।

### चिंतनशिविर - ‘राज्यों के साथ काम करना’ और एसएसएम दिशानिर्देशों का शुभारंभ

नीति आयोग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सहयोग को मजबूत करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के अपने निरंतर प्रयास में दिनांक 27 अप्रैल 2023 को एक परामर्श बैठक आयोजित की। परामर्श बैठक में 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपर मुख्य सचिव, योजना सचिव, स्थानिक आयुक्त और अन्य सम्मानित प्रतिनिधि सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।



27 अप्रैल, 2023 को राज्यों के साथ कार्यों पर चिंतन शिविर

नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में, माननीय सदस्यों और सीईओ की उपस्थिति में, बैठक ने नीति आयोग के लक्ष्य और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी के लिए इसकी अटूट प्रतिबद्धता पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। एसएसएम के प्रमुख विषयों और प्रमुख विषयों जैसे ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, निगरानी और मूल्यांकन इकोसिस्टम को बढ़ाना, साथ ही राज्य स्तर पर परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने में योजना विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने पर चर्चा की गई।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने परामर्श के दौरान सक्रिय रूप से मूल्यवान सुझाव दिए तथा मौजूदा जुड़ाव और साझेदारी को और गहरा करने के लिए नीति आयोग से अपनी अपेक्षाएं व्यक्त कीं। ये सुझाव महत्वपूर्ण मूल्य रखते हैं और उनकी विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में नीति आयोग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करने में योगदान देंगे।

### एसएसएम के तहत परिवर्तन के लिए राज्य संस्था (एसआईटी) का गठन

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नीति आयोग के सहयोग से अपने मौजूदा संस्थाओं जैसे योजना विभागों और बोर्डों की भूमिका पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य परिवर्तन संस्था (एसआईटी) की स्थापना की है। एसआईटी राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) का महत्वपूर्ण घटक होने के नाते एक बहु-विषयक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) का गठन करता है, जो एक अंतः स्थापित टीम है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यकतानुसार एक टीम लीडर सहित क्षेत्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं, ताकि मिशन के तहत एसआईटी की स्थापना को सुकर बनाया जा सके। विशेषज्ञों की अंतः स्थापित टीम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की देखरेख में काम करेगी।

अब तक एसएसएम के अंतर्गत कुल 20 एसआईटी अधिसूचित किए गए हैं, ये सक्रिय रूप से राज्य विशिष्ट विकास चालकों और विकास समर्थकों की पहचान करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और इस प्रकार राज्य और क्षेत्र विशिष्ट कार्यान्वयन और विकास रणनीतियों को तैयार करना सुकर बनाया जा सके।

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एसएसएम के अंतर्गत सफलतापूर्वक कार्य प्रारंभ कर दिया है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसआईटी का नाम
1	आंध्र प्रदेश	राज्य परिवर्तन संस्थान - एपी
2	असम	राज्य नवाचार और परिवर्तन आयोग (एसआईटीए)
3	अरुणाचल प्रदेश	इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल (आईटीए)
4	चंडीगढ़	राज्य परिवर्तन संस्थान - चंडीगढ़
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग (एसपीसी)
6	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	राज्य परिवर्तन संस्थान, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
7	हरियाणा	राज्य परिवर्तन संस्थान, हरियाणा
8	कर्नाटक	राज्य परिवर्तन संस्थान, कर्नाटक (एसआईटीके)
9	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान (मित्रा)
10	मेघालय	सरकार नवाचार प्रयोगशाला (जीआईएल)
11	मिजोरम	राज्य परिवर्तन संस्थान, मिजोरम (एसआईटी-एम)
12	पुदुचेरी	राज्य परिवर्तन संस्थान, पुदुचेरी
13	सिक्किम	स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्किम (एसआईटी-एस)
14	त्रिपुरा	त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (टीआईएफटी)
15	उत्तर प्रदेश	राज्य परिवर्तन आयोग (एसटीसी)
16	उत्तराखंड	उत्तराखंड के सशक्तिकरण और रूपांतरण के लिए राज्य संस्थान (सेतु आयोग)
17	नागालैंड	परिवर्तन के लिए अनुसंधान और मूल्यांकन संस्थान (आरईएसआईटी)
18	दिल्ली	राज्य परिवर्तन संस्थान - दिल्ली
19	राजस्थान	राजस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (आरआईटीआई)
20	हिमाचल प्रदेश	राज्य परिवर्तन प्रकोष्ठ (एसटीसी)

## नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफार्म

एक व्यापक 'राज्य सहायता मिशन (एसएसएम)' के हिस्से के रूप में, नीति आयोग साक्ष्य-आधारित नीति और प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए राज्यों, जिलों और ब्लॉकों में सरकारी पदाधिकारियों का समर्थन करने के लिए नीति फॉर स्टेट्स (एनएफएस) प्लेटफार्म की स्थापना की है। कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल, विनिर्माण, एमएसएमई, पर्यटन, शहरी, जल संसाधन और जल, सफाई एवं स्वच्छता (वॉश) सहित

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के लिए मंच पर ज्ञान उत्पादों का एक सेट रखा गया है। यह मंच सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शासन की सर्वोत्तम पद्धतियों, नीतिगत संसाधनों और डेटा अंतर्दृष्टि का एक विशाल भंडार प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, यह मंच विशेषज्ञ के नेतृत्व वाले हेल्प डेस्क, क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ एकीकरण और सावधानीपूर्वक क्यूरेटेड वार्ता के माध्यम से "सहकर्मी शिक्षण/पीयर लर्निंग" के द्वारा सरकारी नेतृत्व के लिए विश्वसनीय विशेषज्ञता तक पहुंच को सक्षम बनाता है। नीति आयोग न केवल राज्यों के बीच बल्कि वैश्विक हितधारकों के बीच भी मंच को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अंतर्दृष्टि, सूचना और ज्ञान के साथ समृद्ध दृश्यता और जुड़ाव को सक्षम करने के लिए एनएफएस के तहत विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम (वीबीएसआर) भी विकसित किया गया है। भारत सरकार के नीति आयोग में 7 मार्च, 2024 को माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने वीबीएसआर और नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों में केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों को शामिल करने के लिए नीति आयोग के भीतर वीबीएसआर की स्थापना की गई है, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आगे दोहराए जाने के लिए एक ब्लू प्रिंट के रूप में काम कर रहा है।



नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म और विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम का शुभारंभ

## नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला

नीति आयोग ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के अपने मूल जनादेश के तहत 'नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला' शुरू की है। कार्यशालाओं में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास और राष्ट्रीय और वैश्विक हित के अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह राज्यों और केंद्र

शासित प्रदेशों में नीतिगत अंतर्दृष्टियों और सुशासन पद्धतियों आदि को साझा करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रमुख विकास मुद्दों पर सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करती है। इन कार्यशालाओं का आयोजन नीति आयोग के वर्टिकलों/प्रभागों द्वारा किया गया था।

विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नीति आयोग की निरंतर बातचीत के माध्यम से प्राथमिकता वाले विषयों का पता लगाया गया। कार्यशालाओं की योजना राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी के साथ 1 या 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में बनाई गई थी। यह राउंड टेबल और पैनल चर्चाओं का एक संयोजन है और कुछ मामलों में फील्ड/साइट विज़िट के साथ जुड़ा है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, नीति- राज्य कार्यशाला श्रृंखला के तहत 20 कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विषयों को गहराई से जानने और चुनिंदा विषयों में भविष्य के रोडमैप तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। ये कार्यशालाएं निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं:-

	कार्यशाला का विषय
1.	विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर राष्ट्र परामर्श
2.	क्षेत्रीय कार्यशाला-महिलाओं के नेतृत्व में विकास को सक्षम बनाना-अंतिम मील तक पहुंचना (गोवा)
3.	राज्य स्तरीय नवाचार इकोसिस्टम का निर्माण: एक पीयर-लर्निंग कार्यशाला
4.	स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को बढ़ावा देना: निवेश और सार्वजनिक निजी भागीदारी के अवसरों को उत्प्रेरित करना
5.	राज्य स्तर पर नेट-जीरो रोडमैप का विकास
6.	समुद्रीय राज्यों में मत्स्य पालन की संभावना का दोहन
7.	राज्य और जिला स्तरीय नीति और योजना के लिए राज्य डेटा इकोसिस्टम का लाभ उठाना
8.	जल संरक्षण: जलाशयों का कायाकल्प
9.	परियोजना साथ से शिक्षण- शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला - स्कूली शिक्षा परिवर्तन में साथ का अंतःक्षेप
10.	अंतर्देशीय राज्यों में मत्स्य पालन की संभावनाओं का दोहन
11.	कुशल श्रमिकों की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना
12.	भारतीय शहरों में ई-मोबिलिटी को सशक्त करना: 100 ईवी रेडी शहरों का विकास करना
13.	क्षेत्रीय कार्यशाला - महिलाओं के नेतृत्व में विकास को सक्षम बनाना-अंतिम मील तक पहुंचना (अरुणाचल प्रदेश)
14.	वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी - रसायन, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स
15.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना सचिवों/एसडीजी प्रकोष्ठों के प्रमुखों के साथ एसडीजी
16.	निर्यात आधारित विकास के संचालक के रूप में राज्य
17.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नवाचार कौशल और प्रदर्शन में सुधार
18.	भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और देखभाल को मजबूत करने पर राष्ट्रीय कार्यशाला
19.	भारत में विनिर्माण वृद्धि में तेजी लाना
20.	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार

## स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

नीति आयोग ने 27 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में “स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर राष्ट्रीय कार्यशाला” का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन संबंधित हितधारकों के साथ किया गया ताकि भारत में बच्चों और किशोरों को अधिक व्यापक और समग्र देखभाल प्रदान करने के लिए आगे बढ़ने के तरीके को साझा किया जा सके और सहयोगात्मक रूप से विकसित किया जा सके और स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा के 6 स्तंभों जैसे स्वास्थ्य जांच स्क्रीनिंग, रेफरल और उपचार; मानसिक स्वास्थ्य समर्थन और परामर्श; योग, व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली; स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूल पर्यावरण; और प्राथमिक सहायता, तीव्र देखभाल और विशेष प्रावधान में स्कूल स्वास्थ्य को मजबूत करना है। कार्यशाला में केंद्रीय मंत्रालयों, स्वायत्त निकायों (जैसे एनसीईआरटी, सीबीएसई, आदि), बहुपक्षीय एजेंसियों (यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपीए, आदि), विकास भागीदारों (बीएमजीएफ, पीएटीएच, आदि), शिक्षकों, आदि ने भाग लिया।



“नई दिल्ली में 27 जुलाई 2023 को “स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना” विषय पर नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला में गणमान्य व्यक्ति

## राज्यों के लिए नेट शून्य रोडमैप का विकास

नेट जीरो रोडमैप और डीकार्बोनाइजेशन कार्यनीति विकसित करने के लिए राज्यों की नेतृत्व भूमिका को देखते हुए, नीति आयोग ने सीआईआई और गुजरात राज्य सरकार के साथ साझेदारी में 19 अक्टूबर 2023 को अहमदाबाद, गुजरात में “राज्यों के लिए नेट शून्य रोडमैप के विकास पर कार्यशाला” का आयोजन किया। कार्यशाला में कुल लगभग 50 लोगों ने भाग लिया, जिनमें से विभिन्न राज्यों और बाकी जान भागीदारों, थिंक-टैंक और गुजरात स्थित औद्योगिक इकाइयों से 17 पदाधिकारी ने भाग लिया।



19 अक्टूबर, 2023 को अहमदाबाद में "राज्यों के लिए नेट शून्य रोडमैप के विकास पर कार्यशाला" पर नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला में गणमान्य व्यक्ति

### परियोजना साथ-शिक्षा (साथ-ई) को समझना

परियोजना मानव पूंजी परिवर्तन हेतु सतत कार्रवाई-शिक्षा (साथ-ई) को नवीनतम साथ रिपोर्ट - स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए शिक्षण, नीति आयोग द्वारा 19 अक्टूबर, 2023 को आयोजित "प्रोजेक्ट साथ - शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: एक सह शिक्षण कार्यशाला" के साथ सिंक्रनाइजेशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय कार्यशाला सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों, शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनसीटीई, एनआईईपीए, शिक्षाविदों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्ञान भागीदारों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी। चर्चा उचित संसाधनों के साथ इष्टतम स्कूली संरचना को सुनिश्चित करने; सीखने के परिणामों में सुधार और मूल्यांकन को मजबूत करने; राज्य शिक्षा विभागों में संस्थानगत क्षमता और शासन को मजबूत करने पर थी।

### राज्य स्तरीय नवाचार इकोसिस्टम का निर्माण

अटल नवाचार मिशन ने भारत में नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नवंबर 2023 को बेंगलुरु में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करने में मदद की। 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और 8+ केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से कुल 120+ प्रतिभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया, जो नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की हमारी सामूहिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। अगले कदम के रूप में, मासिक वर्चुअल कनेक्ट के साथ-साथ इस प्रारंभिक कार्यशाला के परिणामों के आधार पर इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में तिमाही कार्यशालाएं करने का निर्णय लिया गया है।



बेंगलुरु में राज्य स्तरीय इनोवेशन इकोसिस्टम के निर्माण पर नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति



## गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार

नीति आयोग ने गुरुवार, 2 नवंबर 2023 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 'राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

भारत भर के 20 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सार्वजनिक राज्य विश्वविद्यालयों के 50 से अधिक कुलपतियों और चुनिंदा राज्य उच्च शिक्षा परिषदों के अध्यक्षों ने सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें गुणवत्ता, वित्तपोषण, शासन और रोजगार सहित चार व्यापक विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और परिणामों को मजबूत करने के अभिनव और प्रभावशाली तरीकों का पता लगाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ चल रहे परामर्श अभ्यास के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। इससे पहले 15 सितंबर, 2023 को नीति आयोग में डॉ. वी के पॉल की अध्यक्षता में 20 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च और तकनीकी शिक्षा सचिवों के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। इन दोनों विस्तृत परामर्शों के निष्कर्षों को 'राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार' करने पर सिफारिशों के रूप में एकत्रित किया जा रहा है।



02 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में "राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का विस्तार" पर नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला में गणमान्य व्यक्ति

## निजी स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को बढ़ावा देना

नीति आयोग ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 18 नवंबर 2023 को 'निजी स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को बढ़ावा देना: निवेश और सार्वजनिक निजी भागीदारी के अवसरों को उत्प्रेरित करना' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में टीयर 2 और 3 शहरों में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में मौजूदा कमियों पर चर्चा करने और इन कमियों को दूर करने के लिए संभावित समाधान निकालने तथा प्रमुख मुद्दों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के अन्य हितधारकों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक साथ लाया गया।

इस पूर्ण दिवसीय सम्मेलन में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य विभागों; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग (जीओआई); विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अस्पताल संस्थानों; उद्योग निवेशक (निधि); नाबार्ड; सीआईआई और अन्य उद्योग संघों; आरबीआई, एसबीआई और इंडिया बैंक संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न अन्य प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। चिह्नित किए गए मुद्दों और समाधानों के आधार पर संबंधित विभागों/मंत्रालयों को सिफारिशें प्रस्तुत करना प्रक्रियाधीन है।

## राज्यों में ई-मोबिलिटी और ई-बस विनिर्माण अवसर

नीति आयोग ने 29 नवंबर 2023 को विज्ञान भवन में ई-मोबिलिटी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ राज्य योजना विभाग, राज्य परिवहन उपयोगिताएं और स्मार्ट सिटी अधिकारियों सहित राज्य के अधिकारियों के साथ उपकरण और संसाधन साझा किए गए। नीति आयोग ने 30 नवंबर 2023 को राज्यों में ई-बस विनिर्माण के अवसरों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया। शीर्ष अंतरराष्ट्रीय ई-बस निर्माताओं को राज्यों के अधिकारियों के साथ अपनी योजनाओं को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।



नई दिल्ली में 'ई-मोबिलिटी' पर नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

## पेनेट्रेटिंग ग्लोबल वैल्यू चेन (जीवीसी): इंडियान पोर्टेंशियल एंड प्रॉस्पेक्ट्स

नीति आयोग द्वारा 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) के सहयोग से 'पेनेट्रेटिंग ग्लोबल वैल्यू चेन (जीवीसी): इंडियान पोर्टेंशियल एंड प्रॉस्पेक्ट्स' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में नीति के जीवीसी प्रयास में एक आवश्यक स्तंभ का गठन किया, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग, उद्योग संघों, विशेषज्ञों, थिंक टैंक और समाज के सभी संबंधित हितधारकों के संयुक्त प्रयासों को सुविधाजनक और उत्प्रेरित करता है। कार्यशाला में विचार-विमर्श पर भारत की जीवीसी भागीदारी के लिए चुनौतियों और अवसरों पर गहन चर्चा हुई और दो चयनित क्षेत्रों: मोटर वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित

किया गया। कार्यशाला में नीति आयोग के नेतृत्व की व्यापक और सक्रिय भागीदारी; भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी; उद्योग के नेताओं और 100 से अधिक प्रमुख वैश्विक और घरेलू फर्मों के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता; प्रख्यात उद्योग संघ; और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ उपस्थित रहे। कार्यशाला से मिली सीख परियोजना विश्लेषण और कार्यनीतिक सिफारिशों की पहचान का एक अभिन्न अंग बनी।



नई दिल्ली में, 5 दिसम्बर, 2023 को "पेनेट्रेटिंग ग्लोबल वैल्यू चेन: इंडियाज़ पोर्टेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट्स" पर आयोजित नीति राज्य कार्यशाला श्रृंखला में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति।

## राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नवाचार कुशलता और प्रदर्शन में सुधार

नीति आयोग द्वारा 6 दिसंबर, 2023 को रंग भवन सभागार, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में "राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का नवाचार योग्यता और प्रदर्शन में सुधार" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

निम्नलिखित विषयों पर पांच पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं:-

- (i) भारतीय राज्यों को सशक्त बनाना: विकसित भारत @ 2047 के लिए नवाचार क्षमता को प्रोत्साहित करना,
- (ii) नवोन्मेषी राज्य: परिवर्तनकारी यात्राओं का प्रदर्शन, (iii) सहयोगपूर्ण नवाचार: सामूहिक विकास के लिए राज्यों की भागीदारी, (iv) सीखा गया सबक और नवाचार की सफलता की कहानियों को दोहराना और (v) राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। पैनल चर्चा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार के सचिवों और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए अपने अलग-अलग दृष्टिकोण, अनुभव और अभिनव दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मार्गदर्शन करना था।

## समुद्रीय राज्यों में मत्स्य पालन की संभावनाओं का दोहन

केरल सरकार के सहयोग से केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई), कोच्चि, केरल ने 5 जनवरी, 2024 को 'समुद्रीय राज्य में मात्स्यिकी की संभाव्यता का दोहन' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। एक दिवसीय कार्यशाला का एजेंडा सतता, बाजार संबंध और जमीनी चुनौतियों से निपटने

के क्षेत्र में भारत के विशाल समुद्री मत्स्य क्षेत्र की संभावनाओं को समझने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित था। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, वैज्ञानिकों, उद्योग प्रतिनिधियों और चिकित्सकों के 200 से अधिक प्रमुख हितधारक शामिल हुए।



कोच्चि में आयोजित 'समुद्रीय राज्य में मत्स्य पालन की संभावना का दोहन करना' पर नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

### मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और देखभाल को मजबूत करना

भारत में मानसिक रूग्णता सहित गैर-संचारी रोगों से बहुत लोग पीड़ित हैं, और ऐसे रोगियों की संख्या पिछले 30 वर्षों में दोगुनी हो गई है। मानसिक विकारों के राज्यवार बोझ पर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (जीबीडी, 2019) स्टडी की रिपोर्ट है कि 2017 में 197.3 मिलियन भारतीय मानसिक विकारों से जूझ रहे थे। इस पृष्ठभूमि में और नीति फॉर स्टेट्स पहल के अनुसरण में, नीति आयोग ने 9 जनवरी 2024 को बैंगलोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएएस) और कर्नाटक राज्य के सहयोग से "मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और देखभाल को मजबूत करने" पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूदा कमियों और चुनौतियों पर राज्यों और प्रख्यात मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के विचार जानना और कुछ राज्यों से उन सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को सीखना था, जिन्हें अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी उनके अपने संदर्भ के साथ दोहराया जा सकता है।



9 जनवरी 2024 को बैंगलोर में "मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और देखभाल को मजबूत करना" पर नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

## जलाशयों का कायाकल्प

नीति आयोग द्वारा 12 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में 'जलाशयों का कायाकल्प' नामक एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य अमृत सरोवर मिशन से सीखे गए अनुभवों और पाठों को साझा करना और राज्यों द्वारा जलाशयों के कायाकल्प पहल के लिए एक मंच प्रदान करना था। इसका उद्देश्य जल अभावग्रस्त ब्लॉकों में इन प्रयासों को विस्तारित करने के लिए कार्यनीतियों पर चर्चा करना था, विशेष रूप से नीति आयोग द्वारा पहचाने गए 500 आकांक्षी ब्लॉकों में से 92 सबसे अधिक जल अभावग्रस्त ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करना था। उनके कार्यक्रम दिशानिर्देशों के भाग के रूप में सिफारिशों को अपनाने के लिए मंत्रालयों/विभागों के बीच कार्टवाई योग्य बिंदुओं के रूप में प्रमुख सिफारिशों को साझा किया गया था।



नई दिल्ली में 12 फरवरी, 2024 को 'जलाशयों का कायाकल्प' विषय पर नीति आयोग-राज्य कार्यशाला श्रृंखला में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

## भारत में विनिर्माण विकास में तेजी लाना

नीति आयोग ने 14 फरवरी 2024 को भोपाल, मध्य प्रदेश में "भारत में विनिर्माण विकास में तेजी लाना" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला उद्योग भागीदारों के साथ एक सहयोगी प्रयास था। 200 से अधिक प्रतिभागियों ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतियों पर विचार-विमर्श किया और विनिर्माण क्षेत्र में राज्य स्तरीय सर्वोत्तम प्रवृत्तियों को साझा करने और उद्योग की आवश्यकताओं और चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक मंच प्रदान किया। मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्य भाषण दिया।

## अंतर्देशीय राज्यों में मत्स्य पालन की संभाव्यता का दोहन

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 15 से 16 फरवरी 2024 को 'अंतर्देशीय राज्यों में मत्स्य पालन की संभाव्यता का दोहन' विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन अंतर्देशीय मत्स्य पालन के मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने और इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु आपसी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में अंतर्देशीय मत्स्य पालन से जुड़े सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए किया गया था। नीति

आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधियों, राज्य के मत्स्य पालन प्रतिनिधि, मछुआरे, उद्योगपति और शोधकर्ता सहित लगभग 100 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान कई सुझाव दिए गए जो इस क्षेत्र को उत्कृष्ट बना सकते हैं, जैसे कि एनबीसी और बीएमसी के माध्यम से स्वदेशी मछली प्रजातियों के साथ अंतर्देशीय मत्स्य पालन में विकास के आकांक्षी मॉडल को बढ़ावा देना, अमृत सरोवर पहल के तहत देश भर में समान नीतियां लाना, मछली से बने व्यंजनों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना आदि।



विशाखापट्टनम में 'अंतर्देशीय राज्य में मत्स्य पालन की संभाव्यता का दोहन' विषय पर नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

## सतत विकास लक्ष्यों में तेज़ी लाना

नीति आयोग ने राजस्थान सरकार और भारत में तकनीकी साझेदार यूएनडीपी और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से 4 और 5 मार्च, 2024 को राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जयपुर में 'सतत विकास लक्ष्यों में तेज़ी लाना' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और भारत सरकार के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, नीति आयोग के आदरणीय उपाध्यक्ष और सदस्य जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।

इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एसडीजी के स्थानीयकरण का आकलन करने, उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी को एकीकृत करने के अनुभवों को साझा करने, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर एसडीजी वित्त परिदृश्य का पता लगाने और 2030 एसडीजी एजेंडा के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के बीच में प्रगति में तेज़ी लाने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना था। ज्ञान के आदान-प्रदान को सुकर बनाने के लिए, सम्मेलन में एक एसडीजी प्रदर्शनी भी शामिल थी जहां राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने संबंधित एसडीजी बूथों पर स्थानीयकरण से संबंधित अपने तकनीकी उत्पादों को प्रदर्शित किया। इसके अतिरिक्त, तीन नॉलेज पोर्टलों का उद्घाटन किया गया, जिसमें यूएनडीपी का 'एसडीजी

नॉलेज हब, राजस्थान सरकार का 'खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड' और राजस्थान सरकार का 'एसडीजी -2 (शून्य हंगर) डैशबोर्ड' शामिल है।

कार्यशाला के परिणामों में एसडीजी को स्थानीयकृत करने और एसडीजी रूपरेखा का उपयोग करके प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्रों की पहचान करने, विविध हितधारकों के बीच अभिसरण को बढ़ावा देने, एसडीजी की उपलब्धि के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में राज्यों के लिए समर्थन शामिल था।



जयपुर में 'सतत विकास लक्ष्यों को त्वरित करना' पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

### कुशल कामगारों की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना

नीति आयोग ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 9 मार्च 2024 को 'कुशल कामगारों की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों के बीच ज्ञान साझा करने और चुनौतियों, अवसरों की पहचान करने और अन्य देशों में कुशल कामगार गतिशीलता के लिए मार्गों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों के साथ बातचीत को सक्षम करना था। 32 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया और चार राज्यों ने अंतरराष्ट्रीय श्रम गतिशीलता के लिए कौशल विकास पर अपनी संबंधित पहलों पर प्रस्तुतियां दीं। इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ आईएलओ दिल्ली कार्यालय, इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट, नैसकॉम और एलायंस एयर सहित कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हुए और इस कार्यक्रम में योगदान दिया।



नई दिल्ली में 9 मार्च 2024 को 'कुशल कामगारों की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देना' पर नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

## राज्य वित्त साधन और राज्य समन्वय

राज्य वित्त साधन और समन्वय वर्टिकल को व्यापक आर्थिक, वित्तीय, राजकोषीय और सामाजिक संकेतकों पर राज्यवार डेटाबेस अनुरक्षित करने; केंद्र से राज्यों को अंतरण का आकलन सहित राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने; संरचित समर्थन और पहलों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और राज्यों के वित्त साधनों और बहु-राज्यीय मुद्दों से संबंधित सभी मामलों के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वर्टिकल द्वारा वित्त आयोग, विशेष परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अनुरोध और अंतर्संरकारी अंतरण से संबंधित मुद्दे भी संचालित किए जाते हैं। 2023-24 के दौरान वर्टिकल द्वारा शुरू की गई प्रमुख गतिविधियाँ और अध्ययन इस प्रकार हैं :

### डेटाबेस का संग्रहण

यह वर्टिकल प्रमुख स्थूल, सामाजिक और वित्तीय संकेतकों पर राज्यवार डेटाबेस का अनुरक्षण करता है। वर्टिकल केंद्रीय अंतरण की जानकारी भी रखता है जिसे मासिक आधार पर अद्यतन किया जाता है। नीति आयोग द्वारा विभिन्न नीतिगत मामलों पर राज्यों को महत्वपूर्ण नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है।

### राज्यों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण सहित राज्य के वित्त साधनों का संक्षिप्त विवरण

वर्टिकल ने राज्य बजट 2023-24 में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करते हुए जीएसडीपी वृद्धि, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, स्वयं के करों से उत्पन्न संसाधनों सहित प्राप्तियाँ, पूंजीगत व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय, राजकोषीय और राजस्व घाटा तथा इसकी ऋण स्थिति सहित व्यय जैसे विभिन्न प्रमुख संकेतकों में उनके प्रदर्शन का आकलन करके राज्यों के वित्तीय और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया।

राज्यों के प्रमुख स्थूल-आर्थिक संकेतकों का अंतरराज्यीय विश्लेषण भी किया गया, जिसका उपयोग भावी विकास के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बातचीत/बैठकों में किया जा रहा है।

### राज्यों को आवंटन

केंद्र सरकार राज्यों की क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं और परियोजनाओं की 'देनदारियों को खत्म करने', जिसके लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद बजट प्रावधान नहीं किया गया है, को पूरा करने के लिए उनकी सहायता करने और सामाजिक-आर्थिक-भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है। राज्य वित्त एवं समन्वय वर्टिकल 'राज्यों को अंतरण' के तहत राज्यों को 'विशेष सहायता' के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को नीति आयोग की ओर से की गई सभी सिफारिशों के लिए नोडल वर्टिकल के रूप में कार्य करता है।



## राज्य और क्षेत्र प्रोफाइल

इस वर्टिकल ने राज्य पोर्टल के लिए नीति के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य और क्षेत्र प्रोफाइल के विकास में अपेक्षित सहायता प्रदान की। डेटा प्रोफाइल का उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि और संबद्ध सेवाओं, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और पोषण, विनिर्माण, एमएएसएमई, आजीविका संबंधी कौशल संवर्धन और श्रम कल्याण, पर्यटन, शहरीकरण और पानी और वाश के बारे में 'एक नज़र में' जानकारी प्रदान करना है। प्रोफाइल राष्ट्रीय प्रदर्शन की तुलना में प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है। उपर्युक्त डेटा प्रोफाइल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्र, शोधकर्ताओं आदि द्वारा 'राज्यों के लिए नीति' पोर्टल पर देख सकते हैं।

## राज्यों के साथ विविध कार्यों हेतु जुड़ाव

इसके अलावा समय-समय पर नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकल राज्यों के साथ कई विषयों पर कार्य करने हेतु जुड़े हुए हैं। इनमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों और सीईओ के दौरे शामिल हैं। कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

### अंडमान और निकोबार

अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधिकारियों के लिए निष्पादन परिणाम निगरानी रपरेखा (ओओएमएफ) पर एक दो दिवसीय कार्यशाला (27 - 28 जून 2023) का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विभागों के प्रतिभागी शामिल थे। संघ राज्य क्षेत्र सरकार के 29 विभागों के कुल 70+ अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया। प्रशिक्षण मुख्य रूप से समूह कार्य के रूप में करके सीखने (लर्निंग-बाय-डूइंग) के माध्यम से दिए गए लॉग फ्रेम दृष्टिकोण का उपयोग करके निगरानी की अवधारणाओं को समझाने पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र के कार्य योजना दस्तावेज और एसएफसी प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में भी ओओएमएफ को शामिल करना था। एसडीजी मैपिंग की मदद से ओओएमएफ को मजबूत करने पर भी एक सत्र आयोजित किया गया।

### आंध्रप्रदेश

माननीय प्रधानमंत्री ने भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अगले 25 वर्ष को 'अमृत काल' के रूप में परिकल्पना की है। नीति आयोग की 8वीं शासी परिषद बैठक के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए और विकसित भारत@2047 के लिए लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। इस बात को महत्व दिया गया कि नीति आयोग अगले 25 वर्षों के लिए राज्यों को अपनी रणनीतियाँ विकसित करने और राष्ट्रीय विकास एजेंडा के साथ इसे संरेखित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

"विकसित भारत@2047" के लिए माननीय प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप, नीति आयोग ने विकसित भारत@2047 के लिए राज्य का समग्र रोडमैप तैयार करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के साथ साझेदारी की। राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने के लिए राज्य में नीति आयोग के अधिकारियों और विशेषज्ञों की समर्पित टीम तैनात थी। इस प्रयास से एक टेम्पलेट विकसित होने की उम्मीद थी जिसका उपयोग अन्य राज्य सरकारों द्वारा 'अमृतकाल' के लिए अपने संबंधित विज़न दस्तावेज तैयार करने के लिए किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विज़न दस्तावेज जून 2024 के महीने में जारी होने की संभावना है।

### असम

सहकारी संघवाद के अधिदेश के तहत 29 जनवरी 2024 को सदस्य डॉ. वी.के. पॉल के नेतृत्व में असम राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, उद्योग, अवसंरचना और निवेश के साथ-साथ राज्य सहायता मिशन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।



असम राज्य के साथ जुड़ाव

## गुजरात

“विकसित भारत@2047” के लिए माननीय प्रधानमंत्री की आकांक्षा के अनुरूप, नीति आयोग ने इस विज़न को प्राप्त करने की दिशा में राज्य की यात्रा हेतु एक विस्तृत संरचित योजना तैयार करने के लिए गुजरात राज्य के साथ सहयोग किया। नीति आयोग ने ‘अमृत काल’ के लिए ‘विजन दस्तावेज’ तैयार करने हेतु राज्य के साथ मिलकर काम किया। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में विकसित गुजरात@2047 का शुभारंभ किया गया था। इसके साथ ही गुजरात विज़न दस्तावेज तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया। विकसित गुजरात@2047 की परिकल्पना है कि वर्ष 2047 तक, राज्य के प्रत्येक नागरिक समाज के “मूल्यवान” और “महत्वपूर्ण” ताने-बाने के भीतर “अच्छा कमाएगा” और “अच्छा जीवन बिताएगा”। विकसित गुजरात रोडमैप से नागरिक के जीवन, अर्थव्यवस्था और शासन के प्रत्येक पहलू में रणनीतिक परिवर्तन शुरू होने की उम्मीद है। इसमें तीन स्तंभों- सशक्त नागरिक; उन्नतशील अर्थव्यवस्था; और इसे प्राप्त करने के लिए प्रमुख समर्थक, में वितरित ग्यारह प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

नीति आयोग ने मातृ और बाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए विकास अध्ययन के लिए महिला और शिशु एकीकृत हस्तक्षेप (विंग्स) के संचालन के संबंध में अगस्त 2023 में मुख्य सचिव, गुजरात के साथ एक बैठक भी आयोजित की। चर्चा की एक श्रृंखला के बाद, राज्य सरकार ने आकांक्षी ब्लॉकों में स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी के साथ विंग्स के पूर्व-गर्भावस्था घटकों को संचालित करने की पहल की।

## हिमाचल प्रदेश

वर्ष 2022 में, आर्थिक सहयोग और विकास के लिए जर्मन फेडरल मंत्रालय [बीएमजेड] ने “हरित और सतत विकास भागीदारी को समर्थन” [जीएसडीपी समर्थन परियोजना] परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनल जुसममेनारबेट [जीआईजेड] को अधिकृत किया। यह परियोजना हरित और सतत विकास के लिए भारत-जर्मन साझेदारी का समर्थन करती है जिसे भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच छठे अंतर-सरकारी परामर्श के दौरान मई 2022 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर द्वारा समर्थन दिया गया था।

इस परियोजना के तहत, नीति आयोग और जीआईजेड ने अक्टूबर 2023 से सितंबर 2026 तक “जीएसडीपी-नीति परियोजना” नामक परियोजना के लिए एक कार्यान्वयन समझौता किया है।

यह परियोजना नीति आयोग के साथ आपसी चर्चा और समझौते के माध्यम से चयनित तीन राज्यों में राष्ट्रीय और राज्य स्तरों के एसडीजी पर संस्थागत क्षमता और डेटा प्रणाली में एसडीजी स्थानीयकरण को गहरा करने और निगरानी और महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने पर केंद्रित है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ शुरू की गई है और मेघालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ चर्चा चल रही है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकास अध्ययन के लिए महिला और शिशु एकीकृत हस्तक्षेप (विंग्स) मॉडल के हस्तक्षेपों को एक पायलट मोड में दोहराने में भी रुचि व्यक्त की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार, आईसीएमआर, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (डीबीटी-बीआईआरएसी), सेंटर फॉर हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट-सोसाइटी फॉर एप्लाइड स्टडीज (सीएचआरडी-एसएएस) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के साथ हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में विंग्स को शुरू करने और कार्यान्वयन अनुसंधान हेतु चर्चा और बैठकें आयोजित की गईं।

### जम्मू और कश्मीर

नीति आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में नीति आयोग द्वारा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर का दौरा किया गया। दौरे के दौरान टीम ने उप राज्यपाल, मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य हितधारकों से मुलाकात की। संघ राज्य क्षेत्र में विकास से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रमुख क्षेत्रों जहां नीति आयोग समयबद्ध तरीके से संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान कर सकता है, को चिन्हित किया गया।

मुख्य सचिव के साथ बैठक के दौरान, जम्मू-कश्मीर में जलविद्युत, पर्यटन अवसंरचना, स्टार्ट-वाइपी इकोसिस्टम और बस सेवाओं के विद्युतीकरण की अप्रयुक्त क्षमता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

### झारखंड

विकसित भारत@2047 के विज़न के साथ, नीति आयोग सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई बैठकें आयोजित करता है। वरिष्ठ ने डॉ. वी.के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के बीच रांची में एक बैठक बुलाई। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों जैसे विद्युत, कोयला, जनजातीय कार्य और महिला और बाल विकास मंत्रालयों से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकार के साथ विस्तार से चर्चा की गई थी।

### कर्नाटक

कर्नाटक राज्य में अल्प पोषण और एनीमिया से निपटने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने के लिए डॉ. वी.के. पॉल, सदस्य की अध्यक्षता में कर्नाटक सरकार के साथ परामर्श किया गया। कार्य योजना के विकास पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला 7 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, कर्नाटक सरकार, सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार और मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार ने भाग लिया। कार्यशाला और आगे के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा 23 नवंबर 2023 को एनीमिया मुक्त पौष्टिक कर्नाटक कार्य योजना विकसित और शुरू की गई थी।

### केरल

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नीति आयोग के जुड़ाव के भाग के रूप में, नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ केरल के माननीय मुख्यमंत्री और केरल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 जनवरी 2024 को तिरुवनंतपुरम में मुलाकात की। यात्रा के दौरान, नीति आयोग और केरल राज्य के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों के साथ केरल के विभिन्न विकास पहलुओं पर चर्चा की गई। माननीय उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने यात्रा के दौरान केरल राज्य योजना बोर्ड, केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (केआईआईएफबी) और कुटुंबश्री के अधिकारियों से भी मिले।



केरल के माननीय मुख्यमंत्री के साथ नीति आयोग के वी. सी. की बैठक

### मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई पर भोपाल में 8 अगस्त 2023 को एक चर्चा बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान, डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट की एक प्रति मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की और नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में मध्य प्रदेश द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्रालयों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित कई प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समापन भाषण दिया गया।



भोपाल में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर चर्चा बैठक की झलकियाँ

### मेघालय

मेघालय राज्य के साथ दो बैठकें आयोजित की गईं। पहली बैठक नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार और मेघालय सरकार के मुख्य सचिव के बीच शिलांग में हुई।

नीति आयोग ने राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों और नीति आयोग के साथ मिलकर काम करने के अवसरों जैसे गवर्नेंस इनोवेशन लैब और राज्य भारत परिवर्तन संस्था (एसआईटीआई) पर विस्तार से चर्चा की। दूसरी बैठक नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मेघालय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच शिलांग में हुई। यह बैठक प्रमुख क्षेत्रों में राज्य के विज्ञान और कार्य नीति पर केंद्रित थी।

## राजस्थान

16 जून, 2023 को विश्व खाद्य कार्यक्रम टीम के साथ-साथ राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर के अधिकारियों के लिए ओओएमएफ पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण सत्र में राज्य सरकार के मूल्यांकन विभाग के कुल 20 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण मुख्यतः लॉग फ्रेम दृष्टिकोण, ओओएमएफ में दृष्टिकोण और संकेतक युक्तिकरण का उपयोग करके निगरानी की अवधारणाओं को समझने पर केंद्रित था।

## त्रिपुरा

डॉ. वी.के.सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग ने सहकारी संघवाद के (मेनडेट) अधिदेश के तहत 20 दिसंबर, 2023 को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य अवसंरचना, बांस, रबड़, अगरवुड, अनानास, व्यापार आईटी सेवाओं और स्टार्ट-अप से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

## नागालैंड

योजना और परिवर्तन विभाग, नागालैंड ने 17 अक्टूबर, 2023 को कोहिमा में सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र (एसडीजीसीसी) वेबसाइट, एसडीजी डैशबोर्ड का अनावरण करते हुए एक लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया। उपमुख्यमंत्री श्री टी.आर. जेलियांग ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और एडीजी के महत्व और इसके व्यापक निहितार्थों पर प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है कि नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में योजना और परिवर्तन विज्ञान के भीतर एसडीजी समन्वय केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य है। कार्यक्रम में, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023: नागालैंड का कार्य-निष्पादन और आगे की राह पर एक प्रस्तुति के माध्यम से बहुआयामी गरीबी को कम करने में नागालैंड द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में नीति आयोग और यूएनडीपी के अन्य विद्वानों ने भी भाग लिया। इस विज़िट में वरिष्ठ सलाहकार ने नागालैंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो से मुलाकात की और उन्हें एमपीआई में नागालैंड के प्रदर्शन के बारे में बताया और नागालैंड के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की।



राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023: नागालैंड का प्रदर्शन विश्लेषण और भावी कार्यनीति की झलकियाँ



अंड

3

थिंक-टैक  
गतिविधियाँ

## भूमिका

नीति आयोग का एक अन्य प्रमुख अधिदेश प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के समान विचारधारा वाले थिंक टैंक के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और साझेदारी को प्रोत्साहित करना है। इसे ध्यान में रखते हुए नीति आयोग, विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विख्यात नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नीति आयोग देश को जटिल नीतिगत चुनौतियों का सामना करने और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, नीति आयोग ने पुरानी भागीदारी जारी रखी और ज्ञान, नवाचार तथा उद्यमशीलता इकोसिस्टम बनाने और तीव्र, समावेशी और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए देश और विदेश दोनों के विभिन्न थिंक-टैंक, नागरिक समाज, उद्योग और शैक्षिक तथा नीतिगत अनुसंधान संस्थानों के साथ नई भागीदारी की शुरुआत की।

## नीति आयोग में इन-हाउस व्याख्यान श्रृंखला:

पिछले वर्ष नीति आयोग के अधिकारियों और भारत सरकार के अन्य चुनिंदा अधिकारियों के लिए भारत की विकास रणनीतियों पर एक इन-हाउस व्याख्यान श्रृंखला शुरू की गई। इन व्याख्यानों का उद्देश्य प्रतिभागियों को सरकार की प्रमुख पहलों के बारे में जागरूक करना, उनके ज्ञान को बढ़ाना, क्षमता का निर्माण करना, अधिक उत्पादक और समावेशी वातावरण बनाना, अभिनव सोच को प्रोत्साहित करना और राष्ट्र के विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साझा प्रतिबद्धताओं को विकसित करना है। सितंबर, 2022 से प्रारंभ होकर, दिसंबर, 2022 तक चार इन-हाउस व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई।

इस श्रृंखला का पांचवां व्याख्यान 27 जनवरी, 2023 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका विषय था - भारत के परिवर्तनकारी विकास का दशक। सीईओ, नीति आयोग द्वारा संचालित श्रृंखला में नीति आयोग के सदस्य डॉ अरविंद विरमानी ने मुख्य भाषण दिया, जिसके बाद, सीबीसी के अध्यक्ष श्री आदिल जैनुलभाई, श्री अमित चंद्रा, एमडी, बेन कैपिटल और सुश्री अंजलि बंसल, संस्थापक भागीदार, अवाना कैपिटल की एक पैनल चर्चा हुई।

इस श्रृंखला का छठा व्याख्यान 24 फरवरी, 2023 को डीआरडीओ इंडिया भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था - अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: व्यापक उपलब्धियाँ, अनंत अवसर। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत ने मुख्य भाषण दिया, जिसके बाद नीति आयोग के सीईओ द्वारा संचालित एक सामूहिक चर्चा हुई, जिसमें सुश्री खुशबू एस, एक स्कूली छात्रा भी शामिल थीं, जो आज़ादीसैट बनाने वाली टीम का हिस्सा बनीं।



24 फरवरी, 2023 को "अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: व्यापक उपलब्धियाँ, अनंत अवसर" पर छठा व्याख्यान



इस श्रृंखला का सातवां व्याख्यान 31 मार्च, 2023 को "बुनियादी ढांचे का कार्यान्वयन: सफलता के लिए चुनौतियां और रणनीतियां" विषय पर आयोजित किया गया। आईसीएफ के महाप्रबंधक श्री बी जी माल्या ने मुख्य भाषण दिया। एलएंडटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डीन, श्री वी टी चंद्र शेखर राव और सद्भाव ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री रोहित मोदी सहित सम्मानित सूचीबद्ध पैनल ने रोचक ज्ञान साझा किया जो बुनियादी ढांचे के विकास पर नीतिगत सूत्र का आधार बन सकता है।

आठवां व्याख्यान 28 अप्रैल 2023 को "जी20 नेतृत्व की प्रक्रिया: बदलते विश्व को अपनाना" पर आयोजित किया गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के. बेरी ने मुख्य भाषण दिया, जिसके बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संचालित एक पैनल चर्चा हुई, जिसमें विदेश मंत्रालय के सचिव श्री दम्भू रवि भी शामिल हुए। एनसीईईआर की महानिदेशक डॉ. पूनम गुप्ता ने सितंबर 2023 में आगामी जी-20 नेतृत्व के शिखर सम्मेलन से पूर्व ग्लोबल साउथ के लिए मुख्य प्राथमिकताओं पर चर्चा की।



28 अप्रैल 2023 को "जी20 लीडर्स प्रोसेस: बदलती दुनिया के साथ अनुकूलन" पर आठवां व्याख्यान

नौवां इन-हाउस नीति व्याख्यान भारत की अब तक की ईवी यात्रा और भावी प्रगति पर 30 जून, 2023 को आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री कामरान रिज़वी द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति और भारत के लिए टिकाऊ और प्रगतिशील गतिशीलता समाधानों की सामूहिक खोज में उल्लेखनीय उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए निर्धारित किया गया जिस पैनल में श्री अमिताभ कांत, जी20 शेरपा; श्री शैलेश चंद्रा, एमडी, टाटा मोटर्स; स्विच मोबिलिटी के सीईओ श्री महेश बाबू और एथर एनर्जी के सह-संस्थापक और सीईओ श्री तरुण मेहता शामिल हुए।



30 जून, 2023 को "भारत की अब तक की ईवी यात्रा और आगे की यात्रा" पर नौवां व्याख्यान

दसवां इन-हाउस नीति व्याख्यान हरित क्रांति से अमृत काल तक: भारतीय कृषि के लिए सीख और भावी राह विषय पर 31 अगस्त, 2023 को आयोजित किया गया। प्रो. रमेश चंद्र, सदस्य (कृषि), नीति आयोग ने मुख्य भाषण दिया, जिसके बाद पैनल चर्चा हुई, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री मनोज आहूजा; डॉ. भरत रामास्वामी, अर्थशास्त्र के डीन और प्रोफेसर, अशोका विश्वविद्यालय; निंजाकार्ट के सह-संस्थापक श्री वासुदेवन चिन्नथम्बी शामिल हुए। इसका संचालन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग ने किया।

ग्यारहवां व्याख्यान 9 अक्टूबर, 2023 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भारत की रुढ़ीवादी और सतत परंपरा विषय पर आयोजित किया गया। इसमें मुख्य भाषण यूआईएफ के अध्यक्ष श्री एस गुरुमूर्ति द्वारा दिया गया और पैनल चर्चा का संचालन नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया गया।



09 अक्टूबर, 2023 को 'भारत की रुढ़ीवादी और सतत परंपरा' पर 11वां व्याख्यान

आकाशवाणी भवन में 31 अक्टूबर, 2023 को हरित विकास का वित्तपोषण-शीर्ष से निम्नतम स्तर तक का दृष्टिकोण पर बारहवां इन-हाउस नीति व्याख्यान आयोजित किया गया। आईफॉरेस्ट के अध्यक्ष और सीईओ श्री चंद्र भूषण और 14ट्री फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. प्रवीण भागवत ने हरित विकास की ओर प्रगति पर चर्चा करने के लिए मुख्य भाषण दिया। श्री चंद्र भूषण, डॉ. प्रवीण भागवत और नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र के पैनल ने भागीदारी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्यान्वयन के प्रेरक उदाहरण प्रदर्शित किए।

13वां इन-हाउस नीति व्याख्यान 30 नवंबर, 2023 को रंग भवन, नई दिल्ली में 'गंतव्य 2030: सतत विकास लक्ष्य के लिए उत्प्रेरित कार्रवाई' विषय पर आयोजित किया गया। इस सामूहिक चर्चा में शामिल विशिष्ट वक्ता - सुश्री एलिजाबेथ फौरे, प्रतिनिधि और कंट्री डायरेक्टर, डब्ल्यूएफपी; संयुक्त राष्ट्र महिला से भारत के लिए प्रतिनिधि सुश्री सुजन फर्ग्यूसन और संयुक्त राष्ट्र आरसीओ के अर्थशास्त्री श्री क्रिस्टोफर गैरोवे ने भारत में गरीबी उन्मूलन, पोषण, लैंगिक समानता और एसडीजी वित्तपोषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरि ने पैनल चर्चा का संचालन किया और नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा दी गई समापन टिप्पणी ने दर्शकों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया।



30 नवंबर 2023 को 'गंतव्य 2030: सतत विकास लक्ष्य के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना' पर तेरहवां व्याख्यान

## शिक्षाविदों और थिंक टैंकों के साथ तालमेल

शिक्षाविद और थिंक टैंक के साथ तालमेल नीति आयोग के उच्च प्राथमिकता वाले अधिदेशों में से एक है। नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकलों ने शिक्षाविद और थिंक टैंक के साथ निरंतर आधार पर काम करने के लिए तंत्र तैयार किया है।

चूंकि भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है, माननीय प्रधान मंत्री के विकसित भारत विजन को सुकर बनाने, और अत्याधुनिक विचारों तथा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने, इनक्यूबेट करने और क्यूरेट करने हेतु राज्यों के साथ गहरे तालमेल के लिए नीति आयोग द्वारा एक "चिंतन शिविर" का आयोजन किया गया। इस शिविर का व्यापक विषय "अमृतकाल के विज़न को साकार करने के लिए नीति आयोग की पुनर्कल्पना" था। शिविर के प्रमुख विषयों में से एक अन्य थिंक टैंक/अनुसंधान/शैक्षणिक संगठनों के साथ नीति आयोग की साझेदारी को सुदृढ़ करना है।



चिंतन शिविर का आयोजन 150 विश्वविद्यालयों और प्रमुख शैक्षिक संस्थानों के कुलपतियों/प्रमुखों के साथ किया गया

इस संदर्भ में नीति आयोग ने अप्रैल 2023 में देश भर के प्रख्यात थिंक टैंक/विश्वविद्यालयों के साथ तीन कार्यशालाएं आयोजित की। यह परामर्श कार्यक्रम थिंक टैंकों के साथ नीति आयोग की साझेदारी को मजबूत करना, भारत को विकसित भारत बनाने में मदद करने में नीति आयोग की भूमिका और नीति आयोग को बैंक ऑफ विजडम के रूप में विकसित करने जैसे निम्नलिखित विषयों पर प्रमुख हितधारकों के साथ नीति आयोग के प्रभावी सहयोग में सुधार लाने पर केंद्रित रहा। इस कार्यालय ने नीति निर्माण में योगदान करने और भारत@2047 के लिए विकास और विकास गतिविधि की दिशा में काम करने के लिए सभी सहभागियों के बीच कुशल ज्ञान साझाकरण और सूचना के आदान-प्रदान को अनुकूल बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है।

इसके अलावा, नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकलों द्वारा थिंक टैंक से संबंधित कई गतिविधियों की गई हैं, संबंधित वर्टिकलों की गतिविधियों का विवरण खण्ड 4 में दर्शाया गया है।

## ऊर्जा मॉडलिंग और डेटा प्रबंधन

### भारत का ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 (आईईएसएस 2047) का शुभारंभ

नीति आयोग ने भारत सरकार की विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों के एकीकृत प्रभाव का आकलन करने के लिए 20 जुलाई 2023 को संशोधित आईईएसएस 2047 जारी किया। यह जलवायु लक्ष्यों और ऊर्जा संक्रमण पर प्रगति के लिए ट्रैकिंग टूल के रूप में कार्य कर सकता है। अद्यतन भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (आईईएसएस 2047) नीति आयोग द्वारा विकसित एक ओपन-सोर्स टूल है। यह भारत सरकार की विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, नवीकरणीय खरीद दायित्व, प्रधानमंत्री-कुसुम, अपतटीय पवन कार्यनीति, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, ऊर्जा दक्षता, और अन्यो के सामूहिक प्रभाव का मूल्यांकन करता है। यह उपकरण 2047 तक उत्सर्जन, लागत, भूमि और जल की आवश्यकताओं जैसे कारकों पर विचार करते हुए भारत में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करता है।

आईईएसएस 2047 एक इंटरैक्टिव टूल है जो मंत्रालयों और विभागों को निवल शून्य (नेट जीरो) प्राप्त करने के लिए विविध ऊर्जा संक्रमण परिदृश्य विकसित करने में सहायता करता है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों के लेखांकन को सक्षम बनाता है और भविष्य की आवश्यकता का अनुमान लगाता है और इस प्रकार बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता को कम करता है।

### भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (आईईएसएस) 2047 से 2070 तक बढ़ाना:

इस मॉडल को 2070 तक बढ़ाने के लिए एक विस्तृत प्रयास किया जा रहा है। आईईएसएस मॉडल को अंतिम रूप देने के लिए लाइन मंत्रालयों, उद्योग संघों और थिंक टैंक के साथ व्यापक परामर्श आयोजित किए जाएंगे।

### भारत जलवायु और ऊर्जा डैशबोर्ड का शुभारंभ

नीति आयोग ने 20 जुलाई 2023 को भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड (आईसीईडी) जारी किया। आईसीईडी क्लाउडमेट एक्शन प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इन-बिल्ट एनालिटिक्स के साथ नियर रियल टाइम डेटा प्रदान करता है। यह पोर्टल स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में भारत की प्रगति की निगरानी के लिए डेटा को संश्लेषित करता है। 500 से अधिक मापदंडों, 2000 इन्फोग्राफिक्स और इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन के साथ, आईसीईडी 3.0 भारत के ऊर्जा क्षेत्र और कई इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन का विस्तृत दृश्य प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को भारत के ऊर्जा क्षेत्र की समग्र जानकारी हासिल करने की अनुमति प्राप्त होती है। यह मंच ऊर्जा क्षेत्र, जलवायु

और संबंधित आर्थिक परिदृश्य से संबंधित नियर रियल टाइम डेटा के लिए एक व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करता है।

## परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन

भारत में स्वच्छ, कनेक्टेड, साझा, टिकाऊ और समग्र गतिशीलता पहल के संचालन के लिए, मार्च 2019 में नीति आयोग में ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया गया। तब से इस परिवर्तनकारी गतिशीलता में भारत को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत निर्णय और कार्यनीतियां बनाई गईं तथा सिफारिश की गई।

भारत विश्व का सबसे बड़ा दोपहिया और तिपहिया निर्माता, दूसरा सबसे बड़ा ट्रैक्टर और बस निर्माता, तीसरा सबसे बड़ा भारी ट्रक निर्माता और चौथा सबसे बड़ा कार निर्माता है। ईवी इकोसिस्टम में नवाचार, दक्षता, घरेलू विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के लिए ईवी की प्रारंभिक अग्रिम लागत को कम करने के लिए भारत सरकार ने 5 वर्षों के लिए 7.4 बिलियन अमरीकी डालर के संयुक्त परिव्यय के साथ योजनाएं शुरू कीं। हमारे द्वारा विकसित सभी रणनीतियों और योजनाओं को उद्योग से प्रबल सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

## अंतरराष्ट्रीय सहयोग

### भारत-अमेरिका कार्यनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी के तहत सतत विकास स्तंभ

साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी (एसएजीई) का दूसरा चरण 3 मई, 2023 को लॉन्च किया गया। एसएजीई एक संघ है जिसमें यूएसएआईडी, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग और ऊर्जा विभाग की तीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं शामिल हैं: लॉरेंस बर्कले राष्ट्रीय प्रयोगशाला, राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगशाला और प्रशांत नॉर्थवेस्ट राष्ट्रीय प्रयोगशाला। ऊर्जा के लिए दक्षिण एशियाई समूह का उद्देश्य सतत विकास स्तंभ (एसजी पीलर) के तहत पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए अनुसंधान, क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। सतत विकास स्तंभ की सह-अध्यक्षता बैठक में 2023-24 के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें जीवनचक्र आकलन, निर्माण क्षेत्र मॉडलिंग, क्षमता निर्माण और जैव ऊर्जा आकलन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल था। अमेरिकी प्रयोगशालाओं के परामर्श से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया है।

### नीदरलैंड दूतावास के साथ सहयोग

नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास के बीच हस्ताक्षरित आशय विवरण (एसओआई) के तहत, भारी शुल्क गतिशीलता ईंधन के रूप में एलएनजी पर संयुक्त अध्ययन पूरा हो गया है और दोहरी समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। एमएसएमई डीकार्बोनाइजेशन, अपशिष्ट-से-ऊर्जा और प्रौद्योगिकी लागत वक्रों पर भावी कार्यकलापों के लिए विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एसओआई के दूसरे चरण के लिए एमएसएमई डीकार्बोनाइजेशन, अपशिष्ट से ऊर्जा और प्रौद्योगिकी लागत जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है ताकि नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास के बीच आगे की चर्चा की जा सके। नीति आयोग और नीदरलैंड का दूतावास वर्तमान में ऊर्जा संक्रमण के संबंध में परियोजनाएं शुरू करने के लिए एसओआई पर कार्य कर रहे हैं। एसओआई के भाग के रूप में, 'मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन खंड में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी' विषय पर रिपोर्ट 6 फरवरी 2024 को इंडिया एनर्जी वीक, गोवा में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीदरलैंड के ऊर्जा राजदूत द्वारा शुरू की गई थी।

## भारत जलवायु और ऊर्जा मॉडलिंग फोरम (आईसीईएमएफ):

भारत-अमेरिका कार्यनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (एससीईपी) के सतत विकास स्तंभ (एसजी स्तंभ) के तत्वावधान में 2 जुलाई 2020 को इंडिया क्लाइमेट एंड एनर्जी मॉडलिंग फोरम को मूल रूप से इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम (आईईएमएफ) के रूप में संस्थागत किया गया था। ग्लासगो में सीओपी26 के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई "पंचामृत" प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, आईईएमएफ के दायरे को जलवायु और आर्थिक मॉडलिंग को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया, जिससे आईसीईएमएफ का कार्याकल्प किया जा सके। फोरम में 40 से अधिक सदस्य शामिल हैं और इसका उद्देश्य मॉडलिंग और दीर्घकालिक ऊर्जा नियोजन अभ्यास के लिए शोधकर्ताओं, ज्ञान भागीदारों, थिंक टैंक तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सरकारी एजेंसियों और विभागों को शामिल करना है। विभिन्न ऊर्जा और जलवायु संबंधी मॉडलों, उपकरणों और परिदृश्यों के उपयोग पर नियमित वेबिनार और चर्चाएं आयोजित की गई हैं।

## यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (यूकेआईआईएफबी)

यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (यूकेआईआईएफबी) नीति आयोग और लंदन शहर के संयुक्त नेतृत्व में एक सहयोगी पहल है। यह भारत में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए एकजुट होकर काम करने हेतु दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह औपचारिक रूप से 11 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता में भारत के माननीय वित्त मंत्री और यूनाइटेड किंगडम के राजकोष के चांसलर द्वारा शुरू किया गया।

## ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन पर भारत-फ्रांस वार्ता

ब्लू इकोनॉमी और महासागर प्रशासन पर पहली भारत-फ्रांस वार्ता दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को पेरिस में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नीति आयोग के सीईओ ने किया था और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ध्रुवों और महासागरों के संरक्षक ने किया था।

दोनों पक्षों ने पर्यावरण और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के उद्देश्य से एक-दूसरे की पहलों में सहयोग और समर्थन करने और महासागर शासन पर प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय निकायों में बारीकी से समन्वय करने पर विस्तृत चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडलों ने ब्लू इकोनॉमी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन, ब्लू कार्बन, मत्स्य पालन, तटीय और समुद्री स्थानिक योजना, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग में द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित एजेंडा मदों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय और फ्रांसीसी पक्षों की एजेंसियों की भी पहचान की गई।

पेरिस में अक्टूबर 2023 में आयोजित पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, दोनों पक्षों ने 21 फरवरी 2024 को नीति आयोग, नई दिल्ली में बैठक की और चिह्नित सहयोग क्षेत्रों में कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। 25-26 जनवरी, 2024 को माननीय फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में द्विपक्षीय मंच के माध्यम से हुई प्रगति को स्वीकार किया गया था। दोनों पक्षों ने इस द्विपक्षीय मंच को भारत और फ्रांस के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाने के लिए दोहराया।



ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर पहला भारत-फ्रांस संवाद पेरिस में 12 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया



नीति आयोग, नई दिल्ली में 21 फरवरी, 2024 को आयोजित पहली द्विपक्षीय बैठक के अनुसरण में अनुवर्ती बैठक

## अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुच्छेद IV परामर्श

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में 13 सितंबर, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ भारत आर्टिकल IV कंसलटेशन 2023 के लिए एक बैठक आयोजित की गई। आईएमएफ मिशन के अंतिम वक्तव्य के मसौदे पर आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और आईएमएफ को जानकारी प्रदान की गई।

## भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक आर्थिक साझेदारी

29 अक्टूबर, 2019 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणामस्वरूप स्ट्रेटेजिक पार्टनर काउंसिल (एसपीसी) की स्थापना

की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता क्रमशः भारत के माननीय प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा की जाएगी। यह समझौता कार्यनीतिक भागीदारी परिषद (एसपीसी) के लिए एक सारगर्भित संरचना निर्धारित करता है। एसपीसी के तहत, 'अर्थव्यवस्था और निवेश' नामक मंत्रिस्तरीय कार्यक्षेत्र में से एक का नेतृत्व माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के मार्गदर्शन में नीति आयोग द्वारा किया गया।

28-29 अक्टूबर, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री की रियाद यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 12 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिकी और आईटी और उद्योग और अवसंरचना पर 4 संयुक्त कार्य समूहों के विचार-विमर्श के दौरान कई अवसरों की पहचान की गई और सक्रिय रूप से अनुपालन किया गया। सितंबर 2023 में आयोजित जी 20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर, 6 अतिरिक्त समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और 8 तैयारी के अंतिम चरण में हैं जिन पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

### भारत में सऊदी अरब के निवेश को प्रोत्साहित करना

2016 और 2019 में माननीय प्रधानमंत्री की किंगडम की यात्रा और 2019 में महामहिम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के बाद, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सऊदी निवेश की संभावना पर चर्चा की। फरवरी 2019 में यह घोषणा की गई थी कि सऊदी अरब देश की विकास क्षमता को देखते हुए पेट्रोरसायन, अवसंरचना और खनन के क्षेत्रों में भारत में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर निवेश करने पर विचार कर रहा है।

सितम्बर, 2023 में महामहिम क्राउन प्रिंस की भारत की राजकीय यात्रा में दोनों देश सऊदी पक्ष द्वारा किए गए 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश के वादे को पूरा करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर सहमत हुए। इसमें से 50 बिलियन डॉलर वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी के लिए निर्धारित किया गया था जो सऊदी अरामको, आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी और भारतीय फर्मों द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक मेगा प्लांट है।

भारत में सऊदी अरब के निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, सऊदी अरब के साथ निवेश में अधिकार प्राप्त एक संयुक्त कार्य बल की स्थापना की गई है जो निवेश के लिए नई परियोजनाओं की पहचान करेगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में सचिवों के एक समूह का गठन अक्टूबर 2023 में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं की पहचान करने के लिए किया गया, जिन्हें सऊदी अरब पक्षकार के साथ पेश किया जा सकता है। समूह में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरडी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) और विदेश मंत्रालय (एमईए) के सचिव शामिल हैं। सचिवों का यह समूह सऊदी अरब के साथ संयुक्त कार्यबल का केंद्र भी तैयार करता है।

### अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का दौरा

माननीय उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने "जलवायु से संबंधित कार्टवाइ के व्यापक आर्थिक प्रभाव" विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फ्लैगशिप सम्मेलन में एक विशेष भाषण प्रस्तुत किया, जो 5 और 6 जून, 2023 को वाशिंगटन डीसी में पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस में आयोजित किया गया था। उन्होंने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन द्वारा आयोजित एसडीजी साइड कार्यक्रम में भी भाग लिया और 18 सितंबर, 2023 को सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग में भी भाग लिया। वे 21-24 अप्रैल, 2024 के दौरान कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वित्त और आर्थिक योजना मंत्रियों के लिए 2024 हार्वर्ड मंत्रिस्तरीय नेतृत्व मंच में वर्तमान और पूर्व मंत्रियों के प्रतिष्ठित सहायक संकाय का एक हिस्सा रहे हैं। उन्होंने फोरम में मानव पूंजी विकास के सम्बन्ध में इन्वेस्टमेंट केस के निर्धारण पर मुख्य टिप्पणी भी प्रस्तुत की।



## जी 20 थिंक टैंक कार्यशाला श्रृंखला

भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या 'एक पृथ्वी-एक परिवार-एक भविष्य' के विषय पर केंद्रित जी-20 अध्यक्षता ने जटिल वैश्विक समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण शुरू करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। जी-20 के संदेश को घरेलू प्रणाली में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने और जी-20 नई दिल्ली के नेतृत्व की घोषणा (एनडीएलडी) को लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने हेतु नीति आयोग ने 100 से अधिक थिंक टैंक और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य एनडीएलडी से उभरने वाले प्रमुख मुद्दों/कार्य बिंदुओं की पहचान करना और अन्य प्रासंगिक मुद्दों को उजागर करना है, जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। कार्यशालाओं के परिणामों की परिकल्पना महत्वपूर्ण विषयों पर जी-20 के परिणामों पर गहन चर्चाओं और विश्लेषण के लिए एक संरचित मंच उपलब्ध कराने तथा 10 फीडर कार्यशालाओं के परिणामों को सम्मिलित करते हुए एक समेकित परिणाम दस्तावेज तैयार करने के लिए की गई थी, जिसमें कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा और इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियों के साथ कार्टवाई योग्य परिणाम शामिल होंगे।

जी-20 एनडीएलडी से उभरने वाले निम्नलिखित विशिष्ट महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1 से 10 फीडर विषयगत कार्यशालाओं का आयोजन 1 से 10 नवंबर, 2023 की अवधि के दौरान किया गया:

1. बेहतर समावेशी विश्व के लिए भारत-एयू सहयोग
2. विकास के लिए डेटा का उपयोग (डी4डी)
3. पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप लागू करना
4. डीपीआई के माध्यम से विकास, वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देना
5. सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाना
6. विकास और समृद्धि के लिए समावेशी व्यापार
7. भारतीय विकास मॉडल
8. नारी शक्ति - महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर अग्रसर।
9. विकास और हरित विकास के लिए एमडीबी और वैश्विक वित्त तक पहुंच।
10. सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता

प्रत्येक कार्यशाला में 20-30 थिंक टैंक और विशिष्ट विषयों पर काम करने वाले 8-10 शिक्षाविदों ने भाग लिया।

- 'बेहतर समावेशी विश्व के लिए भारत-एयू सहयोग' पर चर्चा समावेशी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने, गरीबी और असमानता को कम करने तथा यह सुनिश्चित करने की पद्धति पर केंद्रित थी कि सभी लोगों को भोजन, पानी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन उपलब्ध हों।
- 'विकास के लिए डेटा का दोहन' पर विचार-विमर्श में डिजिटल अंतर को पाटने पर जोर दिया गया, जिसमें लिंग और डेटा असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया गया, जबकि विकास उद्देश्यों के लिए डेटा के समावेशी उपयोग का भी समर्थन किया गया।

- 'पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप को लागू करना' पर चर्चा सतत पर्यटन प्रथाओं में एलआईएफई के लिए यात्रा को प्रभावी ढंग से शामिल करने, ग्रीन टूरिज्म अम्ब्रेला के तहत ग्रामीण पर्यटन को आगे बढ़ाने और साहसिक पर्यटन में अधिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही। यह वर्तमान में इस क्षेत्र की प्रमुख बाधाओं की पहचान करने और इसके समाधान उपायों पर चर्चा करने के अतिरिक्त है।
- 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' पर विभिन्न हितधारकों के लिए डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण वास्तुकला के निहितार्थ, एआई में नियामक चुनौतियों, डेटा साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक तंत्र की संभावनाओं और एआई विकास में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे नैतिक विचारों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) जी-20 एनडीएलडी का एक महत्वपूर्ण तत्व होने के नाते, 'सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाना' पर कार्यशाला ने 'भूख रहित', 'अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण' और 'गुणवत्ता शिक्षा' के लक्ष्यों से संबंधित भारत की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया और कल्याण, समावेशी शिक्षा तथा मूलभूत विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण संबंधी चर्चा की गई।
- 'विकास और समृद्धि के लिए समावेशी व्यापार' पर चर्चा दृष्टिकोण, मूल्य श्रृंखला और नवाचार को आगे बढ़ाने की पद्धति, जीवीसी से उत्पादन, व्यापार और निवेश को एकीकृत करने तथा समावेशी, टिकाऊ और सुगम जीवीसी को बढ़ावा देने के तरीकों पर केंद्रित थी।
- 'भारत विकास मॉडल' पर कार्यशाला यह ज्ञात करने पर केंद्रित थी कि भारत कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि सामाजिक विकास और समावेशिता इसकी प्रगति और विकास के केंद्र में है और 'नारी शक्ति- महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर' पर कार्यबल में महिलाओं की सार्थक भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न मार्गों की खोज की गई, इसे प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिका के साथ-साथ महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए आवश्यक संसाधनों की खोज की गई।
- 'विकास और हरित विकास के लिए एमडीबी और वैश्विक वित्त तक पहुंच' पर सत्र तीन पहलुओं पर केंद्रित था। पहला, राज्य सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र जैसे विभिन्न भारतीय हितधारकों पर व्यापक और मजबूत एमडीबी प्रणाली के प्रभाव। दूसरा, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं (जीपीजी) में योगदान करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए घरेलू संसाधन जुटाने (डीआरएम) को बढ़ाने के लिए आवश्यक समर्थकारी स्थितियां। तीसरा, उन विभिन्न पद्धतियों पर विचार-विमर्श करना जिनके माध्यम से उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों की मांग पैदा करने के लिए देश के भीतर अवशोषक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
- 'सतत भविष्य के लिए हरित विकास संधि' पर यह चर्चा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी पहुंच को सुविधाजनक बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अंतःक्षेपों पर केंद्रित थी। ये पहल स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के सामर्थ्य और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। इस विषयगत चर्चा के लिए प्राथमिक ध्यान केन्द्र के क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच, सामर्थ्य, स्थिरता और न्याय शामिल थे।

कार्यन्वयन की कार्यसूची के अग्रेषण हेतु प्रमुख निष्कर्षों को समेकित परिणाम दस्तावेज़ में प्रकाशित किया जाएगा।



B.V.R. SUBRAHMANYAN  
CEO, NITI AAYOG

PRITAM BANERJEE  
CENTRE FOR WTO STUDIES

SANJEET SINGH  
SENIOR ADVISOR, NITI AAYOG

SUMAN BERY  
HON'BLE VC, NITI AAYOG

DR. CHINTAN VAISHNAV  
MD, AIM

DR. CHINTAN VAISHNAV  
MD, AIM

SANJEET SINGH  
SENIOR ADVISOR, NITI AAYOG

SUMAN BERY  
HON'BLE VC, NITI AAYOG

PRAMOD KUMAR  
CHIEF, NITI AAYOG

G20 THINK TANK WORKSHOP SERIES  
TRANSFORMATION  
PROMOTING DEVELOPMENT  
AND INNOVATION THROUGH  
DIGITALIZATION

TRANSFORMING MEDICAL  
DEVELOPMENT AND  
DIGITALIZATION

09 September 2023 |

DR. CHINTAN VAISHNAV  
MD, AIM

DR. CHINTAN VAISHNAV  
MD, AIM

SUMAN BERY  
HON'BLE VC, NITI AAYOG

PRAMOD KUMAR  
CHIEF, NITI AAYOG

## कुछ कार्यशालाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -

### सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौते पर कार्यशाला

जी20 एनडीएलडी में निहित हरित विकास समझौता ऊर्जा, जलवायु, पर्यावरण और आपदा प्रतिरोध से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में राष्ट्रों को मार्गदर्शन देता है। नीति आयोग ने 9 नवंबर 2023 को ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के साथ साझेदारी में "सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य जी20 एनडीएलडी के साथ भारत में हरित विकास समझौते के लिए कार्यान्वयन रणनीतियों पर चर्चा करना और हरित विकास समझौते में निर्धारित मार्गों की वैश्विक उन्नति के लिए भारत की नेतृत्व भूमिका को प्रोत्साहित करना है।



9 नवंबर 2023 को "सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता" विषय पर कार्यशाला

### 'सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर त्वरित प्रगति' पर कार्यशाला

नीति आयोग ने मानव विकास संस्थान(आईएचडी), सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र(सीएसईपी), और यूएनडीपी इंडिया जैसे ज्ञान भागीदारों के सहयोग से 6 नवंबर 2023 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में "सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर त्वरित प्रगति" विषय पर एक कार्यशाला (हाइब्रिड मोड) का आयोजन किया। जी20 एनडीएलडी के विषय पर वेबिनार को संरचित किया गया, जिसमें एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित करना शामिल है। कार्यशाला का उद्देश्य स्वदेशी विशेषज्ञता और ज्ञान पर जोर देते हुए एसडीजी प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना था। इसका प्रमुख फोकस एसडीजी के स्वामित्व और कार्यान्वयन में घरेलू भागीदारी को बढ़ाना था, और इसकी प्रगति में तेजी लाने के लिए थिंक टैंक और शोधकर्तियों की सक्रिय भागीदारी शामिल थी।

इस कार्यक्रम में थिंक टैंक, शिक्षाविद, पेशेवरों और विषयगत विशेषज्ञों सहित देश भर के विभिन्न हितधारकों की भागीदारी देखी गई। कार्यशाला में देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और वक्ताओं के साथ एक लाभप्रद चर्चा हुई, जिससे कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कई प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए। कार्यशाला में लगभग 90 व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया जबकि 7,557 व्यक्तियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया।



सतत विकास लक्ष्यों के त्वरित विकास पर जी20 कार्यशाला की झलक

### पर्यटन पर कार्यशाला

जी20 थिंक टैंक कार्यशाला श्रृंखला के भाग के रूप में, नीति आयोग ने चार विषयों अर्थात् हरित पर्यटन; पर्यटन एमएसएमई; विरासत और धार्मिक पर्यटन पर ध्यान देने के साथ पर्यटन स्थलों का डिजिटलीकरण और कार्यनीतिक प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की। ये विषय गोवा रोडमैप के फोकस क्षेत्र थे, और कार्यशाला में पर्यटन क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूलन करने के कार्यान्वयन के महत्व, पर्यटन क्षेत्र में सामर्थ्य और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं तैयार करने की तत्काल आवश्यकता, उचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले डिजिटल नियमों को लागू करने और पर्यटन के क्षेत्र में कुशल डेटा संग्रह के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के उपायों की पहचान करने पर विचार-विमर्श किया गया। इसने पर्यटन अवसंरचना और सेवाओं के विकास तथा प्रबंधन के लिए सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।



4 नवम्बर, 2023 को 'पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप को कार्यान्वित करना' पर कार्यशाला



खंड

4

क्षेत्रवार उपलब्धियाँ

## भूमिका

नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकल, प्रभाग और एकक नीति आयोग के संचालन के लिए आवश्यक स्तंभ हैं। प्रत्येक वर्टिकल एक विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है और उसे उस क्षेत्र पर तकनीकी इनपुट और विशेषज्ञता प्रदान करने, संबद्ध मंत्रालय/विभाग के साथ संव्यवहार करने और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया है।

वर्टिकल आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में नीति आयोग के विकास के लिए आवश्यक अपेक्षित सहायता प्रदान करते हैं, जिससे इसे तेजी से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए नीति संबंधी कार्यनीतिक विज्ञान प्रदान करने और प्रासंगिक मुद्दों के समाधान में सहायता मिलेगी।

## कृषि

### गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन पर कार्यबल

गौशालाओं की वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने और प्राकृतिक एवं सतत खेती को बढ़ावा देने के लिए आवारा, परित्यक्त और गैर-आर्थिक पशुधन की क्षमता को चैनलाइज़ करने के लिए मार्गदर्शी अंतःक्षेप प्रदान करने हेतु नीति आयोग द्वारा एक कार्यबल का गठन किया गया था। कार्यबल में शिक्षा जगत के विशेषज्ञ, अनुसंधान संस्थान, संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि, गौशालाओं, किसान संघ के प्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्रों के हितधारक तथा विशेषज्ञ शामिल थे। कार्यबल की रिपोर्ट मार्च 2023 में जारी की गई थी।

### मृदा स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक पोषण को बढ़ावा देने की कार्यनीति पर हितधारक कार्यशाला

8 जुलाई, 2023 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में नीति आयोग और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से “मृदा स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक पोषण को बढ़ावा देने की कार्यनीति” पर एक हितधारक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय रासायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की। कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, किसानों, शिक्षाविदों, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उद्योग, गैर सरकारी संगठनों और गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विचार-विमर्श कृषि उत्पादन बढ़ाने, कृषि प्रणालियों को मजबूत करने, मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा देने और कृषि में वैकल्पिक, सुरक्षित समाधानों के उपयोग के उपायों को अपनाने पर केंद्रित था।

### सतत खाद्य प्रणालियों और आत्मनिर्भर भारत के लिए जैविक खेती और जैविक कृषि-आदानों (जैविक उर्वरक और जैव उर्वरक) को बढ़ावा देने पर परामर्श

6 मार्च, 2023 को नीति आयोग और उर्वरक विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से नीति आयोग में “सतत खाद्य प्रणालियों और आत्मनिर्भर भारत के लिए जैविक खेती और जैविक कृषि-इनपुट (जैविक उर्वरक और जैव उर्वरक) को बढ़ावा देने” पर एक परामर्श सत्र का आयोजन किया गया था। यह परामर्श सत्र वर्तमान जैविक इनपुट नियमों, मानकों और विशिष्टताओं और उद्योग और किसानों के दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श के साथ देश में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ाने पर केंद्रित था। परामर्श सत्र में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग, गौशालाओं और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, शोधकर्ताओं और विश्वविद्यालयों और आईआईटी के



वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

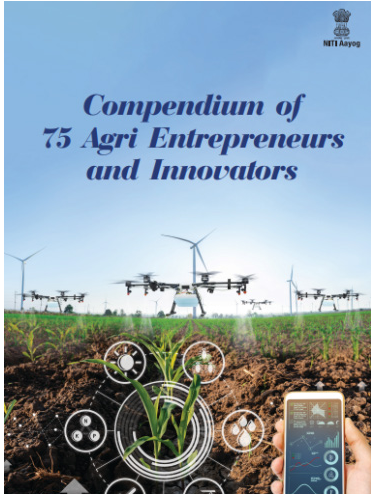
### पशुधन स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए टेलीमेडिसिन: रूपरेखा और दिशानिर्देश

पशुधन उत्पादकता सुनिश्चित करने और पशुधन रोगों से होने वाले सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए पर्याप्त पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता महत्वपूर्ण है। पशु चिकित्सा क्षेत्र में टेलीमेडिसिन को सक्षम करने से पशु चिकित्सा सेवा वितरण में अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है। नीति आयोग ने जुलाई, 2023 में पशु चिकित्सा क्षेत्र में टेलीमेडिसिन के लिए रूपरेखा और दिशानिर्देश प्रकाशित किए। इसके अलावा, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषाओं में पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए 'नीतिवेट' नामक एक उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब-आधारित प्रणाली विकसित की गई थी। पोर्टल के माध्यम से, पशुपालक समयानुसार वीडियो या वॉयस कॉल के माध्यम से पंजीकृत पशु चिकित्सक की सेवाओं का लाभ उठा सकता है। नीति आयोग द्वारा गुजरात और उत्तराखंड राज्यों में पोर्टल का परीक्षण पहले ही शुरू किया जा चुका है।

### किसान उत्पादक संगठनों/किसान उत्पादक कंपनियों के साथ परामर्श

20 दिसंबर, 2023 को नीति आयोग में "किसान उत्पादक संगठन: चुनौतियां और विज़न" पर एक परामर्श सत्र आयोजित किया गया था। परामर्श सत्र में लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी), राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न एफपीओ/एफपीसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह परामर्श सत्र देश में किसानों की आय और कृषि विकास को बढ़ाने के लिए एफपीओ/एफपीसी की भूमिका को सुदृढ़ करने पर केंद्रित था। इसने राज्य सरकारों को संरचनात्मक तंत्र और दिशानिर्देशों के माध्यम से एक स्थायी एफपीओ/एफपीसी इकोसिस्टम स्थापित करने और इसे मजबूत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

### खाद्य तेल की कीमतों को स्थिर करने हेतु एक कार्यनीतिक योजना की सिफारिश करने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी समिति



खाद्य तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए एक कार्यनीतिक योजना तैयार करने हेतु नीति आयोग के तत्वावधान में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया गया था। समिति ने मई 2023 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें खाद्य तेलों और तिलहनों की आपूर्ति, मांग और कीमतों से संबंधित रुझान और वृद्धि और अन्य खाद्य तेलों की घरेलू कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय कच्चे पाम ऑयल की कीमतों की प्रवृत्ति शामिल है। रिपोर्ट में एक ऐसी रूपरेखा भी शामिल है जिसके भीतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और व्यापार नीति एक साथ मिलकर काम करती हैं, ताकि सरकार द्वारा घोषित एमएसपी को ध्यान में रखते हुए बाजार कीमतें किसानों के लिए लाभकारी हों। समिति ने एक आधार मूल्य का भी सुझाव दिया जो एक संदर्भ मूल्य के रूप में कार्य करेगा जिसके आधार पर पाम ऑयल की आयात नीति निर्धारित की जा सकती है।

### एग्री-टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा

नीति आयोग ने 22 फरवरी, 2023 को "75 एग्री-उद्यमियों और नवप्रवर्तकों का एक संग्रह" जारी किया, जिसमें 75 उद्यमियों के नवाचारों को शामिल किया गया है, जिन्होंने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को रूपांतरित करने में मदद की है।

## पोषण और स्थिरता के लिए मिलेट को बढ़ावा देना

नीति आयोग, ने यूएन-डब्ल्यूएफपी इंडिया के सहयोग से 12 जनवरी, 2024 को 72 मिलेट हितधारकों की सफलता की कहानियों को शामिल करते हुए "भारत, एशियाई और अफ्रीकी देशों में मिलेट मुख्यधारा: क्षेत्र से प्रेरणादायक कहानियों का एक संग्रह" शीर्षक से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष और आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में एक संग्रह जारी किया। मिलेट के घरेलू प्रचार के लिए मिलेट कॉर्नर और वेंडिंग मशीन की शुरुआत, मिलेट पकाने में नीति कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए क्षमता निर्माण सत्र आदि जैसी कई पहल की गईं।

## कृषि वानिकी (ग्रो) के साथ बंजर भूमि की हरियाली और कायाकल्प

भारत 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति बनाने वाला दुनिया का पहला देश है जो उत्पादकता, लाभप्रदता, विविधता और इकोसिस्टम की स्थिरता को बढ़ाने पर केंद्रित है। कृषि वानिकी वर्तमान युग की खाद्य, पोषण, ऊर्जा, रोजगार, प्राकृतिक संसाधन, भूमि क्षरण और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे सामाजिक और पारिस्थितिक चुनौतियों का एक साथ समाधान करने के लिए सक्षम एक कृषि वैज्ञानिक प्रकृति आधारित भूमि उपयोग प्रणाली है।

नीति आयोग ने 12 फरवरी 2024 को "कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि की हरियाली और कायाकल्प" संबंधी एक तकनीकी रिपोर्ट और पोर्टल जारी किया है। रिपोर्ट ने कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के साथ देश के हरियाली और कायाकल्प के लिए उपयुक्त बंजर भूमि का नक्शा बनाने और प्राथमिकता तय करने के लिए कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक (एएसआई) तैयार करने हेतु जीआईएस प्रौद्योगिकी और रिमोट सेंसिंग डेटासेट के प्रयोग के बारे में खोज की। देश भर में राज्यवार और जिलेवार क्षेत्र की प्राथमिकता तय करने में बंजर भूमि, भूमि उपयोग भूमि कवर, जलाशय, 1:50,000 पैमाने पर मृदा जैविक कार्बन और ढलान जैसे बहुविषयगत डेटासेट का उपयोग किया गया था। इस पोर्टल को इसरो के भुवन-भारतीय भू-प्लेटफॉर्म द्वारा होस्ट किया गया है।



नीति आयोग में 12 फरवरी 2024 को "कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि की हरियाली और कायाकल्प (ग्रो)" पर रिपोर्ट जारी की गई

## मांग और आपूर्ति अनुमानों पर कार्य समूह

विकसित भारत @ 2047 के लिए विभिन्न खाद्य वस्तुओं की मांग और आपूर्ति का आकलन करने के लिए, नीति आयोग ने निदेशक, आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान की अध्यक्षता में क्रोप हस्बैंडरी, कृषि आदान, मांग और आपूर्ति पर एक कार्य समूह का गठन किया था।

कार्य समूह ने खाद्य वस्तुओं की मांग और आपूर्ति, आदान मांग और निर्यात के व्यवहार्य स्तरों के वास्तविक अनुमानों पर पहुंचने के लिए डेटा आवश्यकताओं और कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दों का आकलन और जांच की। कार्य समूह की रिपोर्ट 20 फरवरी 2024 को नीति आयोग में जारी की गई थी।



नीति आयोग में 20 फरवरी, 2024 को कार्य समूह रिपोर्ट जारी की गई

## डाटा प्रबंधन और विश्लेषण

वर्तिकात्मक रूप से डाटा प्रबंधन, उन्नत सांख्यिकीय प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित मुद्दों को हल करता है। इनके मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

- सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग के विशेषज्ञों के सहयोग से नीति पत्र और कार्यनीति दस्तावेज़ तैयार करने के साथ-साथ सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- ज्ञान और नवाचार सहायता प्रणाली बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक, शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों, नागरिक समाज और उद्योग के साथ सहयोग करना।
- डाटा प्रबंधन और उपयोग से संबंधित मुद्दों का दस्तावेजीकरण करना, उन्नत सांख्यिकीय प्रणालियों और प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
- सरकार में क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित करना।

### राष्ट्रीय डाटा एवं विश्लेषण मंच (एनडीएपी)

नीति आयोग ने 13 मई 2022 को राष्ट्रीय डाटा और विश्लेषण मंच (एनडीएपी) लॉन्च किया। वर्तमान में, प्लेटफॉर्म 45 मंत्रालयों और 15 क्षेत्रों में 2000+ प्रकाशित सरकारी डाटा सेट को सुव्यवस्थित और सुसंगत तरीके से होस्ट करता है। यह डाटा को सुलभ, अंतः प्रचालनीय, इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक सरकारी डाटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करता है। यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों से डाटासेट होस्ट करता है, उन्हें सुसंगत रूप से प्रस्तुत करता है, और विश्लेषण और डेमोकटाइज़ के लिए उपकरण प्रदान करता है।

एनडीएपी की तर्ज पर कर्नाटक और मेघालय राज्य के लिए एक राज्य डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म भी विकसित किया गया है, जिसे क्रमशः कर्नाटक डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (केएडीएपी) और मेघालय एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (मेगडीएपी) कहा जाता है।

## भारतीय सांख्यिकी प्रणालियों पर कार्यबल

नीति आयोग ने उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में भारतीय सांख्यिकी प्रणालियों पर एक कार्यबल का गठन किया है, जिसमें सचिव सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), मुख्य आर्थिक सलाहकार और अन्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं, जो भारतीय सांख्यिकी प्रणालियों से संबंधित मुद्दों की जांच करेंगे और सुशासन के लिए डाटा की उपयोगिता पर एक सामंजस्यपूर्ण कार्यनीति तैयार करेंगे। कार्यबल ने विशिष्ट क्षेत्रों का गहन मूल्यांकन करने और सर्वेक्षण की गुणवत्ता में सुधार, सर्वेक्षण डाटा के सामंजस्य और डाटा के उपयोग के मामलों की पहचान करने से संबंधित समाधान प्रस्तावित करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन करने का निर्णय लिया। विचार किए जा सकने वाले डाटा डोमेन की बड़ी श्रृंखला के कारण, यह निर्णय लिया गया कि विशेषज्ञ समूह पोषण, श्रम और व्यावसायिक सांख्यिकी के क्षेत्रों में आधारभूत अध्ययन और विश्लेषण करेगा।

## अर्थ एवं वित्त।

वर्टिकल यह सुनिश्चित करता है कि भारत जीवन स्तर में लगातार सुधार, अवसरों में तेजी और निवेश के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम बनाकर कार्यनीतिक क्षेत्रों में बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में एक स्थायी पथ पर बना रहे। वर्टिकल मजबूत समष्टि आर्थिक मॉडलिंग, परिदृश्य निर्माण अभ्यास और उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य के साथ अपने नीति मार्गदर्शन को संरेखित करके नीतिगत सुधारों को चलाकर इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है।

वर्टिकल के मुख्य कार्य

1. समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण - समष्टि अर्थशास्त्र, वित्तीय और बाहरी क्षेत्र में विकास की निरंतर ट्रैकिंग और विश्लेषण।
2. संरचनात्मक सुधार - आर्थिक संवृद्धि और विकास को बढ़ाने के लिए संभावित संरचनात्मक सुधारों का विश्लेषण।
3. क्रॉस-फंक्शनल ज्ञान साझाकरण- नीति आयोग के अन्य वर्टिकलों और सरकार के विभागों के बीच विविध क्षेत्रों में ज्ञान साझाकरण और रिसर्च सपोर्ट।
4. क्षमता निर्माण और विशेषज्ञ परामर्श- सरकार के भीतर क्षमता निर्माण और विशेषज्ञ परामर्श

### 2023-24 के दौरान वर्टिकल द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं में शामिल हैं:-

1. **मैक्रो मॉडलिंग - भारतीय अर्थव्यवस्था का पूर्वानुमान (2024-2047)** - 'विकसित भारत' के विज़न के साथ, बेहतर और व्यापक पूर्वानुमान संभावित जनसांख्यिकीय बदलाव, आंतरिक और बाहरी संतुलन स्थितियों और नीति निर्माताओं द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न नीतिगत बदलावों को दर्शाते हुए मजबूत व्यापक आर्थिक पूर्वानुमान द्वारा निर्देशित नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विज़न@2047 अभ्यासों के भाग के रूप में मैक्रो मॉडलिंग को निष्पादित किया गया था, जिसमें विकसित भारत और विज़न @ 2047 गुजरात के लिए समग्र आर्थिक संकेतकों के अनुमान उपलब्ध कराए गए थे।
2. **कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करना** - प्रकोष्ठ कर्जदारों के लिए बैंक वित्त का विकल्प प्राप्त करने और दीर्घावधि वित्तपोषण के लिए एक कुशल लागत-न्यूनीकरण प्रक्रिया विकसित करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारों को मजबूत करने के लिए प्रमुख नीतिगत सिफारिशों के साथ एक समग्र अनुसंधान विकसित करने की प्रक्रिया में है जो अपेक्षाकृत कम अवधि की देनदारियों के खिलाफ दीर्घकालिक ऋण देने के लिए बैंक का समर्थन करने; बीमा कंपनियों और पेंशन फंड धारकों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद करने; जोखिमों को फैलाने/बांटने और चलनिधि अंतराल का प्रबंधन करने के लिए एक तंत्र जो वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

**3. ट्रेड वॉच और ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट -** व्यापार में वर्तमान और नवीनतम विकास से अवगत रहने के लिए, वर्टिकल का लक्ष्य सरकार, उद्योग, थिंक टैंक और जनता की वैश्विक और देश स्तर पर व्यापार में विस्तृत विकास का निरीक्षण करने की मदद के लिए दो त्रैमासिक प्रकाशन "ट्रेड मंथली और ट्रेड वॉच" लाना है। ये रिपोर्ट भारत के निर्यात के लिए संभावित और सुदृढ़ व्यापार क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगी।

### आर्थिक अनुसंधान:

वर्टिकल ने बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, असमानता और 16वें वित्त आयोग और 'सतत विकास के लिए भारत का पथ' के लिए विचारार्थ विषयों जैसे विभिन्न व्यापक आर्थिक संकेतकों के हालिया परिदृश्यों पर इनपुट प्रदान किया। वर्टिकल ने महत्वपूर्ण विषयों और उपयुक्त जानकारी को शामिल करते हुए ओडिशा की एक विस्तृत राज्य प्रोफाइल विकसित की। विकास को गति प्रदान करने के लिए अर्थव्यवस्था के 5 प्रमुख क्षेत्रों पर एसजीओएस 6 बैठक में एक सुव्यवस्थित रणनीति और कार्य योजना प्रस्तुत की गई। कई रिपोर्टों पर टिप्पणियाँ और सुझाव दिए गए- 'भारत में राज्य बजट: 1990 से 2020 तक अवलोकन समय प्रवृत्ति विश्लेषण'; 'भारतीय राज्यों में स्पष्ट बजट सॉल्यूशन चयनित राज्यों का मामला'; आईएमएफ का 'अनुलग्नक IX. भारत में विकास के चालक' और विश्व बैंक का 'भारत विकास अपडेट'।

## अर्थ एवं वित्त ॥

वर्टिकल का उद्देश्य भारत को अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में आर्थिक सिद्धांतों और वित्तीय अवधारणाओं के अध्ययन और प्रयोग के लिए विश्व के अग्रणी और सतत केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह वर्टिकल अनुसंधान, चर्चा और शैक्षिक पहलों के माध्यम से ज्ञान प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य कर इन क्षेत्रों की व्यापक समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वर्टिकल नीतिगत सुधारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है जिसका उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना, पूंजी निर्माण में तेजी लाना, कार्यनीतिक क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, वित्त तक पहुंच में सुधार करना, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी की लागत को कम करना और प्रत्येक नागरिक के लिए अवसरों को बढ़ाते हुए जीवन की समग्र गुणवत्ता को उन्नत करना है।

### समष्टि आर्थिक विश्लेषण

#### अर्थव्यवस्था की स्थिति

नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी एक आवर्ती प्रक्रिया में लगे हैं जिसमें भारतीय और वैश्विक दोनों अर्थव्यवस्थाओं का वास्तविक समय का प्रदर्शन विश्लेषण शामिल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन नौ अलग-अलग क्षेत्रों में फैले 40-50 उच्च आवृत्ति संकेतकों की जांच के माध्यम से किया जाता है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण गतिशील और विकसित आर्थिक परिदृश्य की ओर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए एक व्यापक मूल्यांकन का अवसर देता है। वास्तविक समय के डेटा और संकेतकों के विविध सेट का उपयोग आर्थिक रुझानों की बारीक समझ सुनिश्चित करता है और चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए सुविज्ञ कार्यनीतियों और नीतियों को तैयार करने में मदद करता है।

वर्टिकल ने वैश्विक स्थिति और भारत के लिए संभावित प्रभाव, आर्थिक दृष्टिकोण, बचत दर और चालू खाता शेष आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों और सीईओ द्वारा भाग लेने वाली उच्च स्तरीय बैठकों के लिए इनपुट प्रदान किए। इसने एक छोटे से सर्वेक्षण के माध्यम से एक घरेलू भावनात्मक विश्लेषण भी किया।

#### कार्यनीतिक विनिवेश और सीपीएसई के प्रदर्शन में सुधार

वर्टिकल के पास कार्यनीतिक क्षेत्रों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के विनिवेश के लिए विश्लेषण और सुझाव प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इन सिफारिशों को औपचारिक रूप से निवेश और लोक

परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीपम) और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों के समूह (सीजीओ) की समिति को प्रस्तुत करने से पहले संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है।

## जी20 और बहुपक्षीय संस्थानों के साथ विभिन्न जुड़ाव

### भारत की जी20 अध्यक्षता

नीति आयोग का जी20 प्रकोष्ठ भारत की जी20 अध्यक्षता से संबंधित विभिन्न पहलों में सक्रिय रूप से शामिल है। इस भागीदारी में जी20 सचिवालय को तकनीकी अंतर्दृष्टि प्रदान करना और निर्गम टिप्पणी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने में योगदान देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रकोष्ठ ने लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की, कार्य समूहों की बैठकों में भाग लिया, और अन्य गतिविधियों के बीच कार्यशालाओं का समायोजन किया।

जी20 प्रकोष्ठ ने जी20 सचिवालय और विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में 23 जुलाई, 2022 को जी20 कार्यकारी संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने की जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और नीति आयोग के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

### वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा' पर एक रिपोर्ट का शुभारंभ

एक महत्वपूर्ण सहयोगात्मक प्रयास में, नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (आईडीआरसी) और वैश्विक विकास नेटवर्क (जीडीएन) के साथ साझेदारी में, 28-29 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित जी20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही के आधार पर, 'वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक हरित और सतत विकास एजेंडा' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें विश्व भर के 14 देशों के 40 प्रमुख विशेषज्ञ शामिल हुए। श्री भूपेंद्र यादव, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में एक जी20 रिपोर्ट, 'वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक हरित और सतत विकास एजेंडा' लॉन्च की। यह रिपोर्ट इस विषय पर ज्ञान भंडारण में वृद्धि करेगी और ब्राजील के लिए मूल्यवान इनपुट भी प्रदान करेगी क्योंकि यह भारत से जी20 की अध्यक्षता का कार्यभार लेगा।



'वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा' पर एक रिपोर्ट का शुभारंभ

## एडीबी की भारत देश भागीदारी कार्यनीति, 2023-2027

भारत और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बीच साझेदारी के लिए कार्यनीतिक दिशाओं और रोडमैप को संरचित करते हुए एक दस्तावेज तैयार किया गया था। भारत को लाभान्वित करने के लिए वित्तीय, तकनीकी, सलाह और ज्ञान सहायता प्रदान करने में एडीबी की बहुपक्षीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने के साथ संरेखित नीतियों और अवधारणाओं को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

## सतत और समावेशी विकास के लिए दक्षिण एशिया का मार्ग: आईएमएफ

दक्षिण एशियाई क्षेत्र के समक्ष मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों को उजागर करते हुए एक दस्तावेज का मसौदा तैयार किया गया था। इसने महामारी के दौरान क्षेत्र में छोटी अर्थव्यवस्थाओं के जीवन और आजीविका को संरक्षित करने में भारत की भूमिका और विकासवात्मक सहायता पर जोर दिया। नोट में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सतत विकास के लिए कार्यनीति तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था।

## मूडीज की वार्षिक समीक्षा सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पर चर्चा

भारत के सॉवरेन बॉन्ड रेटिंग के वार्षिक मूल्यांकन के लिए मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस (एमआईएस) के साथ आर्थिक कार्य विभाग के सहयोग से एक सत्र आयोजित किया गया। नीति आयोग ने मूडीज को महत्वपूर्ण दृष्टिकोण और विचारों को प्रस्तुत किया, जिसमें भारत की क्रेडिट रेटिंग की पुनः पुष्टि पर जोर दिया गया। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में देश की मौलिक शक्तियों और लचीलेपन को रेखांकित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

## नियति तैयारी सूचकांक पर इनपुट

नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियति तैयारी सूचकांक (ईपीआई) 2022 का तीसरा संस्करण जारी किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने रिपोर्ट जारी की। ईपीआई 2022 में तुलनात्मक विश्लेषण राज्य सरकारों को निर्णय लेने, क्षमता की पहचान करने, कमियों को दूर करने और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापक विकास को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह रिपोर्ट अपने क्षेत्र-विशिष्ट और जिला-स्तरीय व्यापारिक नियति प्रवृत्तियों के साथ वित्त वर्ष 2022 में भारत के नियति प्रदर्शन का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ईपीआई 2022 रिपोर्ट चार स्तंभों - नीति, व्यापार इकोसिस्टम, नियति इकोसिस्टम और नियति निष्पादन में राज्यों के कार्यानिष्पादन का मूल्यांकन करती है। सूचकांक 56 संकेतकों का उपयोग करता है जो राज्य और जिला-स्तर दोनों पर नियति के मामले में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की नियति तैयारी को समग्र रूप से दर्ज करते हैं।

यह रिपोर्ट राज्य सरकारों को नियति के लिए उनकी संदर्भ-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राज्य अपने उत्पादों को बढ़ावा देकर और उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए सुगम बनाकर अपनी प्राकृतिक विविधता का दोहन भी कर सकते हैं।

## शिक्षा

शिक्षा वर्टिकल नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से एक अनुकूल शिक्षण वातावरण की सुविधा प्रदान करता है ताकि लोग अपनी संपूर्ण क्षमता का विकास कर सकें। वर्टिकल बच्चों के बीच स्कूल जाने के लिए तत्परता, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा, महत्वपूर्ण और उच्च-क्रम की सोच और ग्रेड-स्तरीय क्षमता को सुकर बनाने का प्रयास करता है। यह उच्च गुणवत्ता, सुलभ, न्यायसंगत, जवाबदेह और वहनीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से युवाओं को रोजगार कौशल, अनुसंधान प्रकृति और विषय वस्तु विशेषज्ञता के साथ सशक्त बनाना चाहता है।

## स्कूली शिक्षा

### परियोजना साथ-शिक्षा

सहकारी संघवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, नीति आयोग ने शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन का आरंभ करने के लिए 2017 में परियोजना- 'मानव पूंजी को बदलने के लिए सतत कार्टवाइ' (साथ)-शिक्षा शुरू की। परियोजना साथ-शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र के लिए भविष्य के तीन 'रोल मॉडल' राज्यों की पहचान करना और निर्माण करना है। परियोजना चुनौती पद्धति के माध्यम से साथ-शिक्षा के लिए एक विस्तृत चयन प्रक्रिया के बाद तीन राज्यों- झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश को चुना गया था। यह परियोजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी और अक्टूबर, 2022 में सफलतापूर्वक पूरी की गई थी। तीनों साझेदार राज्यों में परियोजना साथ-शिक्षा के माध्यम से 1.7 लाख स्कूलों में 2 करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए।

### परियोजना साथ - अरुणाचल प्रदेश

नीति आयोग, अरुणाचल प्रदेश सरकार, और एक नॉलेज पार्टनर ने 03 वर्षों (2022-25) की अवधि के लिए अरुणाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा परिवर्तन लाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना में अरुणाचल प्रदेश के ग्रेड 1-12 के 2 लाख से अधिक बच्चों को शामिल किया गया है।

#### • शैक्षणिक सुधार

- » संस्थागत राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण
- » कक्षा 1-5 (06 सप्ताह) के लिए स्कूल तैयारी कार्यक्रम शुरू किया गया
- » कक्षा 1-12 (वर्ष भर) के लिए लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम शुरू किया गया
- » बोर्ड परीक्षा प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कक्षा 10 और 12 के लिए परीक्षा और उससे आगे टूलकिट शुरू की गई

#### • क्षमता विकास

- » शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) प्रदान किया गया
- » स्कूलों को सहायता प्रदान करने के लिए बीआरसी, सीआरसी और जिला अधिकारियों की क्षमता निर्माण
- » शिक्षकों को नियमित शैक्षणिक सहायता के लिए शिक्षक हेल्पलाइन की स्थापना की गई

#### • शासन और जवाबदेही

- » साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए एक एमआईएस और लाइव डैशबोर्ड स्थापित करना
- » प्रत्येक स्तर पर निगरानी और समीक्षा तंत्र (डेटा चालित)

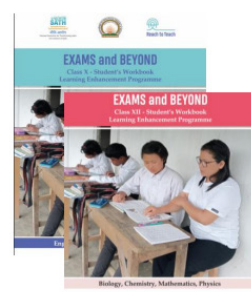
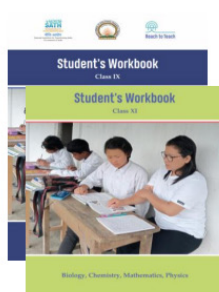
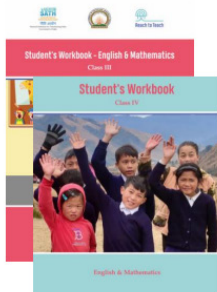
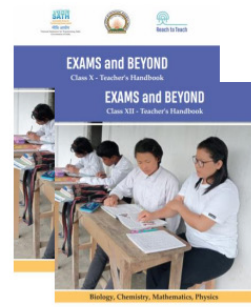
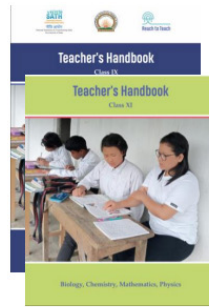
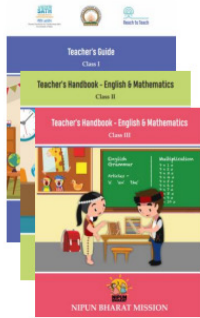
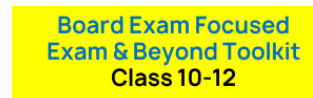
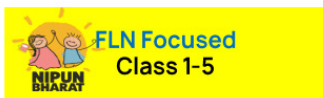
#### • सामुदायिक जुड़ाव

- » शिक्षा में माता-पिता के जुड़ाव को मजबूत करना
- » एसएमसी, गाँव बुद्धा और स्थानीय शासन की क्षमता निर्माण
- » वार्षिक रूप से संरचित नामांकन अभियान चलाना
- » स्कूल समुदाय सहयोग का समर्थन करने में सिस्टम से जुड़े अधिकारियों की क्षमता-निर्माण





सरकारी स्कूलों में स्कूल तैयारी कार्यक्रम (एसआरपी) लागू किया जा रहा है



(शिक्षक और छात्र संसाधन सामग्री)

## साथ रिपोर्ट: स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए सीख

रिपोर्ट में साथ राज्यों के प्रासंगिक अंतःक्षेप शामिल हैं और यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की स्कूली शिक्षा प्रणालियों को सीखने, लागू करने और बदलने के लिए एक रेडी-रेकनर है और इसमें अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संदर्भ के अनुसार पहल करने में सहायता प्रदान करने की क्षमता है।



साथ रिपोर्ट की लॉन्च: स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए सीख

## युवा कार्यक्रम और खेल

वर्ष 2023-24 के दौरान, शिक्षा वर्टिकल के अधिकारियों ने परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकों, विभागीय परियोजना अनुमोदन समिति (डीपीएसी) की बैठकों, स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और मंत्रालय की राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) को वित्तीय सहायता के लिए परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकों जैसी विभिन्न बैठकों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

## इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

नीति आयोग में ईवी मिशन कौशल और विशेषज्ञता में ज्ञान हस्तांतरण के लिए दुनिया भर के संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है। यह दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से ज्ञान हस्तांतरण और सीखने को प्रोत्साहित करने के ईवी मिशन के निरंतर प्रयास का एक हिस्सा है। इसका विचार प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करना और लघु/दीर्घकालिक साझेदारी बनाना है जो भारत को ईवी इकोसिस्टम में आने वाले मुद्दों और चुनौतियों का सर्वोत्तम संभव समाधान प्रदान करने में मदद कर सकता है।

## एडीबी के साथ तकनीकी सहायता कार्यक्रम:

ईवी अपनाने में चुनौतियों का समाधान करने के लिए, नीति आयोग और एडीबी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर तकनीकी सहायता के माध्यम से कई उच्च स्तरीय पहलों पर मिलकर काम कर रहे हैं। तकनीकी सहायता के तहत महत्वपूर्ण गतिविधियों में संपूर्ण ईवी मूल्य श्रृंखला में विभिन्न ईवी बेड़े ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों के लिए ऋण वृद्धि, भारत में ईवी और ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर घटक विनिर्माण के लिए आपूर्ति श्रृंखला मूल्यांकन शामिल है। इसके अलावा, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की मैपिंग और अंतरराष्ट्रीय

सर्वोत्तम प्रथाओं का एक इंटरैक्टिव पोर्टल बनाना, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपनाना, भारत में ईवी स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना और टियर-1 शहरों (सूरत, कोलकाता और लखनऊ) के लिए व्यापक ई-मोबिलिटी योजनाएं विकसित करने की पहल की गई है।

## परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण

भारत सरकार ने पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का परिनियोजन करके बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अगस्त 2023 को "पीएम-ईबस सेवा योजना" शुरू की है। 50,000 ई-बसों की कुल मांग के लिए राष्ट्रीय ई-बस कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य ईवी एक्सेलेरेटर कार्यक्रम से प्रेरित होकर 34 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईवी नीतियां लेकर आए हैं। अब तक आईआईटी में ईवी और बैटरी स्टोरेज में उत्कृष्टता और उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के 16 अनुसंधान एवं विकास केंद्र शुरू किए गए हैं। नीति आयोग के ई-अमृत पोर्टल को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी टेक टाइटन ऑफ इंडिया 2023 प्राप्त हुआ है। नीति आयोग ने सीओपी28, इंडिया पवेलियन में सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ आईएम, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वैश्विक थिंक टैंक के साथ भारत की ईवी क्रांतिकारी यात्रा पर प्रकाश डालने और त्वरित परिवर्तन प्राप्त करने के लिए अपनाए जा रहे नवीन व्यवसाय मॉडल का प्रदर्शन करने हेतु एक पैनल की मेजबानी की।

## भारत की इलेक्ट्रिक गतिशीलता में तेजी लाने के लिए नीति समर्थन और उसे सक्षम बनाने पर जी20 कार्यक्रम

नीति आयोग ने 19 जुलाई, 2023 को भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत चौथे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह (ईटीडब्ल्यूजी) की बैठक के साथ गोवा में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। गोवा के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के जी20 अध्यक्षता के शेरपा और अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम के उद्घाटन की शोभा बढ़ाई।



इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 10 देशों और 41 शहरों के नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों, शोधकर्ताओं, फाइनेंसरों और उद्यमियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई। इसने परिवहन विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्य वित्तपोषण मार्गों, सार्वजनिक परिवहन के लिए विद्युतीकरण मार्गों, क्रॉस-सेक्टरल और वैश्विक अंतर्दृष्टि, और ई-मोबिलिटी पारगमन में तेजी लाने के लिए कार्यक्रमों और साझेदारी पर चर्चा के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया।

## उन्नत रसायन विज्ञान सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम:

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 'उन्नत रसायन विज्ञान सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' के परिव्यय के साथ एसीसी की पचास (50) गीगा वाट घंटा (जीडब्ल्यूएच) और "आला" एसीसी की 5 गीगावाट की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए वर्ष 2021 में 18,100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। एसीसी पीएलआई कार्यक्रम के तहत विनिर्माण सुविधा दो वर्षों की अवधि के भीतर स्थापित करनी होगी। इसके अलावा, 3 कम्पनियों को समझौते के पत्र जारी किया गया। चयनित बोलीदाताओं से अपेक्षित प्रस्तावित निवेश 45,000-50,000 करोड़. रु. तक है।

## इको लॉजिस्टिक्स योजनाएँ:

नीति आयोग आईसीएलईआई - लोकल गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, दक्षिण एशिया पहल के सहयोग से इकोलॉजिस्टिक्स-कम कार्बन शहरी माल ढुलाई योजनाओं के विकास के साथ शिमला, पणजी और कोच्चि शहरों का समर्थन कर रहा है। इसका उद्देश्य स्थानीय कार्टवाइ और राष्ट्रीय समर्थन के माध्यम से कम कार्बन वाली शहरी माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए क्षमताओं, कार्यनीतियों और नीतियों को बढ़ाना है। परियोजना का चरण- II गंगटोक, इंपाल और रांची शहरों को समर्थन देने के लिए बढ़ाया गया है।

## शून्य अभियान - सभी राइड-हेलिंग और डिलीवरी को ईवी में बदलने के लिए एक 'नज प्लेटफॉर्म':

"शून्य - जीरो प्रदूषण गतिशीलता" नीति आयोग और आरएमआई द्वारा शुरू और संचालित एक कॉर्पोरेट और उपभोक्ता-सामना करने वाला अभियान है। यह अभियान शुरू में 01 सितंबर, 2021 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य राइडहेलिंग और डिलीवरी के लिए ईवी की तैनाती में तेजी लाना है। अभियान की महत्वपूर्ण आकांक्षा जागरूकता पैदा करके और शून्य-प्रदूषण गतिशीलता पर साहसिक कॉर्पोरेट कार्टवाइ को सुविधाजनक बनाकर सभी शहरी वाणिज्यिक वाहनों को ईवी में परिवर्तित करना है। शहरी डिलीवरी और राइड-हेलिंग वाहन अपनी बढ़ती प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के कारण शीघ्र विद्युतीकरण के लिए प्रमुख उम्मीदवार हैं।

भारत में शून्य अभियान के लॉन्च के बाद से, 182 से अधिक कॉर्पोरेट भागीदार इस अभियान में शामिल हुए हैं, और सामूहिक रूप से 80 मिलियन शून्य डिलीवरी और 50 मिलियन शून्य राइड पूरी की हैं। इसके अलावा, शून्य अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च की गई एक उपभोक्ता जागरूकता ब्रांड फिल्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 80 मिलियन से अधिक बार देखा गया।

## राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम:

2021 में, डीएचआई ने योजना के तहत ई-बस अपनाने में तेजी लाने के लिए 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नौ शहरों को लक्षित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) को ओपेक्स आधार पर फेम-II योजना के तहत शेष ई-बसों की मांग को एकत्र करने का काम सौंपा गया था। सीईएसएल द्वारा जारी निविदा 5450 ई-बसों के लिए ग्रैंड चैलेंज (जीसी) के तहत ई-बस खरीद के लिए जारी की गई दुनिया की सबसे बड़ी निविदा थी। सीईएसएल द्वारा सक्रिय परामर्श, नीति आयोग और डब्ल्यूआरआई इंडिया द्वारा समर्थित, 9 पात्र शहरों से कुल मांग के लिए पारगमन एजेंसियों, वित्तपोषण संस्थानों, ई-बस निर्माताओं और थिंक-टैंक के साथ आयोजित किया गया था, जिनमें से पांच शहरों ने सदस्यता ली थी। ग्रैंड चैलेंज ने निविदा शर्तों को संशोधित करके और बोलीदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर निजी क्षेत्र की भागीदारी के जोखिमों को सफलतापूर्वक कम कर दिया, जिससे रिकॉर्ड कम कीमतें कम हुईं।

जीसी के तहत कीमत का पता लगाने के परिणामस्वरूप पिछली ई-बस निविदाओं की तुलना में 50% तक की

कमी आई है, जो भारतीय बाजार में पहले कभी नहीं देखी गई और ई-बसों की परिचालन लागत डीजल और सीएनजी बसों की तुलना में कम हो गई। ई-बसों के एकत्रीकरण के लाभों को शीर्ष 9 शहरों (जनसंख्या के अनुसार) से परे शहरों तक बढ़ाने के उद्देश्य से और सार्वजनिक बसों के तेजी से विद्युतीकरण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, नीति आयोग ने देश भर में स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 50,000 ई-बसों की तैनाती को इनेबल करने "राष्ट्रीय ई-बस एकत्रीकरण कार्यक्रम" का प्रस्ताव दिया है।

## अन्य ई-मोबिलिटी गतिविधियां

इस इकाई ने टीईआरआई के साथ डाक सेवा विभाग के विद्युतीकरण पर एक हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया और एनडीसी, टीआईए परियोजना के लिए जीआईजेड के साथ सहयोग किया। इसने ऊर्जा संक्रमण सामग्री में आत्मनिर्भरता पर उन्नत पहलों के लिए ईटीएमए के साथ और पीएम ई-बस सेवा से जुड़े मुद्दों के संबंध में एमओएचयू के साथ भी सहयोग किया। इकाई ने सीमेंट मालभाड़ा क्षेत्र में गतिशाल पारगमन के लिए सीमेंट कंपनियों और आपूर्ति इको-सिस्टम में तेजी लाने के लिए ई-वाहन ओईएम के साथ एक बैठक का आयोजन किया था। इसने ई-बस क्षेत्र पर द्विपक्षीय विनिमय पर केएफडब्ल्यू मिशन के साथ भी सहयोग किया।

## राज्य सहायता

1. राज्य ईवी नीति निमाण, सीईएसएल और बीईई के साथ समन्वय के संबंध में राज्यों को निरंतर आधार पर सहायता दी जा रही है।
2. बिहार की जलवायु कार्टवाई रणनीति के लिए राज्य के साथ सहयोग।
3. ई-मोबिलिटी पर एसएसएम हेल्पड डेस्क के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया।
4. आरटीडीसी के साथ हिमाचल प्रदेश की ई-मोबिलिटी प्रगति की समीक्षा की।

## हरित परिवर्तन, ऊर्जा, जलवायु और पर्यावरण

### हरित परिवर्तन, जलवायु और पर्यावरण

हरित परिवर्तन, जलवायु और पर्यावरण (जीटीसी) वर्टिकल का व्यापक मिशन वनों के स्थायी प्रशासन, वन्यजीवों और आवासों की सुरक्षा, एक प्राचीन और पारिस्थितिक रूप से सुदृढ़ वातावरण सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल कार्यनीतियों और नीतियों के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देना है। यह वर्टिकल शैक्षिक, थिंक टैंक, साथ ही केंद्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श को बढ़ावा देकर नीतिगत रूपरेखा विकसित करने की आकांक्षा रखता है। यह संसाधनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए उभरती राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नई नीतियों को तैयार करने में भी सक्रिय भूमिका निभाता है।

### परियोजना आकलन एवं मूल्यांकन

वर्टिकल व्यापक मूल्यांकन प्रदान करते हुए एसएफसी/ईएफसी प्रस्तुत करने के लिए विविध परियोजना प्रस्तावों का गंभीर रूप से आकलन करता है। इसमें बाहरी रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं की जांच शामिल है, जहां वर्टिकल वित्तीय सहायता के लिए तकनीकी टिप्पणियां और सिफारिशें प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, वर्टिकल तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता पर इनपुट प्रदान करते समय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए बहुपक्षीय संस्थानों और समूहों के साथ कार्यान्वयन योजनाओं/समझौता ज्ञापनों को विकसित करने में शामिल है।

वर्टिकल कैबिनेट/सीसीईए, स्थापना व्यय समिति (सीईई)/सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के रूप में प्रस्तुत प्रस्तावों के निर्माण की सुविधा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, टिप्पणियों को प्रमाणित करने के साथ-साथ व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और विकास परियोजनाओं के लिए मास्टर योजनाएं बनाने में परामर्शदाताओं को नियुक्त करने हेतु वर्टिकल योग्यता के लिए अनुरोध-सह-प्रस्ताव दस्तावेजों के लिए अनुरोध तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है।

### चिह्नित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय करने के लिए राष्ट्रीय कार्य बल

वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल और नियामक दृष्टिकोण बनाने वाले प्लास्टिक विकल्पों या प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान के विकास का आकलन करने के लिए नीति आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट बाजार की तैयारी, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं और इन उत्पादों को अपनाने के लिए आवश्यक नियामक ढांचे पर केंद्रित है।

### ट्रांस-बाउंड्री लैंडस्केप और हिंदू-कुश हिमालय (एचकेएच) कॉल टू एक्शन पहल पर राष्ट्रीय समन्वय समिति

नीति आयोग समिति का सदस्य है जिसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर नीति और कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने की भूमिका और जिम्मेदारी प्रदान की गई है। वर्टिकल विभिन्न बैठकों का हिस्सा रहा है और उसने अपनी अंतिम रिपोर्ट के लिए सिफारिशें दी हैं।

### जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) की समीक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन पर विशेषज्ञ समिति

वर्टिकल विभिन्न राज्यों के एसएपीसीसी की जांच करता है और कार्य योजनाओं में आगे के संशोधनों के लिए टिप्पणियां प्रदान करता है। नीति आयोग अब तक लगातार 12 बैठकों का हिस्सा रहा है और वर्ष 2023 में कर्नाटक, केरल, असम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के एसएपीसीसी की समीक्षा में योगदान दिया है।

### भारत-नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल के लिए परियोजना संचालन समिति

भारत सरकार ने महासागर और “ब्लू इकोनॉमी” विकसित करने के लिए सहयोग करने पर नॉर्वे सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत, एक पहल भारत-नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल थी, जिसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, नॉर्वे के बीच आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए गए थे। समिति का गठन भारत-नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल और पर्यावरण से संबंधित अन्य भारत-नॉर्वेजियन मामलों के तहत भारत-नॉर्वेजियन परियोजना के निष्पादन और निगरानी पर ध्यान रखने के लिए किया गया था।

### हरित जलवायु निधि अधिकार प्राप्त समिति (जीसीएफ-ईसी)

समिति का गठन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को निर्धारित करने, जीसीएफ इंडिया परियोजनाओं को मंजूरी देने, परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी, जीसीएफ बोर्ड में देश का दृष्टिकोण तय करने और जलवायु परिवर्तन के वित्तपोषण के लिए विभिन्न एजेंसियों के कार्य में तालमेल लाने के लिए मंच के रूप में कार्य करने के लिए किया गया था।

## एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

समिति वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राज्यों की प्रगति और समीक्षा की देखरेख करती है। समिति में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व जीटीसी वर्टिकल द्वारा किया जाता है।

## परिवर्तन, अनुकूलन और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय संस्थान (निरंतर) पर उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति

समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी), भारत सरकार के आदेश पर भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरडी) द्वारा विकसित निरंतर के तहत एक वर्चुअल एकीकृत पोर्टल पर साझा किए जाने वाले एमओईएफएंडसीसी के संस्थानों के अनुसंधान कार्य और प्रकाशनों की तुलना करने और साझा करने के लिए निगरानी कर मार्गदर्शन प्रदान करती है।

## मूल्यांकन

नीति आयोग के हरित परिवर्तन (ग्रीन ट्रांजिशन), जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण वर्टिकल ने एमओएफसीसी की विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं से संबंधित ईएफसी, एसएफसी, पीपीआर, कैबिनेट नोट और परियोजना प्रस्तावों के मसौदे की समीक्षा की और अपनी टिप्पणी दी। वर्ष 2023 में, वर्टिकल ने संयुक्त रूप से 25 से अधिक ईएफसी, एसएफसी, कैबिनेट नोट और परियोजना प्रस्तावों की जांच की।

## चक्रीय अर्थव्यवस्था

10 क्षेत्रों के लिए अंतिम रूप दी गई चक्रीय अर्थव्यवस्था कार्ययोजना वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र के लिए संबंधित हितधारकों के साथ संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा, नीति आयोग चक्रीय अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो कार्ययोजना में बताए गए कार्यों को लागू करने के लिए क्षेत्रीय और क्रॉस-सेक्टर चालकों की पहचान करेगी। यह एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के लिए कुछ क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा जो भारत के भीतर चक्रीय मॉडल की क्षमता का उपयोग करता है। परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित करने के लिए नीति और प्रशासनिक सिफारिशें तैयार करने में मदद मिलेगी कि भारत में उद्योग और अनौपचारिक क्षेत्र में परिपत्र प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रणाली अच्छी तरह से तैयार है।

## ऊर्जा

ऊर्जा वर्टिकल भारत को ऊर्जा-सुरक्षित बनाने के लिए सभी हितधारकों को नीतिगत सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य एक कुशल, टिकाऊ और स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देना है। वर्टिकल ऊर्जा आयात को कम करने, ऊर्जा की वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित करने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास करता है। नीतिगत ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया है कि भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए कुशल बाजारों के माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है।

## कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण

जीवाश्म आधारित ऊर्जा कार्बन डाई आक्साईड (सीओ<sub>2</sub>) उत्सर्जन का कारण बनती है, इस प्रकार क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। भारत में सीसीयूएस के परिनियोजन का समर्थन करने के लिए सहायता हेतु नीति आयोग ने देश में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) के परिनियोजन की सुविधा के लिए पहल की है। इस उद्देश्य से, निम्नलिखित पहल की गई हैं:

## कार्बन कैप्चर, उपभोग और भंडारण पर अध्ययन रिपोर्ट

29 नवंबर, 2022 को नीति आयोग ने “भारत में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) नीतिगत ढांचे और इसके विकास तंत्र की वृद्धि” शीर्षक से एक महत्वपूर्ण अध्ययन रिपोर्ट जारी की। यह व्यापक रिपोर्ट भारत में सीसीयूएस अनुप्रयोगों को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत अंतःक्षेपों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इन अंतःक्षेपों में सीओ<sub>2</sub> कैप्चरिंग, उपयोग, और भंडारण तथा परिवहन, प्रौद्योगिकी चयन, शुद्धिकरण, दबाव, गुणवत्ता आश्वासन और भंडारण और परिवहन के लिए वित्त-पोषण जैसे महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं।



“भारत में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण नीतिगत ढांचे एवं इसके विकास तंत्र की वृद्धि पर” अध्ययन रिपोर्ट का शुभारंभ

## कार्यबल की स्थापना

नीति आयोग ने भारत में सीसीयूएस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक नीतिगत ढांचे के विकास हेतु एक कार्यबल का गठन किया है। सीसीयूएस पहल के इष्टतम कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन समितियों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सदस्य शामिल हैं। नीति आयोग के मार्गदर्शन में, विद्युत मंत्रालय ने, एनटीपीसी के सहयोग से, भारतीय जी20 प्रेसीडेंसी के तहत 5 फरवरी, 2023 को मुंबई में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

सलाहकार समिति के निर्देश पर, नीति आयोग ने सुरक्षा और तकनीकी मानक विकास, सीओ<sub>2</sub> कैप्चर, उपयोग, परिवहन और भंडारण के क्षेत्रों में चार अंतर-मंत्रालयी तकनीकी समितियों का गठन किया है। प्रत्येक तकनीकी समिति में विशेषज्ञता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) के सदस्य शामिल होते हैं। मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिनका प्रयोग सीसीयूएस पर नीति बनाने के लिए किया जाना है।

अमेरिकी ऊर्जा विभाग और विश्व बैंक ने राष्ट्रीय सीसीयूएस नीति के विकास को और मजबूत करने के क्रम में जान साझा करने के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग करने में गहरी रुचि व्यक्त की है। इस सहयोगात्मक प्रयास का लक्ष्य पूरे देश में सीसीयूएस पहलों का मार्गदर्शन और समर्थन करने वाला एक मजबूत ढांचा स्थापित करना है।

## एनर्जी ट्रांजिशन में छोटे माॅड्यूलर परमाणु रिएक्टरों की भूमिका:

सहयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतराल को दूर करने के विषय के तहत, भारत की जी20 अध्यक्षता में, छोटे



मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों (एसएमआर) के प्रौद्योगिकी अंतराल में से एक की पहचान की गई थी। नीति आयोग ने परमाणु ऊर्जा विभाग के परामर्श से भारत में एसएमआर के विकास और तैनाती के लिए नीतिगत ढांचे पर काम करने की पहल की है। इस संबंध में, "एसएमआर" पर एनर्जी ट्रांजिशन कार्यसमूह के तहत एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला निर्धारित की गई थी और एक अध्ययन रिपोर्ट "ऊर्जा पारगमन में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की भूमिका" भी लॉन्च की गई थी। उपर्युक्त पहलों के परिणाम ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को एसएमआर के क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रेरित किया है और अब सहयोग के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं।

## आईईएसएस 2047 और आईसीईडी पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला

17 अक्टूबर 2023 को नीति आयोग में भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (आईईएसएस) 2047 और भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड (आईसीईडी) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें संबंधित मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया।

## पक्षों का सम्मेलन-कॉप 28

पक्षों का सम्मेलन (कॉप) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के तहत सदस्य देशों की एक वार्षिक सभा है। कॉप बैठकें जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के वैश्विक प्रयासों पर चर्चा करने और उसका समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। कॉप का 28वां सत्र 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में आयोजित किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कॉप बैठकों के समाधानों पर आगे की कार्रवाई करने के लिए नोडल मंत्रालय है। जलवायु परिवर्तन वार्ताओं पर सलाहकार समूह की पहली अंतर-मंत्रालयी बैठक के दौरान छह कार्य समूहों का गठन किया गया है, जिसमें नीति आयोग (i) शमन; (ii) जलवायु वित्त; (iii) पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 से संबंधित मामले; और (iv) ग्लोबल स्टॉक टेक विषयों का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

## भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र

नीति आयोग ने भारत का एक व्यापक भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। यह मानचित्र भारत के ऊर्जा क्षेत्र का संपूर्ण दृश्य प्रदान करता है, जिसमें नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय दोनों बिजली संयंत्र, तेल और गैस अनुप्रवाह क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जीवाश्म ईंधन संसाधन और अन्य ऊर्जा संपत्तियां शामिल हैं। ये मानचित्र भविष्य के सौर पार्कों, कोयला ब्लॉकों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए बुनियादी ढांचे की योजना सहित संसाधन नियोजन में सहायता करते हैं।

## टाइम्स-वेदा का उपयोग करके इष्टतम ऊर्जा मार्गों का विकास:

नीति आयोग टाइम्स-वेदा का उपयोग करके एक इन-हाउस ऊर्जा क्षेत्र लागत अनुकूलन मॉडल विकसित कर रहा है। यह मॉडल बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करता है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों का अनुकरण करता है। मॉडल से लक्षित आउटपुट में निम्नलिखित शामिल हैं: i) निवल शून्य लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक वैकल्पिक मार्ग में इष्टतम ऊर्जा मिश्रण ii) उत्सर्जन प्रक्षेपवक्र iii) क्षेत्रीय और कुल निवेश आवश्यकता और प्रौद्योगिकी विकास की पहचान और माप iv) स्रोत द्वारा प्राथमिक ऊर्जा खपत, अंत तक- उपयोग क्षेत्र, और सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई v) विस्तृत बिजली क्षेत्र क्षमता पूर्वानुमान आदि।

## कोयला गैसीकरण:

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और तकनीकी समिति आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए कार्यक्रम और परियोजनाओं की समीक्षा करती है। इस संबंध में, सीआईएल की

तीन कोयला गैसीकरण परियोजनाएं और एनएलसीआईएल की एक परियोजना वर्तमान में निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन अलग-अलग श्रेणियों के तहत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन हेतु 8500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कोयला/लिंगनाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को भी मंजूरी दे दी है।

### भारतीय कार्बन व्यापार बाज़ार:

नीति, बीईई को राष्ट्रीय कार्बन बाजार विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से ज्ञान सहायता प्रदान कर रहा है। प्रस्तावित कार्बन बाजार के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव प्रदान किए गए हैं, जिन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (सीसीटीएस) नियमों में शामिल किया गया है। नीति आयोग ने भारतीय कार्बन मार्केट गवर्निंग बॉडी (आईसीएमजीबी) के हिस्से के रूप में इस काम का समर्थन करना जारी रखा है।

### भारत-अमेरिका कार्यनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी

#### भारत-अमेरिका कार्यनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के तहत सतत विकास स्तंभ

भारत-अमेरिका कार्यनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (एससीईपी) के तहत, नीति आयोग और यूएसएआईडी सतत विकास स्तंभ का नेतृत्व करते हैं। सतत विकास स्तंभ के हिस्से के रूप में भवन क्षेत्र मॉडलिंग पर ज्ञान साझा करना, जीवन चक्र मूल्यांकन, जीसीएम के उपयोग के माध्यम से कम कार्बन प्रौद्योगिकियों के विश्लेषण के लिए क्षमता निर्माण और बायोमास एनर्जी मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना जैसी गतिविधियां शुरू की जा रही हैं।

### अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) मंत्रिस्तरीय बैठक 2024

पेरिस में स्थित भारतीय दूतावास के अनुरोध पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने आईईए की पूर्ण सदस्यता के भारत के आवेदन पर औपचारिक वार्ता की पहल को स्वीकार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 में भाग लिया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने आईईए के मंत्रिस्तरीय स्वागत और आधिकारिक उद्घाटन के साथ-साथ आईईए के पारिवारिक भोज के दौरान एक पैनल चर्चा में भाग लिया। उन्होंने सिंगापुर, जापान, यूरोपीय संघ, अमरीका तथा जर्मनी के साथ ही कार्यकारी निदेशक, आईईए और महासचिव, ओईसीडी के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

## शासन और अनुसंधान

शासन प्रभाग नौ केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों - उर्वरक विभाग, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संचार मंत्रालय - के संबंध में केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की नीतियों और कार्यक्रमों, उनके कार्यान्वयन और निगरानी अनुवीक्षण से संबंधित मुद्दों को देखता है। अनुसंधान प्रभाग नीति आयोग (या आरएसएनए) की अनुसंधान योजना की देखरेख करता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों का समर्थन करना है। प्रभाग संयुक्त राष्ट्र सतत समन्वय रूपरेखा 2023-24 के संबंध में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ भी समन्वय करता है।

## सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाएं: एक सार-संग्रह, 2023

नीति आयोग ने 1 मई, 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से "सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाएं: नामक एक सारांश, 2023" जारी किया है। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, इस संग्रह में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, ई-गवर्नेंस और डिजिटलीकरण, कृषि, महिला सशक्तिकरण, खेल और वित्तीय समावेशन सहित 14 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित 75 केस स्टडी शामिल हैं। केस स्टडी में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारत सरकार के 30 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है। पचहत्तर सर्वोत्तम प्रथाएँ उन मॉडलों को उजागर करती हैं जो नवीन, टिकाऊ, अनुकरणीय और प्रभावशाली हैं। इस प्रथा का उद्देश्य भविष्य के लिए जमीनी स्तर पर जीवन के विस्तार, संवर्द्धन और सुधार के लिए सीखों का संश्लेषण करना था।



नीति आयोग में मई 2023 में सर्वोत्तम प्रथाओं के सार-संग्रह का शुभारंभ

## संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023-2027 पर हस्ताक्षर

भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क 2023-27 पर जून 2023 में हस्ताक्षर किए। भारत सरकार-यूएनएसडीसीएफ पर नीति आयोग के सीईओ श्री बी वी आर सुब्रह्मण्यम और भारत के संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक श्री शोम्बी शार्प ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी और नीति आयोग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, भारत में केंद्रीय मंत्रालय और सभी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रमुखों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। भारत सरकार-यूएनएसडीसीएफ 2023-27 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, लैंगिक समानता, युवा सशक्तिकरण, मानवाधिकार और कई अन्यो के मध्य जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए विकास के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली की सामूहिक पेशकश का प्रतिनिधित्व करता है।



भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क 2023-27 पर 16 जून, 2023 को हस्ताक्षर

## नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) के बीच हस्ताक्षर किया गया आशय विवरण (एसओआई)

नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) ने कृषि और खाद्य नीतियों पर अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए एक आशय विवरण पर दिसंबर 2023 में हस्ताक्षर किए हैं। आशय विवरण पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी की उपस्थिति में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद और आईएफपीआरआई के महानिदेशक डॉ. जोहान स्विनन ने हस्ताक्षर किए। साझेदारी कृषि परिवर्तन और ग्रामीण विकास के लिए साक्ष्य आधारित नीतिगत रूपरेखा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, और इस प्रकार विकसित भारत@2047 की दिशा में एक रोडमैप प्रदान करेगी।



दिसंबर 2023 में नीति आयोग और आईएफपीआरआई के बीच एसओआई पर हस्ताक्षर

## यूरिया इकाइयों द्वारा लक्ष्य ऊर्जा मानदंडों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन।

नई यूरिया नीति (एनयूपी) - 2015 के तहत शामिल सभी पच्चीस गैस आधारित यूरिया इकाइयों द्वारा 1 अप्रैल, 2025 से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य ऊर्जा मानदंडों के संबंध में सिफारिशें देने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया गया है।

समिति एनयूपी-2015 के तहत कोयला आधारित संयंत्रों के लिए लक्ष्य ऊर्जा मानदंडों को संशोधित करने की सिफारिशें भी करेगी, जिन्हें उनके ऊर्जा मिश्रण में कोयले का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी गई है और नेफ्था परिवर्तित इकाइयों द्वारा अनुकूलन और सुसंगतता के लिए ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का सुझाव दिया जाएगा। यूरिया उत्पादन के संदर्भ में प्रदर्शन और जलवायु परिवर्तन और दुनिया भर में विकसित ऊर्जा परिदृश्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप यूरिया उत्पादन में हाइड्रोजन के लाभकारी उपयोग की संभावना का पता लगाना। विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक 27 फरवरी, 2024 को नीति आयोग में सम्पन्न हुई।

## पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के तहत अंतर-मंत्रालयी समिति की प्रति किलोग्राम सब्सिडी दर की सिफारिश करेगी

प्रत्येक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर के लिए प्रति किलोग्राम सब्सिडी दर की सिफारिश करने के लिए उर्वरक विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है, जिसमें नीति आयोग भी एक प्रमुख सदस्य है और वर्ष के दौरान आयोजित समिति की बैठकों में भाग लेता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उचित समय पर किफायती मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश में उर्वरक के सुचारु उत्पादन को बढ़ावा देना और इसकी कमी की स्थिति में उर्वरकों का सुचारु और समय पर आयात करना और अंततः उर्वरक के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

## मूल्यांकन

नीति आयोग के शासन और अनुसंधान वटिकल ने मसौदा ईएफसी, एसएफसी, कैबिनेट नोट्स, के साथ-साथ प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी) और परियोजनाओं की समीक्षा की और अपनी टिप्पणियां दीं। इसमें उर्वरक

और रसायन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं से संबंधित परियोजना शामिल है। वर्ष में, वर्टिकल ने 20 से अधिक ईएफसी, एसाएफसी, डीआईबी और परियोजना प्रस्तावों की जांच की।

## नीति आयोग की अनुसंधान योजना (आरएसएनए)

नीति को ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के अधिदेश के अनुरूप, नीति आयोग की अनुसंधान योजना का उद्देश्य संस्थागत और व्यक्तिगत आधार पर अनुसंधान सहित बड़े अनुसंधान कार्य करना, सेमिनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों की सहायता करना और साथ ही विभिन्न आयोजनों के लिए नीति आयोग लोगो के उपयोग के माध्यम से गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2023-24 के दौरान (31 मार्च, 2024 तक) कुल 2.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। 13 नए शोध अध्ययनों के वित्तपोषण के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे (अनुलग्नक 2- तालिका 2.1) एवं वर्ष के दौरान 14 चालू अध्ययनों को पूरा किया गया (तालिका 2.2)। इसके अलावा, विषयों और क्षेत्रों के व्यापक स्पेक्ट्रम के आयोजनों के लिए 36 संस्थानों को लोगो समर्थन दिया गया। इन रिपोर्टों और कार्टवाइयों की प्रतियां नीति के भीतर संबंधित वर्टिकलों में परिचालित की गईं, फिर इन रिपोर्टों की जांच की गई और आगे की कार्टवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दी गईं।

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पोषण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य विकास और प्रबंधन में शामिल प्रमुख हितधारकों को सलाह और नीति दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष मंत्रालय, औषध विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण(एनएचए), राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ जुड़ा है। प्रभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नीतिगत दृष्टिकोण पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने की दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, विकास भागीदारों और प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ भी सहयोग करता है।

## सिकल कोशिका एनीमिया का उन्मूलन

सिकल कोशिका रोग (एससीडी) एक क्रोनिक एकल-जीन विकार है जो क्रोनिक एनीमिया, तीव्र दर्दनाक एपिसोड, ऑर्गन इन्फार्कशन और क्रोनिक अंग क्षति और जीवन प्रत्याशा में महत्वपूर्ण कमी की विशेषता वाले दुर्बल प्रणालीगत सिंड्रोम का कारण बनता है। नीति आयोग के सदस्य के नेतृत्व में बहु-हितधारक बैठकों के बाद 40 वर्ष की आयु तक के सभी व्यक्तियों की सिकल कोशिका एनीमिया की जांच करने का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2023-24 में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जुलाई 2023 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। मिशन का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है और अगले तीन वर्षों में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच करना है। पूरे देश में 17 उच्च-फोकस वाले राज्यों में लागू किया गया मिशन का उद्देश्य रोग की व्यापकता को कम करते हुए सभी एससीडी रोगियों की देखभाल और संभावनाओं में सुधार करना है।

## स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना

भारत में बच्चों (0-18 वर्ष) की जनसंख्या 47.3 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 39% है (2011 की जनगणना)। भारत में स्कूलों में लगभग 26 करोड़ बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से 17 करोड़ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित हैं। बच्चों और किशोरों के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य मिशन की परिकल्पना की जा रही है

ताकि न केवल बेहतर सीखने के परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें बल्कि कम उम्र से ही आबादी की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। नीति आयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और अन्य हितधारक मंत्रालयों के सहयोग से बच्चों और किशोरों की जरूरतों को पूरा करने वाले चल रहे स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा और सुधार पर काम कर रहा है ताकि इसे अधिक व्यापक और सर्वांगीण रूप से बनाया जा सके।

## भविष्य में महामारी से बचाव की तैयारी

जैसा कि विश्व कोविड -19 महामारी से उबर रहा है, यह जरूरी है कि हम देश और वैश्विक अनुभव से सबक लें और संभावित भविष्य की महामारी से बचाव के लिए तैयारियों के तत्वों और मार्गों की कल्पना करें और एक दृष्टिकोण परिकल्पित करें कि कैसे एक नई शक्ति के साथ और भी अधिक प्रभावकारिता और गति के साथ इस परिमाण की भविष्य की चुनौती से कैसे निपटा जाए। इसे देखते हुए नीति आयोग ने इन मुद्दों का गहराई से अध्ययन करने, अन्य विशेषज्ञों (राष्ट्रीय/वैश्विक) से परामर्श करने और कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न सीखों का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए भविष्य की महामारी की तैयारी पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। विशेषज्ञ समूह भविष्य में बड़े पैमाने पर ऐसे किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, इस पर एक स्पष्ट कार्यनीति और रोड मैप प्रस्तुत करेगा। अब तक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ इस विशेषज्ञ समूह की सात बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

## रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)

एएमआर 1.0 (2017-2022) के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) 6 स्तंभों पर स्थापित की गई थी - जागरूकता और समझ; ज्ञान एवं साक्ष्य; संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण; उपयोग का अनुकूलन करें; नवाचार एवं अनुसंधान एवं विकास; और नेतृत्व - जिसमें लगभग 40 हितधारकों को शामिल किया गया है। यूएनजीए, जी7 से लेकर जी20 तक कई उच्च-स्तरीय मंचों पर एएमआर पर नीतिगत संवाद को फिर से वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में फोकस में लाया गया है।

तदनुसार, भारत कई मंत्रालयों/विभागों और संगठनों के इनपुट के साथ एनएपी-एएमआर 2.0 कार्यनीति (2024-28) भी तैयार कर रहा है। इससे कमियों को दूर करने और व्यक्तिगत हितधारकों के लिए विशिष्ट कार्य योजना और रोडमैप तैयार करने में मदद मिलेगी।

अब तक, नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एनएपी-एएमआर 2.0 के लिए तीन बहु-हितधारक बैठकें आयोजित की गई हैं। आगे बढ़ते हुए, एनएपी-एएमआर 2.0 रूपरेखा पर सभी हितधारकों से इनपुट और प्रतिबद्धताएं मांगी गई हैं और राष्ट्रीय एएमआर कार्यनीति में इसके अंतिम समावेश के लिए अगले कदम उठाए जाएंगे।

## नैदानिक मनोविज्ञान और मनोरोग सामाजिक कार्य में एम. फिल कार्यक्रम के विकल्प

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 उच्च शिक्षा सहित भारत में शिक्षा के परिदृश्य को बदलने के लिए एक नीतिगत अधिदेश प्रदान करती है। इसकी कई सिफारिशों में, एम.फिल कार्यक्रमों को बंद करने का निर्णय महत्वपूर्ण है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस जटिल मुद्दे में कई मंत्रालय और हितधारक शामिल हैं, नीति आयोग ने डॉ. वी. के. पॉल, सदस्य की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति में शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय पुनर्वास परिषद की भागीदारी और इन एम. फिल पाठ्यक्रमों को चलाने वाले प्रमुख विश्वविद्यालयों के पेशेवर विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व शामिल था। पाठ्यक्रमों की इष्टतम अवधि और मार्ग की जांच करने के लिए बहु-क्षेत्रीय हितधारक परामर्श की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम है जो नैदानिक अभ्यास के लिए आवश्यक योग्यता प्रदान करेंगे। विस्तृत चर्चा के बाद, समिति बंद किए गए एम.फिल को बदलने के

लिए नैदानिक मनोविज्ञान और मनोरोग सामाजिक कार्य पाठ्यक्रमों के लिए दो समवर्ती मार्गों की व्यापक सिफारिशों पर पहुंची। बंद एमफिल पाठ्यक्रम 2024 शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाएंगे। प्रक्रिया और सिफारिशों की व्यापक रिपोर्ट आगे की उपयुक्त कार्रवाई के लिए दिसंबर 2023 माह में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी।

## मेडिकल स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाना

नए मेडिकल कॉलेज खोलकर 1:1000 डॉक्टर अनुपात हासिल करने की दिशा में प्रगति के बावजूद, भारत अभी भी विकसित देशों की तुलना में 4x-5x गुना तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी का सामना कर रहा है। निजी क्षेत्र, जिसके पास देश के आधे से अधिक अस्पताल बिस्तर हैं, पीजी सीटों को अनलॉक करने के लिए एक बड़ी अप्रयुक्त क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिशा में बाधाओं और संभावित समाधानों को समझने के लिए, नीति आयोग ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) के साथ-साथ प्रमुख निजी क्षेत्र के अस्पताल संस्थानों के साथ परामर्श किया।

राष्ट्र के लिए इष्टतम मानसिक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में मनोचिकित्सकों की कमी प्रमुख मुद्दों में से एक है। नीति आयोग ने संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परामर्श करके मौजूदा सरकारी मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों/संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों से मनोचिकित्सा में वितरण योग्य पीजी सीटों का विस्तृत अंतर विश्लेषण किया। वर्तमान में, नीति ने इन संस्थानों से मनोचिकित्सा पीजी सीटों में वांछित वृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियामक मार्गों की सुविधा के लिए एनबीईएमएस और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) नेतृत्व के साथ काम किया है।

## परिवार चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से एमडी डॉक्टरों में वृद्धि

नीति आयोग देश में नए एम्स/आईएनआई के लिए अपने संबंधित चिकित्सा संस्थानों में पारिवारिक चिकित्सा कार्यक्रम शुरू करने के मार्ग को सुगम बना रहा है। यह आशा की जाती है कि भारत के प्रमुख एम्स/आईएनआई में चल रहे एमडी परिवार चिकित्सा कार्यक्रम या पाठ्यक्रम की शुरुआत करने से देश भर के मेडिकल कॉलेजों में ऐसे पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा। एम्स के केंद्रीय संस्थान निकाय (सीआईबी) ने नए एम्स में एमडी परिवार चिकित्सा शुरू करने के लिए नीति आयोग द्वारा संचालित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके लागू होने पर नए एम्स संस्थानों से सालाना एमडी परिवार चिकित्सा में 34 सीटें होंगी।

## संगम योजना

संगम योजना 2020 नीति आयोग के सदस्य के मार्गदर्शन में नीति आयोग में तैयार की गई थी और इसे 2021 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हुआ था। इस योजना के माध्यम से, सरकारी मेडिकल कॉलेज स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की भर्ती संख्या बढ़ाने के लिए सैन्य अस्पतालों की अवसंरचना का उपयोग करते हैं।

पिछले वर्ष, जोधपुर और झांसी के दो और एएफएमएस अस्पतालों ने संगम योजना के तहत स्थानीय सरकारी मेडिकल कॉलेज के साथ समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत में पीजी सीटों में वृद्धि होगी। आज तक, 5 एएफएमएस अस्पताल इस योजना में शामिल हुए हैं।

## सभी नए और आगामी एम्स में आयुष शैक्षणिक विभाग

एम्स की सेंद्रल इंस्टीट्यूट बॉडी (सीआईबी) ने अपनी छठी बैठक में नए एम्स में आयुष को एक अलग शैक्षणिक विभाग के रूप में बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया और सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, और निर्णय लिया कि आयुष विभाग से परामर्श के साथ भर्ती नियम बनाए जाने चाहिए। नीति आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,



आयुष मंत्रालय और एम्स, नई दिल्ली के परामर्श से भर्ती नियम तैयार करने से संबंधित कार्य का नेतृत्व किया। नीति आयोग के सदस्य द्वारा जुलाई 2023 में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर सीआईबी की सातवीं बैठक में आयुष शैक्षणिक विभाग के लिए संकाय और गैर-संकाय पदों की संरचना, उनके भर्ती नियमों और संबंधित नए एम्स में एकीकृत किए जाने वाले आयुष की धारा पर एक प्रस्तुति दी गई थी। सीआईबी ने प्रस्ताव पर विचार किया और अनुमोदित किया।

## फार्मा कंपनियों द्वारा विपणन पद्धतियाँ

फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों में डॉक्टरों/चिकित्सकों के नुस्खे लिखने के पैटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है, जिसे फार्मा उद्योग की ओर से अनुचित माना जा सकता है और चिकित्सा पेशेवरों द्वारा अनैतिक आचरण के रूप में देखा जा सकता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (यूसीपीएमपी) हेतु यूनिफॉर्म कोड 1 जनवरी 2015 से लागू है। इस कोड को फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सभी प्रमुख संघों द्वारा अपनाया गया है।

यूसीपीएमपी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और फार्मा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से लागू तंत्र की आवश्यकता की जांच करने के लिए सितंबर 2022 में नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सात बैठकें बुलाईं और सिफारिशें प्रस्तुत कीं, इनमें से कई सिफारिशों को फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा 12 मार्च, 2024 को जारी फार्मास्यूटिकल विपणन पद्धतियों के लिए संशोधित समान कोड 2024 में अपनाया गया था।

## दुर्लभ रोगों के लिए दुर्लभ औषधियाँ (ऑफ़न ड्रग) एवं उपचार

एक दुर्लभ बीमारी अक्सर प्रति 1000 जनसंख्या (डब्ल्यूएचओ के अनुसार) में एक या उससे कम की व्यापकता के साथ एक दुर्बल आजीवन रहने वाली बीमारी की स्थिति होती है, और ऐसे दुर्लभ विकारों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को ऑफ़न ड्रग्स कहा जाता है। भारत में, ऐसी स्थिति का इलाज करने के लिए बनाई जाने वाली दवा जो 5 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती है, उसे ऑफ़न ड्रग्स कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि दुर्लभ बीमारियों के लिए उपचार की अनुपलब्धता और दवाओं की अत्यधिक कीमतें चिंता का विषय है और इस पर ध्यान देने और समय पर कार्रवाई की आवश्यकता है, नीति आयोग ने भारत में दुर्लभ बीमारियों के रोगियों के लिए दवाओं की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से एक प्रयास किया है।

इस संबंध में, "दुर्लभ बीमारियों के लिए ड्रग्स और खुराक फॉर्म: निर्माताओं के साथ जुड़ाव" पर जुलाई 2022 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें सदस्य, नीति आयोग अध्यक्ष और नियामक - फार्मास्यूटिकल्स विभाग और चिकित्सकों के प्रतिनिधित्व के साथ - प्राथमिकता वाले विकारों/संकेतों और उनके संबंधित उपचारों के एक सेट की पहचान पर विचार करने के लिए शामिल किया गया था जो दुर्लभ दवाओं के घरेलू निर्माण के लिए सक्षम हो सकते हैं। मार्च 2024 तक, 15 बैठकें बुलाईं गई हैं, और दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए 4 दवाएं वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, चार औषधियां आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं और इन्हें अगले वर्ष की पहली छमाही तक वहनीय लागत पर उपलब्ध कराया जाएगा।

## मेड-टेक मित्र

नीति आयोग ने अन्य हितधारकों के साथ मिलकर मेडटेक नवाचार में कमियों को दूर करने और वास्तविक जीवन व्यवस्था में नैदानिक/सामुदायिक मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली बनाने के रास्ते की तलाश की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ विस्तृत दौर की चर्चा की गई ताकि चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकास और विनिर्माण में कमियों को दूर करने और नैदानिक मूल्यांकन, नियामक सुविधा

और नए उत्पादों के पहल के लिए नवप्रवर्तकों का समर्थन करने के लिए एक मार्ग तैयार किया जा सके। इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप, नवप्रवर्तकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और नैदानिक मूल्यांकन, नियामक सुविधा और नए उत्पादों के पहल के लिए नवप्रवर्तकों को सहायता प्रदान करके मेडटेक इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए 'मेडटेक मित्र' के रूप में एक आम मंच विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य किफायती और सुलभ, स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों और निदान के विकास को बढ़ावा देना है।



माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में सुशासन दिवस पर "मेडटेक मित्र" का शुभारंभ

इस परिवर्तनकारी मंच, "मेडटेक मित्र" को 25 दिसंबर 2023 को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा समर्थन किया गया और लॉन्च किया गया था, जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया गया था।

## चिकित्सा उपकरणों के लिए भारतीय मानक

भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा वितरण में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत का चिकित्सा उपकरण उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण (एनएमडी) नीति, 2023 को मंजूरी दी थी। इस नीति से पहुंच, वहनीयता, गुणवत्ता और नवाचार के सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के व्यवस्थित विकास की सुविधा मिलने की आशा है। इस नीति के तहत विनियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के घटकों में से एक घटक में बीआईएस जैसे भारतीय मानकों की भूमिका को बढ़ाना शामिल है। नीति आयोग ने चिकित्सा उपकरणों के लिए भारतीय मानकों की स्थापना को प्राथमिकता देने और "चिकित्सा उपकरणों के लिए भारतीय मानकों को अपनाने और विस्तार" कार्य बिंदु के लिए कार्यनीतियों को विकसित करने के लिए आवश्यक तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने से संबंधित कार्य

का संचालन किया। इसके बाद, पहचान किए गए कार्य क्षेत्रों के अनुरूप, फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने निदान सहित चिकित्सा उपकरणों की सूचियों को प्राथमिकता देने के लिए एक समिति का गठन किया है ताकि इन उपकरणों के लिए मानकों को स्थापित करने और प्रकाशित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की सिफारिश की जा सके। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने आईसीएमआर के माध्यम से “आवश्यक सहायक उत्पादों की राष्ट्रीय सूची” को शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने की कवायद को भी आगे बढ़ाया है।

### ‘भारत में चिकित्सा उपकरणों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना’ पर गोलमेज सम्मेलन

27 मार्च 2023 को भारतीय चिकित्सा सांसद फोरम (आईएमपीएफ) और नीति आयोग द्वारा ‘भारत में चिकित्सा उपकरणों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने’ पर एक गोलमेज चर्चा की सह-मेजबानी की गई। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य, संसद सदस्य, फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव और सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, मेड-टेक उद्योग के प्रतिनिधि, चिकित्सक और अन्य व्यक्ति उपस्थित थे।

गोलमेज बैठक में भारत में चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच से संबंधित सीमाओं और चुनौतियों और देश भर में उपकरणों के अंतिम मील उपयोग को बढ़ाने के संभावित तरीकों पर व्यावहारिक चर्चा हुई। चिकित्सा उपकरणों की सार्वजनिक खरीद, क्षेत्र में आयात निर्भरता और भारत में मेड-टेक क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए स्थानीय विनिर्माण क्षमता के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

### राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम में सुधार

मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंग दान और प्रत्यारोपण भारत में एक सरकारी-विनियमित गतिविधि है, जिसे पहली बार 1994 में संसद द्वारा पारित किया गया था। नीति आयोग ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) की जांच करने की पहल की है, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) के सहयोग से एक बेहतर और उन्नत एनओटीपी की स्थापना को सक्षम करने की प्रक्रिया में है।

एनओटीपी की समीक्षा के लिए नीति आयोग ने मई 2022 से कई बैठकें कीं। इस समीक्षा के कुछ परिणामों में विभिन्न हितधारकों के लिए अंग प्रत्यारोपण पर मानकीकृत जानकारी शुरू करने के लिए एक प्रत्यारोपण मैनुअल का विकास और प्रत्यारोपण समन्वयकों के लिए उनके प्रशिक्षण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक कोर्स पाठ्यक्रम शामिल है; जीवित अंग दान करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 42 दिनों तक की विशेष आकस्मिक छुट्टी का प्रावधान बनाना; पूरी तरह से डिजिटल आधार-प्रमाणीकृत राष्ट्रीय अंग प्रतिज्ञा रजिस्ट्री का निर्माण; और विभिन्न तरीकों (जैसे, हवाई, रेल, सड़क, मेट्रो इत्यादि) में अंग परिवहन पर मॉडल एसओपी विकसित करना, जो आठ मंत्रालयों के साथ साझेदारी में अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, मेट्रो के माध्यम से अंग परिवहन की अनुमति देने के लिए मई 2023 में मेट्रो रेलवे नियम 2014 में संशोधन किया गया था। हवाई मार्ग से अंग परिवहन के लिए कुशल प्रणाली कैसे विकसित की जाए, इसके लिए नई दिल्ली हवाई अड्डे पर दो ड्राई ड्रिल भी आयोजित की गईं।

### नीति आयोग में अंग प्रतिज्ञा जागरूकता अभियान

नीति आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ), और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ साझेदारी में 12 दिसंबर 2023 को सभी कर्मचारियों के लिए अंग प्रतिज्ञा अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने की, नीति समूह को अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में किए गए हालिया सुधारों और अंग दान के महत्व और विशेष रूप से, मृत व्यक्तियों के अंग दान के बारे में शिक्षित किया गया।



नीति आयोग में ऑर्गेन प्लेजिंग कैंपेन सत्र (बाएं) और एनओटीटीओ हेल्प-डेस्क (दाएं) के स्नैपशॉट्स

एनएचए ने ऑनलाइन प्लेज पंजीकरण प्रक्रिया का प्रदर्शन किया और ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान किया। व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर देने और अंग प्रतिज्ञा में सहायता करने के लिए एक एनओटीटीओ सहायता डेस्क पूरे दिन उपलब्ध था। अभियान का उद्देश्य बाधाओं को हटाना और अंग दान की शक्ति के बारे में जागरूकता फैलाना था।

### एमईआई-एमईजे फोरम पर कार्यशाला

नीति आयोग और चिकित्सा उत्कृष्टता जापान (एमईजे) ने 14 मार्च 2023 को पहली एमईआई-एमईजे फोरम कार्यशाला का आयोजन किया। सत्र का विषय "चिकित्सा डिजिटलीकरण के माध्यम से भारत में गंभीर चिकित्सा में सुधार के लिए पद्धति" था। कार्यशाला का संचालन सदस्य, नीति आयोग ने किया और इसमें एमईजे, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञों और उद्योग तथा शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सत्र में भारत में गंभीर चिकित्सा में मौजूदा चुनौतियों के लिए संभावित समाधानों का पता लगाया गया। भारत और जापान के विषय विशेषज्ञों ने गंभीर चिकित्सा परिदृश्य और चिकित्सा डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग पर अपनी प्रस्तुति दी।

### कनटिक मस्तिष्क स्वास्थ्य पहल (केए-बीएचआई)

नीति आयोग द्वारा निर्देशित कनटिक मस्तिष्क स्वास्थ्य पहल (केए-बीएचआई), कनटिक सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (निमहांस), बेंगलूर का सहयोग है। इस पहल का उद्देश्य आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के मंच पर न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य का एक प्राथमिक देखभाल मॉडल विकसित करना है। भारत में तंत्रिका संबंधी बीमारियों वाले व्यक्तियों की बेहतर देखभाल की आवश्यकता के लिए एक अनूठी और पहली प्रतिक्रिया के रूप में, कनटिक मस्तिष्क स्वास्थ्य पहल (केएबीएचआई), जनवरी 2022 में शुरू की गई थी।

कोलार, चिक्काबल्लापुरा और बेंगलूर दक्षिण के तीन जिलों के कुल 122 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल डॉक्टरों को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (निमहांस) के न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों द्वारा एक मानकीकृत प्रोटोकॉल का उपयोग करके सामान्य तंत्रिका संबंधी रोगों का इलाज करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत स्तर पर शीघ्र पहचान और लागत प्रभावी उपचार के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और घरों में रोगियों की जांच करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अगले कदम के रूप में, नीति आयोग ने अनुशंसा की है कि केएबीएचआई परियोजना को आईसीएमआर के साथ समन्वित किया जाए ताकि इसे कार्यान्वयन अनुसंधान पहल के रूप में लिया जा सके।

## भारत में वयोवृद्ध व्यक्तियों की देखभाल में सुधार: वयोवृद्ध व्यक्तियों की देखभाल प्रतिमान की पुनः कल्पना

संभावित जनसांख्यिकीय परिवर्तन के साथ, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। यह वर्तमान में कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत है और इसके 2030 तक 12 प्रतिशत और 2050 तक 20 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। 2047 तक विकसित भारत के मिशन और विज्ञान की पूर्ति के लिए, भारत के लिए वयोवृद्ध व्यक्तियों की देखभाल नीति हेतु शीघ्र संवाद शुरू करना अनिवार्य है।

इस उद्देश्य से, नीति आयोग ने भारत में वयोवृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के वर्तमान परिदृश्य को मैप करने के लिए एक अभ्यास शुरू किया है, और भविष्य की नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए स्वास्थ्य, सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल समावेशन के संबंध में वयोवृद्ध व्यक्तियों की देखभाल में जरूरतों और अंतराल को कम करने एवं बुजुर्ग आबादी के उच्च अनुपात वाले देशों के अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

नीति आयोग ने 16 फरवरी 2024 को एक स्थिति पत्र जारी किया - "भारत में वयोवृद्ध व्यक्तियों की देखभाल में सुधार वरिष्ठ देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना"। आशा है कि यह स्थिति-पत्र देश में वयोवृद्ध व्यक्तियों की देखभाल में इकोसिस्टम के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के इस विमर्श में नीति-निर्माताओं, अभ्यासकर्ताओं और हितधारकों के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में काम करेगा।

### आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सिस्टम में परिवर्तन

प्रत्येक वर्ष भारत में करीब 4.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं, जिनमें से 1.5 लाख लोग प्रत्येक वर्ष मर जाते हैं। पीड़ित ज्यादातर युवा, कार्यशील वर्ग के होते हैं जो अक्सर आजीविका कमाने वाले होते हैं। इसके अलावा, हर साल 25 लाख दिल के दौरों, 15 लाख सांप के काटने, 26,000 जहर खाने, 1.4 लाख आत्महत्या और 35 लाख समय पूर्व प्रसव के होती हैं, इसके अतिरिक्त 70 लाख ब्रेन स्ट्रोक और 5.5 करोड़ चिरकालिक फेफड़ों की बीमारियों के रोगी भी हैं, जो अक्सर आपातकालीन स्थितियों के रूप में सामने आते हैं। ये कई अन्य चिकित्सा आपातकालीन स्थितियों के अलावा हैं जो आपातकालीन विभागों में मौजूद हैं।

नीति आयोग ने देश में आपातकालीन देखभाल सेवाओं पर राष्ट्रव्यापी अध्ययन की सुविधा प्रदान की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर आपातकालीन और ट्रॉमा केयर पर एक व्यापक राष्ट्रीय मिशन विकसित किया।

#### मिशन के दो घटक हैं:

1. पूरे देश में विश्व स्तरीय एम्बुलेंस सेवाओं को बढ़ावा देना। शुरुआत से लेकर स्वास्थ्य सुविधा तक पहुँचने में सही कौशल के साथ सही जगह पर आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सेवाओं की समय पर, निर्बाध निरंतरता प्रदान करने के लिए मौजूदा प्री-हॉस्पिटल/एम्बुलेंस स्वास्थ्य प्रणालियों को बदलना।
2. जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में आपातकालीन देखभाल विभागों को मजबूत करना। समग्र इष्टतम आपातकालीन देखभाल, शीघ्र स्थिरीकरण और जीवन-सहायक उपाय प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में आपातकालीन देखभाल विभागों का निर्माण/उन्नयन करना ताकि सही समय पर निश्चित उपचार के लिए शीघ्र स्थिरीकरण सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रस्ताव पर अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया लागू की जा रही है।

## मूल्यांकन

नीति आयोग के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वटिकल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, औषध विभाग और आयुष मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं से संबंधित ईएफसी, एसएफसी, कैबिनेट मेमो के साथ-साथ डीआईबी और पीआईबी के मसौदे की समीक्षा की और उन पर अपनी टिप्पणियां दीं। वर्ष 2023 में, वटिकल ने कुल 6 कैबिनेट नोट का मसौदा और 20 से अधिक ईएफसी, एसएफसी, पीआईबी और डीआईबी का मूल्यांकन किया।

## आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ)

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और औषध विभाग के ओओएमएफ की वार्षिक समीक्षा बैठकें सदस्य की अध्यक्षता में आयोजित की गईं, जिसमें संबंधित विभागों के सचिवों ने भाग लिया। वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ इसी प्रकार की समीक्षा बैठक आयोजित की जानी है।

## आयुष्मान भारत का दौरा – पूरे भारत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्ववर्ती एबी – स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर) और आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का दौरा

आयुष्मान भारत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एबी-एएएम; पूर्ववर्ती एबी-एचडब्ल्यूसी) को फरवरी 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम (एबीपी) के तहत लॉन्च किया गया था, ताकि चुनिंदा स्वास्थ्य देखभाल से सभी आयु वर्ग के लिए निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक देखभाल में फैली सेवाओं की अधिक व्यापक श्रृंखला की ओर कदम बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम के एएएम घटक का उद्देश्य दिसंबर 2022 तक 1,50,000 मौजूदा सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को एएएम के रूप में अपग्रेड और परिचालित करना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 01 जनवरी 2024 तक, देश भर में कुल 1,63,852 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) परिचालन में हैं। इसके समग्र कामकाज की प्रगति, इन सुविधाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं, मौजूदा चुनौतियों और इन सुविधाओं के प्रति समुदाय की धारणा को समझने के लिए, 12 राज्यों और 01 संघ राज्य क्षेत्र के 37 जिलों में कुल 93 एएएम हैं। नीति आयोग की टीमों द्वारा सभी छह क्षेत्रों का दौरा किया गया। नीति आयोग की टीमों ने आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) की समग्र प्रगति और कामकाज को देखने के लिए 9 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में फैले कुल 34 एचडब्ल्यूसी का दौरा किया।

## राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का कार्यान्वयन

नीति आयोग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग के लिए दिशानिर्देशों के विकास में योगदान दिया, जिसे अप्रैल 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा जारी किया गया था। यह परिकल्पना की गई है कि संवर्ग नैदानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों का सीमांकन करके सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य और अस्पताल सेवाओं, दोनों के प्रबंधन को मजबूत करेगा। इससे राज्यों में उपलब्ध विशेषज्ञों की संख्या का और बेहतर उपयोग भी होगा। चार प्रकार की संरचनाओं और रूपरेखाओं का सुझाव दिया गया है और राज्यों को अपनी स्थानीय स्थिति और रूपरेखा के अनुसार संरचनाओं को अपनाए और संशोधित करने की सुविधा है।

इसके लिए नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में नीति आयोग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने राज्य स्वास्थ्य विभागों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ नीति आयोग ने कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशिष्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एनएचएसआरसी के माध्यम से सहायता प्रदान की है।

## उद्योग

### वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को बढ़ावा देना

उद्योग वर्टिकल ने 2023-24 के दौरान नीति आयोग की एक प्रमुख पहल का संचालन किया, जिसने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण विकास को लक्षित किया। जीवीसी अंतरराष्ट्रीय उत्पादन साझाकरण है - जिसमें, एक उत्पाद को उसके उत्पादन से लेकर अंतिम उपयोग तक और उससे परे (अर्थात् डिजाइन, उत्पादन, विपणन, वितरण, अंतिम उपभोक्ता को समर्थन, आदि) लाने के लिए गतिविधियों की पूरी श्रृंखला भौगोलिक स्थानों में कई फर्मों और श्रमिकों के बीच विभाजित है।

जीवीसी ने हाल के दशकों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विनिर्माण में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक व्यापार का लगभग 70% जीवीसी में निहित है। हालांकि, जीवीसी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की भागीदारी का वर्तमान स्तर कम है और इसमें वृद्धि की व्यापक क्षमता है।



एक प्रतिनिधिक वैश्विक मूल्य श्रृंखला: अंतिम उत्पाद प्रदायगी हेतु विभिन्न देशों में मूल्य संवर्धन

भारत के लिए अपनी जीवीसी भागीदारी बढ़ाने के महत्व और महत्वपूर्ण समय को स्वीकार करते हुए, नीति आयोग के उद्योग वर्टिकल ने प्रमुख क्षेत्रों में जीवीसी की जांच करने और भारत की भागीदारी को अधिकतम करने के लिए कार्रवाई-उन्मुख रणनीतियों को विकसित करने के लिए एक पहल की अवधारणा की। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

- मौजूदा उत्पाद और घटक इकोसिस्टम, नीति और नियामक कारकों, टैरिफ और कर संरचनाओं, रसद और बुनियादी ढांचे, श्रम मुद्दों, कौशल विकास, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं आदि के संबंध में भारत की जीवीसी भागीदारी के लिए बाधाओं और सक्षमकतियों की पहचान।
- रणनीतियों और कार्रवाई के कदमों के साथ अंतःक्षेप की सिफारिश जीवीसी परियोजना आंतरिक रूप से और प्रतिष्ठित बाहरी संस्थाओं के साथ गहन विश्लेषण और विचार-विमर्श के माध्यम से आकार ले रही है। 2023-24 के दौरान कई मील के पत्थर हासिल किए गए:

- **आधार विश्लेषण**, यह पता लगाना कि भारत को अपनी जीवीसी भागीदारी को अधिकतम क्यों करना चाहिए, क्षेत्र-वार बाजार आकार और अवसर, प्रमुख उत्पाद खंड, उत्पादन और निर्यात की वैश्विक तुलना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, घरेलू क्षेत्रीय स्थिति और विकास, घरेलू चुनौतियां आदि।
- **ज्ञान पार्टनर के साथ गहन क्षेत्र विश्लेषण**: उद्योग के तथ्य आधार और दृष्टिकोण की विस्तार से जांच करने, वैश्विक शिक्षा और गहन भारत-विशिष्ट निदान विकसित करने, और विशिष्ट अंतःक्षेपों की अनुशंसा करने हेतु परियोजना के लिए एक ज्ञान पार्टनर को शामिल किया गया था।
- **उद्योग और उद्योग विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श**: ओईएम, ओडीएम और घटक निर्माताओं सहित इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर वाहन दोनों क्षेत्रों में अग्रणी घरेलू और वैश्विक फर्मों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ परामर्श आयोजित किया गया। विशिष्ट जीवीसी मुद्दों पर प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ गहन विचार-विमर्श भी किया गया। उभरती अंतर्दृष्टि और चुनौतियों का उपयोग परियोजना विश्लेषण को सूचित करने और अनुशंसित समाधान विकसित करने के लिए किया गया था।

## उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम

भारत से विनिर्माण और निर्यात को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, नीति आयोग ने मंत्रालयों और विभागों के साथ विस्तृत परामर्श में पांच/छह वर्षों की अवधि के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 11 नवंबर, 2020 को हुई बैठक में मंजूरी दे दी थी।

पीएलआई स्कीम विनिर्माण को प्रोत्साहन देने और सशक्त क्षेत्रों में वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए शुरू की गई थी। प्रमुख विशिष्ट क्षेत्रों में पीएलआई स्कीम भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, निर्यात बढ़ाने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए तैयार किया गया है।

नीति आयोग संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ सभी पीएलआई स्कीमों की रूपरेखा तैयार करने में सहायक रहा है। सभी स्कीम वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं। नीति आयोग के सीईओ सभी 14 क्षेत्रों की पीएलआई स्कीमों की निगरानी के लिए अधिकार प्राप्त सचिव समूह (ईजीओएस) का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग के सीईओ एमईआईटीवाई के बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, महत्वपूर्ण केएसएम/डीआई/एपीआई और औषधि विभाग के चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण पर पीएलआई स्कीम के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं।

## खनिज पदार्थ

नीति आयोग देश में लाल मिट्टी से दुर्लभ पृथ्वी निष्कर्षण के लिए प्रौद्योगिकियों की स्थापना पर एक उप-समिति की सिफारिशों पर काम कर रहा है। "धात्विक मूल्यों के निष्कर्षण और अवशेषों के उपयोग के लिए लाल मिट्टी के समग्र उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकास" के संबंध में राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल), खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमएमटी), जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी), नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (नाल्को), हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और वेदांता के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना 1 अक्टूबर, 2021 को 3 वर्ष की समय सीमा के साथ शुरू हुई और परियोजना का दायरा बॉक्साइट अवशेषों के चयनित ग्रेड से पुनर्प्राप्ति मूल्यों और इसकी तकनीकी-



आर्थिक व्यवहार्यता के लिए पूर्ण द्रव्यमान और ऊर्जा संतुलन के साथ मास्टर प्लान शीट की रूपरेखा तैयार करना है। इसमें एल्यूमिना, आयरन, टाइटेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, नीति आयोग दुर्लभ पृथ्वी को मैग्नेट में बदलने की संभावनाओं को स्थापित करने पर उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर देश में आरई को मैग्नेट में बदलने की संभावनाओं को स्थापित करने का काम कर रहा है। "दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग करके डाउनस्ट्रीम उद्योग की स्थापना के लिए प्रोत्साहन ढांचे" के लिए एक रोड मैप भी विचाराधीन है।

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में, एमएसएमई रोजगार सृजन, निर्यात और समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह क्षेत्र 11 करोड़ से अधिक नौकरियां मुहैया कराता है और भारत की जीडीपी में लगभग 27% का योगदान देता है। इसके अलावा एमएसएमई का कुल विनिर्माण उत्पादन में 38.4% हिस्सा है और देश के कुल निर्यात में 45.03% का योगदान है।

एमएसएमई वर्टिकल भारत में एमएसएमई क्षेत्र की नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित मामलों से जुड़ा कार्य करता है। वर्टिकल का एक मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने और आगे बढ़ाने में एमएसएमई मंत्रालय को उचित सहायता प्रदान करना है।

नीति आयोग का एमएसएमई वर्टिकल लगातार प्रमुख मुद्दों को हल करने और शोध पत्रों के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों और विभागों को कार्रवाई योग्य सुझाव प्रदान करने से संबंधित है। वर्टिकल ने एमएसएमई नियामकों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने, व्यापार करने में उनकी आसानी में सुधार करने और इन बाधाओं को दूर करने के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए एमएसएमई से निर्यात को बढ़ावा देने जैसे अध्ययन शुरू किए हैं। एमएसएमई योजनाओं में ओवरलैप की पहचान करने के लिए वर्टिकल ने बेहतर प्रभाव पैदा करने और निधि के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए उनके अभिसरण पर एक अध्ययन शुरू किया है। मध्यम उद्यमों को बड़े उद्यमों तक बढ़ाने के महत्व और आवश्यकता को पहचानते हुए, मध्यम उद्यमों के लिए डिजाइनिंग नीति पर एक अध्ययन भी शुरू किया गया है।

## प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

एमएसएमई क्षेत्र के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक कारीगरों और शिल्पकारों के लाभ के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत थी। यह योजना 13000 करोड़ ₹ के परिव्यय के साथ ऋण सहायता, पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड, प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और 18 व्यापारों यथा - बढ़ई (सुथार/बढ़ई), नाव निर्माता, शस्त्रसाज, लोहार, हथौड़ा और उपकरण किट निर्माता, तालासाज, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला, फुटवियर कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने के जाल निर्माताओं को विपणन सहायता प्रदान करती है।

नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में एक संचालन समिति ने योजना के शुभारंभ के लिए सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं और कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया। यह योजना पूरे भारत में लागू की जा रही है। 05 मई 2024 तक, 2 करोड़ से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत नामांकन किया है।



माननीय प्रधानमंत्री 17 सितंबर, 2023 की विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर शिल्पकारों से बातचीत करते हुए

## सूचना प्रौद्योगिकी (सीमांत प्रौद्योगिकी सहित) एवं दूरसंचार

नीति आयोग में आईटी और दूरसंचार वर्टिकल सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और डाक से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार नोडल वर्टिकल है। यह डिजिटल इंडिया, सशक्त और समावेशी ज्ञान समाज की प्राप्ति को बढ़ावा देने और सहायता करने और डिजिटल विभाजन को कम करने का प्रयास करता है। यह दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संचार मंत्रालय की विभिन्न पहलों के लिए नीतिगत अंतःक्षेप से भी जुड़ा हुआ है।

वर्टिकल के व्यापक कार्य हैं:

- तीन सरकारी विभागों यथा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और डाक विभाग से नीतिगत संदर्भ/कैबिनेट/सीसीईए नोट्स की जांच करना।
- योजनाओं, एसएफसी/ईएफसी/पीआईबी/पीएससी/टीटीडीएफ नोट्स की जांच करना और इन विभागों की समिति की बैठकों में भाग लेना।
- डीएमईओ के समन्वय से इन मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के निष्पादन की जांच करना।
- रोबोटिक्स, भारत एआई मिशन और स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति के लिए मसौदा कार्यनीति पर अंतर-मंत्रालयी समितियों का प्रतिनिधित्व

### कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर सलाहकार समूह

भारत सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में भारत विशिष्ट नियामक एआई की रूपरेखा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) (एआई) पर एक सलाहकार समूह का गठन किया है, जिसका उद्देश्य एआई विनियमन पर सलाह प्रदान करना और सतत विकास इनेबल करने हेतु एआई-आधारित प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक नियामक अंतर्दृष्टि का समर्थन करना है। नीति आयोग ने एक सदस्य के रूप में वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित सलाहकार समूह की विभिन्न बैठकों में भाग लिया।

## मूल्यांकन

वर्टिकल ने मसौदा ईएफसी, एसएफसी, कैबिनेट नोट्स, 23वें डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी), उप-डीसीसी और निर्माता फोरम (एमएफ) के साथ-साथ प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी), परियोजना संचालन समिति (पीएससी) एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं डाक विभाग की विभिन्न स्कीमों एवं परियोजनाओं से संबंधित परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा की और अपनी टिप्पणियां दीं। वर्ष के दौरान वर्टिकल ने लगभग 25 ईएफसी/पीएससी एवं परियोजना प्रस्तावों की जांच की है। वर्टिकल ने उच्च स्तरीय बैठकों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री तैयार की है और उप-डीसीसी और एमएफ और अंतरमंत्रालयी परामर्शों में भी भाग लिया है।

## आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) की समीक्षा बैठके

वर्टिकल को डीएमईओ, नीति आयोग के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ; दूरसंचार विभाग; और डाक विभाग के ओओएमएफ की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। वर्टिकल ने 23 फरवरी, 2024 को नीति आयोग में आयोजित इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की समीक्षा बैठक का समन्वय किया जिसमें मंत्रालय की योजनाओं पर चर्चा की गई और सुझाव दिए गए।

## इंफ्रास्ट्रक्चर- कनेक्टिविटी (परिवहन)

इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी टीम भारत की आर्थिक दृष्टि के समर्थन में एक एकीकृत, कनेक्टेड, तकनीकी रूप से उन्नत, कुशल और टिकाऊ बुनियादी ढांचे और परिवहन प्रणाली के विकास की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करती है।

अपने उद्देश्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए, टीम को नीति अनुसंधान करने, चर्चा और नीति पत्रों के रूप में नीतिगत सिफारिशें और अंतःक्षेप शुरू करने और परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में परियोजनाओं, कार्यक्रमों, योजनाओं, नीतियों और कैबिनेट नोट्स का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया है। अपने उद्देश्यों के लिए, टीम निगरानी और समन्वय गतिविधियाँ, क्षेत्रीय समीक्षाएँ, अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता, वकालत और राज्य की भागीदारी के साथ जागरूकता सृजन, बाजार संपर्क और सरकारी, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और नागरिक समाज के नेटवर्क का लाभ उठाने सहित गतिविधियों पर भी कार्य करती है। प्रमुख क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स, सड़क और राजमार्ग, रेलवे, नागर विमानन, बंदरगाह और शिपिंग, अंतर्देशीय जलमार्ग, शहरी परिवहन, रोपवे और इलेक्ट्रिक गतिशीलता शामिल हैं। वर्टिकल भारत के लिए ईवी मिशन का कार्य संभालता है।

## परियोजना मूल्यांकन, तकनीकी इनपुट और सीखना

### रेलवे

वर्टिकल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। पश्चिमी गलियारा (जेएनपीटी से दादरी) 1506 कि.मी. और पूर्वी गलियारा 1875 कि.मी. (दानकुनी से लुधियाना) कार्यान्वयनाधीन हैं। परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डीएफसीसीआईएल बोर्ड में नीति आयोग को प्रतिनिधि बनाया गया है। परियोजना की भौतिक प्रगति 96 प्रतिशत है।

वर्टिकल भारत में रेलवे क्षेत्र के लिए नीतिगत इनपुट और विस्तार के लिए भी जिम्मेदार है। इसने कनेक्टिविटी बढ़ाने और नई लाइन के निर्माण, गेज परिवर्तन को दोगुना करने जैसे व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण शहरों/पर्यटन स्थानों के लिए रेलवे परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों, मार्च 2024 तक

12,62,610 करोड़ रुपये की लागत के साथ 39,615 रुट किमी मार्ग की सिग्नलिंग और स्टेशन आधुनिकीकरण के नवीनीकरण की जांच की है।

रेलवे यूनिट ने रेल मंत्रालय के 10.47 लाख करोड़ रुपये के कार्यक्रम को समाहित कर कैबिनेट प्रस्तावों की जांच की है। इसमें शामिल हैं : (क) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारों के लिए कनेक्टिविटी; (ख) उच्च घनत्व वाले मार्गों की क्षमता बढ़ाना और (ग) संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) और पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का वित्तपोषण और कार्यान्वयन योजना (घ) भारतीय रेलवे पर स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के लिए नीतिगत ढांचा (ङ) बंदरगाहों (रेल सागर) तक रेल कनेक्टिविटी बढ़ाना। यूनिट ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर स्वच्छ कार्गो टर्मिनलों के विकास के लिए रेल मंत्रालय को विश्व बैंक की तकनीकी सहायता की भी जांच की।

### बंदरगाह और शिपिंग

वर्टिकल ने 16 एसएफसी और डीआईबी प्रस्तावों की जांच की और विस्तृत सुझाव और टिप्पणियां प्रदान की गईं। प्रस्तावों में जेटी और बर्थ की क्षमता वृद्धि, लक्षद्वीप द्वीप के विभिन्न द्वीपों पर समुद्र तट के सामने सुविधाओं और परिधीय सड़कों के निर्माण के लिए सागरमाला फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल था।

वर्टिकल ने "शिपिंग पर गैर-प्रमुख बंदरगाहों के प्रभाव" पर एक थिंक टैंक द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन का भी पर्यवेक्षण किया। मसौदा रिपोर्ट मार्च 2024 में प्रस्तुत की गई थी।

### नागर विमानन

#### पीआईबी निवेश बोर्ड (पीआईबी)

वर्टिकल ने आगरा, बागडोगरा एवं बिहटा और दरभंगा हवाई अड्डों पर सिविल एन्क्लेव के विकास और लेह हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण पर पीआईबी प्रस्तावों की भी जांच की और तीन साल की ऑनसाइट वारंटी सुविधा और पुर्जों के पांच साल के विस्तृत वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) सुविधा के साथ विभिन्न हवाई अड्डों पर बॉडी स्कैनर्स की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के प्रस्ताव की भी जांच की।

टीम ने वर्ष के दौरान नागर विमानन से संबंधित 05 कैबिनेट नोटों का भी मूल्यांकन किया एवं टिप्पणियां मंत्रालय को भेज दी गईं।

### राजमार्ग, सड़कें, लॉजिस्टिक्स और शहरी परिवहन:

टीम ने अक्टूबर 2020 से लगभग 24 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 1343 से अधिक सड़क/लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिनमें से 1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 269 परियोजनाओं का मूल्यांकन वर्ष 2023-24 में किया गया था। लगभग 90 मूल्यांकन बैठकों में भाग लिया; मूल्यांकन, सिफारिशों और कार्यनीतियों से मिली कई सीखों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसकी एजेंसियों के साथ साझा किया गया और क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। ये परियोजनाएँ पूरे भारत में ईएफसी, एसएफसी, पीपीआर, पीएटीएससी, एनईएसआईडीएस, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुसंधान सलाहकार समिति की श्रेणियों के तहत थीं।

### महत्वपूर्ण पहल और कार्य

#### भारतीय अर्थव्यवस्था में नागर विमानन क्षेत्र की संभावनाओं पर कार्यशाला

यह अनुमान है कि 2047 तक वार्षिक हवाई यात्री मांग लगभग 2-3 बिलियन तक बढ़ सकती है, जो वर्तमान

मूल्य, 300 मिलियन से 8 गुना अधिक है। इसके लिए भारत की विकास आकांक्षाओं के अनुरूप हवाई अड्डे और एयरलाइन बुनियादी ढांचे, उपकरण, एमआरओ सेवाओं और पट्टे और वित्तपोषण, लॉजिस्टिक्स और अन्य विमानन संबद्ध सेवाओं में बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता होगी।

इस पृष्ठभूमि में, अनुसूचित यात्री सेवा क्षेत्र में विमानन क्षेत्र में प्रमुख हितधारकों और कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा और प्रकाश डालने के लिए 8 मार्च 2024 को विज्ञान भवन में नीति आयोग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला माननीय राज्य मंत्री, नागर विमानन मंत्रालय और सदस्य, नीति आयोग के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित की गई थी। कार्यशाला में नागर विमानन मंत्रालय, अन्य संबंधित मंत्रालयों और निजी क्षेत्र की एयरलाइंस, हवाईअड्डा संचालकों, एमआरओ, विमान पट्टा, वित्तपोषण, बैंकिंग और बीमा सेवाओं आदि के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधित्व देखा गया।



8 मार्च 2024 को भारतीय अर्थव्यवस्था में नागर विमानन क्षेत्र की संभावनाओं पर कार्यशाला

### भूमि मूल्य अधिग्रहण और साझाकरण (एलवीसी एंड एस) तंत्र को तेजी से अपनाना:

भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई) के साथ साझेदारी में "एलवीसी तंत्र को तेजी से अपनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तत्परता का मूल्यांकन" शीर्षक पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य पूरे भारत में एलवीसी एंड एस इको सिस्टम में सुधार को सुविधाजनक बनाना है। रिपोर्ट में भारत के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में एलवीसी एंड एस उपकरणों के कार्यान्वयन में पद्धतियों और अनुभवों को शामिल किया गया है। यह पहले की कार्यशालाओं और वैश्विक अच्छी प्रथाओं के दस्तावेजीकरण के अनुक्रम में है और इसके साथ राज्य विशिष्ट रूपरेखाओं और क्षमता निर्माण कार्यनीतियों का पालन करने की योजना बनाई गई है।

### भवन सूचना मॉडलिंग (बीआईएम)

ब्रिटिश उच्चायोग के विदेश राष्ट्रमंडल विकास कार्यालय (एफसीडीओ बीएचसी) के सहयोग से एआरयूपी के माध्यम से बीआईएम कार्ययोजना के रूप में बीआईएम को तेजी से अपनाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। बीआईएम के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों और समाधानों की पहचान भारतीय प्रासंगिक संदर्भ में एनेबलर्स के साथ की गई है। सार्वजनिक/निजी और शैक्षणिक क्षेत्रों में संबद्ध हितधारकों की पहचान की गई है और उन्हें एक उपयुक्त शासन संरचना के तहत शामिल किया गया है। टीम के अनुरोध पर एफसीडीओ-बीएचसी ने जनवरी 2024 में नीति आयोग के साथ मुख्य प्रस्तुतीकरण देते हुए बीआईएम पर एक प्रमुख हाइब्रिड कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सफल आयोजन में लगभग 10 मंत्रालयों तथा निजी क्षेत्र एवं शिक्षा जगत के 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।



जनवरी 2024 में भवन सूचना मॉडलिंग की क्षमता पर राष्ट्रीय कार्यशाला

### अवसंरचना को जोखिम मुक्त करना (सुदृढ़ अवसंरचना)

नीति आयोग द्वारा सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों संबंधी सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्विस री इंस्टीट्यूट के साथ किए गए शोध को नवीनतम संदर्भ के साथ अद्यतन किया गया है। अन्य बातों के अलावा प्राकृतिक आपदा हेतु सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करने वाले सुदृढ़ पहलुओं में जोखिम रजिस्टर विकसित करने और अवसंरचना बीमा शुरू करने के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।

### रसद लागत फ्रेमवर्क

भारत की रसद लागत को निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणालियों की मजबूती संबंधी उपलब्ध सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए, भारत के लिए एक अधिक प्रासंगिक और वैज्ञानिक आधार वांछनीय था। नीति आयोग ने एनसीएईआर और डीपीआईआईटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट- "भारत में रसद लागत - मूल्यांकन और दीर्घकालिक तंत्र" के निर्माण के लिए समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान किया।

### पीएम गतिशक्ति और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी)

नीति आयोग ने पीएम गतिशक्ति के उपयोग की अवधारणा विकसित करने, कार्यान्वयन करने और समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) के एक प्रमुख सदस्य के रूप में नीति आयोग ने लगभग 67 एनपीजी बैठकों में भाग लिया, 148 मेगा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया, जिनकी कुल लागत विभिन्न मंत्रालयों में 17.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। वर्ष 2023-24 में आयोजित की गई 22 बैठकों में 77 मेगा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिनकी कुल लागत 12.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक थी।

नीति आयोग शासन के विभिन्न स्तरों पर जैसे कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय निकायों पर अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पीएम गतिशक्ति के उपयोग की सक्रिय रूप से समर्थन करता रहा है। जागरूकता पैदा करने और गतिशक्ति फ्रेमवर्क की एक वृहद् तस्वीर और जटिलताओं को साझा करने के लिए नीति आयोग द्वारा 10 से अधिक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लिया गया।

इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वर्टिकल विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) और पारादीप (ओडिशा) के बंदरगाहों के लिए; क्षेत्रीय और स्थानिक नियोजन दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाते हुए जीआईएस, गतिशक्ति, भुवन, एनआईसी-भारतमैप्स और भारत सरकार के अन्य विभिन्न डेटा प्लेटफॉर्मों के उपयोग को प्रदर्शित करते हुए कडप्पा (आंध्र प्रदेश) और उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) के आकांक्षी जिलों के लिए भारत में योजना और स्थापत्य कला के तीन स्कूलों की साझेदारी में 5 अध्ययनों का मार्गदर्शन भी कर रहा है। ऐसे अध्ययनों से प्राप्त परिणामों और अनुकरणीय शिक्षा को विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और स्थानीय सरकारों के साथ-साथ बीआईएसएजी-एन, एनआरएससी और एनआईसी जैसे प्लेटफॉर्म डेवलपर्स के साथ भी साझा किया जा रहा है।

इस वर्टिकल ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और आकांक्षी जिला कार्यक्रम को वैचारिकता और मार्गदर्शन प्रदान किया है ताकि इन्हें पीएम गति शक्ति के साथ जोड़ा जा सके और जिला तथा ब्लॉक स्तर पर योजना बनाने एवं निर्णय लेने के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाया जा सके।

### ई-फ़ास्ट इंडिया (स्थाई परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ़्रेट एक्सेलेरेटर - भारत) की निरंतर प्रगति:

नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआई इंडिया) के सहयोग से और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ), कैलस्टार्ट व आरएमआई इंडिया द्वारा समर्थित, भारत का प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ़्रेट प्लेटफॉर्म-ई-फास्ट इंडिया (सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ़्रेट एक्सेलेरेटर- भारत) लॉन्च किया। ई-फास्ट प्लेटफॉर्म नवीन साधन विद्युतीकरण समाधानों को चिह्नित करने और समर्थन देने के साथ-साथ आपूर्ति और मांग पक्ष पर साझेदारी सुदृढ़ करने के लिए माल डुलाई इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों को एकजुट करता है। अपनी तरह के ऐसे प्रथम प्लेटफॉर्म का लक्ष्य ऑन-ग्राउंड प्रदर्शन पायलटों और साक्ष्य-आधारित अनुसंधान द्वारा समर्थित माल विद्युतीकरण संबंधी जागरूकता बढ़ाना है। ई-फास्ट इंडिया भारत में माल डुलाई विद्युतीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से नीतियों की भी जानकारी देगा।

### ऊर्जा परिवर्तन में छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों की भूमिका

भारत ने अपनी परमाणु यात्रा 1962 से शुरू की और अब तक 7.48 गीगावॉट की कुल स्थापित क्षमता सृजित करने में सक्षम रहा है। वर्ष 2032 तक यह क्षमता 22 गीगावॉट तक होने का अनुमान है। नेट-शून्य परिदृश्यों के तहत, भारत को 2070 तक लगभग 265 गीगावॉट परमाणु क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है। विश्व स्तर पर माना जा रहा है कि छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर (एसएमआर) ऊर्जा परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह बड़े परमाणु रिएक्टरों की तुलना में मॉड्यूलरीकरण, कम भूमि की आवश्यकता, कम परमाणु विशिष्टता क्षेत्र और निष्क्रिय सुरक्षा प्राप्त करने पर निर्माण में कम समय लेता है।

नीति आयोग ने परमाणु ऊर्जा विभाग के परामर्श से भारत में एसएमआर के विकास और स्थापना के लिए नीतिगत रूपरेखा पर काम करने की पहल की है। इस संबंध में, "एसएमआर" पर ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह के तहत एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला निर्धारित की गई थी और एक अध्ययन रिपोर्ट "ऊर्जा परिवर्तन में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की भूमिका" भी लॉन्च की गई थी।

## द्वीप विकास

राष्ट्र के विकास में योगदान करने की अपार क्षमता के कारण द्वीप विकास को एक फोकस क्षेत्र के रूप में लिया गया है। भारत में द्वीपों के दो कार्यनीतिक समूह हैं अर्थात्, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह। द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, विशिष्ट द्वीपों के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों की पहचान की गई है ताकि यह द्वीपों की प्रगति को बढ़ावा दे। द्वीपों की प्रगति कई कारकों के कारण महत्वपूर्ण हो गई है जिसमें द्वीपों की कार्यनीति, प्रकृति, लोग और उनकी आकांक्षाएं, पर्यावरण और मूल निवासी, विशेष रूप से कमजोर जनजातियां शामिल हैं।

उपर्युक्त विजन को प्राप्त करने के लिए, कई परियोजनाओं की पहचान की गई और विकासात्मक योजनाएं लागू की गई हैं। तदनुसार, सम्बद्ध एजेंसियों ने पर्यटन संवर्धन, रोजगार सृजन, स्थानीय उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना आदि के लिए योजनाओं का और अधिक ब्यौरा देने तथा आकर्षक परियोजनाएं तैयार करने के लिए योजनाओं को बढ़ावा दिया है। हवाई अड्डा, पत्तन और नगरीय परियोजनाओं जैसी अवसंरचना के सृजन का प्रस्ताव प्रगति पर है।

## मिशन लाइफ - पर्यावरण के लिए जीवन शैली

भारत मिशन लाइफ - लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के माध्यम से ऐसी अवधारणाओं को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री ने 2021 में ग्लासगो में सीओपी 26 में, जलवायु संबंधी कार्ययोजना को उत्प्रेरित करने के लिए व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन के महत्व पर जोर दिया। पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफ) परिवर्तनकारी व्यक्तिगत पहलों को जलवायु घटकों के समक्ष लाने और 'विवेकहीन तथा विनाशकारी खपत' के वर्तमान परिदृश्य से भविष्य में 'विचारशील और सतर्क उपयोग' के साथ आगे बढ़ने पर केंद्रित है।

नीति आयोग मिशन लाइफ कार्यक्रम को डिजाइन करने और प्रारंभ करने में शामिल रहा है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने संयुक्त रूप से 20 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया था।

भारत के लिए, 7 श्रेणियों में 75 कार्यों की पहचान की गई है, जिनमें से अधिकांश (i) विशिष्ट और मापदंड योग्य; (ii) न्यूनतम आपूर्ति-पक्ष निर्भरता के साथ व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों द्वारा अभ्यास करने में आसानी; और (iii) संचालित आर्थिक गतिविधियों के लिए गैर-विघटनकारी तथा निकट भविष्य में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना आदि हैं। इसने अगले 5 वर्षों तक 1 बिलियन भारतीयों द्वारा पर्यावरण हितैषी कार्यों को अपनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

जी20 ने सतत विकास के लिए जीवनशैली पर उच्च-स्तरीय सिद्धांतों का समर्थन किया और एकीकृत तथा समावेशी दृष्टिकोण को अपना कर अल्प-जीएचजी/निम्न-कार्बन उत्सर्जन, जलवायु अनुकूल और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास उपायों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध किया।

5 जून 2022 को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष श्री बिल गेट्स; लॉर्ड निकोलस स्टर्न, जलवायु अर्थशास्त्री; प्रो. कैस सनस्टीन, नज थ्योरी के सह-लेखक; सुश्री इंगर एंडरसन, यूएनईपी ग्लोबल हेड; श्री डेविड मालपास, विश्व बैंक के अध्यक्ष, और अन्य की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर आइडियाज एंड पेपर्स (जीसीआईपी) की घोषणा की गई। लाइफ जीसीआईपी वैश्विक नागरिकों को अधिक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की दिशा में प्रेरित करने की व्यापक पहल है।

जीसीआईपी को तीन मंत्रों के साथ लॉन्च किया गया:

- व्यक्तिगत व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करना: व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करके लाइफ को एक जन आंदोलन बनाकर।
- विश्व स्तर पर सह-निर्माण: शीर्ष विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों, शिक्षाविदों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों से अनुभवजन्य और स्केलेबल विचारों को क्राउडसोर्स करके।
- स्थानीय संस्कृतियों का लाभ उठाना: अभियान चलाने के लिए दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों के जलवायु-अनुकूल सामाजिक मानदंडों, विश्वासों और दैनिक घरेलू प्रथाओं का लाभ उठाकर।

लाइफ के लिए अब तक 2,538 प्रतिभागियों ने विचार प्रस्तुत किए। 67 देशों के प्रतिभागियों ने लाइफ जीसीआईपी के चरण-1 के लिए अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें एशिया के 2264 प्रस्तुतीकरण, उत्तरी अमेरिका के 115 प्रस्तुतीकरण, यूरोप के 88 प्रस्तुतीकरण, अफ्रीका के 56 प्रस्तुतीकरण और शेष प्रस्तुतीकरण दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के शामिल हैं।

### मिशन लाइफ के अंतर्गत प्रकाशन

इस वर्टिकल ने मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) के तहत 3 रिपोर्टें प्रकाशित कीं। व्यक्तियों द्वारा छोटे कार्यों के 'मूल दर्शन' के तहत ये प्रकाशन तैयार किए गए हैं, जिन्हें अंततः जलवायु संकट से जोड़ सकते हैं



और इस संकट को थोड़ा कम कर सकते हैं।

**i. जीवन के लिए विचार नेतृत्व**

प्रकाशन शिक्षाविदों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विचारों और सुझावों का संकलन है जो लाइफ मूवमेंट की दिशा में वैज्ञानिक और औसत दर्जे के समाधान की दिशा में योगदान दे रहे हैं।

**ii. सचेतन जीवन- दुनिया भर की लाइफ प्रथाओं का संग्रह।**

यह रिपोर्ट केस स्टडीज को प्रदर्शित करने के लिए लाइफ मूवमेंट के हिस्से के रूप में विकसित हुई है जो व्यवहार परिवर्तन के लोकाचार का प्रतीक है, टिकाऊ खपत को सुविधाजनक बनाता है तथा जलवायु परिवर्तन की ओर ध्यानाकृष्ट करता है। रिपोर्ट में सात विषयक क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनके नाम हैं- i.) पानी की बचत; ii.) अपशिष्ट प्रबंधन; iii.) सतत खाद्य प्रणाली; iv.) ऊर्जा संरक्षण; v.) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन; vi.) सतत जीवन शैली; और vii) ई-अपशिष्ट प्रबंधन।

**iii. अपने प्लैनेट के लिए मनन**

यह रिपोर्ट लाइफ मिशन को वैश्विक जन आंदोलन बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर 67 देशों से प्राप्त 2,500 विचारों में से चयनित और संकलित 75 सर्वश्रेष्ठ विचारों का संकलन है।

ऐसे दस्तावेजों के अंगीकरण हेतु जनता के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए इन्हें सार्वजनिक डोमेन में डाला गया है।



**उत्तर पूर्वी राज्य**

इस प्रभाग की गठन नीति आयोग के उपाध्यक्ष और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री की सह-अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी राज्यों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास हासिल करने के साथ उपयुक्त अंतःक्षेपों की सिफारिश करने के लिए की गई है।

### प्राथमिक परियोजना प्रस्ताव (पीपीआरआईडीएस)

बहुपक्षीय एजेंसियों से विदेशी निधियां प्राप्त करने वाले 28 पीपीआरआईडीएस का निपटान उत्तरपूर्वी प्रभाग द्वारा किया गया। प्रस्तावों पर समेकित टिप्पणियां/अवलोकन तैयार कर अपलोड किए गए।

### उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन)

केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त-पोषित पीएम-डिवाइन नामक एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना में पीएम गतिशक्ति की संकल्पना के तहत अवसंरचना के वित्तपोषण की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन किया जाता है, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा किए जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के अंतरालों को दूर किया जाता है। नीति आयोग अधिकार प्राप्त अंतर-मंत्रालयी समिति (ईआईएमसी) का सदस्य है। नीति आयोग ने इस योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों, पूर्वोत्तर परिषद और अन्य संस्थानों से स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, शहरी विकास, उद्यमिता, कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन किया।

### पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना

भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त-पोषित पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना नामक एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना केंद्रीय बजट 2017-18 में घोषित की गई थी। यह योजना कुछ चिन्हित क्षेत्रों जैसे कनेक्टिविटी, बिजली, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा में अवसंरचना के अंतराल को पूरा करने के लिए लागू की गई थी। नीति आयोग ईआईएमसी का सदस्य है। नीति आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों की खेल-कूद, सड़क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, डिजिटल अधिगम और दूरसंचार अवसंरचना से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन किया है।

## लोक वित्त और नीतिगत विश्लेषण

नीति आयोग के लोक वित्त और नीतिगत विश्लेषण (पीएफपीए) द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में से एक सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों, स्कीमों एवं परियोजनाओं का मूल्यांकन है। तदनुसार, इस प्रभाग को निम्नलिखित कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा गया है:

- नीतिगत विश्लेषण और लोक वित्त संबंधी स्वीकृत सिद्धांतों को लागू करते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों की प्रमुख परियोजनाओं और कार्यक्रमों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करना।
- सभी पीपीआर प्रस्तावों का विश्लेषण करना और सिफारिशें प्रस्तुत करना, जिन्हें भविष्य में ईएफसी/पीआईबी के प्रस्ताव में रूपांतरित होने की संभावना है।
- ईएफसी/पीआईबी/सीईई और ईबीआर जैसी विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करना। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन, आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों और कैपेक्स योजनाओं से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करना, जिसमें प्राप्त संदर्भों के आधार पर पीएसयू के संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं।
- कार्यक्रमों और परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली में सुधार करने हेतु अनुसंधान संबंधी अध्ययन करना ताकि बेहतर योजना/परियोजना निर्माण, निष्पादन पर जोर देकर प्रभाव मूल्यांकन और अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से लोक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्हें नीतिगत विश्लेषण और सार्वजनिक वित्त की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप रखा जा सके।
- विभिन्न सार्वजनिक वित्त-पोषित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए व्यय प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देशों और प्रारूपों की सिफारिश करना।

- vi. सार्वजनिक खरीद, अनुबंध संरचना और परियोजना प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों की सिफारिश करना।
- vii. योजना और परियोजना प्रस्तावों के विकास के लिए उचित प्रक्रियाएँ स्थापित करने में केंद्रीय मंत्रालयों/राज्यों की सहायता करना।
- viii. नीतिगत विश्लेषण और लोक वित्त के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की पहल करना।

### सार्वजनिक कार्यक्रमों, स्कीमों एवं परियोजनाओं का मूल्यांकन

यह प्रभाग सार्वजनिक निवेश बोर्ड और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) से संबंधित 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं/स्कीमों का व्यापक मूल्यांकन करता है। विस्तारित रेलवे बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचारणीय 500 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक लागत वाले रेल मंत्रालय के प्रस्तावों का भी मूल्यांकन करता है। लागत एवं समय आधिक्य के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यवहार्यता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु प्रभाग द्वारा संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) के प्रस्तावों का भी मूल्यांकन किया जाता है।

अपने तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के माध्यम से इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में पी.एफ.पी.ए. ने सार्वजनिक परियोजनाओं और योजनाओं की संरचना और तैयारी के लिए मूल्यांकन तंत्र तथा प्रक्रियाओं में एक आमूल चूल परिवर्तन किया है। वर्टिकल ने अपने मूल्यांकन जापन के माध्यम से, सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं की प्रभावकारिता और वितरण तथा परिणामों के संदर्भ में खर्च के उद्देश्य से प्रणालीगत सुधार लाने और सुझाव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्ष 2023-24 (31 मार्च, 2024 तक) के दौरान, पीएफपीए ने 202 ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया, जिसमें 2976863.86 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली योजनाएं/परियोजनाएं शामिल हैं। 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च, 2024 तक मूल्यांकित योजनाओं/परियोजनाओं का क्षेत्र-वार वितरण अनुलग्नक-1 पर सारिणी में दिया गया है:

### सूत्रम

नीति आयोग को मूल्यांकन के लिए विभिन्न मंत्रालयों के ईएफसी, एसएफसी आदि से संबंधित दस्तावेज प्राप्त होते हैं। ऐसी योजना/परियोजना दस्तावेज और संबंधित डेटा पहले एनआईसी द्वारा विकसित ऑनलाइन डेटाबेस में रखे जाते थे और नीति आयोग के आंतरिक सर्वर पर स्टोर किए जाते थे। वर्टिकल द्वारा सूत्रम, जो खोजने योग्य डेटा भंडार है, की संकल्पना की गई और इसे योजना दस्तावेजों तथा योजना मेटाडेटा को शामिल करके विकसित किया गया है। पुराने डेटाबेस में उपलब्ध डेटा और दस्तावेजों को सूत्रम में स्थानांतरित कर दिया गया है और डेटाबेस में अपलोड किए गए पीडीएफ/वर्ड डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट सर्च सहित खोज सुविधा के साथ मौजूदा डेटा के अपडेशन और नए डेटा और दस्तावेजों को अपलोड करने का प्रावधान किया गया है।

नीतिगत और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जो किसी प्रस्तावित योजना या परियोजना का हिस्सा नहीं हैं उनको अपलोड करने के लिए डेटाबेस के भीतर एक लाइब्रेरी बनाई गई है। इससे मूल्यांकन करते समय मंत्रालयों से प्राप्त प्रस्ताव का व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने में सुगमता होती है।

## सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)

वर्टिकल अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिमान्य माध्यम के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की पहुंच को गहन बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसका उद्देश्य समयबद्ध ढंग से विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करना और अवसंरचना क्षेत्र में निजी क्षेत्र और संस्थागत पूंजी को आकर्षित करना है।

## शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी

नीति आयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से छात्रावास सुविधाओं को विकसित करने के लिए मॉडल बोली दस्तावेज (प्रस्ताव और मॉडल रियायत समझौता के लिए अनुरोध) तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। परिकल्पित पीपीपी मॉडल का उद्देश्य 'अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता हेतु स्कीम' के अंतर्गत सरकार से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के विकल्प के साथ डीबीएफओटी (डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण) आधार पर छात्र आवास सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र के निवेश और दक्षता का लाभ उठाना है। उक्त मॉडल के आधार पर 3 परियोजनाओं के विकास के लिए वीजीएफ प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाने वाला है।

## सड़क में सार्वजनिक निजी भागीदारी

नीति आयोग ने बीओटी (टोल) मोड पर पीपीपी के माध्यम से चार लेन से छह लेन तक जाने वाले राजमार्गों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रियायत ढांचे को मजबूत करने के लिए 'बीओटी (टोल) पर क्षमता वृद्धि के लिए मॉडल रियायत समझौते (एमसीए)' के संशोधन और अद्यतन के लिए सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य किया। उक्त परियोजनाओं की बोली क्षमता, व्यवहार्यता और बैंक योग्यता में वृद्धि करने के उद्देश्य से व्यापक विचार-विमर्श के बाद संशोधित एमसीए को (जारी संशोधनों के साथ) अंतिम रूप दे दिया गया है।

## वस्त्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी

भारत सरकार ने 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों में 7 पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (पीएम मित्र पार्क) की स्थापना को मंजूरी दी। इस योजना में वस्त्र उद्योग की कुल मूल्य श्रृंखला (अर्थात् खेत से फाइबर से कारखाने से फैक्ट्री से विदेश तक) के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा विकसित करने की परिकल्पना की गई है। नीति आयोग ने पीपीपी मोड पर इन पीएम मित्र पार्कों के विकास और संचालन के लिए बोली दस्तावेज (रियायत समझौता और प्रस्ताव के लिए अनुरोध) तैयार करने पर वस्त्र मंत्रालय के साथ गहनता से कार्य किया, जिसमें संबंधित राज्य सरकारों के साथ चर्चा करना शामिल है।

## कोल्ड स्टोरेज में सार्वजनिक निजी भागीदारी

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विकल्प विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) शीत भंडारण नेटवर्क स्थापित करने, सीडब्ल्यूसी गोदामों में शीतागार स्थापित करने, मूल्य स्थिरीकरण के लिए शीतागारों का नेटवर्क बनाने और शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं में अपव्यय/भंडारण हानियों को कम करने तथा सर्वोत्तम/कुशल कोल्ड स्टोरेज प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण और आधुनिकीकरण पर कार्य कर रहा है। नीति आयोग पीपीपी के आधार पर शीत भंडारणों के विकास और संचालन के लिए उपयुक्त मॉडलों के विश्लेषण तथा तैयार करने में सीडब्ल्यूसी और डीओएफपीडी के साथ कार्य कर रहा है।

## प्रमुख बंदरगाहों में सार्वजनिक निजी भागीदारी

'अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता योजना' के तहत, पीपीपी वर्टिकल, नीति आयोग ने बढ़ते कंटेनर यातायात के लिए अवसंरचना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया। 7056 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत के साथ प्रस्तावित, जिसमें से 20 प्रतिशत उक्त योजना के तहत भारत सरकार से व्यवहार्यता अंतर वित्त-पोषण के रूप

में मांग की गई, इस परियोजना में प्रत्येक 1000 मीटर कचे लंबाई के चार कंटेनर बर्थ का विकास और कंटेनर कार्गो को संभालने के लिए उनका मशीनीकरण शामिल है। इस परियोजना के परिणामस्वरूप अधिक लंबी कचे लंबाई और उच्च ड्राफ्ट टर्मिनल तथा बड़ा बैक अप क्षेत्र होगा, जिससे वीओसीपीटी पड़ोसी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों के विकल्प के रूप में उभर सकेगा, जिससे मैरीटाइम इंडिया विजन -2030 (एमआईवी -2030) को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

## एकल-चरण बोली के लिए प्रस्ताव हेतु मॉडल अनुरोध

नीति आयोग एकल चरण बोली के प्रस्तावों के लिए मॉडल अनुरोध (आरएफपी) तैयार करने के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग के साथ काम कर रहा है। एक सेक्टर एग्नॉस्टिक मॉडल दस्तावेज के रूप में तैयार उक्त मॉडल आर.एफ.पी. में अंतर्निहित लचीलेपन और दिशानिर्देश हैं जो बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में परियोजनाओं में इसके उपयोग और तैनाती को सक्षम बनाते हैं।

## भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) स्कीम

पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना प्राधिकरणों को एक कुशल, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से परियोजनाओं के पुरस्कार और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक परियोजना दस्तावेज तैयार करने और लेनदेन को बंद करने के लिए विशेषज्ञ वित्तीय, कानूनी और तकनीकी सलाह की आवश्यकता होती है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से आईआईपीडीएफ योजना राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के पीपीपी परियोजना प्राधिकरणों के लिए उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य परियोजनाओं की विकास संबंधी लागतों को पूरा करना है जिसमें व्यवहार्यता अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव अध्ययन, वित्तीय संरचना, विधिक समीक्षा और परियोजना/बोली दस्तावेज में सुधार से संबंधित व्यय भी शामिल हैं।

आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त-पोषण का लाभ अनिवार्य रूप से परामर्शदाताओं और संव्यवहार सलाहकारों की लागत को वित्त-पोषित करने के लिए लिया जा सकता है। पीपीपी वर्टिकल ने इस योजना के तहत वित्तपोषण हेतु देश के विभिन्न राज्यों के प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य किया है। वर्ष 2023 में ऐसे 18 प्रस्तावों के तहत मांगी गई निधियन हेतु मंजूरी प्रदान की गई है।

## राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की स्थिति

केंद्रीय बजट 2021-22 में मुख्य परिसंपत्ति मुद्रीकरण को संवर्धित और सतत अवसंरचना के वित्त-पोषण के लिए देश के तीन स्तंभों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया। बजट में नीति आयोग को ब्राउनफील्ड की मुख्य अवसंरचना परिसंपत्तियों के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) का निर्माण करने का काम सौंपा गया। अगस्त 2021 में एनएमपी जारी किया गया, जिसमें 4 वर्ष (वित्त वर्ष 2022 से 2025) की अवधि में केंद्रीय मंत्रालयों/सीपीएसई की 6.0 लाख करोड़ रुपये के सांकेतिक मूल्य वाली संभावित मुख्य परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण नीति और पाइपलाइन को सूचीबद्ध करने के लिए रूपरेखा विहित की गई। यह सड़क, रेल, विमानन, विद्युत, तेल और गैस तथा भंडारण सहित विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में संभावित मुद्रीकरण के लिए तैयार परियोजनाओं की पहचान करने के लिए मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में कार्य करता है।

इसकी शुरुआत से नीति आयोग ने निवेश और संव्यवहार संरचना, प्रगति की समीक्षा और अंतर-मंत्रालयी तथा संरचनात्मक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य किया। वर्ष 2021-22 से 2022-23 की अवधि के दौरान, प्रोद्भवन या निजी निवेश के संदर्भ में लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये के कुल मुद्रीकरण मूल्य वाला संव्यवहार पूरा किया गया।

## केंद्र सरकार की सार्वजनिक-निजी भागीदारी का मूल्यांकन

1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान, पीपीपी वर्टिकल द्वारा 1.98 लाख करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत (19,000 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली 6 वीजीएफ परियोजनाओं सहित) वाली 185 पीपीपी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इन मूल्यांकित पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार वितरण नीचे तालिका में दिया गया है:

**तालिका: 1 जनवरी, 2023 और 31 मार्च, 2024 के दौरान मूल्यांकित पीपीपी परियोजनाएं**

क्रमांक	मूल्यांकित परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (करोड़ रुपये में)
1.	सड़क	159	1,66,609
2.	समुद्री बंदरगाह	15	19,081
3.	अस्पताल	4	1,983
4.	साइलोज	2	4,165
5.	मल्टी मॉडल टर्मिनल	1	1,111
6.	रोपवे	1	102
7.	दूरसंचार	1	3,000
8.	ठोस अपशिष्ट	2	2,028
	कुल	185	1,98,079

## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थाएं

नीति आयोग का ग्रामीण विकास वर्टिकल ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग को समग्र नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी भी करता है।

ग्रामीण विकास वर्टिकल द्वारा मंत्रालय की जिन प्रमुख योजनाओं की निगरानी की जाती है वे सीएसएस योजनाएं हैं, जैसेकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम), दीनदयाल उपाध्याय - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)। यह वर्टिकल उपर्युक्त योजनाओं से संबंधित रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के लिए इनपुट प्रदान करता है।

ग्रामीण विकास क्षेत्र की योजनाओं जैसे कि मनरेगा, पीएमएवाई-जी, डीएवाई-एनआरएलएम, एनएसएपी, एसएजीवाई, एसपीएमआरएम और पीएमजीएसवाई के संबंध में वास्तविक और वित्तीय स्टेटस तैयार किया गया और प्रधानमंत्री/उपाध्यक्ष के राज्यों के दौरों के लिए प्रदान किया गया।

वर्टिकल ने 'सहकारी संघवाद को पुनः जीवंत बनाना' पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से कार्य योजना के अंग के रूप में नीति आयोग के उपाध्यक्ष/सदस्यों तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच आयोजित बैठकों पर राज्यों

द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के संबंध में उत्तर/स्पष्टीकरण प्रदान करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समन्वय किया। इस वर्टिकल ने मंत्रालय की वार्षिक निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक में भी भाग लिया।

इस वर्टिकल ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरडीटीपी), महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी), स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) - चरण III पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न बैठकों में भाग लिया। वर्टिकल ने प्रो. रमेश चंद, सदस्य की अध्यक्षता में यूटी डेल्फ्ट, नीदरलैंड में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉ. आर आर वेंटेशा प्रसाद द्वारा "टेकिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) टू द एक्सट्रीम" पर एक वार्ता का आयोजन किया।

ग्रामीण विकास वर्टिकल ने डीएमईओ द्वारा सृजित कार्यानिष्पादन-परिणाम अनुवीक्षण तंत्र के अद्यतन की समीक्षा के लिए डीएमईओ के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक का समन्वय किया। अगले वर्ष के लिए संकेतकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, वर्टिकल ने दो कैबिनेट नोट्स और एक एसएफसी और राज्य सरकारों तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त चार पीपीआर का मूल्यांकन किया।

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी

### “नए भारत में नवाचार के लिए एक नया लेंस - तकनीकी-वाणिज्यिक तैयारी और मार्केट मेच्योरिटी मैट्रिक्स का परिचय” पर नीतिगत वर्किंग पेपर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्टिकल ने डॉ. वी के सारस्वत, सदस्य के मार्गदर्शन में जुलाई 2023 में एक नीति कार्य-पत्र प्रकाशित किया। इस कार्य-पत्र का उद्देश्य प्रौद्योगिकियों की व्यावसायिक तत्परता को मापने की रूपरेखा तैयार करना था। यह प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल), व्यावसायीकरण तत्परता स्तर (सीआरएल) और बाजार तत्परता स्तर (एमआरएल) के पैमाने के विकास और उनके लाभ और सीमाओं पर ध्यान आकर्षित करता है। यह तकनीकी-व्यावसायिक तत्परता और बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स (टीसीआरएम मैट्रिक्स) रूपरेखा नामक एक संयुक्त मूल्यांकन रूपरेखा का प्रस्ताव करता है जो अतिरिक्त अंतर्दृष्टि और कार्रवाई योग्य आसूचना प्रदान कर सकता है। कार्य-पत्र नवाचार के विभिन्न मॉडलों पर प्रकाश डालता है जिन्होंने संयुक्त मूल्यांकन रूपरेखा के विकास को प्रभावित किया है और यह भी रेखांकित करता है कि कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है और प्रमुख वित्त पोषण निकायों, देशों और फर्मों द्वारा अपनाए जाने के लिए इसे और अधिक स्वीकार्य बनाया जा सकता है।

### “विश्व स्तरीय प्रतिभा के केंद्र के रूप में भारत का विकास” पर नीति आयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) द्वारा सहयोगात्मक अध्ययन

एनएससीएस-नीति आयोग के शीर्ष समन्वय तंत्र के सुझावों के आधार पर, “विश्व स्तरीय प्रतिभा केंद्र के रूप में भारत का विकास” को इंडिया@100 के विज्ञान को साकार करने की थीम के रूप में चिन्हित किया गया। परिणामस्वरूप, विशेष रूप से महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों और औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए डिजिटल कौशल और इस विषय से संबंधित अन्य बारीकियों के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभा के निर्माण पर एनएससीएस और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से एक सहयोगात्मक अध्ययन शुरू किया गया। पूर्ण संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट निर्देशित पहल की पहचान करती है जहां भारत सरकार, उद्योग और नागरिक भविष्य के उद्योगों और सुदृढ़ तथा समृद्ध भारत के निर्माण के लिए इकोसिस्टम में सार्वजनिक और निजी निवेश से ठोस रिटर्न की आशा की जा सकती है। यह एक अग्रणी वैश्विक प्रतिभा केंद्र के रूप में भारत के स्तर को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई योग्य

कार्यनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है, जो नवाचार और विकास के लिए अनुकूल इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है।

### स्वदेशी कृत्रिम हृदय के विकास और व्यावसायीकरण के लिए मिशन

कार्डियोलॉजी विभाग, एम्स, नई दिल्ली के प्रोफेसर और पूर्व प्रमुख डॉ. राजीव नारंग की अध्यक्षता में स्वदेशी कृत्रिम मानव हृदय के विकास और व्यावसायीकरण पर एक मिशन समिति का गठन किया गया। समिति का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी कृत्रिम मानव हृदय के विकास और व्यावसायीकरण पर मिशन दस्तावेज तैयार करना है, जिसे बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बहु-संगठनात्मक मिशन परियोजना के रूप में औपचारिक मंजूरी के लिए लिया जा सकता है। मिशन समिति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

### राज्य के स्वामित्व वाले और निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान और विकास की परंपरा में सुधार करना

नीति आयोग के सदस्य के मार्गदर्शन में वर्टिकल, उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) में अनुसंधान और विकास से संबंधित वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और मुद्दों और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अन्य अवसरचक्रात्मक चुनौतियों का आकलन करने के उद्देश्य से एक परामर्श अध्ययन आयोजित कर रहा है। वर्टिकल कई ऐसे विश्वविद्यालयों और संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ इस तरह की परामर्श बैठकें आयोजित करता रहा है- जो गैर-आई.आई.टी./एन.आई.टी. और गैर-एआईआईएमएस/पीजीआईएमईआर हैं और अधिकांशतः देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थित हैं।



10 जुलाई 2023 को राज्य के स्वामित्व वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ बैठक आयोजित की गई।

यह चर्चा बैठक के दौरान महत्वपूर्ण अंतरालों और चुनौतियों की पहचान करने तथा सर्वोत्तम प्रथाओं और समाधानों को साझा करने पर केंद्रित थी, जिन्होंने विशिष्ट चुनौतियों से निबटने में मदद की है। इनसे उन उपायों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी जिन्हें पूरे देश के शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास के इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए शुरू करने की आवश्यकता है।



## भारत में सीओ2 उपयोग परियोजनाओं पर तकनीकी समिति

विज्ञान और तकनीकी वर्टिकल को भारत में सीओ2 उपयोग परियोजनाओं पर तकनीकी समिति की जिम्मेदारी दी गई। भारत में सीओ2 उपयोग परियोजना पर तकनीकी समिति ने वर्ष के दौरान 9 बार बैठक की और सीओ2 के क्षेत्र विशिष्ट उपयोग पर विस्तार से चर्चा की। सीओ2 उपयोग बनाम भंडारण, भारत में कार्बन उपयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने में कार्बन बाजार की भूमिका और सीओ2 उपयोग और भावी आरएंडडी आवश्यकताओं में आरएंडडी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं।

तकनीकी समिति के विभिन्न सदस्यों से प्राप्त विचार-विमर्श और इनपुट के आधार पर, सीओ2 उपयोग पर तकनीकी समिति की एक रिपोर्ट तैयार की गई। सीओ2 उपयोग पर तकनीकी समिति के अध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुमोदित अंतिम रिपोर्ट अग्रिम उचित कार्रवाई के लिए नीति आयोग के ऊर्जा वर्टिकल को प्रस्तुत की गई है।

## भारत की परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छोटे पैमाने के परमाणु रिएक्टर

विभिन्न क्षेत्रों से बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत सरकार कार्बन फुटप्रिंट पर देश की निर्भरता कम करने के लिए अगले दशक में परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाने की योजना बना रही है। लघु एवं मध्यम स्तर के परमाणु विद्युत संयंत्रों की संभाव्यता का मूल्यांकन करने और उनके लाभों एवं चुनौतियों का आकलन करने की दृष्टि से इस कार्य के लिए समवेत प्रयास की आवश्यकता होगी। सदस्य (विज्ञान और प्रौद्योगिकी), नीति आयोग की अध्यक्षता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्टिकल परियोजना के लिए भावी कार्यनीति विकसित करने के लिए विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए बैठकों का समन्वय कर रहा है। जी20 कैलेंडर के भाग के रूप में, नीति आयोग ने 16 मई 2023 को मुंबई में 'ऊर्जा परिवर्तन में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) की महत्वपूर्ण भूमिका' पर एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार की मेजबानी की। उपर्युक्त कार्यक्रमों में एसएमआर का विकास और परिणियोजन, डिजाइन, मानकीकरण, मॉड्यूलरीकरण के लिए वैश्विक स्थिति एवं उभरते अवसरों पर विचार-विमर्श किया गया और साथ ही नीति विनियमन तथा सुरक्षा उपायों के साथ-साथ चुनौतियों और सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी ध्यानाकृष्ट किया गया।

## भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की निगरानी

नीति आयोग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से वर्टिकल समवय आरएंडडी डैशबोर्ड नामक एक व्यापक डैशबोर्ड के विकास और रोल-आउट पर काम कर रहा है। यह डैशबोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में चल रही सभी अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) संबंधी परियोजनाओं की निगरानी के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करेगा।

इसके अतिरिक्त, वर्टिकल ने पूरे भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू की गई अनुसंधान एवं विकास संबंधी परियोजनाओं की निगरानी के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए इस डैशबोर्ड का उपयोग करने की योजना बनाई है। यह विस्तार इन परियोजनाओं के प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) और व्यावसायीकरण तत्परता स्तर (सीआरएल) दोनों को बढ़ावा देने और बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## उद्योग और शिक्षा जगत के साथ वचनबंध

वर्टिकल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने, ज्ञान साझा करने और अनुसंधान और नवाचार के अवसरों का पता लगाने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के साथ विभिन्न बैठकों/बातचीत का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य तकनीकी प्रगति और इस क्षेत्र में प्रगति को आगे बढ़ाना है। उनमें से कुछ पर निम्नानुसार प्रकाश डाला गया है :

1. अत्यधिक ठंडे मौसम के कारण चुनौतियों पर काबू पाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए उपयुक्त तकनीकी समाधान।
2. सोलर सेल के बड़े पैमाने पर विकास को गति देने के लिए फोटोवोल्टिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य।
3. एंजाइमैटिक कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) और भारत में इसकी क्षमता।
4. ऊर्जा संबंधी मामलों में नीति आयोग के ज्ञान साझेदार के रूप में एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस, नोएडा की संभावित भूमिका।
5. अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से हाइड्रोजन पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड के साथ विभिन्न प्रौद्योगिकियों और उनकी व्यवहार्यता पर चर्चा।
6. भारत में अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स (एएमसीएचएएम) के सदस्यों के साथ भारत में डेटा सेंटर नीति के लिए सरकार के विजन पर चर्चा, उन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना जो राष्ट्र को डेटा केंद्रों के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने में मदद कर सकती हैं।
7. आरआईएसई कार्यक्रम (भारत-ऑस्ट्रेलिया त्वरक कार्यक्रम) और सीएसआईआरओ के विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (सीएसआईआरओ), ऑस्ट्रेलिया के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्टिकल और अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया जिससे सहयोग के संभावित अवसरों का पता लगाया जा सके।
8. कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकियों और इसे मूल्य वर्धित उत्पादों में परिवर्तित करने के तरीकों पर उद्योगों के साथ चर्चा करने के लिए भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए तकनीकी समिति।

## वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई)

नीति आयोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में भारत की रैंक में सुधार के लिए भारत सरकार का नोडल संगठन है। तदनुसार, जीआईआई पर डेटा/इनपुट को अपडेट करने की प्रगति की निगरानी करने और जीआईआई में भारत की रैंकिंग में सुधार कार्यों का सुझाव देने के लिए नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में नीति आयोग द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति (आईएमसीसी) का गठन किया गया था।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ), जिनेवा द्वारा 27 सितंबर, 2023 को जारी की गई जीआईआई 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत ने अपने संकेतक डेटा 2020 के लिए संदर्भ वर्ष के बावजूद अपनी 40वीं स्थिति (132 अर्थव्यवस्था में) बनाए रखी, जो प्रारंभिक महामारी को चिह्नित करता है। दूसरी ओर, भारत ने न केवल अपना 40वां स्थान बरकरार रखा, अपितु घरेलू बाजार के संकेतक में विश्व स्तर पर शीर्ष रैंक भी हासिल की। भारत निम्न मध्यम आय वर्ग के देशों और मध्य तथा दक्षिणी एशिया क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है। वैश्विक लॉन्च के एक दिन बाद शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को भारत में जीआईआई 2023 का शुभारंभ नीति आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से बहुत सफलतापूर्वक ऑनलाइन आयोजित किया गया।



वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023

## भारत नवाचार सूचकांक

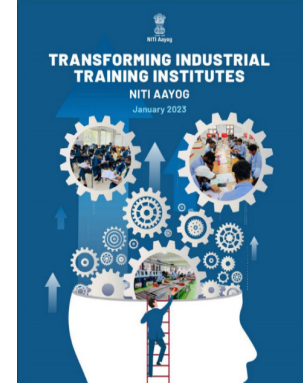
भारत नवाचार सूचकांक देश के नवाचार इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है। यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके नवाचार प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान करता है और उनके बीच मजबूत प्रतिस्पर्धा तैयार करता है। नीति आयोग एक ज्ञान साझेदार के रूप में प्रतिस्पर्धा संस्थान के समन्वय में प्रति वर्ष भारत नवाचार सूचकांक जारी करके अपनी अभिनव क्षमताओं के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग के लिए उत्तरदायी है। नीति आयोग, सहकारी संघवाद के पुनरोत्थान के लिए भारत नवाचार सूचकांक में अपनी रैंकिंग में सुधार करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता भी कर रहा है। राज्य स्तर पर नवाचार प्रदर्शन में विकास और सुधार के परिणामस्वरूप जीआईआई में भी भारत की रैंकिंग में सुधार होगा।

## कौशल विकास और उद्यमिता, श्रम और रोजगार

यह वर्टिकल कौशल विकास, आजीविका और श्रम कल्याण के क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, निजी क्षेत्र तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से नीतिगत पहलों में तेजी लाने के लिए ज्ञान के निर्माण और साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए अधिगम उत्पादों और कार्यनीतियों का निर्माण, भावी कार्य और उभरती कुशल आवश्यकताओं के लिए कार्यबल तैयार करना, महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाना, कुशल श्रमिकों के विदेश प्रवास हेतु अवसर विकसित करना उजागर करना तथा डिजिटल, देखभाल और हरित अर्थव्यवस्थाओं जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए कार्यबल को तैयार करना शामिल है।

## ‘औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का परिवर्तन’ पर नीति रिपोर्ट का विमोचन:

31 जनवरी 2023 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा ‘औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का परिवर्तन’ पर नीति आयोग की रिपोर्ट जारी की गई। अनुसंधान विश्लेषण और हितधारक परामर्श के आधार पर, यह अध्ययन देश में आईटीआई के इकोसिस्टम पुनरुत्थान हेतु परिवर्तनकारी विचारों पर प्रकाश डालता है। यह रिपोर्ट मंत्रालयों, राज्य सरकारों, आईटीआई और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करेगी ताकि वे आईटीआई के लिए गुणवत्ता के प्रति जागरूकता, निष्पादन पर आधारित, डिजिटल रूप से सक्षम और तकनीकी रूप से सशक्त इकोसिस्टम को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर सकें।



31 जनवरी 2023 को ‘ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स’ पर जारी नीति रिपोर्ट

## भारत में गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था:

### क. आईआईटी बॉम्बे में गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर नीति संवाद

‘भारत की उभरती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था’ पर नीति आयोग की रिपोर्ट में दी गई अंतर्दृष्टि और सिफारिशों के आधार पर, एसडीई वर्टिकल ने 25 नवंबर 2022 को मुंबई में सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज, आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर भारत में गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर एक नीति संवाद का आयोजन किया। नीति संवाद के प्रतिभागियों और वक्ताओं में महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और छात्रों सहित क्षेत्र के हितधारकों का एक विविध समूह शामिल था। कार्यक्रम में आकर्षक चर्चाओं और विचार-विमर्श से गिग और प्लेटफॉर्म क्षेत्र में कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण और डेटा प्रशासन पर समृद्ध अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई, जो वर्टिकल के चल रहे कार्य और भावी अनुसंधान कार्यसूची में शामिल होगी।

### ख. आईएसबी मोहाली के सहयोग से गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर संगोष्ठी

25 जनवरी 2023 को आईएसबी मोहाली के सहयोग से ‘भारत में गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था’ पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में ‘भारत की उभरती गिग और मंचीय अर्थव्यवस्था: भावी कार्य के लिए परिप्रेक्ष्य और सिफारिशें’ पर नीति आयोग की रिपोर्ट से उभरती अंतर्दृष्टि और सिफारिशों पर चर्चा की गई। संगोष्ठी के प्रतिभागियों और वक्ताओं में और पंजाब और चंडीगढ़ सरकार के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों, थिंक टैंक प्लेटफॉर्म और छात्रों सहित क्षेत्र के हितधारकों का एक विविध समूह शामिल था। कार्यक्रम में आकर्षक चर्चाओं और विचार-विमर्श से गिग और प्लेटफॉर्म सेक्टर में कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण पर समृद्ध अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई।

### ग. जी20 के रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) में ‘भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा’ पर नीति आयोग की प्रस्तुति

नीति आयोग ने 2 से 4 फरवरी 2023 तक जोधपुर में आयोजित जी20 की रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की पहली बैठक में ‘भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा’ पर प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए विशिष्ट चुनौतियों के साथ-साथ भारत में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए चल रही और नई पहलों और संभावित समाधानों पर प्रकाश डाला गया।

## रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बहु-हितधारक परामर्श:

वर्टिकल 'देखभाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने' की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के साथ सहयोग कर रहा है। वर्टिकल ने मई 2023 को आईएलओ नई दिल्ली के सहयोग से 'भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने' पर नीति आयोग में एक बहु-हितधारक परामर्श का आयोजन किया। परामर्श बैठक की अध्यक्षता अपर सचिव, नीति आयोग और उप निदेशक आईएलओ नई दिल्ली ने संयुक्त रूप से की और इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और नागरिक समाज के संगठनों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। परामर्श में बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए देखभाल सेवाओं का विस्तार और कौशल विकास सहित देखभाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

### कार्य का भविष्य

तकनीकी प्रगति जैसे मेगाट्रेंड के बाद से कार्य का भविष्य चर्चा का एक प्रमुख विषय है; जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण कार्य जगत को प्रभावित कर रहे हैं। 'कार्य का भविष्य' विषय के तहत आयोजित प्रमुख परामर्श/चर्चा का विवरण इस प्रकार है:

#### क. कृषि क्षेत्र में कार्य के भविष्य पर बहु-हितधारक परामर्श

वर्टिकल ने अपर सचिव, नीति आयोग की अध्यक्षता में 28 जून 2023 को कृषि में कार्य के भविष्य पर पहले क्षेत्रीय बहु-हितधारक परामर्श का आयोजन किया। चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि उभरती प्रौद्योगिकियां और जलवायु परिवर्तन कृषि कार्य, उत्पादकता और आजीविका को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इस चर्चा में अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंक, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, क्षेत्र कौशल परिषदों और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया।

#### ख. 'वैश्विक दक्षिण में नई तकनीकें और कार्य का भविष्य' पर सम्मेलन:

वर्टिकल ने 17 से 19 जुलाई 2023 तक आईआईसी, दिल्ली में आयोजित 'वैश्विक दक्षिण में नई तकनीकें और कार्य का भविष्य' विषय पर आयोजित सम्मेलन में मानव विकास संस्थान, डब्ल्यूआईटीएस विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ सहयोग किया। सम्मेलन में नए तकनीकी परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि एआई, उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों, रोबोटाइजेशन और ऑटोमेशन पर चर्चा की गई।



जुलाई 2023 में 'नई प्रौद्योगिकियां और वैश्विक दक्षिण में कार्य का भविष्य' पर सम्मेलन

## ग. शिक्षा प्रौद्योगिकी और कौशल के भविष्य पर गोलमेज चर्चा

8 अगस्त 2023 को संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में शिक्षा प्रौद्योगिकी और कौशल के भविष्य पर एक गोलमेज विशेषज्ञ परामर्श का आयोजन किया गया। परामर्श का उद्देश्य इस संबंध में विशेषज्ञों और हितधारकों के दृष्टिकोण प्राप्त करना था कि शिक्षा प्रौद्योगिकी भविष्य में नौकरियों और कौशल की आवश्यकता को कैसे बदल देगी, और भविष्य के लिए कार्यबल को कुशल बनाने में किस प्रकार के कौशल प्रशिक्षण और श्रम बाजार जुड़ाव (प्रशिक्षुता, कार्यगत प्रशिक्षण आदि) उपयोगी साबित हो रहे हैं। इस परामर्श में प्रैक्टिशनर्स, उद्योग संघ, सेक्टर कौशल परिषदों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और निजी संगठनों ने भाग लिया।

## कुशल श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए मार्गों का विकास करना

वर्टिकल ने कुशल श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए मार्गों का विकास करने के लिए संभावित कार्यनीतियों और पहलों पर चर्चा करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श का आयोजन किया। नीति आयोग ने 16 मार्च 2023 को जापान सरकार द्वारा शुरू किए गए तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम और निर्दिष्ट कुशल श्रमिक कार्यक्रम पर बहु-हितधारक गोलमेज चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सहयोग किया।

## सार्वजनिक नीति में गुणात्मक अनुसंधान की विधियों पर दो-दिवसीय कार्यशाला

नीति आयोग ने 22 और 23 मार्च, 2023 को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) के सहयोग से नीति आयोग में सार्वजनिक नीति में गुणात्मक अनुसंधान की विधियों पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन जी20 'यूनिवर्सिटी कनेक्ट' पहल के हिस्से के रूप में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य नीति पेशेवरों और छात्रों के लिए गुणात्मक अनुसंधान की एक्सपोजर गतिविधि और इस पर बातचीत शुरू करना था कि कैसे यह नीति डिजाइन और मूल्यांकन के लिए प्रेरणा बन सकता है। कार्यशाला व्यावहारिक थी और इसमें ब्रेकआउट समूहों में कार्यशाला की गतिविधियाँ शामिल थीं।

## निष्पादन-परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) समीक्षा बैठकें

इस वर्टिकल ने डीएमईओ के साथ नीति भवन में दिनांक 13.12.2023 को श्रम और रोजगार मंत्रालय की और दिनांक 14.12.2023 को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओओएमएफ समीक्षा बैठक का आयोजन किया जिसमें योजनाओं के निष्पादन और मंत्रालयों की डीजीक्यूआई स्थिति पर चर्चा की गई और कुछ सुझाव दिए गए।

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता

सामाजिक न्याय और अधिकारिता वर्टिकल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग), जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए नोडल डिविजन के रूप में कार्य कर रहा है। वर्टिकल समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी), अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर समूहों जैसे दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों आदि के हितों की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में इनपुट प्रदान करता है। यह वर्टिकल अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना और अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है।

वर्ष 2023-24 के दौरान वर्टिकल द्वारा की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- पीवीटीजी की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने

विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श किया था और तदनुसार पीवीटीजी मिशन स्थापित करने के सुझाव के साथ नीति आयोग द्वारा बजट 2023-24 के लिए इनपुट दिए गए थे और इसे पीवीटीजी विकास मिशन की स्थापना के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित किया गया था। इसके बाद, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया गया था।

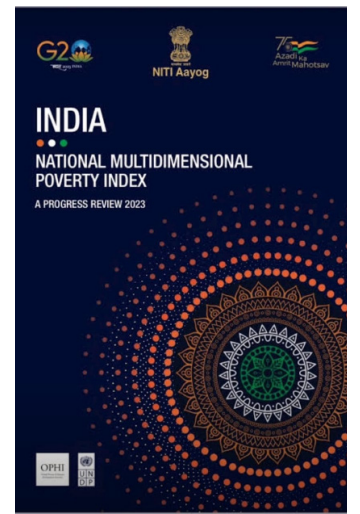
- वटिकल ने नीति आयोग के स्वास्थ्य वटिकल के साथ भी मिलकर काम किया है और 'भारत में वटिष्ठ नागरिक देखभाल सुधार' पर अपनी रिपोर्ट के लिए इनपुट प्रदान किए हैं।
- वटिकल ने भारत में सहायक प्रौद्योगिकी (एटी) की बढ़ती मांग को पूरा करने और भारत को विश्व में एक अग्रणी एटी विनिर्माण केन्द्र के रूप में बढ़ावा देने के तरीकों पर भी एटी उत्पादों/उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों के साथ कई परामर्श किए।
- वटिकल ने विभिन्न समितियों, ईएफसी और एसएफसी बैठकों में भाग लिया है और कमजोर समूहों के समग्र कल्याण के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। वटिकल ने सीसीडीए, ईएफसी, एसएफसी, योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन आदि से संबंधित नोडल मंत्रालयों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की जांच की और संबंधित संरचनात्मक सुझाव भी दिए।

## सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

भारत में, नीति आयोग 2030 एजेंडा के लिए नोडल एजेंसी है और इसलिए, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी प्रयासों के समन्वय तथा पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। इस उद्देश्य से, नीति आयोग ने कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने और राज्यों/जिलों को रैंक करने के लिए एसडीजी भारत सूचकांक, एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक तथा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) जैसे अनुवीक्षण संबंधी उपकरण विकसित किए हैं, जिससे प्रतिस्पर्धी संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। यद्यपि एसडीजी भारत सूचकांक को विविध एसडीजी पर सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य निष्पादन का समग्र मूल्यांकन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जिला स्तर पर लक्ष्य-वार कार्य निष्पादन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। राष्ट्रीय एमपीआई 12 संकेतकों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन आयामों में अतिव्यापी अभावों को निर्धारित करता है। ये सूचकांक निष्पादन-कर्ताओं और परिवर्तनकर्ताओं को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं।

## राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक

भारत सरकार की पहल जिसे सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (जीआईआरजी) के नाम से जाना जाता है, द्वारा निर्देशित, भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एमपीआई की अनुवीक्षण तंत्र और कार्यप्रणाली का उपयोग करना है। ये लक्षित कार्यक्रम संबंधी कार्रवाइयों और सुधारों को शुरू करने के लक्ष्य के साथ, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों कार्य निष्पादनों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात, नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) के साथ मिलकर भारत का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) विकसित किया जो गरीबी पर बहुआयामी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।



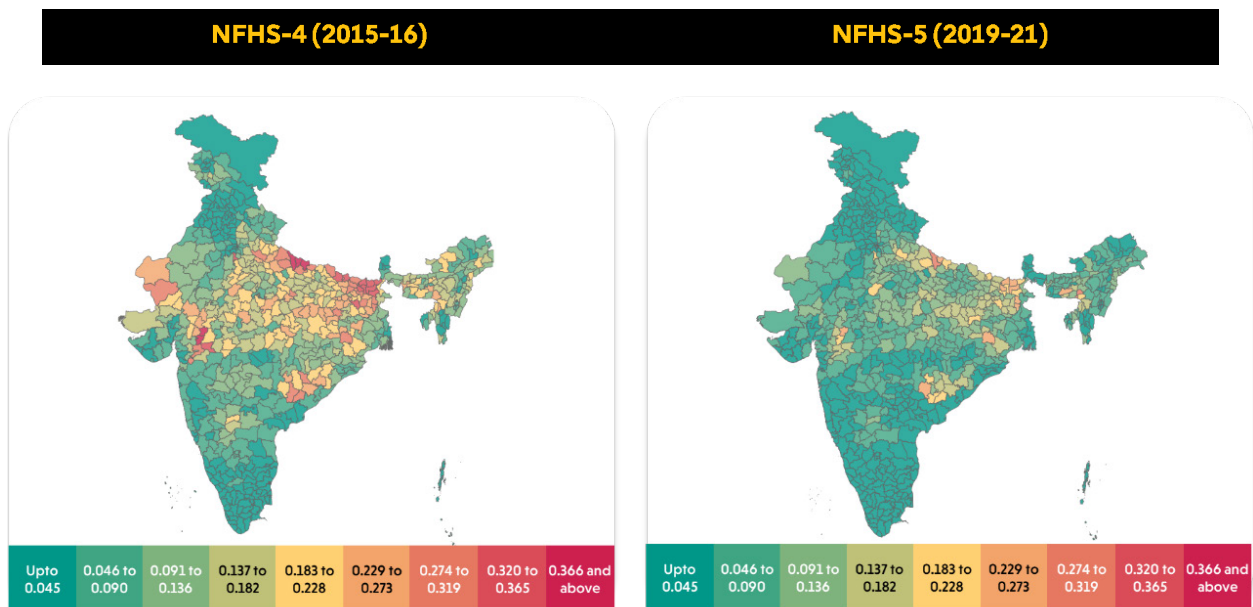
नीति आयोग ने 17 जुलाई, 2023 को एसडीजी वटिकल द्वारा तैयार 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक

प्रगति समीक्षा 2023' शीर्षक से राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एनएफएचएस-4 (2015-16) से एनएफएचएस-5 (2019-21) तक बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाते हुए, यह रिपोर्ट एनएफएचएस-5 पर आधारित बहुआयामी गरीबी की स्थिति पर ध्यान आकृष्ट कराती है। राष्ट्रीय एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से महत्वपूर्ण आयामों में एक साथ अभावों को मापता है जो 12 एसडीजी संरक्षित संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं।

- रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है कि 2015-16 से 2019-21 की अवधि के बीच भारत के बहुआयामी गरीबों का अनुपात 24.85 प्रतिशत से लगभग आधा होकर 14.96 प्रतिशत हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप 5 वर्ष की अवधि के दौरान 13.5 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए।
- यह प्रगति रेखांकित करती है कि भारत एसडीजी लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की राह पर है, जिसका लक्ष्य 2030 तक "राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार सभी आयामों में गरीबी में रहने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को घटाकर कम से कम आधा" करना है।
- उप राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुआयामी गरीबी में लगातार गिरावट देखी गई है। उत्तर प्रदेश ने सबसे महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन किया, 2015-16 से 2019-21 के बीच सबसे अधिक संख्या में लोग (3.43 करोड़) बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए, इसके बाद बिहार के लोग (2.25 करोड़) और मध्यप्रदेश के लोग (1.36 करोड़) मुक्त हुए।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एनएमपीआई) बहुआयामी गरीबी का समाधान करने की दिशा में भारत की उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाता है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की वैश्विक खोज के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर डालता है।

### बहुआयामी गरीबी सूचकांक के स्कोर का तुलनात्मक दृश्य (जिलावार)



उपर्युक्त रंग राज्यों के एम.पी.आई. स्कोर को दर्शाता है। जैसे-जैसे एमपीआई स्कोर बढ़ता है, हरा रंग पीला होते हुए लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। हरा रंग उन क्षेत्रों को दर्शाता है जिनका एमपीआई स्कोर सबसे कम है जबकि लाल अधिकतम एमपीआई स्कोर को दर्शाता है। यह संकेतिका 2015-16 के मूल्य पर आधारित भारत में एमपीआई स्कोर के रेंज को दर्शाती है। ये दोनों तुलनात्मक मानचित्र 2015-16 से 2019-21 के बीच के एमपीआई स्कोर में परिवर्तन को दर्शाने के लिए एक ही संकेतिका का उपयोग करते



हैं। धूसर रंग उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन दोनों एनएफएचएस (2015-16 और 2019-21) के बीच की अवधि के लिए केवल 575 जिलों को तुलना के लिए उपयुक्त पाया गया है। इनमें से, 436 जिले 95% स्तर की विश्वसनीयता के साथ, सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण हैं।

एनएमपीआई के अनुमानों का जिला स्तर पर पृथक्करण मूल्यवान और विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जो गरीबी को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप और सूचित कार्यों को सुगम बना सकता है।



राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट का शुभारंभ

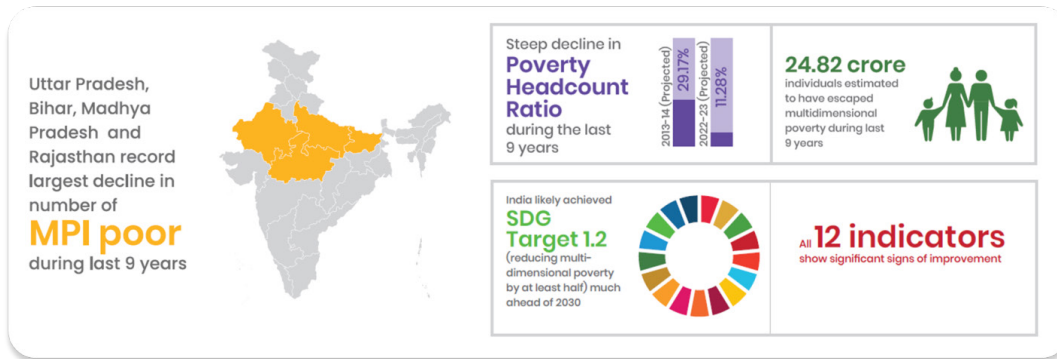
### चर्चापत्र: वर्ष 2005-2006 से भारत में बहुआयामी गरीबी

यूएनडीपी के सहयोग से नीति आयोग ने हाल ही में भारत में वर्ष 2005-06 से बहुआयामी गरीबी पर एक चर्चा पत्र प्रकाशित किया, जो राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट के परिणामों पर आधारित है। यह पत्र विशेष रूप से 2005-06 से 2022-23 तक भारत में बहुआयामी गरीबी की व्यापकता पर ध्यान केंद्रित करता है, जब एनएफएचएस डेटा अनुपलब्ध था, तब एनएफएचएस डेटा और प्रक्षेपण विधियों दोनों का प्रयोग किया गया था।

चर्चापत्र के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी में काफी कमी आई है, जो 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप 9 वर्षों की अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश में एमपीआई गरीब व्यक्तियों की संख्या में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई, पिछले नौ वर्षों में 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।

इसके अतिरिक्त, पत्र में इंगित किया गया है कि बहुआयामी गरीबी की घटनाओं में गिरावट की गति, परिवर्तन की संयोजित वार्षिक दर का उपयोग करके गणना की गई, 2015-16 से 2019-21 के बीच बहुत तेज थी, 2005-06 की तुलना में 10.66 प्रतिशत वार्षिक गिरावट दर के साथ 2015-16 तक 7.69 प्रतिशत वार्षिक गिरावट दर के साथ दर्शायी गई।

परिणामस्वरूप, भारत को 2030 की समयसीमा से बहुत पहले ही बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है। चर्चापत्र सरकार की विभिन्न पहलों को भी रेखांकित करता है जिन्होंने निर्धारित अवधि में इस उपलब्धि को प्राप्त करने में योगदान प्रदान किया है।



भारत में बहुआयामी गरीबी का स्नेपशॉट

## समझौता ज्ञापन - नीति आयोग और यूएनडीपी

नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से प्रगति के प्रति आपसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए एसडीजी स्थानीयकरण, डेटा पर आधारित निगरानी, आकांक्षी जिले और ब्लॉक, आदि सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने के लिए अगस्त, 2023 में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

एमओयू पर पांच साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए। नीति आयोग राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी को अपनाने और निगरानी के समन्वय के लिए नोडल संस्थान है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एसडीजी पर तेजी से प्रगति के प्रयासों के समन्वय में समाकलक की भूमिका निभाता है। नीति आयोग के सीईओ श्री बी वी आर सुब्रमण्यम की उपस्थिति में नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार (एसडीजी) डॉ. योगेश सूरी और यूएनडीपी इंडिया की रेजिडेंट प्रतिनिधि सुश्री शोको नोडा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



नीति आयोग और यूएनडीपी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

## संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) का 78वां एसडीजी शिखर सम्मेलन

18-19 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क में एसडीजी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। महासभा के अध्यक्ष द्वारा बुलाए गए शिखर सम्मेलन ने एजेंडा 2030 और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा के आधे रास्ते को चिन्हित किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने एसडीजी शिखर सम्मेलन

2023 में भाग लिया और एसडीजी को अपनी राष्ट्रीय विकास कार्यनीतियों में एकीकृत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और कार्रवाइयों का आश्वासन देते हुए वक्तव्य दिया और 20 सितंबर, 2023 को 'एसडीजी प्राप्त करने के लिए एकीकृत नीतियों और सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करने' और 'विकास के लिए वित्त पोषण पर लीडर्स डायलॉग में भी भाग लिया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने बहुआयामी गरीबी पर केंद्रित उच्च स्तरीय पार्श्व कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जहां राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वैश्विक अग्रणियों ने अपने अनुभव साझा किए और गरीबी में कमी लाने, नीतिगत कार्यों का मार्गदर्शन करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए एमपीआई की भूमिका पर प्रकाश डाला और कोएलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय परिसर में एक पार्श्व कार्यक्रम और सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग की अध्यक्षता की।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने एसडीजी सूचकांक के डेटा संबंधी मुद्दों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग के निदेशक के अलावा ब्राजील, जर्मनी और यूरोपीय आयोग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।



यूएनजीए एसडीजी सम्मेलन में उपाध्यक्ष नीति आयोग

## जीएसडीपी-नीति परियोजना

हरित और सतत विकास के लिए भारत-जर्मन साझेदारी [जीएसडीपी] को आगे बढ़ाने के लिए, जिसका समर्थन भारत के माननीय प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर द्वारा मई 2022 में भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच छठे अंतःशासकीय परामर्श के दौरान की गई थी। कम से कम 3 राज्यों में एसडीजी केंद्रों की स्थापना के माध्यम से एसडीजी के कार्यान्वयन और स्थानीयकरण के उद्देश्य से नीति आयोग और जीआईजेड इंडिया के बीच एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन केंद्रों को 2024 के दौरान हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

## बोन, जर्मनी में सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रम

भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय समझौते के बाद, जीआईजेड (जर्मनी की संघीय सरकार के तहत एक संगठन) को जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमजेड) द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि में तेजी लाने और पेरिस जलवायु समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 'हरित और सतत

विकास के लिए भारत-जर्मन साझेदारी के समर्थन (जीएसडीपी) को लागू करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस परियोजना के तहत, जीआईजेड इंडिया और नीति आयोग कम से कम तीन राज्यों में राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर योजना, निगरानी और बजट के संदर्भ में एसडीजी के कार्यान्वयन और स्थानीयकरण की सुसंगतता को मजबूत करने के लिए सहयोग कर रहे हैं।

इस संदर्भ में, नीति आयोग ने 8-9 नवंबर, 2023 के दौरान बोन, जर्मनी में एसडीजी के संबंध में जीआईजेड द्वारा आयोजित बैठकों की एक श्रृंखला में भाग लिया। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भारत की कार्यनीतियों को साझा करने के लिए 'गंतव्य 2030: एजेंडा 2030 के लिए उत्प्रेरक कार्रवाई' पर गोलमेज बैठक के लिए एक प्रमुख रूप से पैनल का सदस्य भी था। यह दौरा जीआईजेड द्वारा नीति आयोग, बीएमजेड, जीआईजेड और जर्मनी के अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच दोनों देशों में एजेंडा 2030 के कार्यान्वयन और विकास सहयोग की भूमिका के संबंध में अनुभवों, सीख और सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञान के आदान-प्रदान की सुगमता के लिए आयोजित की गई थी।

## मानव विकास की बढ़ोत्तरी के लिए एक नीति उपकरण के रूप में 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' पर पैनल चर्चा

मानव विकास की बढ़ोत्तरी हेतु एनएमपीआई का लाभ उठाने के तरीकों को चिन्हित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यूएनडीपी और नीति आयोग ने संयुक्त रूप से 12 जनवरी 2024 को आईएचडी के ग्लोबल कॉन्क्लेव 2024 में एक पैनल चर्चा आयोजित की। नीति आयोग ने भारत के एनएमपीआई का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करते हुए चर्चा शुरू की और एनएमपीआई रिपोर्ट के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिससे भारत में मानव विकास के लिए नीति और योजना प्रक्रियाओं को आकार देने में एनएमपीआई की क्षमता से संबंधित विस्तृत चर्चा के लिए मंच तैयार हुआ। इसमें यूएनडीपी, यूएन महिला, हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा नेपाल के योजना आयोग के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया एवं अलग-अलग डेटा संग्रह तथा अनुवीक्षण, सांस्कृतिक विचारों, लैंगिक समानता और बुनियादी जरूरतों से परे गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता पर विचार करते हुए लक्षित अंतःक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया। मानव विकास की उन्नति उद्देश्य से नीति और नियोजन प्रक्रियाओं के लिए एमपीआई का लाभ उठाने की सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा किया गया।

## 'बहुआयामी गरीबी और कल्याण संबंधी डेटा की उपलब्धता और उपयोग में सुधार' पर विशेषज्ञ कार्यशाला

ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 'बहुआयामी गरीबी और कल्याण संबंधी डेटा की उपलब्धता और उपयोग में सुधार' पर एक उच्च प्रभावशाली विशेषज्ञ कार्यशाला आयोजित की, जो घरेलू सर्वेक्षण से बहुआयामी गरीबी और कल्याण से संबंधित डेटा के संकलन और उपलब्धता में सुधार लाने पर केंद्रित थी। यह कार्यशाला 7-9 फरवरी 2024 के दौरान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूके में आयोजित की गई और इसमें बहुआयामी गरीबी माप और घरेलू सर्वेक्षण डेटा के क्षेत्र में दुनिया भर से विशेषज्ञों और प्रवर्तकों को एकजुट कराया गया। वक्ताओं में राष्ट्रीय सरकारों, विश्व बैंक, अन्य संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और जनसांख्यिकी स्वास्थ्य सर्वेक्षण (डीएचएस), मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे (एमआईसीएस) जैसे प्रमुख घरेलू सर्वेक्षण प्रदाताओं के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यशाला ने एसडीजी प्राप्त करने हेतु बहुआयामी गरीबी माप और कार्यनीतियों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया। कार्यशाला में, नीति आयोग ने ओपीएचआई द्वारा प्रस्तुत "बहुआयामी गरीबी से संबंधित डेटा के भविष्य को सुरक्षित करना और वास्तव में वैश्विक उपाय" पर एक सत्र का संचालन किया और "एमपीआई को कम करने में भारत की प्रगति" पर एक मुख्य भाषण भी प्रस्तुत किया।

## सतत विकास लक्ष्यों के लिए 11वां एशिया प्रशांत फोरम (एपीएफएसडी) 2024

नीति आयोग ने 19-22 फरवरी 2024 तक बैंकॉक में सतत विकास के लिए '11वें एशिया प्रशांत फोरम (एपीएफएसडी) 2024 में भाग लिया। इस क्षेत्रीय मंच का उद्देश्य क्षेत्रीय रुझानों की पहचान करके और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के प्रयासों में एशिया- प्रशांत देशों को सूचित करना, सशक्त बनाना और समर्थन करना है। 11वें एपीएफएसडी बैंकॉक, थाईलैंड के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केंद्र (यूएनसीसी) में "सतत विकास के लिए 2030 कार्यसूची को सुदृढ़ करना और कई संकटों के समय में गरीबी उन्मूलन: एशिया और प्रशांत में सतत, लचीले और अभिनव समाधानों की प्रभावी वितरण" विषय के तहत आयोजन किया गया था।

सम्मेलन में, नीति आयोग ने प्री- इवेंट: 'बदलती दुनिया में सामाजिक सुरक्षा पर नए मोर्चे' में 'मुख्य भूमिका निभाने वाली महिलाओं के द्वारा विकास और गरीबी उन्मूलन पर सामाजिक सुरक्षा के प्रभाव के साथ- साथ बहुआयामी गरीबी से मुक्त होने के लिए भारत की कार्यनीतियों' पर भारत की प्रमुख पहलों को प्रस्तुत किया और 'एशिया- प्रशांत (एलएनओबी) बैठक' में भाग लिया और बहुआयामी गरीबी से मुक्त होने के लिए और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत की समावेशी और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण कार्यनीतियों पर प्रकाश डाला।



एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश के प्रतिनिधियों की स्मारक तस्वीर

## पर्यटन और संस्कृति

पर्यटन प्रभाग पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कार्यात्मक और दिशात्मक मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रभाग विशिष्ट पर्यटन, इको पर्यटन और निरोगता पर्यटन, अवसंरचना विकास, क्षमता विकास और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन नीतियों के विकास के माध्यम से भारत को पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करना चाहता है। संस्कृति प्रभाग भारत की कला, संस्कृति और विरासत को विकसित, संरक्षित और बढ़ावा देना चाहता है।

## शहरीकरण

शहरीकरण प्रभाग प्रबंधनीय, आर्थिक रूप से उत्पादक, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त और न्यायसंगत शहरीकरण पर डेटा-आधारित नीतिगत विश्लेषण प्रदान करता है। यह शहरी नियोजन, विकास और प्रबंधन में शामिल प्रमुख हितधारकों को सलाह और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह प्रभाग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय सरकारों के साथ नीतियां, कार्यक्रम, पहल और सुधार तैयार करने में कार्यरत है। यह शहरीकरण के प्रबंधन के लिए नीतिगत दृष्टिकोण पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने की दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, विकास भागीदारों और प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ भी सहयोग करता है।

### शहरी स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन सुधार:

पंद्रहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रारंभिक स्तर की शर्त के रूप में लेखा परीक्षित वार्षिक खातों को जारी करने की सिफारिश की है, जिससे इस महत्वपूर्ण सुधार की तात्कालिकता की भावना पैदा हुई है। भारत में अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय अभी भी नकदी-आधारित लेखांकन प्रणाली का पालन करते हैं। नकदी आधारित से संचय आधारित लेखांकन प्रणालियों में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए, जिसका ऑडिट भी किया जा सकता है, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और एआरएफ (अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन) के साथ मिलकर एक बेहतरीन अभ्यास पुस्तिका तैयार की है। इस रिपोर्ट से शहर की सरकारों को लेखापरिष्कृत वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशित करने के अंतिम उद्देश्य की दिशा में उनके लेखांकन सुधार प्रयासों की संरचना के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करने की आशा है।

### पहाड़ी क्षेत्रों के लिए योजना और वास्तुकलात्मक रूपरेखा:

पहाड़ी क्षेत्र में शहरीकरण के अपने विशिष्ट मुद्दे हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शहरीकरण की अनुमानित प्रवृत्ति को देखते हुए और क्षमता आधारित शहरी नियोजन, बेतरतीब निर्माण, कमजोर स्थलाकृति और संवेदनशील वातावरण जैसी कई चुनौतियों का समाधान करना; नीति आयोग द्वारा 'पहाड़ी क्षेत्रों के लिए योजना और वास्तुकलात्मक रूपरेखा' तैयार करने के लिए बहु-विषयक विशेषज्ञों के एक समूह के साथ एक 'विशेषज्ञों की समिति' का गठन किया गया था। रिपोर्ट में स्विस डेवलपमेंट कोऑपरेशन का योगदान था जिसमें पहाड़ी शहरों (हिल टाउन) की स्थानिक योजना को मजबूत करने के लिए विशिष्ट कार्यनीतियों का विवरण दिया गया था।

अंतिम रिपोर्ट में पहाड़ी क्षेत्रों में सतत शहरी विकास और पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में शहरी और ग्रामीण नियोजन प्रणाली को मजबूत करने की सिफारिशें हैं।

### उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम:

शहरी क्षेत्रों में रहने की स्थिति में सुधार के लिए शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर डाटा गवर्नेंस मॉडल को अपनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक आकांक्षी शहर कार्यक्रम रूपरेखा विकसित की गई। रूपरेखा में 100 कम विकसित शहरों की पहचान करने और बाद में वांछित मापदंडों पर इन शहरों के आगे की ओर बढ़ने के लिए समय-समय पर उनकी निगरानी करने के लिए केपीआई शामिल हैं। प्रस्तावित रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए, 20 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बजट सत्र में 'आकांक्षी शहर कार्यक्रम' योजना की घोषणा की गई है।

## आर्थिक विकास के इंजन के रूप में शहर

माननीय प्रधानमंत्री ने 1 मार्च 2023 को बजट के बाद वेबिनार के दौरान स्पष्ट किया कि अमृत काल में शहरी नियोजन हमारे शहरों के भाग्य का निर्धारण करेगा और ये सुनियोजित शहर ही हैं जो भारत के भाग्य का निर्धारण करेंगे। भारत, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है, जो कुल वैश्विक शहरी आबादी का 11% हिस्सा है, जिसमें लगभग 31% भारतीय शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जो वर्ष 2036 तक लगभग 40% और वर्ष 2050 तक 50% होने का अनुमान है। वर्ष 2011 की स्थिति के अनुसार, शहरी क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 63% योगदान होने का अनुमान है, जो वर्ष 2040 तक बढ़कर 75% होने का अनुमान है।

शहरी केंद्र कुशल श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी जैसे संसाधनों को केंद्रित करके, निवेश आकर्षित करने, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और नवाचार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास के लिए शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। न्यूयॉर्क, लंदन और कई अन्य वैश्विक शहर अपने सकल घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। हालाँकि, भारतीय शहर अभी भी आर्थिक विकास और आजीविका पर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में बहुत पीछे हैं। भारत में मौजूदा योजना और नीति-निर्माण तंत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्यों द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास गतिविधियाँ व्यवस्थित की जाती हैं और कई राज्य-स्तरीय विभागों में बिखरी हुई हैं। शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) बड़े पैमाने पर शहर की सेवाओं के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि शहरी विकास प्राधिकरण भूमि विकास और शहर के विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। दृष्टिकोण प्रतिक्रियाशील रहता है। इसके अतिरिक्त, शहरों के लिए एक एकीकृत आर्थिक दृष्टि रोडमैप तैयार करने की न तो प्रथा है और न ही वैधानिक अधिदेश। आर्थिक दृष्टि के अभाव में, यूडीए/टीपीडी द्वारा तैयार किए गए प्रमुख योजना मुख्य रूप से एक नियामक कार्य के रूप में कार्य करते हैं, न कि विकासात्मक दृष्टि के रूप में। इस मौन दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप समग्र विकास परिप्रेक्ष्य और योजना के एकीकरण की कमी होती है। इसके अतिरिक्त, शहरों की भौतिक योजना भी यूएलबी और विकास प्राधिकरणों की सीमाओं तक ही सीमित है, जो प्रशासनिक सीमाओं से परे फैले जलग्रहण क्षेत्रों में समूहन अर्थव्यवस्थाओं की उपेक्षा करती है।

कार्यनीतिक, बहु-क्षेत्रीय प्रादेशिक आर्थिक मुख्य योजना के अभाव में, भारतीय शहर बिना किसी पूर्व नियोजित आर्थिक दिशा के संघटित रूप से बढ़ रहे हैं। इससे विभिन्न मोर्चों पर शहरों का कार्य-निष्पादन महत्वपूर्ण हो रहा है।

## नीति आयोग की शहरी-क्षेत्रीय विकास केन्द्र (ग्रोथ हब) (जी-हब) पहल

शहर अपनी नगरपालिका सीमाओं से परे संघटित रूप से अथवा अव्यवस्थित ढंग से बढ़ रहे हैं। समूहीकृत अर्थव्यवस्थाओं के लाभ लेने के लिए, उनके आर्थिक विकास को विकास संचालकों की ओर लक्षित करने और व्यापक तरीके से संरचित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार भारत की विकास योजना प्रथाओं में एक अधिक समग्र दृष्टिकोण की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव अपेक्षित है जो शहरी केंद्रों और व्यापक भौगोलिक संदर्भ में उनके आसपास के क्षेत्र के आर्थिक संबंधों की जाँच करता है। यह दृष्टिकोण विभिन्न सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है, जिसमें संतुलित विकास प्राप्त करना, बुनियादी ढांचे, रोजगार और संसाधन तक पहुंच में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, भूमि और प्राकृतिक संसाधन उपयोग अनुकूलन, और बेहतर नियोजित बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना शामिल है।

तदनुसार, नीति आयोग द्वारा एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने, राष्ट्र के लिए मेगा-विकास केंद्रों के रूप में शहरों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में एक प्रायोगिक 'शहरी-क्षेत्रीय विकास केन्द्र ग्रोथ हब पहल' शुरू की गई है। यह पहल स्थानिक योजना के साथ राज्य और शहरी सरकारों द्वारा नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। प्राथमिक उद्देश्य शहर-क्षेत्रों को राष्ट्र के लिए मेगा-विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना, संरचित तरीके से फोकस क्षेत्रों

में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना और समग्र क्षेत्रीय समृद्धि के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने के लिए नीति आयोग द्वारा अधिकारियों और विशेषज्ञों की समर्पित समूहों को राज्य में तैनात किया गया था।

जी- हब पहल समावेशी विकास योजना और कार्यान्वयन के लिए एक अभिनव और अग्रणी बॉटम- अप दृष्टिकोण अपनाती है। चरण 1 में, नीति आयोग ज्ञान साझेदार आईएसईजी फाउंडेशन और डब्ल्यूआरआई इंडिया के साथ मार्ग-दर्शकों के रूप में 4 शहर- क्षेत्रों के लिए आर्थिक मुख्य योजना विकसित कर रहा है। चयनित पायलट क्षेत्र देश भर में भौगोलिक रूप से फैले विभिन्न आर्थिक आकार (मेगा, बड़े और मध्यम आकार के शहर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रारंभिक चरण का उद्देश्य प्रक्रिया टेम्पलेट विकसित करना था।

शहरी क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

- मेगा- मुंबई महानगर क्षेत्र (महाराष्ट्र), जिसमें 5 जिले शामिल हैं
- बड़ा - सूरत- जिसमें 6 जिले (गुजरात) शामिल हैं,
- बड़ा - विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) - जिसमें 8 जिले शामिल हैं
- मध्यम आकार - वाराणसी (उत्तर प्रदेश) - जिसमें 6 जिले शामिल हैं

चरण 2 में भावी राह के रूप में, प्रारंभिक चरण से टेम्पलेट को लागू करने और अध्ययन करने हेतु देश में 16-20 से अधिक शहरी- क्षेत्रों को चिन्हित करना प्रस्तावित है।

### आर्थिक मास्टर प्लान की तैयारी:

आर्थिक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 5-चरणों की प्रक्रिया अपनाई जाती है। योजनाएँ क्षेत्र- विशिष्ट की हैं और इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के लिए समान प्रक्रिया टेम्पलेट का पालन करते हुए भी अंतिम रूपरेखा भिन्न हो सकती है।

#### चरण 1: अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे एवं स्थिरता निदान के लिए जैसा है वैसा दस्तावेज़ तैयार करना।

- क्षेत्र का चित्रण
- भूमि सुरक्षा और भूमि उपयोग के लिए आधार मानचित्र तैयार करना -
- आर्थिक संकेतकों की रिपोर्टिंग:
  - » वर्तमान, क्षेत्रीय और जिला- स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद
  - » सकल घरेलू उत्पाद प्रति वर्ग किमी. / प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद / ऐतिहासिक विकास दर
  - » वैश्विक व्यापार और निर्यात उन्मुखीकरण
  - » रोज़गार; संसाधन
  - » सरकारी नीतियां
  - » उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र
- कार्यनीतिक अवसंरचना को चिन्हित करना
  - » मौजूदा अवसंरचना
  - » अवसंरचना के विकास के लिए अपेक्षित विश्लेषण
- जीवन की गुणवत्ता मापना



- सामाजिक विकास
  - » जनसांख्यिकीय विभाजन
  - » सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व
- कार्यान्वयन योग्य शहर आपदा प्रबंधन योजना
- जलवायु परिवर्तन और स्थिरता:
  - » नेट ज़ीरो बेंचमार्किंग - नवीकरणीय ईवी, ऊर्जा कुशल भवन आदि।
- शासन की गुणवत्ता

### चरण 2: टॉप-डाउन आर्थिक, स्थिरता और भौतिक बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण की बेंचमार्किंग।

- वर्ष 2035 और वर्ष 2047 के लिए अनुमानित जीडीपी गणना
- चरण 1 और हितधारक परामर्श के आधार पर टॉप- डाउन आर्थिक, स्थिरता और भौतिक बुनियादी ढांचे की विज़न तैयार करना
- आकांक्षाएं और आर्थिक बेंचमार्किंग निर्धारित करना (उदाहरण के लिए शहर में झुग्गी-झोपड़ियाँ न हों संबंधी दृष्टिकोण)
- आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक टॉप- डाउन क्षेत्रीय निवेश का विश्लेषण करना

### चरण 3: शहर का एसडब्ल्यूओटी और वृत्ति विश्लेषण

- पिछले आर्थिक संचालकों, वर्तमान चैंपियन क्षेत्रों, डेल्टा विकास, संभावित विकासशील / नए क्षेत्रों को चिन्हित करना
- शहर की वृत्ति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ 10 विकास संचालकों को चिन्हित करना

### चरण 4: शहरी क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ 5-7 या इससे अधिक आर्थिक विकास संचालकों की सूची बनाना

- वित्तपोषण, अवसंरचना और कनेक्टिविटी, कुशल श्रमिक बल की उपलब्धता और निवेश संचालकों के लिए अपेक्षित विश्लेषण के साथ सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय विकास संचालकों का विवरण। ऐसे विकास संचालकों के कुछ उदाहरणों में बंदरगाह शहर, पर्यटन केंद्र, एयरोसिटी हब, स्वास्थ्य सेवा केंद्र शामिल हो सकते हैं
- निवेश योग्य परियोजनाओं और प्रमुख केपीआई को चिन्हित करना और निवेश पर रिटर्न का विवरण प्रस्तुत करना

### चरण 5: कार्यान्वयन ढांचा

- आवश्यक संगठनात्मक और वित्तीय अनलॉक तथा लघु- सूचीबद्ध विकास संचालकों के लिए माइलस्टोन योजना
- चिन्हित शहरों और परियोजनाओं के लिए ऋण घटक (बहु- पक्षीय, नगर निगम बांड आदि) के वित्तपोषण हेतु योजनाओं की तैयारी
- आर्थिक दृष्टि के लिए लीडरशिप और प्रशासनिक संरचना

## जी-हब पहल - सहकारी संघवाद पर एक केस अध्ययन

इस दृष्टिकोण की सफलता की कुंजी एक मजबूत संस्थागत रूपरेखा विकसित करना है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ज्ञान साझेदार और निजी क्षेत्र की स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हों।

**राष्ट्रीय स्तर:**

- नीति आयोग राज्य सरकार के साथ मिलकर इस पहल का संचालन और समर्थन कर रहा है। नीति आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है।
- आईएसईजी फाउंडेशन और डब्ल्यूआरआई इंडिया को ज्ञान साझेदार के रूप में चिन्हित किया गया, जो इस पहल को आधार प्रदान करने के लिए अपेक्षित व्यावसायिक समर्थन देने हेतु नीति आयोग के साथ काम कर रहे हैं।

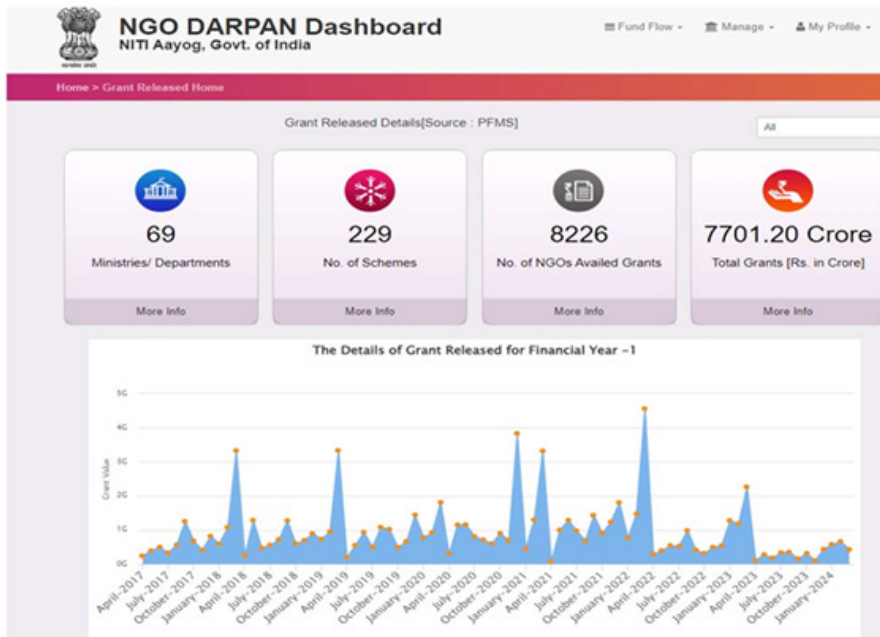
**राज्य स्तर: 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक के प्रारंभ में निम्नलिखित संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया।**

- सभी 4 राज्यों में संबंधित विभागों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया है।
- परिचालन मामलों के समाधान हेतु संबंधित संस्थाओं के समर्पित अधिकारियों के साथ शहर- क्षेत्र स्तर पर जी- हब कैंक इकाई का गठन किया गया।
- व्यापक समझ, समन्वय एवं परामर्श हेतु शहरों में 3-4 पूर्णकालिक कार्मिकों की नियुक्ति की गई।
- समग्र समन्वय स्थापित करने के लिए एक नोडल अधिकारी (सचिव अथवा समान रैंक के अधिकारी) को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

उपर्युक्त दृष्टिकोण से आर्थिक मास्टर प्लानों के विकास की अनुमति मिली, जिसकी प्रक्रिया को जारी रखते हुए संबंधित राज्य सरकारों के साथ सभी हितधारकों द्वारा सामूहिक रूप से जांच, विचार- विमर्श और सिफारिश की गई है।

## स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ

स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ एनजीओ दर्पण पोर्टल के माध्यम से गैर- लाभकारी संगठनों (एनपीओ) के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और व्यापार करने की सहायता को बढ़ावा देना है। 26.03.2024 की स्थिति के अनुसार, एनजीओ- दर्पण पोर्टल पर लगभग 2.06 लाख एनजीओ/ वीओ ने पंजीकरण कराया है।



## जल और भूमि संसाधन

यह वर्टिकल राष्ट्र के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल और भूमि संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। यह उन्नत और उपयोग के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों की क्षमता का दोहन करने के लिए नीति निर्देश तैयार करता है और परामर्श प्रदान करता है एवं जल और भूमि संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। इस वर्टिकल का उद्देश्य इन दो महत्वपूर्ण संसाधनों तक आसानी से पहुंच को सक्षम करके सभी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, और सभी हितधारक संगठनों को सतत विकास में बाधा डाले बिना सेवा प्रदायगी के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। जल और भूमि संसाधन क्षेत्रों के लिए नीति अनुशासनों को तैयार करने में वर्टिकल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्यों के साथ विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है, सरकार को एक कार्यनीतिक योजना परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, और चल रही बातचीत और चर्चाओं के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करता है। वर्टिकल में विभिन्न जल क्षेत्र एवं भूमि संसाधन योजनाओं/कार्यक्रमों/नीतियों का मूल्यांकन भी किया जाता है।



वर्ष 2023-24 में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

### क. जल संसाधन क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों का संग्रह संबंधी प्रकाशन

विभिन्न सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों आदि द्वारा कई अंगीकृत और सफल सर्वोत्तम पद्धतियां हैं। वर्टिकल ने कृषि, भूजल, जल-संभर, जल अवसंरचना और जलवायु जोखिम और अनुकूलन को कवर करने वाली चयनित सर्वोत्तम पद्धतियों 3.0 का विश्लेषण और दस्तावेजीकरण किया है, जिसे पूरे देश में अपनाया जा सकता है। जल प्रबंधन 3.0 में सर्वोत्तम पद्धतियों का सार संग्रह जुलाई, 2023 में प्रकाशित हुआ था।

### ख. जल तटस्थता, जल सकारात्मकता और जल नकारात्मकता के मूल्यांकन के लिए मानक और दिशानिर्देश तैयार करना

जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण, दक्षता में सुधार, अपशिष्ट जल शोधन, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण सर्वोपरि है। चूंकि अधिक से अधिक उद्योग पानी के चक्रीय उपयोग को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जल तटस्थता और जल सकारात्मकता को परिभाषित करने और उसका आकलन करने के लिए स्पष्ट मानकों और पद्धति की आवश्यकता है। नीति आयोग ने जल तटस्थता के मूल्यांकन के लिए मानकों और दिशानिर्देशों का प्रस्ताव देने के लिए सदस्य के रूप में संबंधित विभागों के सचिवों के साथ प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया है। इसके आधार पर वर्टिकल ने जुलाई 2023 में जल तटस्थता - उद्योग के लिए परिभाषा और दृष्टिकोण के मानकीकरण पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उद्योग के लिए जल की स्थिति पर मौजूदा परिभाषाओं और रूपरेखाओं का मानकीकरण शामिल है, जो जल के प्रयोग की स्थिति के मूल्यांकन के लिए बेहतर समझ और मजबूत रूपरेखा प्रदान कर सकता है।

### ग. भारत में शहरी/परिनगरीय कृषि में शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग पर कार्यनीतिक पत्र की तैयारी

इस दस्तावेज में शहरी/परिनगरीय कृषि में शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की गुंजाइश, इसकी चुनौतियों और भविष्य की कार्यनीति पर प्रकाश डाला गया है। जैसे-जैसे शहरी केंद्र शहरीकरण की तेज गति को समायोजित करने के लिए विकसित हो रहे हैं, शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की संभावना बढ़ती जा रही है। इसके अलावा, शोधित अपशिष्ट जल में मौजूद नाइट्रोजन और फास्फोरस इसे कृषि के लिए उपयोग करते समय कच्चे ताजे पानी की तुलना में लाभ की स्थिति में पहुंचाता है। यह देखकर खुशी है कि कई राज्य शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए विशिष्ट नीति के साथ आगे आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस प्रकाशन से चल रहे प्रयासों को मजबूती मिलेगी और इच्छुक हितधारकों को इस मूल्यवान संसाधन का प्रभावी पुनःप्रयोग करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

### मूल्यांकन

वर्ष 2023-24 में वर्टिकल ने जल क्षेत्रों से संबंधित वर्ष के दौरान चार कैबिनेट नोट, तीन सार्वजनिक निवेश बोर्ड जापनों का मूल्यांकन किया।

## महिला और बाल विकास

महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) प्रभाग महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं तथा बाल पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। प्रभाग महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचे और पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है और उनकी प्रगति और उनकी प्रभावकारिता की निगरानी करता है। यह प्रमुख हितधारकों और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय थिंक टैंक, शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों को सलाह प्रदान करता है और उनके बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। प्रभाग पोषण पर एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र का भी रखरखाव करता है।

### रक्ताल्पता से निपटने के लिए कार्य योजना का विकास

चूंकि एनएफएचएस सर्वेक्षण के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे, किशोर और महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, इसलिए रक्ताल्पता देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। भारत सरकार ने रक्ताल्पता से निपटने के लिए एक सार्वभौमिक रणनीति के रूप में 2018 में रक्ताल्पता मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम शुरू किया। हालांकि, पिछले 50 वर्षों में इन प्रयासों के बावजूद, भारत में रक्ताल्पता के प्रसार में कमी प्रति वर्ष 1 प्रतिशत से कम रही है। नीति आयोग ने अनुसंधान में संभावित अंतराल और एएमबी कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों को समझने के लिए एक पहल शुरू की है।

कार्यक्रम संबंधी कमियों पर विचार-विमर्श करने के लिए 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ राष्ट्रीय परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित की गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति, रक्ताल्पता से संबंधित हस्तक्षेपों की कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों और इन हस्तक्षेपों को बढ़ाने के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया।

आईएनसीएलईएन ट्रस्ट द्वारा 15 राज्यों में एएमबी के 6X6X6 हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन का राष्ट्रीय स्तर पर त्वरित मूल्यांकन किया गया। नीति आयोग ने भी आईसीएमआर के साथ एएमबी के छह अंतःक्षेपों में से प्रत्येक के प्रभाव पर विचार-विमर्श करने के लिए कई दौर की वैज्ञानिक समीक्षा बैठकें कीं और प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान की गई।

चिन्हित शोध अंतरालों के आधार पर विचार-मंथन के लिए एनसीईआर-ए, एम्स, नई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यूनिसेफ, आईएफपीआरआई के विशेषज्ञों और एनीमिया पर भारत के विभिन्न संस्थानों के स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ विशेषज्ञ समूह की बैठकें आयोजित की गईं।

### प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल और शिक्षा (ईसीडीसीडी)

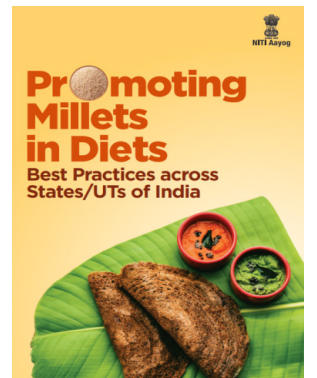
जीवन के पहले छह वर्ष अवसर की एक अनूठी अवधि है जब जीवन भर इष्टतम स्वास्थ्य और विकास की नींव स्थापित की जाती है। यह जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भाग है जब न्यूरोनल कनेक्शन बनाए और संवारे जाते हैं।

बच्चों के उच्चतम संभव प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास, देखभाल और शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के विचार के साथ, नीति आयोग ने वैश्विक ईसीडी मॉडल सहित साहित्य की गहन इन-डेस्क समीक्षा की और विशेष रूप से 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए ईसीडी पहल को समझने के लिए कई परामर्शों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, शिक्षाविदों अन्य विशेषज्ञों से परामर्श किया।

इन परामर्शों से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर नीति आयोग में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल और शिक्षा (ईसीडीसीडी) पर एक मिशन की संकल्पना की गई है।

### आहार में श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम पद्धतियों पर संग्रह

अप्रैल, 2023 में आहार में श्रीअन्न को बढ़ावा देना: भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम पद्धतियां शीर्षक से सर्वोत्तम पद्धतियों का एक संग्रह लॉन्च किया गया। यह रिपोर्ट राज्य सरकारों और संगठनों द्वारा श्रीअन्न मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से उत्पादन, प्रसंस्करण और खपत में अपनाई गई अच्छी और नवीन प्रथाओं का एक सेट प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट तीन विषयों में विभाजित है अर्थात् (क) श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्य मिशन और पहल; (ख) आईसीडीएस में श्रीअन्न को शामिल करना; (ग) नवीन पद्धतियों के लिए अनुसंधान और विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग। यह रिपोर्ट आहार में मिलेट को फिर से शामिल करने और मुख्यधारा में लाने के लिए मार्गदर्शक संग्रह के रूप में काम करेगी।



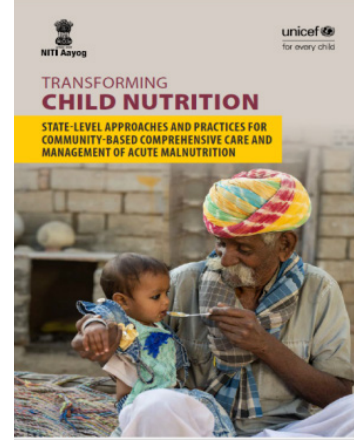
### आरसीएच - पोषण ट्रैकर एकीकरण

नीति आयोग आरसीएच और पोषण ट्रैकर को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए महिला एवं बाल विकास

मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एनएचए के बीच समन्वय स्थापित कर रहा है। एकीकरण की प्रगति के अनुवीक्षण के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग और एनईजीडी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गई हैं।

## गंभीर कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन

नीति आयोग ने दिसंबर 2023 में “बाल पोषण में बदलाव: गंभीर कुपोषण के समुदाय आधारित व्यापक देखभाल और प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय दृष्टिकोण और प्रथाएं” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट गंभीर कुपोषण के समुदाय आधारित प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है। इसकी शुरुआत समय पर विकास निगरानी और हस्तक्षेप के महत्व पर जोर देते हुए सामुदायिक संचेतना और जागरूकता के साथ होती है। पोषण, चिकित्सा प्रबंधन और शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को रेखांकित किया गया है, जिसमें फ्रंटलाइन कार्यकर्ता कौशल और उत्पाद आपूर्ति को अभिन्न घटक के रूप में चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र की स्थापना और निरंतर क्षमता निर्माण की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।



## महिला अनुकूल कार्यस्थल नीति

भारत में महिलाएं देश की आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पांच ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, महिलाएं ऐसे अनुकूल इकोसिस्टम के बिना पूरी तरह और प्रभावी ढंग से भाग लेने में समर्थ नहीं होंगी जो उनकी सुरक्षा, संरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल नहीं होगा।

इस संदर्भ में, नीति आयोग ने नीति आयोग में लैंगिक परिप्रेक्ष्य से उनकी जरूरतों और मौजूदा अंतराल को समझने के लिए सभी महिला कर्मचारियों के साथ आंतरिक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की। तत्पश्चात, नीति आयोग द्वारा कार्यस्थल पर महिला अनुकूल नीति का मसौदा तैयार किया गया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साझा किया गया।

## भारत में क्रेच के ईको सिस्टम का विस्तार

क्रेच आम तौर पर 6 साल तक के बच्चों को समूह देखभाल प्रदान करते हैं, ताकि देख-रेख करने वाले अपने काम, अध्ययन या ऐसी अन्य जगहों में जाने हेतु सक्षम हो सकें। भारत में 30 लाख से अधिक क्रेच की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रेच के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए मॉडल के विकास पर ध्यान देने के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और इस क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के साथ चर्चा की।

## नारी शक्ति सप्ताह का आयोजन

नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए 4-8 मार्च 2024 तक नारी शक्ति सप्ताह का आयोजन किया। नारी शक्ति सप्ताह का शुभारंभ 4 मार्च, 2024 को सुरक्षित स्थानों की बढ़ोतरी थीम के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। नीति आयोग की महिला कर्मचारियों के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा 5 मार्च, 2024 को एक महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।



नीति आयोग में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने हेतु नारी-शक्ति सप्ताह का शुभारंभ

महिलाओं की भूमिकाओं और चुनौतियों के बारे में चर्चा करने के लिए, नीति आयोग ने 6 मार्च 2024 को महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने और बाधाओं को लांघकर आगे बढ़ने वालों से संबंधित एक कार्यक्रम के लिए किरण बेदी (पहली महिला आईपीएस अधिकारी), गीतांजलि जे एंग्मो (सह- संस्थापक और सीईओ, एचआईएएल), शिवानी मलिक (निदेशक, दा मिलानो इटालिया), एकता भ्याण (पैरा एथलीट और स्वर्ण पदक विजेता, 2018 एशियाई पैरा गेम्स), अनु आचार्य (सीईओ, मैपमायजीनोम), देबजानी घोष (अध्यक्ष, नैसकॉम), लावण्या नल्ली (उपाध्यक्ष, नल्ली सिल्क साड़ीज़), और प्रेमलता अग्रवाल (विश्व की 7 सबसे ऊंची महाद्वीपीय चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला) जैसी जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित महिलाओं को आमंत्रित किया। अपने संगठनों में महिला- अनुकूल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई अपनी पहलों को साझा करने के लिए एयर इंडिया लिमिटेड, एकसेंचर, ताज होटल्स, जेनपैक्ट, ईवाई, एचडीएफसी बैंक और टेक महिंद्रा जैसे संगठनों को भी आमंत्रित किया गया था।



महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना और बाधाओं को तोड़ना





खंड

5

अनुवीक्षण एवं  
मूल्यांकन

## विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय

विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) भारत सरकार का शीर्ष अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय है। नीति आयोग के सहकारी और प्रतिस्पर्धी अधिदेश के तहत, इसके काम के दायरे में राज्यों को तकनीकी सलाह देना भी शामिल है। विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) का नेतृत्व महानिदेशक (डीजी) करते हैं। पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता के लिए, डीएमईओ को विशेष रूप से एक अलग बजटीय आवंटन प्रदान किया गया है।

डीएमईओ की भूमिका इस प्रकार है: (i) कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचे की प्रगति और प्रभावकारिता की निगरानी करने के साथ-साथ आवश्यक मध्य-पाठ्यक्रम सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए पहल; और (ii) सफलता की संभावना और वितरण के दायरे को मजबूत करने के लिए कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन करना।

2023-24 में डीएमईओ द्वारा प्रारंभ की गई प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं:

- आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग रूपरेखा (ओओएमएफ)
- डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई)
- सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांकों की निगरानी (जीआईआरजी)
- मूल्यांकन
- क्षेत्र की समीक्षा
- राज्यों के साथ परियोजना
- क्षमता निर्माण

## आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क

आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) कार्य 2017 के मध्य में डीएमईओ को सौंपा गया था और तब से यह एक वार्षिक कार्य बन गया है। इसका उद्देश्य आउटकम अनुवीक्षण को संस्थागत बनाना है ताकि भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों का ध्यान भौतिक और वित्तीय प्रगति को ट्रैक करने से हटाकर किए गए कार्य के परिणामों पर नज़र रखने पर केंद्रित किया जा सके। ओओएमएफ की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- प्रत्येक वर्ष, केंद्रीय बजट के साथ संसद में फ्रेमवर्क रखी जाती है।
- नियम 54, सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 ओओएमएफ को मंत्रालयों/विभागों के लिए एक अभिन्न प्रक्रिया बनाता है।
- इसमें 69 मंत्रालय/विभाग शामिल हैं।
- 13+ लाख करोड़ रुपये के संचयी वार्षिक बजटीय परिव्यय के साथ 400+ केंद्रीय क्षेत्रक (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)
- प्रगति और अनुपालन रिपोर्ट के माध्यम से डैशबोर्ड पर 3000+ आउटपुट और आउटकम संकेतक ट्रैक किए गए।

डीएमईओ ओओएमएफ डेटा का लाभ उठाकर साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों (एम/डी) और व्यय विभाग के साथ मिलकर काम करता है। यह उल्लेखनीय है कि यह कार्य मंत्रालयों/विभागों

द्वारा अपनी संबंधित योजनाओं के निष्पादन को समझने के लिए पूरे वर्ष किया जाता है। वर्ष 2020 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के ओओएमएफ से संबंधित वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने भाग लिया ताकि निम्न की समीक्षा की जा सके; (i) सीएस/सीएसएस की प्रगति; (ii) विशेष रूप से राष्ट्रीय विकास एजेंडा और एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में इसके परिणामों की निगरानी करना, (iii) पिछले वर्ष की ओओएमएफ समीक्षा बैठक से संबंधित कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर प्रगति और (iv) अन्य मुद्दे और चुनौतियां।

इसके अतिरिक्त, डीएमईओ का निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले अधिकारियों की क्षमता में सुधार हो। इस संबंध में, राज्य (जैसे राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल आदि) और संस्थान (जैसे एलबीएसएनएए, एनआईजीपीए, एनआईएलईआरडी आदि) के साथ ज्ञान-साझाकरण और क्षमता-निर्माण सत्रों की एक श्रृंखला भी आयोजित की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 09 क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जे-पीएल/सीएलईएआर एसए के साथ 'आउटकम बजटिंग पर सर्वोत्तम अभ्यास संग्रह' शीर्षक एक ज्ञान उत्पाद प्रकाशित किया गया है।

## भारत में डेटा गवर्नेंस में परिवर्तन: डीजीक्यूआई पहल

त्वरित डिजिटलीकरण और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास ने दुनिया भर में शासन की प्रकृति को बदल दिया है। पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी की बढ़ती मांग ने अपने जीवन चक्र में सार्वजनिक नीति में डेटा की भूमिका को संशोधित किया है। डेटा तैयारी सरकारों को अच्छी तरह से डिज़ाइन और अच्छी तरह से लक्षित नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने, मध्य-पाठ्यक्रम सुधार करने और भविष्य के निर्णयों को सूचित करने के लिए अपने जीवनचक्र के अंत में प्रभाव का मूल्यांकन करने की अनुमति देती है।

पिछले दो दशकों में, भारत सरकार के अधिकांश मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों ने अपनी पहलों के बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी के लिए डिजिटल एमआईएस और डैशबोर्ड विकसित किए हैं। हालांकि, उनके डेटा ग्रैनुलैरिटी, आवृत्ति के साथ-साथ गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं। डेटा अक्सर गैर-इंटरऑपरेबल प्रारूपों में साइलोज़ में भी मौजूद होता है, जिससे यह क्रॉस-फंक्शनल एनालिटिक्स उद्देश्यों के लिए कम उपयोगी हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, भले ही सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियाओं में बहुत सारे डेटा उत्पन्न होते हैं, लेकिन दिन-प्रतिदिन के निर्णयों को चलाने और निबंध सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग करने के मामले में इसकी क्षमता को इष्टतम दोहन की आवश्यकता होती है।

इस पृष्ठभूमि में, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) कार्य 2020 में डीएमईओ द्वारा एनआईसी/एनआईसीएसआई और सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों के समर्थन से शुरू किया गया था। डीजीक्यूआई कार्य का पहला चरण 2020 में स्व-मूल्यांकन मोड में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 250 सीएस/सीएसएस योजनाओं को कवर करते हुए 65 मंत्रालय/विभाग शामिल थे। मंत्रालयों/विभागों ने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण भरा, जिसकी प्रतिक्रियाओं का उपयोग डीजीक्यूआई स्कोरकार्ड के साथ आने के लिए किया गया था। इस कार्य ने मंत्रालयों/विभागों के बीच भारी असमानताओं को दिखाया और बोर्ड भर में सुधार की एक बड़ी गुंजाइश पर प्रकाश डाला। इसके बाद, डीजीक्यूआई 2.0 को 2021 में उन्नत क्षैतिज (डेटा तैयारी के सभी तीन चरणों, यानी, डेटा कार्यनीति, सिस्टम और डेटा-संचालित परिणामों को कवर करते हुए) और ऊर्ध्वधर दायरे (मंत्रालय/विभाग और योजनाओं की संख्या के साथ-साथ गैर-योजनाबद्ध हस्तक्षेपों के संदर्भ में) के साथ शुरू किया गया था।

डीजीक्यूआई कार्य डेटा उत्पादन, डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी एकीकरण, विश्लेषण, प्रसार, सुरक्षा जैसे छह विषयों में विभाजित 3 स्तंभों पर केंद्रित है और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को प्रोत्साहित करता है। अब तक अभ्यास

के 6 दौर पूरे हो चुके हैं और डीजीक्यूआई 2.0 अभ्यास के सातवें चल रहे दौर के हिस्से के रूप में, 75 मंत्रालय/विभाग लगभग 579 अंतःक्षेपों पर अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

स्थापना के पश्चात, कई मंत्रालयों/विभागों ने अत्यधिक सुधार का प्रदर्शन किया और अधिकांश मंत्रालयों की रैंकिंग उत्कृष्ट श्रेणी में है। हालाँकि, सूचकांक में मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रतिक्रियाओं के गहन विश्लेषण ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। उनके समाधान हेतु, डीएमईओ ने एक व्यापक क्षमता-निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया है, जहां डेटा साझाकरण और अंतरसंचालनीयता की कमी पर चुनौतियों का समाधान दर्शाया गया है और मंत्रालयों/विभागों को उनके समाधान हेतु मानकीकृत प्रक्रियाओं, प्रारूपों और ओपन-सोर्स दस्तावेज़ीकरण प्लेटफार्मों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इन मंत्रालयों/विभागों में डेटा और कार्यनीति इकाइयों को इंटर-मंत्रालयों/विभागों के सहयोग को बढ़ावा देने और सभी योजनाओं के बीच डेटा स्थिरता और एकरूपता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

इसके अतिरिक्त, यह पद्धति राज्यों की भागीदारी को दृढ़ता से प्रोत्साहित करती है जिससे उन्हें अपने विभागों में नीति कार्यान्वयन और योजना-तंत्र में लाभ होगा। डीजीक्यूआई सर्वोत्तम प्रथाओं, नवीन दृष्टिकोणों और आम चुनौतियों के समाधान साझा करने के लिए सहयोग एवं सीखने की संस्कृति का निर्माण करता है। एक प्रमुख लाभ सर्वोत्तम प्रथा भंडार का निर्माण है जो विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए नवीन डेटा-संचालित पहलों को प्रदर्शित करता है।

## सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (जीआईआरजी)

भारत सरकार की जीआईआरजी पहल का उद्देश्य देश में विकास और सुधारों को चलाने के लिए 27 वैश्विक सूचकांकों (जीआई) की निगरानी का लाभ उठाना है। जीआईआरजी के तहत निगरानी के लिए चुने गए 27 जीआई 18 अद्वितीय वैश्विक एजेंसियों (प्रकाशन एजेंसियों) द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, जिनमें बहुपक्षीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ, निजी संगठन और विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो चार व्यापक विषयों (नामत: अर्थव्यवस्था, विकास, शासन और उद्योग) में फैले हुए हैं। इन 27 सूचकांकों को 18 नोडल मंत्रालयों को आवंटित किया गया है। इसके अलावा, जीआईआरजी को चलाने के लिए एमओएसपीआई, एमईए और एमआईबी को शामिल किया गया है।

जीआईआरजी पहल का प्राथमिक उद्देश्य भारत और इसकी वैश्विक रैंकिंग के बारे में वैश्विक धारणा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और विकास मापदंडों में भारत के प्रदर्शन को बढ़ावा देना, सुधारों को आगे बढ़ाना और प्रगति की निगरानी करना है।

डीएमईओ, नीति आयोग को इस कार्य को चलाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने हेतु ज्ञान भागीदार और समन्वयक के रूप में नामित किया गया है। 28 वैश्विक सूचकांकों के लिए नोडल मंत्रालय/विभागों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने के लिए कैबिनेट सचिव के स्तर पर जीआईआरजी पहल की लगातार समीक्षा की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान नीति आयोग के सीईओ और डीएमईओ के महानिदेशक स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, प्रकाशन एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कुल 19 बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में विभिन्न सूचकांकों पर विचार-विमर्श किया गया और इन सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन में सुधार के लिए रणनीति तैयार की गई। कैबिनेट सचिव द्वारा दो समीक्षा बैठकें और दो पीएमओ बैठकें भी आयोजित की गईं, जिसमें सूचकांकों की एक पूरी श्रृंखला शामिल थी।

## मूल्यांकन

डीएमईओ साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक नीति-निर्माण को सक्षम बनाने वाली भारत सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन स्वतः संज्ञान या मंत्रालयों के अनुरोध पर किए जाते हैं। व्यापक साहित्य समीक्षा और सर्वेक्षण डेटा विश्लेषण पर आधारित ये मूल्यांकन योजनाओं/कार्यक्रमों के कामकाज में सुधार करने और इसके इच्छित उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मूल्यांकन यह समझने के उद्देश्य से किया जाता है कि क्या काम करता है, क्यों, किसके लिए और किन परिस्थितियों में, जिसके आधार पर कार्यक्रमों/योजनाओं को परिष्कृत, अनुकूलित और मध्यावधि सुधार किया जाता है ताकि योजनाओं/कार्यक्रमों को उनके वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

डीएमईओ ने व्यय विभाग के अनुरोध पर आयोजित तीन मंत्रालयों की नौ केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। उनकी अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ साझा की गई है। डीएमईओ चार मंत्रालयों से संबंधित छह अन्य केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन को भी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के नीति आयोग के लक्ष्य के तहत अनुवीक्षण और मूल्यांकन क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करके क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डीएमईओ विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी जुड़ रहा है। क्षमताओं को और बढ़ाने, क्षमता में वृद्धि करने और राज्य स्तर पर मौजूदा विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए, डीएमईओ मूल्यांकन में अपनी भागीदारी के माध्यम से केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों की निगरानी और मूल्यांकन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की अपनी तरह की पहली पहल कर रहा है। भारत सरकार की आठ योजनाएँ दस राज्यों में फैली हुई हैं।

## सेक्टर की समीक्षा

क्षेत्रों के निष्पादन की निगरानी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष क्षेत्र बैठकें आयोजित की जाती हैं। डीएमईओ संबंधित मंत्रालयों/विभागों और नीति आयोग के वर्टिकलों के साथ समन्वय में 2017 से प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए सेक्टर समीक्षा की सुविधा प्रदान कर रहा है। समीक्षाओं के तहत शामिल क्षेत्रों में 10 बुनियादी ढांचा क्षेत्र शामिल हैं जैसे परिवहन (सड़क, नागरिक विमानन, रेलवे और बंदरगाह), ऊर्जा (बिजली, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) और अन्य (डिजिटल, खनन)।

ये समीक्षाएं क्षेत्रों के प्रदर्शन का एक क्रॉस-मिनिस्ट्रियल दृष्टिकोण प्रस्तुत करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत की क्षेत्रीय ताकत और कमजोरियों की गहन रूप से जांच करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं। बाधाओं की पहचान करके और हस्तक्षेप का सुझाव देकर, समग्र विकास परिणामों में सुधार के लिए सरकार के उच्चतम स्तर से तत्काल कार्रवाई अक्सर शुरू की जाती है। नवीनतम बैठक जून-जुलाई 2023 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी जिसमें 9 क्षेत्रों को शामिल किया गया था।

## क्षमता निर्माण

डीएमईओ के लक्ष्यों में से एक सरकारी नीति और कार्यक्रमों के सभी स्तरों पर निगरानी और मूल्यांकन के अनुप्रयोग को संस्थागत बनाना है, जिससे दक्षता, प्रभावशीलता, इच्छिती, स्थिरता और परिणामों की उपलब्धि में सुधार होता है। पिछले एक वर्ष में, डीएमईओ केंद्र और राज्य स्तरों पर व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं के

निर्माण के लिए कई पहल कर रहा है। इन पहलों को सरकारी हितधारकों, वैश्विक विशेषज्ञों, थिंक टैंक और अकादमिक संगठनों के साथ सहक्रियात्मक साझेदारी के माध्यम से समर्थित किया जाता है।

## राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों का क्षमता निर्माण

सहकारी संघवाद के लक्ष्य के अनुसरण में, डीएमईओ ज्ञान-साझाकरण के साथ-साथ निगरानी और मूल्यांकन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ रहा है। विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के इस नेटवर्क के साथ प्रारंभिक साझेदारी का उद्देश्य महत्वपूर्ण लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के त्वरित क्षेत्र-स्तरीय मूल्यांकन करना है। विश्वविद्यालयों के क्षमता निर्माण का पहला दौर वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है और 10 विश्वविद्यालयों के साथ 10 राज्यों में किया जा रहा है। उसी का दूसरा दौर चल रहा है और 14 राज्यों के 14 विश्वविद्यालयों के सहयोग से किया जाना प्रस्तावित है।

## विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के साथ आशय विवरण

23 मार्च 2023 - डीएमईओ और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने भारत में निगरानी और मूल्यांकन को मजबूत करने के लिए रणनीतिक और तकनीकी सहयोग का विस्तार करने के लिए एक आशय पत्र (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए। आशय विवरण (एसओआई) पर डीएमईओ के महानिदेशक श्री संजय कुमार और विश्व खाद्य कार्यक्रम, भारत की प्रतिनिधि और केंद्री डायरेक्टर सुश्री एलिजाबेथ फॉरे ने हस्ताक्षर किए। डीएमईओ और डब्ल्यूएफपी के बीच साझेदारी एम एंड ई पर सरकारी अधिकारियों के लिए मूल्यांकन अध्ययन और क्षमता निर्माण के साथ-साथ एम एंड ई से संबंधित ज्ञान प्रसार और आउटरीच गतिविधियों के लिए सहयोग के लिए तकनीकी सहायता पर केंद्रित होगी।

डीएमईओ ने वार्षिक लोकल मूल्यांकन सप्ताह के 5 वें संस्करण में 2 कार्यक्रमों की मेजबानी की, जो वैश्विक मूल्यांकन पहल द्वारा आयोजित एक वैश्विक निगरानी और मूल्यांकन ज्ञान-साझाकरण गतिविधि है।

## राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षमता निर्माण

डीएमईओ क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बातचीत कर रहा है और साथ ही उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग राज्यों के साथ निगरानी और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश और टूलकिट साझा कर रहा है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के नीति आयोग के जनादेश के अनुरूप, डीएमईओ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना विभागों के साथ जुड़ रहा है।

## राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण सत्र

देश भर में एम एंड ई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, डीएमईओ ने पिछले वर्ष के दौरान कई प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए:

डीएमईओ, नीति आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। एलबीएसएनएए, मसूरी में चरण III, मिड- कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (9 से 11 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके आईएएस अधिकारियों के लिए) के 19वें राउंड के लिए दो दिवसीय (6-7 जून 2023) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण सत्र "साक्ष्य- आधारित नीति निर्माण के लिए अनुवीक्षण/ मूल्यांकन और ओओएमएफ" मॉड्यूल पर केंद्रित थे। कार्यक्रम में वर्ष 2007 से वर्ष 2015 बैच के 180 आईएएस अधिकारी शामिल हुए। राजस्थान सरकार और अंडमान एवं निकोबार के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित किए गए।



## राज्यों के साथ परियोजनाएं

डीएमईओ ने मूल्यांकन को सुदृढ़ करने के उपायों को संस्थागत बनाने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की सहायता करने के लिए एक नैदानिक उपकरण भी विकसित किया है। डीएमईओ की टीम ने 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बातचीत की है। राष्ट्रीय और राज्य रिपोर्ट के मसौदे को प्रतिक्रिया के लिए साझा किया गया है। डीएमईओ राज्यों में निगरानी और मूल्यांकन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एसएसएम टीम के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है।





खंड

6

अटल इनोवेशन  
मिशन

## भूमिका

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। एआईएम ने स्कूली बच्चों के बीच समस्या सुलझाने वाली अभिनव मानसिकता का पोषण करने और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और एमएसएमई में उद्यमिता का एक इकोसिस्टम बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है।

एआईएम की सभी पहलों का वर्तमान में तत्क्षण एमआईएस प्रणालियों और गतिशील डैशबोर्ड के माध्यम से व्यवस्थित रूप से निगरानी और प्रबंधन किया जा रहा है। निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए, एआईएम ने अपने कार्यक्रमों की नियमित रूप से तृतीय-पक्ष एजेंसियों द्वारा समीक्षा कराई है।



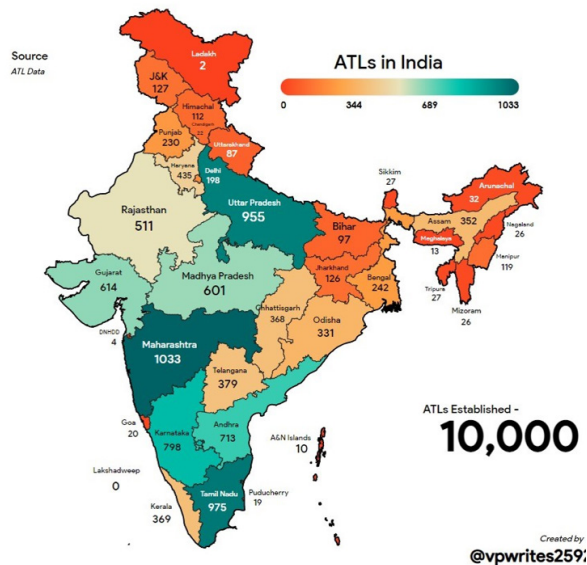
### AIM Ecosystem Development Program (AEDP)

60+ domestic and 16+ international partners  
10+ Strategic Programs

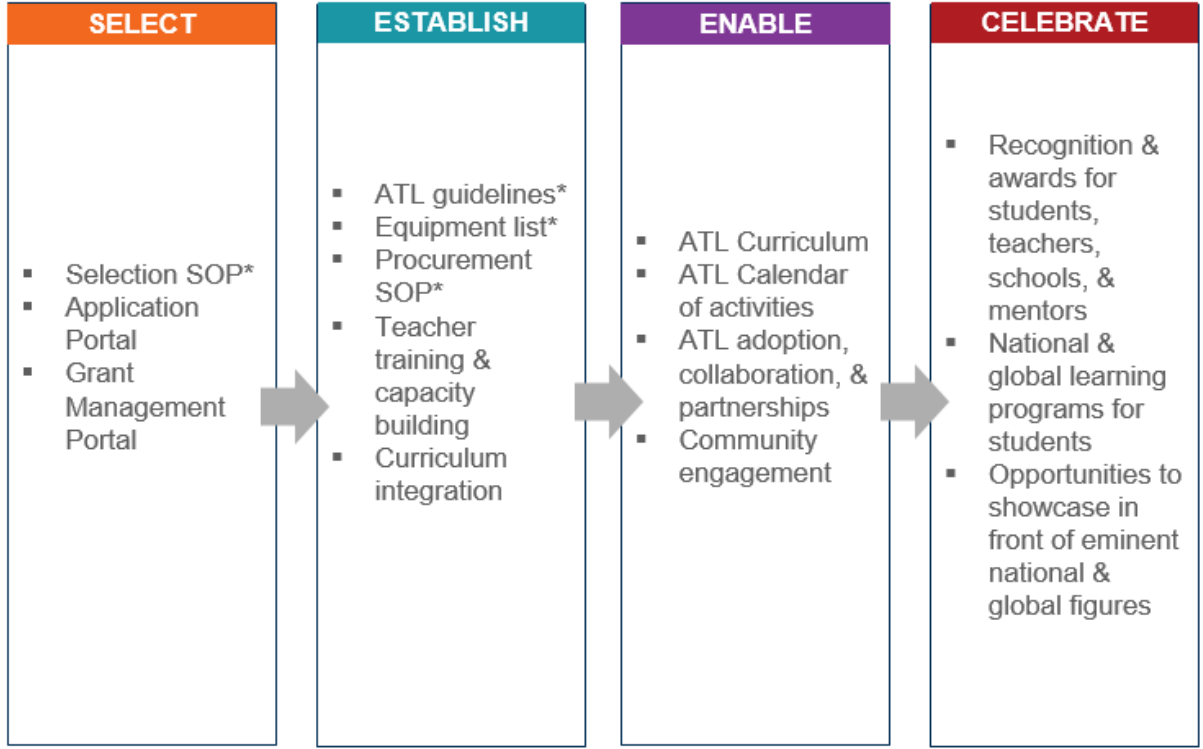
एआईसी/ईआईसी द्वारा समर्थित स्टार्टअप का सेक्टरवार ब्यौरा

## अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल)

अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) का स्कूल में स्थापित एक अत्याधुनिक स्थान है, जिसका लक्ष्य 21वीं सदी के उपकरणों और प्रौद्योगिकियों जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3डी प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग उपकरण, रोबोटिक्स, लघु इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वयं करें किट और बहुत कुछ के माध्यम से देश भर में 6वीं से 12वीं कक्षा के स्तर पर युवाओं के मन में जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य एटीएल और आसपास के समुदायों के बच्चों के भीतर समस्या समाधान की नवाचारी मानसिकता को प्रोत्साहित करना है। अब तक, एआईएम ने भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 700 से अधिक जिलों के स्कूलों में 10,000 एटीएल स्थापित किए हैं।



एटीएल राज्य-वार कवरेज



एटीएल कार्यक्रम रूपरेखा

## एटीएल कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

### 1. एटीएल प्रतियोगिताएं - एटीएल मैराथन और टिकरप्रेन्योर और स्पेस इनोवेशन चैलेंज

भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की थीम पर आधारित एआईएम की महत्वपूर्ण नवाचार प्रतियोगिताएं - एटीएल मैराथन 2023-24 में छात्र टीमों द्वारा 20,000 नवाचार परियोजनाएं प्रस्तुत किए जाने के साथ पूरे भारत से भारी भागीदारी देखी गई। एटीएल टिकरप्रेन्योर - डिजिटल स्किलिंग बूटकैंप में भी डिजिटल उपकरण बनाने वाली 25,000 से अधिक टीमों की भागीदारी देखी गई। आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की चुनौतियों को हल करने के लिए सभी स्कूली छात्रों के लिए आयोजित राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती में 27000 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।

### 2. एटीएल टिकरिंग पाठ्यक्रम और उपकरण का शुभारंभ

एटीएल टिकरिंग पाठ्यक्रम एक संरचित शिक्षण मार्ग है जिसे छात्रों के नवाचार कौशल को विकसित करने और निखारने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पाठ्यक्रम में बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिकी से लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक की अवधारणाओं (जैसे 3डी प्रिंटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स) की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उपकरण मैनुअल में प्रत्येक उपकरण और यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें विनिर्देशों, अनुप्रयोगों और परियोजनाओं के उदाहरण शामिल हैं, जिन्हें उनका उपयोग करके बनाया जा सकता है।

### 3. एटीएल सारथी

एटीएल के लगातार बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एटीएल सारथी एक व्यापक स्व-निगरानी ढांचा है। इस पहल के चार स्तंभ हैं जो प्रक्रिया में नियमित सुधार के माध्यम से एटीएल के प्रदर्शन

में वृद्धि सुनिश्चित करते हैं, जैसे 'मायएटीएल डैशबोर्ड' के रूप में जाना जाने वाला स्व-रिपोर्टिंग डैशबोर्ड और वित्तीय और गैर-वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के लिए अनुपालन एसओपी, क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के सहयोग से एटीएल की ऑन-ग्राउंड सक्षमता और प्रदर्शन सक्षमता (पीई) मैट्रिक्स के माध्यम से अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए स्कूलों को स्वामित्व प्रदान करता है।

#### 4. छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में राज्य स्तरीय एटीएल हैकथॉन

बिलासपुर के सरकारी स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय एटीएल हैकथॉन में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के एटीएल स्कूलों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। टिंकरेथॉन में 78 एटीएल स्कूलों की 110 टीमों ने भाग लिया। तूतुकुडी के एक एटीएल स्कूल में आयोजित इसी तरह के हैकथॉन में तमिलनाडु के सभी जिलों के स्कूलों की 442 एटीएल टीमों ने भाग लिया, जो युवा नवप्रवर्तकों के उल्लेखनीय उत्साह और रुचि को दर्शाता है।



बिलासपुर में राजस्तरीय एटीएल हैकथॉन

#### 5. एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ और अखिल भारतीय शिक्षा समागम का दूसरा संस्करण

भारत भर से 27 एटीएल टीमों ने जुलाई 2023 में प्रगति मैदान में नई शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ और अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दूसरे संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री को अपनी नवाचार परियोजनाओं का प्रदर्शन किया।

### अटल इनक्यूबेशन सेंटर

अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) कार्यक्रम 2017 में बिजनेस इनक्यूबेटर्स के इकोसिस्टम के निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जहां उद्यमी भौतिक अवसंरचना, प्रशिक्षण और शिक्षा सहित विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और निवेशकों, अन्य नवोन्मेषकों और सलाहकारों सहित प्रमुख हितधारकों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीन फील्ड इनक्यूबेटर्स को एआईसी के रूप में और ब्राउन फील्ड इनक्यूबेटर्स को स्थापित इनक्यूबेशन सेंटर (ईआईसी) के रूप में 5 वर्ष की अवधि में 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।

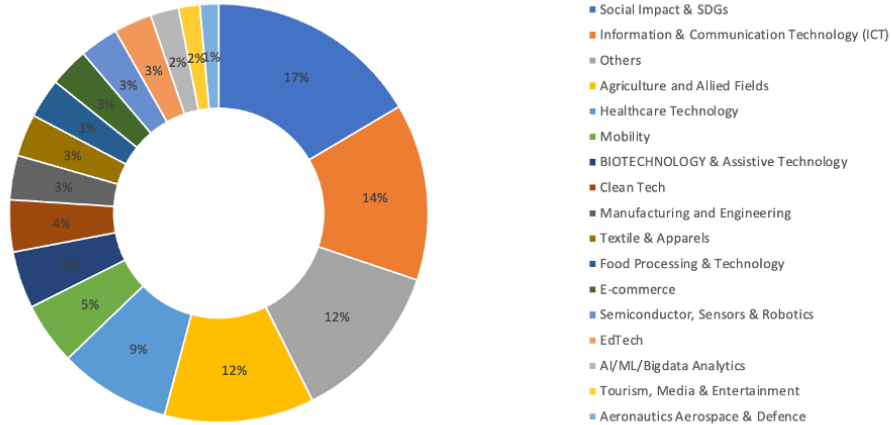


एआईएम ने अब तक भारत के 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक संस्थानों में 72 एआईसी स्थापित किए हैं। इन केंद्रों ने देश भर में 3500 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन किया है और देश भर में 40,000 से अधिक रोजगार पैदा किया है जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और फोकस करते हैं।

इसका विभाजन नीचे दिया गया है:



Each △ Signifies Atal Incubation Center (AIC)  
Each ○ Signifies Established Incubation Center (EIC)



## एआईसी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

### 1. स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर के लिए मूल्यांकन ढांचा

एआईएम ने एआईसी के प्रदर्शन की निगरानी और बेंचमार्क करने के लिए स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर के लिए वर्ष 2021 में मूल्यांकन ढांचे का शुभारंभ किया। यह ढांचा इनक्यूबेटर्स के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक वार्षिक अभ्यास बन जाएगा और ऐसी परिकल्पना की गई है कि यह देश भर में इनक्यूबेटर्स के मूल्यांकन के लिए एक मानक ढांचा बनेगा।

जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की शिखर बैठक स्टार्टअप 20 शिखर के हिस्से के रूप में "स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटरों के लिए मूल्यांकन ढांचा" नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।



जुलाई 2023 में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटरों के लिए मूल्यांकन रूपरेखा पुस्तक का लॉन्च

### 2. परिवर्तन स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम

एआईएम ने नवाचार और बदलाव को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी में परिवर्तन स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम का 7वां संस्करण लॉन्च किया। यह पहल लगभग 20 इनक्यूबेटर्स और एक्सेलेरेटर्स को 10 करोड़ रुपये तक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) फंडिंग और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करेगी। ये इनक्यूबेटर स्वतंत्र रूप से विषयगत/क्षेत्रीय इनक्यूबेशन/त्वरण

कार्यक्रमों का संचालन करेंगे और चुनिंदा स्टार्टअप में परोपकारी पूंजी का निवेश करेंगे। ऐसी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से स्केलअप फंडिंग के साथ 40-50 स्टार्टअप को मदद मिलेगी और चयनित इनक्यूबेटर भागीदारों द्वारा चलाए जा रहे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से बड़ी संख्या में स्टार्टअप लाभान्वित होंगे।

### 3. स्टार्टअप और \$1 मिलियन के डेमो डे के लिए फंडिंग

ऑटोक्रेसी - ईआईसी एलीप में इनक्यूबेट किए गए इस एग्रीटेक स्टार्टअप ने 1.2 मिलियन डॉलर जुटाए

कार्ड 91 - एआईसी ग्रेट लेक्स और एआईसी डीएसयू में इनक्यूबेट किए गए इस फिनटेक स्टार्टअप ने 13 मिलियन डॉलर जुटाए

वेकमोकॉन - एआईसी आईएसबी मोहाली में ईवी क्षेत्र में इनक्यूबेट किए गए इस स्टार्टअप ने 5.2 मिलियन डॉलर जुटाए

बायो फ्यूल - एआईसी रेज में इनक्यूबेट किए गए इस क्लीनटेक स्टार्टअप ने 2 मिलियन डॉलर जुटाए

Phyx44 - ईआईसी सीसीएमबी में इनक्यूबेट किए गए इस स्टार्टअप ने 1.2 मिलियन डॉलर जुटाए

Rises.Ai - एआईसी एलएमसीपी में इनक्यूबेट किए गए इस स्टार्टअप ने 1 मिलियन डॉलर जुटाए

फोटो 1 एनर्जी - एआईसी प्रेस्टीज में इनक्यूबेट किए गए इस ग्रीन ऊर्जा स्टार्टअप ने 550 हजार डॉलर जुटाए

मेडीसेवा - एआईसी आरएनटीयू में इनक्यूबेट किए गए इस हेल्थटेक स्टार्टअप ने 500 हजार डॉलर जुटाए

एआईएम ने वेंचर कैटलिस्ट्स के सहयोग से एआईसी और ईआईसी से जुड़े स्टार्टअप के लिए \$1 मिलियन डेमो डे का दूसरा सीजन लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य एआईसी और ईआईसी से जुड़े शुरूआती चरण और क्षेत्र के संशयवादी स्टार्टअप का समर्थन करना है ताकि उन्हें अपने नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए निवेश और नेटवर्किंग के उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया जा सकें। ऑटोक्रेसी मशीनरी ने डेमो डे का पहला संस्करण जीता और और वेंचर कैटलिस्ट्स के नेतृत्व में 1.2 मिलियन डॉलर का फंडिंग सीड राउंड जुटाया।

### 4. एआईसी इकोसिस्टम की सफलता की कहानियां

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) और एएफडी (एजेंस फ्रांसेइस डी डेवलपमेंट) द्वारा आयोजित स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज 2.0 के तहत एआईसी प्रेस्टीज में इनक्यूबेट किए गए एआरसी रोबोटिक्स नामक स्टार्टअप को शीर्ष 30 स्टार्टअप में चुना गया है।
- एआईसी - आईएसबी मोहाली में इनक्यूबेट किए गए नीरएक्स नामक स्टार्टअप के संस्थापकों को "फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया: विनिर्माण, उद्योग और खेती में नवप्रवर्तक" के तहत मान्यता दी गई है। अहमदाबाद स्थित यह स्टार्टअप स्मार्ट सेंसर का उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को समझने में किसानों की मदद करता है।
- विभिन्न स्थानों पर एआईसी में इनक्यूबेट किए गए 10 स्टार्टअप ने 2023 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जीता। ये स्टार्टअप एग्रीटेक, ऊर्जा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- एआईएम के समर्थन से स्थापित इनक्यूबेशन केंद्रों में से एक सीसीएमपी ने 'इकोसिस्टम एनेबलर' श्रेणी के तहत राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 जीता।

## अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र

नवाचार के लिए सक्षम अवसंरचना और सुगम वातावरण प्रदान करके भारत के वंचित/असेवित क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (एसीआईसी) शुरू किए गए हैं। अब तक, 9 राज्यों में 14 एसीआईसी चालू किए गए हैं तथा एसीआईसी स्थापित करने के लिए 36 और केंद्र अनुपालन जांच के दौर से गुजर रहे हैं। एआईएम का उद्देश्य 2024 के अंत तक 50 से अधिक एसीआईसी स्थापित करने का है। पूरे भारत में संचालित एसीआईसी को कुल 12+ करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। अब तक 450 से अधिक स्टार्टअप की मदद की गई है, जिससे 1300 से अधिक रोजगार पैदा हुआ है, जिनमें से 30 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाओं/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा किया जा रहा है। एसीआईसी द्वारा 300 से अधिक संपर्क और धन जुटाने के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

### एसीआईसी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

#### 1. “परिवर्तन की कहानियां” का शुभारंभ

एआईएम ने “परिवर्तन की कहानियां” शुरू की जो जमीनी स्तर के 15 परिवर्तनकर्ताओं की यात्रा पर प्रकाश डालने वाली श्रृंखला है। इस पहल का उद्देश्य उन व्यक्तियों की प्रभावशाली कहानियों को प्रदर्शित करना है, जिन्होंने चुनौतियों के बावजूद अपने जीवन में और समुदायों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह श्रृंखला उद्यमशीलता को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो नवप्रवर्तकों को अपनी सफलता और संघर्षों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

#### 2. सामुदायिक नवप्रवर्तक फेलोशिप (सीआईएफ) के पहले समूह को स्नातक की उपाधि (सीआईएफ)



सामुदायिक नवप्रवर्तक फेलोशिप (सीआईएफ) कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से एआईएम की एक पहल है, जो ज्ञान निर्माण को सुगम बनाता है और उद्यमशीलता की यात्रा के लिए इच्छुक सामुदायिक नवप्रवर्तकों को आवश्यक अवसंरचना सहायता प्रदान करता है। यह एक साल तक चलने वाला गहन फेलोशिप कार्यक्रम है जिसमें महत्वाकांक्षी सामुदायिक नवप्रवर्तक को अटल सामुदायिक नवप्रवर्तन केंद्र की मेजबानी में रखा जाता है और वह अपने विचार पर काम करते हुए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के बारे में जानकारी, उद्यमशीलता कौशल और जीवन कौशल प्राप्त करता है।

अब तक 73 सीआईएफ एसीआईसी और एआईएम के नेटवर्क के सहायता से प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग ले चुके हैं।



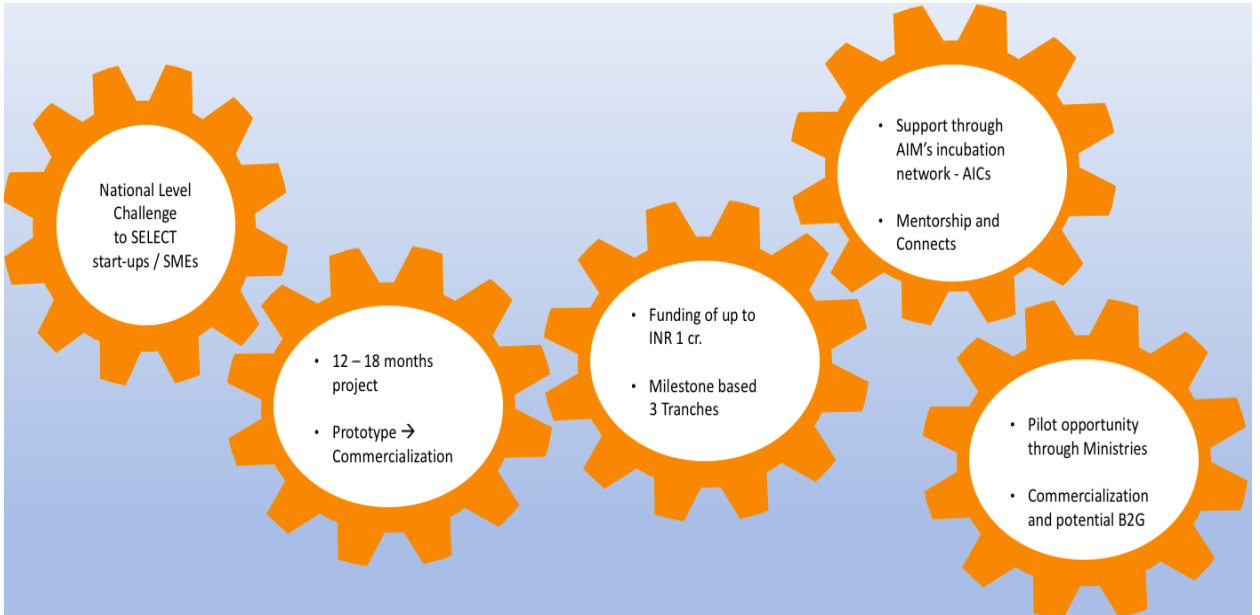
## अटल न्यू इंडिया चैलेंज

अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) एआईएम का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी पर आधारित नवाचारों की तलाश, चयन, समर्थन और पोषण करना है जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करते हैं। एएनआईसी का विजन दो तरफा है:

- (क) राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित नवाचार विकसित करने में मदद करना
- (ख) नवाचारों का समर्थन करने और नवाचार को अपनाने के लिए सरकार में एक संस्थागत संरचना विकसित करना

एएनआईसी कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य भारत के विकास और वृद्धि के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, ऊर्जा, गतिशीलता, अंतरिक्ष अनुप्रयोग आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। एएनआईसी का उद्देश्य परीक्षण, संचालन और बाजार निर्माण के लिए संसाधनों तक पहुंच से जुड़े जोखिमों से पार पाने के लिए नवप्रवर्तकों को समर्थन प्रदान करना है।

एएनआईसी प्रोटोटाइप चरण में नवाचारों का आग्रह करता है और 12 से 18 महीने के व्यावसायीकरण चरण के दौरान एआईएम नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से 1 करोड़ रुपये तक के वित्त पोषण और अन्य संबंधित सहायता के माध्यम से चयनित स्टार्टअप का समर्थन करता है।



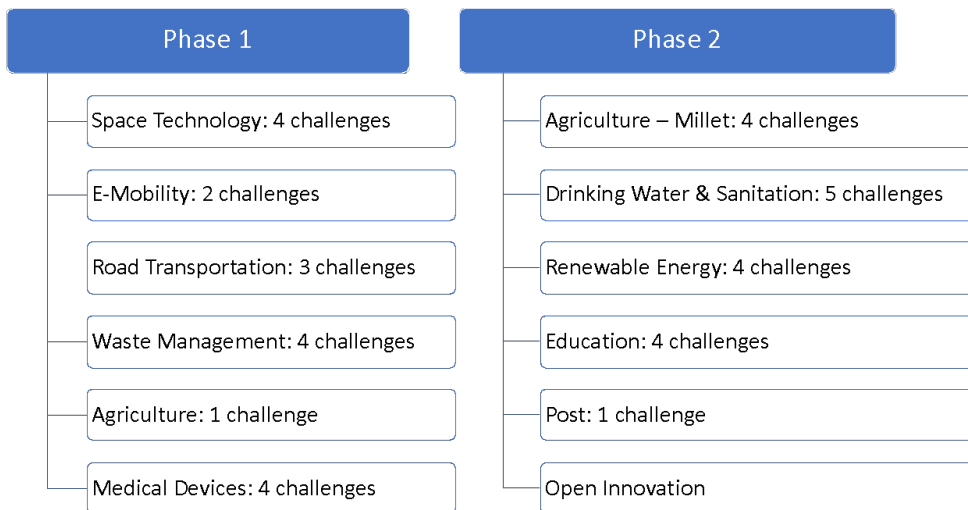
### एएनआईसी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

एएनआईसी ने "एएनआईसी 2.0" के नाम से कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया। एएनआईसी 2.0 के तहत 12 क्षेत्रों को कवर करते हुए 2 चरणों में 36 चुनौतियाँ शुरू की गईं।

एआईएम से वित्त पोषण और अन्य संबंधित सहायता के लिए एएनआईसी 2.0 के तहत 120 स्टार्टअप/एमएसएमई का चयन किया गया है। एएनआईसी के पिछले समूह यानी एएनआईसी 1.0 और एएनआईसी-एराइज ने 9 मंत्रालयों के सहयोग से 39 चुनौतियाँ शुरू की थीं। वर्तमान में 55 स्टार्टअप/एमएसएमई को एआईसी के माध्यम

से 33 करोड़ से अधिक के स्वीकृत सहायता अनुदान और इन्क्यूबेशन समर्थन के साथ सहायता प्रदान की जा रही है। स्टार्टअप के पहले समूह ने 400 से अधिक नौकरियां पैदा करके और 150 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी वित्त पोषण जुटाकर सफलता के संकेत दिए हैं।

एएनआईसी से प्राप्त कुछ उल्लेखनीय सफलताएं इस प्रकार हैं:



**BioPrime**  
AGRSOLUTIONS PVT LTD

**Climate Smart Agriculture**

- Agri-Biologicals – patented SNIPR technology
- increase **efficiency of inputs**, reduce crop loss and increase **shelf life** at post harvest stage
- impacted > 1 lakh farmers in 4 states
- > 20 cr. incremental farmers income
- Reduced urea consumption of 30 lakh kg

[BioPrime Video](#)

**padcare**

**Waste Management**

- Hygiene Management solution that completes the loop of **menstrual hygiene economy** by generating harmless, **recyclable output** out of soiled pads

[Padcare Video](#)

**recity**

**Circular Economy: Cities**

- Inclusive and Sustainable Waste Management System
- **cityloop** system creates traceable and trackable waste monitoring
- Impacted > 1500 waste workers empowered
- > 17000 MT waste diverted from landfills
- 10+ city level interventions



## एआईएम पारिस्थितिकी तंत्र विकास कार्यक्रम

एआईएम पारिस्थितिकी तंत्र विकास कार्यक्रम (एईडीपी) संरचित कार्यक्रमों के ढांचे से परे एआईएम के लाभार्थियों को अतिरिक्त मूल्य प्रदान करने के लिए प्रासंगिक हितधारकों के नेटवर्क का निर्माण करके एआईएम के नवाचार और उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने वाले सभी कार्यनीतिक कार्यक्रमों के बीच से होकर जाने वाला कार्यक्रम है।

एईडीपी ने विभिन्न निगमों, प्रतिष्ठानों में 70 से अधिक साझेदारियों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) का निर्माण किया है जो उद्योग के नेतृत्वकर्ताओं और संकाय के साथ कार्यरत हैं और अवसंरचना और प्रौद्योगिकी, बाजार और

निवेशक पहुंच, माँड्यूल के निर्माण और एटीएल को अपनाने के माध्यम से एआईएम के लाभार्थियों का समर्थन करते हैं।

## ईडीपी की मुख्य विशेषताएं:

### 1. स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप

स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने और स्टार्टअप, कॉर्पोरेट, निवेशकों, इनोवेशन एजेंसियों और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच तालमेल को सक्षम करने के लिए एक वैश्विक नैरेटिव का निर्माण करने के लिए 2023 में भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की शुरुआत की गई है।

इस समूह का उद्देश्य सक्षम करने वालों की क्षमताओं के निर्माण, वित्त पोषण अंतराल की पहचान, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, एसडीजी लक्ष्यों की उपलब्धि और जलवायु लचीलापन और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के रूप में कार्टवाई योग्य मार्गदर्शन विकसित करने के लिए एक साथ आगे बढ़ने के लिए जी20 के सदस्य देशों के स्टार्टअप को एक साझा मंच प्रदान करना है।

यह एंगेजमेंट ग्रुप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ 4 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल था:

- **स्टार्टअप 20 हैदराबाद स्थापना बैठक:**

जी20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप ने हैदराबाद में अपनी स्थापना बैठक आयोजित की, जिसमें जी20 देशों के प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षक देशों के नौ विशेष आमंत्रित सदस्यों, बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। भारत द्वारा अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद जी20 के तहत गठित समूह ने जी20 देशों की उद्यमिता और नवाचार संबंधी प्राथमिकताओं पर नीतिगत सिफारिशों के रचनात्मक विकास की आशा करते हुए 28-29 जनवरी, 2023 को अपनी पहली बैठक बुलाई। इस बैठक ने स्टार्टअप का समर्थन करने और स्टार्टअप, कॉर्पोरेट, निवेशकों, नवाचार एजेंसियों और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक नैरेटिव तैयार किया।

- **स्टार्टअप 20 की सिक्किम सभा:**



सिक्किम में स्टार्टअप-20 एंगेजमेंट ग्रुप की दूसरी बैठक

स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की दूसरी बैठक गंगटोक, सिक्किम में आयोजित की गई। एंगेजमेंट ग्रुप के कार्यबल के सदस्यों (जिसमें जी20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं) ने आधिकारिक नीति विज्ञप्ति के पहले मसौदे पर चर्चा और विचार-विमर्श किया। सिक्किम सभा में जी20 के सदस्यों और आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 300 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सिक्किम सभा ने अपनी स्थापना के दौरान अंतिम रूप दिए गए एजेंडे को अग्रेषित किया। बैठक के दौरान, सभी प्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करने के लिए तीन कार्यबलों अर्थात् फाउंडेशन और गठबंधन, वित्त, और समावेशन और संधारणीयता के उद्देश्यों और प्रदेयताओं पर फिर से काम किया गया।

• **स्टार्टअप 20 गोवा संकल्पनाः**

सामूहिक संकल्प के लिए संस्कृत शब्द “संकल्पना” की भावना को अपनाते हुए, गोवा में हुई तीसरी बैठक ने सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुभवी सदस्यों को एक मंच पर लाया। बैठक का मुख्य बिंदु नीति विज्ञप्ति के मसौदे पर आम सहमति बनाना था, जिसे स्टार्टअप 20 ने आम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए प्रकाशित किया था। बैठक में एक स्टार्टअप शोकेस, स्टार्टअप 20x श्रृंखला के हिस्से के रूप में रोमांचक वार्ता, सांस्कृतिक अनुभव और दस्तावेज में उल्लिखित विचारों के कार्यान्वयन और लाभों पर चर्चा शामिल थी।

• **स्टार्टअप 20 शिखर गुरुग्रामः**

जुलाई 2023 में गुरुग्राम में आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन ने स्टार्टअप 20 के उद्घाटन वर्ष के सफल समापन और अंतिम नीति विज्ञप्ति के जारी होने का आयोजन करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाया।

स्टार्टअप संगोष्ठी शिखर सम्मेलन का अभिन्न हिस्सा थी, जहां स्टार्टअप ने अपने अभिनव उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया, निवेशक पिचों, परामर्श सत्रों और उद्योग पेशेवरों के साथ नेटवर्क में भाग लिया। इस कार्यक्रम में कला और संस्कृति के तत्वों को भी शामिल किया गया, जिससे सभी प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव तैयार हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, ब्राजील की निरंतर भागीदारी पर प्रकाश डाला गया और स्टार्टअप को परिभाषित करने और 1 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की मांग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसने स्टार्टअप के लिए सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने और वैश्विक नवाचार अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में 15 से अधिक देशों के स्टार्टअप के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इनक्यूबेट किए गए 100 से अधिक घरेलू स्टार्टअप को प्रदर्शित किया गया। अलग-अलग निवेश पिच सत्रों के कारण 20 वीसी फर्मों द्वारा 25 से अधिक स्टार्टअप के लिए निवेश पर उदार प्रतिबद्धताएं हुईं।

**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023**

भारत में नवीनतम तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए दिनांक 11 से 14 मई, 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 का विषय था “स्कूल से स्टार्टअप: नवप्रवर्तन के लिए युवा प्रतिभाओं को प्रज्वलित करना”। भारत की आर्थिक प्रगति और विकास में नवाचार और उद्यमिता के महत्व को उजागर करने के लिए इस विषय को चुना गया था।



मई 2023 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह में प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री की झलक

इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, जिन्होंने देश में युवा वैज्ञानिकों के समर्थन और पोषण के महत्व पर प्रकाश डाला। अपने नवाचारों और उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनी में 5000 से अधिक स्कूली छात्रों, 1500 से अधिक अन्य आगंतुकों, 800 प्रदर्शकों, 200 से अधिक छात्र प्रदर्शकों और विभिन्न क्षेत्रों के 100 से अधिक स्टार्टअप ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी के योगदान को बढ़ावा देना और सम्मानित करना था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह में 20 से अधिक एआईसी समर्थित स्टार्टअप ने भाग लिया, जहां उन्होंने नवाचारी समाधानों का प्रदर्शन किया।



मई, 2023 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह

## नवाचार के लिए सीएसआर का शुभारंभ

भारत में नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सीएसआर वित्त पोषण को बढ़ावा देने और उसका लाभ उठाने के लिए, एआईएम ने देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर सहयोग को सक्षम करने के लिए कॉर्पोरेट, इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर, अनुसंधान और विकास संस्थानों और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के लिए सत्व कंसल्टिंग के साथ साझेदारी की है।

## अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- एआईएम-आईसीडीके:** इंडो-डेनिश द्विपक्षीय हरित कार्यनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में, एआईएम ने इनोवेशन सेंटर डेनमार्क (आईसीडीके) जो डेनमार्क दूतावास और डेनमार्क तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के अधीन एक इकाई है, के साथ साझेदारी में भारत में जल नवाचार चुनौतियों को डिजाइन किया, योजना बनाई और कार्यान्वित किया। एआईएम ने टीमों का मार्गदर्शन करने के लिए शैक्षणिक साझेदारों यानी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल केंद्र और इनक्यूबेटर भागीदारों यानी एआईसी-संगम और एआईसी एफआईएसई को शामिल किया। टीमों को जल विशेषज्ञों के सावधानीपूर्वक तैयार किए गए और विख्यात पैनल द्वारा परामर्श सहायता प्रदान की गई।
- दुबई/जीआईटीईएक्स:** जीआईटीईएक्स सबसे बड़े और इस तरह के युवा उद्यमिता, नवाचार और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में से एक है, जो नॉर्थ स्टार दुबई का हिस्सा है जो 10 से 13 अक्टूबर, 2023 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था। एआईएम के मिशन निदेशक (एमडी) ने विशेष अतिथि और वक्ता के रूप में जीआईटीईएक्स यूथएक्स में भाग लिया। मिशन निदेशक की भागीदारी से भारत और खाड़ी देशों के स्टार्टअप के पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संबंधों का निर्माण करने में मदद मिली और कई भारतीय स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और छात्रों के माध्यम से भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र की दृश्यता बढ़ी।
- डब्ल्यूआईपीओ के महानिदेशक (डीजी) के नेतृत्व में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल का दौरा:** एआईएम ने भारतीय पेटेंट कार्यालय और डीपीआईआईटी के साथ मिलकर डब्ल्यूआईपीओ के महानिदेशक और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के 8 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के लिए एक दिवसीय इनोवेशन इकोसिस्टम एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया। कार्यनीतिक बैठक ने भारतीय नवाचार और उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र, विशेष रूप से एटीएल के बारे में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद की।



नीति आयोग  
राष्ट्रीय एकता दिवस  
शपथ समारोह  
31/10/2023

खंड

7

प्रशासन और  
सहायक इकाइयां

## भूमिका

नीति आयोग का प्रशासन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी सेवा नियमावली और भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है। प्रशासन अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े सभी पहलुओं, भर्ती, पदोन्नति, तैनाती, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा मामलों से संबंधित अदालती मामलों से संबंधित कार्यों को देखता है और इन मामलों पर आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना भी प्रदान करता है। इसे सार्वजनिक डोमेन में नीति आयोग की नीतियों के कार्यानीतिक संचार का काम भी सौंपा गया है। राजभाषा (हिन्दी) अनुभाग ने वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग की दिशा में अपना प्रयास जारी रखा।

## सामान्य प्रशासन, आरटीआई सहित प्रशासन/मानव संसाधन

### प्रशासन/मानव संसाधन

नीति आयोग का प्रशासन प्रभाग नीति आयोग में कार्यरत कर्मचारियों के कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी किए गए भर्ती नियमावली/प्रक्रियाओं/सेवा नियमावली और भारत सरकार के अन्य मौजूदा अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है। प्रशासन प्रभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े सभी पहलुओं अर्थात् भर्ती, पदोन्नति, तैनाती, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा मामलों से संबंधित अदालती मामलों से सरोकार रखता है और इन मामलों के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। इसे स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर छात्रों अथवा भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में नामांकित शोध छात्रों के लिए इंटरशिप योजना से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

नीति प्रशासन ने वर्ष के दौरान फ्लेक्सि पूल में स्वास्थ्य नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि नीति के क्षेत्र में 03 वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार के पदों और जलवायु परिवर्तन, पीएएमडी, ग्रामीण विकास, आर्थिक नीति, सार्वजनिक निजी भागीदारी, कृषि, इन्फ्रा कनेक्टिविटी, शहरी अर्थशास्त्र, इकोनोमेट्रिक्स मॉडलिंग/कार्यानीतिक नियोजन, उद्योग/विनिर्माण के क्षेत्रों में वरिष्ठ विशेषज्ञ/विशेषज्ञ के 10 पदों के लिए विज्ञापन दिया है। सतत विकास लक्ष्यों के क्षेत्र में सीनियर लीड/लीड के एक पद को भी भरा गया है।

नीति आयोग में दो वरिष्ठ एसोसिएट और एक सहायक फोटोस्टेट-सह-उपकरण ऑपरेटर की भी नियुक्ति की गई। नीति आयोग ने अनुबंध के आधार पर नीति आयोग में परामर्शदाता के रूप में काम करने के लिए केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त प्रधान निजी सचिवों/निजी सचिवों की नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन दिया है। नीति आयोग के पुस्तकालय में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (एलआईओ) का एक पद सृजित किया गया। एलआईओ के पद के लिए भर्ती नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उपाध्यक्ष के निजी स्टाफ में विशेष कार्य अधिकारी का एक पद सृजित किया गया।

नीति आयोग को शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने मूल कार्यों से उत्पन्न होने वाली विविध जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इसे गतिशील और दूरदर्शी संगठन होना चाहिए। इसलिए, इसे नए और उभरते विचारों पर लगातार काम करने और रणनीतिक समाधान प्रदान करने की आवश्यकता है। नीति आयोग शासन की लगातार बदलती जरूरतों के अनुसार विविध कौशल्यों का पूल तैयार करने के लिए वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता ग्रेड -2 / परामर्शदाता ग्रेड -1 / यंग प्रोफेशनलों (वाईपी) को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करता है। उनसे ऐसे क्षेत्रों में काम करने की उम्मीद की जाती है जहां नीति आयोग के ढांचे के भीतर इन-हाउस विशेषज्ञता



आसानी से उपलब्ध नहीं है। वे उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर हैं, जो नीति आयोग की आवश्यकताओं के अनुसार अर्थशास्त्र, वित्त, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन, अवसंरचना आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने में सक्षम हैं।

नीति परामर्श दिशानिर्देशों को जुलाई 2023 को संशोधित किया गया है, जिससे इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को पोर्टल पर अपना प्रोफाइल पंजीकृत करने में सक्षम बनाने के लिए पूरे वर्ष खुले रहने वाले एक रिसोर्स पूल पोर्टल को लॉन्च करके और संसाधनों का एक पूल तैयार करके परामर्शदाताओं/वाईपी की नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं, जहां से आवश्यकता पड़ने पर परामर्शदाताओं/वाईपी की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। नीति आयोग के लिए परामर्शदाताओं और वाईपी की सीमा भी बढ़ाकर 450 कर दी गई है जो पहले 95 थी। चयन के पहले चक्र में, 154 परामर्शदाताओं/वाईपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है और मार्च 2024 तक नीति आयोग में 121 चयन किए गए हैं।

### नीति आयोग के स्टाफ की संरचना (नीति आयोग, डीएमईओ और एआईएम)

क्र. सं.	अधिकारियों का स्तर	सरकारी	पार्श्व प्रवेशी प्रोफेशनल	आउटसोर्स किए गए अन्य प्रोफेशनल	कुल
1.	अपर सचिव और समकक्ष	12	1	0	13
2.	संयुक्त सचिव और समकक्ष	10	0	8	18
3.	निदेशक और समकक्ष	19	9	19	47
4.	उप सचिव और समकक्ष	28	2	0	30
5.	अवर सचिव और समकक्ष	61	7	27	95
6.	स्तर 10 और समकक्ष में अनुसंधान अधिकारी/एसोसिएट	17	9	11	37
7.	अनुभाग अधिकारी और समकक्ष	37	0	113	150
8.	सहायक अनुभाग अधिकारी (स्तर 7) और समकक्ष	70	0	0	70
9.	अन्य सहायक कर्मचारी	153	0	4	157
10.	आउटसोर्स किए गए कार्मिक	0	0	135	135
	<b>कुल</b>	407	28	317	752

परामर्शी पदों के अलावा, नीति आयोग का अपना विशिष्ट/रेजीडेंट/गैर-रेजीडेंट फेलोशिप कार्यक्रम है। फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को चुनकर विभिन्न क्षेत्रों में उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। यह कार्यक्रम सरकारी नीति तैयार करने में पारंपरिक नियोजन से आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में वैश्विक विशेषज्ञता को आकर्षित करना चाहता है। यह एक प्रतिस्पर्धी फेलोशिप है जो क्षमतावान वरिष्ठ और करियर मध्य पेशेवरों को नीतिगत पहलों पर व्यावहारिक व क्रियाशील ढंग से काम करने की अनुमति देगी। यह उन्हें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों और विद्वानों जैसे भारतीय नीति क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न वृत्तिकों के साथ बातचीत करने और विशिष्ट अनुसंधान कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा।

नीति आयोग के पास नीति इंटरशिप स्कीम भी है जिसका उद्देश्य अवर स्नातक/स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में नामांकित छात्रों या शोध छात्रों को "इंटरन" के रूप में शामिल करना है। इन इंटरन को नीति आयोग के भीतर विभिन्न वरिष्ठ/प्रभागों/इकाइयों में काम करने का अवसर दिया जाता है और उनसे इन-हाउस और अन्य सूचनाओं के अनुभवजन्य संग्रह और मिलान के माध्यम से नीति आयोग के भीतर विश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने की उम्मीद की जाती है।

### आजीविका प्रबंधन

नीति आयोग का आजीविका प्रबंधन (सीएम) अनुभाग नीति आयोग में सभी स्तरों के सभी अधिकारियों/कर्मिकों के प्रशिक्षण और करियर प्रबंधन से संबंधित मामलों के साथ-साथ विदेशी प्रशिक्षण और विदेशी दौरे से संबंधित मामलों को भी देखता है।

- 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च, 2024 के बीच सत्तानवे (97) अधिकारियों/कर्मिकों को अलग-अलग देशों में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों (सम्मेलन/कार्यशाला/सेमिनार/बैठक आदि) में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। विदेशी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारियों में नीति आयोग के अधिकारी (उपाध्यक्ष, कुछ सदस्य, सीईओ और कुछ अन्य अधिकारी/कर्मिक) शामिल थे, जबकि इनमें से कुछ अधिकारी/कर्मिक अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) जो नीति आयोग का संबद्ध कार्यालय है, और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के कार्यालय (पीएम की ईएसी) से थे।
- 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 के बीच नीति आयोग के एक सौ बत्तीस (132) अधिकारियों/कर्मचारियों/कर्मिकों को कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) द्वारा या अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा या कुछ अन्य प्रशिक्षण संस्थानों/संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों (कैडर प्रशिक्षण या अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम) में भाग लेने के लिए नामांकित किया गया। उक्त अवधि के दौरान विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नीति आयोग के 04 अधिकारियों को नामित किया गया। उपरोक्त में से 132 अधिकारियों/कर्मिकों को विभिन्न घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया, कुछ अधिकारियों/कर्मिकों को कुछ उद्योग संगठनों के साथ विभिन्न उद्योग निमज्जन या जुड़ाव कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया। इस अवधि के दौरान क्षमता निर्माण पहल के भाग के रूप में क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) द्वारा इन उद्योग निमज्जन या जुड़ाव कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई थी।
- नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मिकों को अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) सहित नीति आयोग की व्यापक संरचना, भूमिका, कार्य और प्रमुख पहलों/कार्यक्रमों से परिचित कराने के उद्देश्य से नीति आयोग में 13 से 15 जून, 2023 के दौरान नीति आयोग

के फ्लेक्सी पूल के नव नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों (अर्थात् वरिष्ठ सहयोगी/सहयोगी/वरिष्ठ विशेषज्ञ/विशेषज्ञ आदि) और संविदा पर काम करने वाले व्यक्तिगत कर्मियों (अर्थात् युवा पेशेवर/परामर्शदाता आदि) के लिए तीन (03) दिवसीय आंतरिक प्रेरण-सह-अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया गया, जिसमें अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के इस तरह के कुछ अधिकारियों/कर्मियों को भी शामिल किया गया था। उक्त प्रेरण-सह-अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को नीति आयोग के प्रशासनिक ढांचे और प्रक्रियाओं का व्यापक सिंहावलोकन, आधिकारिक संचार के विभिन्न रूपों, आचरण नियमावली की बुनियादी अवधारणाओं जैसे कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (एमओपी) का बुनियादी सिंहावलोकन और सरकारी ढांचे में काम करने वालों के लिए प्रासंगिक कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानूनों/नियमों/दिशानिर्देशों, ई-ऑफिस के उपयोग पर विस्तृत सैद्धांतिक और व्यावहारिक इनपुट और सार्वजनिक नीति की व्यापक अवधारणाएँ जैसे कुछ अन्य उपयोगी विषयों पर इनपुट प्रदान किए गए।

- 16 जून, 2023 को नीति आयोग में आईएसएस प्रोबेशनर्स (2023 बैच) के लिए नीति आयोग की भूमिका और कार्यों/पहलों के सिंहावलोकन पर चर्चापरक सत्र के साथ एक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुरोध पर नीति आयोग में जनवरी, 2023, से फरवरी, 2024, तक को विदेश मंत्रालय (एमईए) के 'भारत को जानो' (केआईपी) के क्रमशः 64वें, से 74वें तक संस्करण के तहत दुनिया के विभिन्न देशों से भारत आने वाले भारतीय प्रवासी युवाओं के लिए चर्चापरक सत्र के साथ एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 01 सितंबर, 2023 को नीति आयोग में आर्मी वॉर कॉलेज, मद्रास से नीति आयोग का दौरा करने वाले वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के लिए एक (01) दिवसीय चर्चापरक अनुदेशात्मक एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गाम्बिया गणराज्य के वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए 21 सितंबर, 2023 को नीति आयोग (डीएमईओ सहित) की भूमिका और कार्यों/पहलों के सिंहावलोकन पर चर्चापरक सत्र के साथ एक एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरएंडपीजी) के तहत राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) में एक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे, जिसमें गाम्बिया गणराज्य के इन वरिष्ठ सिविल सेवकों ने 21 सितंबर 2023 को गैम्बियन उच्चायोग, दिल्ली के कांसुलर अधिकारियों के साथ नीति आयोग में उक्त चर्चापरक एक्सपोजर सत्र कार्यक्रम में भाग लिया।
- 15वें मिड-आजीविका प्रशिक्षण (चरण IV) कार्यक्रम के तहत बातचीत के लिए नीति आयोग में दिनांक 1 फरवरी, 2024 को आईएफओएस अधिकारियों की एक एक्सपोजर विजिट आयोजित की गई थी। 8 तथा 9 फरवरी, 2024 की एनएएए शिमला के आईए एंड एएस अधिकारी प्रशिक्षुओं (2023 बैच) के लिए एक एक्सपोजर विजिट का भी आयोजन किया गया था। 15 फरवरी, 2024 को नीति आयोग में आईआईडीएल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के परास्नातक छात्रों के साथ एक चर्चापरक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिनिधिमंडल में 12 राज्यों के 20 छात्र शामिल थे। इसके अलावा, 27 फरवरी, 2024 को नीति आयोग में श्रीलंका सरकार के अधिकारियों के साथ एक संवाद भी आयोजित किया गया था। 28 फरवरी, 2024 को नीति आयोग में मिशिगन विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्रों के साथ एक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया।

## सामान्य प्रशासन

### राजभाषा (हिन्दी) अनुभाग

राजभाषा अनुभाग ने हमेशा की तरह राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके तहत बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम और संघ की

राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अधिकतम करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा।

राजभाषा विभाग को तिमाही प्रगति रिपोर्टें भेजी गईं तथा संबद्ध कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा की गई। हिंदी अनुभाग ने वार्षिक रिपोर्ट, अनुदान के लिए मांग, संसदीय स्थायी समिति से संबंधित सामग्री, मंत्रिमंडल नोट, संसद प्रश्न, अधिसूचना, आदेश, ओएम, एमओयू, आरटीआई मामले, प्रपत्र एवं प्रारूप, पत्र, आदि जैसे विभिन्न दस्तावेजों का अनुवाद किया।

## कार्यान्वयन

### 1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन:

राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम तथा अन्य आदेशों/अनुदेशों को सूचनार्थ तथा निर्देश के लिए नीति आयोग के सभी अनुभागों एवं इसके संबद्ध कार्यालयों को अग्रेषित किया गया।

### 2. 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन (फिजी सम्मेलन):

12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी, 2023 के दौरान नाडी, फिजी में आयोजित किया गया था। हिंदी के प्रसार के लिए यह सम्मेलन फिजी सरकार के सहयोग से विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में नीति आयोग के प्रतिनिधि के रूप में सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री नवीन कुमार टोप्पो ने भाग लिया।

### 3. तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन (पूणे सम्मेलन):

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। तीसरा सम्मेलन 14-15 सितंबर 2023 के दौरान पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में, डॉ. आशीष कुमार पंडा, उप सचिव (राजभाषा एवं और प्रशासन) श्री सूरज प्रकाश बडगुजर, परामर्शदाता (राजभाषा) और श्री रामबाबू वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी श्रीमती तपोजा दत्ता, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने नीति आयोग की तरफ से भाग लिया तथा राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।

## संवर्धन

### 1. हिंदी में मौलिक टिप्पण एवं आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना:

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन योजना 2022-23 में भी जारी रही। इस योजना के तहत 5000 रुपये के दो प्रथम पुरस्कार, 3000 रुपये के तीन द्वितीय पुरस्कार और 2000 रुपये के पांच तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत आठ पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

### 2. हिंदी में डिक्टेशन के लिए नकद पुरस्कार योजना:

हिंदी में डिक्टेशन के लिए अधिकारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना चल रही है। इस योजना के तहत

5000 रुपये के दो नकद पुरस्कारों (एक हिंदी भाषी स्टाफ के लिए और दूसरा गैर हिंदी भाषी स्टाफ के लिए) का प्रावधान है।

### 3. हिंदी दिवस और पखवाड़ा:

विगत वर्षों की भाँति दिनांक 14 से 30 सितम्बर, 2023 तक नीति आयोग में हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवधि में कुल 13 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें 116 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा कुल 53 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र और पुरस्कार दिया गया। दिनांक 14 सितम्बर 2023 को माननीय योजना राज्य मंत्री ने नीति आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना अधिकतम सरकारी कार्य राजभाषा हिंदी में करने का निदेश दिया।

### 4. हिंदी सलाहकार समिति:

दिनांक 5 मई 2022 की संकल्प संख्या ई-11011/1/2018-हिन्दी के अनुसार समिति का पुनर्गठन किया गया है। योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता वाली समिति में 15 गैर-सरकारी सदस्य और 13 सरकारी सदस्य हैं। इस समिति के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक 15 दिसंबर 2022 को हुई और दूसरी बैठक 04 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई थी। इन बैठकों में माननीय मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों तथा माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

### 5. राजभाषा कार्यान्वयन समिति:

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में काम करती है। इस समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में त्रैमासिक हिंदी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। समिति केंद्र सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित उपाय सुझाती है। नीति आयोग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने का भी निदेश दिया गया।

### 6. हिंदी कार्यशालाएं:

वर्ष के दौरान, राजभाषा के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं पर चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं और उनमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए। व्यापक अनुभव और ज्ञान वाले विशेषज्ञों ने कार्यशाला ली और प्रासंगिक और उपयोगी जानकारी साझा की।

### 7. चर्चा-परिचर्चा कार्यक्रम:

हिंदी अनुभाग, नीति आयोग ने राजभाषा को बढ़ावा देने और कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि विकसित करने के लिए जीवनवर्धक चर्चा सत्रों का आयोजन किया। अब तक 4 महत्वपूर्ण विषयों जैसे आपदा प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन, कार्डियक अरेस्ट- इसके कारण एवं निवारण, महिला सशक्तिकरण पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत चर्चा की गई एवं प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।

### 8. राजभाषा अनुभाग द्वारा नीति आयोग के अनुभागों एवं संलग्न कार्यालयों का निरीक्षण:

नीति आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने नीति आयोग के सभी 42 अनुभागों का निरीक्षण किया और संबंधित अनुभागों को सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निर्देश, इनपुट और मूल्यांकन दिए गए। इसके अलावा, दो संबद्ध कार्यालयों (1) डीएमईओ और (2) एनआईएलईआरडी का भी निरीक्षण किया गया और इनपुट दिए गए।

## पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

नीति आयोग का पुस्तकालय भारत सरकार के मंत्रालयों में सबसे पुराने और सबसे व्यापक पुस्तकालयों में से एक है।

पुस्तकालय में 1.88 लाख से अधिक किताबें, रिपोर्टें, जर्नल के जिल्दबद्ध खंड और 1326 ऑडियो-विजुअल सामग्री (एल्बम और सीडी) का संग्रह है। इसमें योजना आयोग के दौर के दस्तावेजों का संग्रह है। यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 147 पत्रिकाएं, जर्नल एवं समाचार पत्र मंगाता है। यह नीति नियोजन और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आधुनिक सुविधाओं जैसे कि 12 ऑनलाइन डेटाबेस, 8 ई-जर्नल्स, 10 ई-समाचार पत्र (भारतीय और विदेशी), 4 ई-बुकस डेटाबेस (अंग्रेजी और हिंदी) तक पहुंच और 5 ई-टूल्स और विश्लेषणात्मक उपकरण के लिए लाइसेंस से भी सुसज्जित है। वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार नीति आयोग के पुस्तकालय को श्रेणी IV पुस्तकालय के रूप में सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया गया है। पुस्तकालय नीति आयोग के अलावा अन्य विभागों के सभी अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों में नामांकित शोध छात्रों को इस समृद्ध डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करता है।

वर्तमान पुस्तकालय समिति में अध्यक्ष के रूप में एक वरिष्ठ सलाहकार, सदस्य के रूप में सलाहकार और सहायक निदेशक (राजभाषा) और सदस्य-संयोजक के रूप में एक निदेशक (पुस्तकालय) शामिल हैं। पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का चयन करने के लिए नियमित अंतराल पर समिति की प्रतिवर्ष दो बैठकें आयोजित की जाती हैं।

यह पुस्तकालय साफ्टवेयर कोहा की मदद से पूर्णतः स्वचालित है और किसी भी दस्तावेज का सही स्थिति पता करने के लिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग का प्रयोग करती है। सदस्य अब एक ही मंच खोज के माध्यम से नीति आयोग के पुस्तकालय की विविध सामग्री तक दूर से भी पहुंच सकते हैं। इस पुस्तकालय को mLibrary नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है, जो एंड्रॉइड पर प्ले स्टोर और आईफोन पर एपीपी स्टोर पर उपलब्ध है। नीति आयोग विभिन्न पुस्तकालयों की कैटालॉग तक पहुंच के लिए डेलनेट सेवा भी प्रदान करती है।

अपनी नियमित सेवाओं के हिस्से के रूप में, पुस्तकालय निम्नलिखित का संचालन करता है:

- दैनिक बुलेटिन जिसमें अर्थव्यवस्था, वित्त और नीति पर वैश्विक और राष्ट्रीय समाचार होते हैं।
- दैनिक डाइजेस्ट (भाग क और ख) जिसमें नीति आयोग से संबंधित समाचार लेख और विभिन्न विषयों पर विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ऑफ-एड होते हैं।
- साप्ताहिक बुलेटिन जो कृषि और ग्रामीण विकास, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग और अवसंरचना जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रमुख अपडेट को कवर करता है।

नीति आयोग का पुस्तकालय भारत के विभिन्न संस्थानों में पुस्तकालय विज्ञान के अध्ययनरत/कार्यरत छात्रों/पेशेवरों को समय-समय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण/इंटरनीशिप भी प्रदान करता है।

यह पुस्तकालय भारतीय पुस्तकालय संघ (आईएलए), केंद्रीय सरकार पुस्तकालय संघ (सीजीएलए) और दिल्ली पुस्तकालय संघ (डीएलए) का संस्थागत सदस्य है। निदेशक (पुस्तकालय) और अन्य अधिकारी समय-समय पर आयोजित आईएलए, आईएएसएलआईसी और सीजीएलए के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं।

## ओएमएंडसी अनुभाग

ओएमएंडसी अनुभाग जनवरी 2018 से सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से ऑनलाइन लोक शिकायतों का निपटान करता है और लोक शिकायत से जुड़ी अपीलों का भी निवारण कर रहा है।

यह वर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए भी जिम्मेदार है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 21 जून, 2023 को "वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग" विषय पर आयोजित किया गया था।

आयुष मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित कार्य किए गए:

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2023 के आयोजन की पृष्ठभूमि बताते हुए आंतरिक दिशानिर्देश जारी किए गए और जानकारी के लिए नीति आयोग के पोर्टल पर आयुष मंत्रालय द्वारा सामान्य योग प्रोटोकॉल भी जारी किया गया।
- नीति आयोग की वेबसाइट पर आईडीवाई का लोगो प्रदर्शित किया गया।
- आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया योगा ब्रेक (वाई-ब्रेक प्रैक्टिस) मोबाइल एप्लिकेशन, जो कामकाजी पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया पांच मिनट का योग प्रोटोकॉल है, नीति आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचित कराने के लिए नीति आयोग के पोर्टल पर परिचालित किया गया।
- नीति आयोग में 15 से 20 जून, 2023 तक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), आयुष मंत्रालय के सहयोग से विशेषज्ञों द्वारा योग कार्यशाला, योग डेमो और योग व्याख्यान जैसी गतिविधियों सहित एक योग प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसका आयोजन नीति आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के हित में योग के प्रति रुचि पैदा करने, सभी को योगाभ्यास के लिए प्रोत्साहित करने और योग को अपनाने के लिए किया गया है।
- 21 जून 2023 को योग दिवस 2023 समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने किया। इस आयोजन में नीति आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।
- नीति आयोग/डीएमईओ/एआईएम के सभी अधिकारियों/पदाधिकारियों के लिए 31 अक्टूबर, 2023 को माननीय उपाध्यक्ष, नीति आयोग के नेतृत्व में "राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ" (राष्ट्रीय एकता) का आयोजन किया गया।
- नीति आयोग/डीएमईओ/एआईएम के सभी अधिकारियों/कर्मिकों के लिए 26 नवंबर, 2023 को सीईओ, नीति आयोग द्वारा "संविधान दिवस - संविधान की प्रस्तावना का वाचन" का आयोजन किया गया।
- जानकारी के लिए नीति आयोग के पोर्टल पर नीति आयोग की प्रेरण सामग्री परिचालित की गई।
- 01 जनवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार डीओपीटी को एससी, एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व पर समेकित डेटा अपलोड किया गया।
- सार्वजनिक शिकायतों, सांसदों और राज्य सरकारों के संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी परामर्शों, संसदीय आश्वासनों आदि के निपटान के लिए 2 से 31 अक्टूबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 चलाया गया।
- नीति आयोग के अधिकारियों के लिए डीएआरपीजी से प्राप्त 15वें सिविल सेवा दिवस, 2023 (20-21 अप्रैल, 2023) के निमंत्रण कार्ड का वितरण।

- भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के लिए निमंत्रण कार्ड जारी करने के लिए नीति आयोग और उसके अधीनस्थ/संबद्ध संगठनों के अपर सचिव और उच्च स्तर के अधिकारियों का विवरण भारत व्यापार संवर्धन संगठन को अग्रेषित किया गया।
- स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, 2023 के निमंत्रण कार्ड जारी करने के लिए नीति आयोग और उसके अधीनस्थ/संबद्ध संगठनों के अपर सचिव और उससे उच्च स्तर के अधिकारियों का विवरण रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित किया गया।
- इंडिया ईयर बुक 2024 के संबंध में नीति आयोग के अनुभागों/प्रभागों/वर्टिकल से प्राप्त अद्यतन जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अग्रेषित की गई।
- नीति आयोग के कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों, जिनके निवास क्षेत्र में सीजीएचएस की सुविधा नहीं है, के लाभ के लिए पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनरों को अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट (एएमए) के रूप में नियुक्त करने से संबंधित कार्य।
- नीति आयोग में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा, 2023 का आयोजन किया गया।
- नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष ने 2 अक्टूबर, 2023 को नीति आयोग में स्वच्छ भारत शपथ दिलाई, जिसके बाद नीति आयोग के परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया।

## आरटीआई प्रकोष्ठ

आरटीआई सेल पर ऑनलाइन और डाक के माध्यम से भौतिक रूप से प्राप्त सभी आरटीआई प्रश्नों का जवाब देता है। वर्ष 2022-2023 और 2023-24 के दौरान ने, प्रकोष्ठ निम्नलिखित कार्यकलाप किए:

### वार्षिक वर्ष 2023-2024 (1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 तक)

- 976 आरटीआई आवेदन और 63 अपीलें प्राप्त हुईं
- सीआईसी की 13 सुनवाई में उपस्थित हुए।

## संचार कक्ष

नीति आयोग का संचार कक्ष पारंपरिक मीडिया (प्रिंट और ऑडियो-विजुअल), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नीति आयोग वेबसाइट सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से नीति वर्टिकल्स से निकलने वाले ज्ञान और अंतर्दृष्टि को समेकित और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

## सिंहावलोकन

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, संचार कक्ष ने सामग्री निर्माण से लेकर संपादित डिजाइन, हैशटैग चयन और समग्र संचार कार्यनीति जैसे कार्यों को संभालते हुए नीति के सोशल मीडिया स्पेस को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया। इस व्यापक दृष्टिकोण ने एबीपी फेलो ट्रेनिंग, भारत के बढ़ते कदम, राज्यों के लिए नीति, संकल्प सप्ताह (चैंपियंस फॉर चेंज का शुभारंभ), आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, वोकल फॉर लोकल, विकसित भारत और जी20 परिणाम श्रृंखला कार्यशालाएं जैसे विभिन्न अभियानों और महत्वपूर्ण आयोजनों में सोशल मीडिया सामग्री का निर्बाध समन्वय सुनिश्चित किया। इसके अतिरिक्त, कक्ष ने एक सामंजस्यपूर्ण और प्रभावशाली ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए, संपादित और प्रेस विज्ञप्तियों का प्रबंधन किया।



**वर्ष 2023-24 के दौरान की गई विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:**

**भारत के बढ़ते कदम**

आकांक्षी जिलों से सामने आने वाली वीडियो, रील और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से परिवर्तन की परिवर्तनकारी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इस अभियान को विकसित किया गया था। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कुल 512 पोस्ट साझा किए गए, जिसमें प्रभावकारी कुल 17.63 मिलियन लोग एकत्रित हुए।

**ASPIRATIONAL DISTRICTS PROGRAMME**

Chatra, Jharkhand

Nourishing Lives: Mobile POSHAN Van Tackles Child Malnourishment

#BharatKeBadhteKadam

@NITIAayog niti.aayog NITI Aayog @NITIAayogOfficial /niti.aayog

**ASPIRATIONAL DISTRICTS PROGRAMME**

Fatehpur, Uttar Pradesh

Fostering Success in Government Schools with 'Mission Sankalp' Upgrading Infrastructure, Enrolment, and Learning Outcomes

#BharatKeBadhteKadam

@NITIAayog niti.aayog NITI Aayog @NITIAayogOfficial /niti.aayog

**नीति फॉर स्टेट्स**

'नीति फॉर स्टेट्स' पहल एक अंतर-क्षेत्रीय ज्ञान मंच के रूप में कार्य करती है जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीएल) बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। "राज्यों के लिए नीति" प्लेटफॉर्म के लॉन्च के लिए फिल्में और कोलेटरल डिजाइन किए गए थे और दिनांक 07 मार्च, 2024 को संचार, रेलवे एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च कार्यक्रम में फिल्म दिखाई गई थी। यह लाइव था -देश भर में स्ट्रीम किया गया था तथा इस कार्यक्रम में राज्य के सभी विभाग वर्चुअली शामिल हुए थे।

**NITI FOR STATES**

Towards a Viksit Bharat @2047

Launch of NITI For States Platform and Viksit Bharat Strategy Room

7 March 2024

Rang Bhawan Auditorium, Akashvani Bhawan, New Delhi

### संकल्प सप्ताह

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 30 सितंबर, 2023 को भारत मंडपम में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए 'संकल्प सप्ताह' नामक एक अद्वितीय सप्ताह भर का कार्यक्रम शुरू किया। एबीपी चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल और समग्र आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर फिल्में तैयार की गईं।



### विकसित भारत @2047

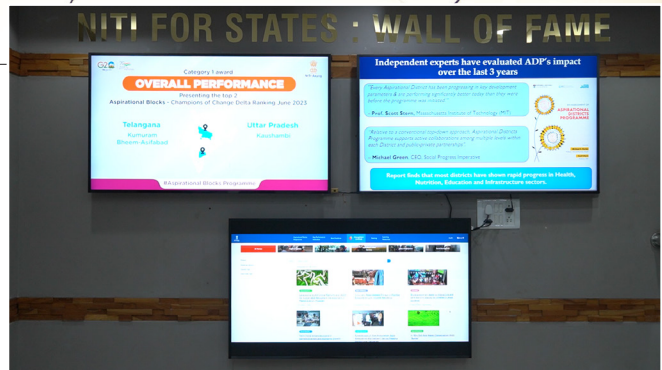
विकसित भारत @2047 के लॉन्च के लिए भारत भर के विश्वविद्यालयों और छात्रों से सुझाव आमंत्रित करते हुए फिल्मों का निर्माण किया गया। विज्ञान दस्तावेज़ के लिए सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक अनवरत सोशल मीडिया अभियान चलाया गया। यह फिल्म 11 दिसंबर, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च कार्यक्रम में दिखाई गई और देश भर के सभी राजभवनों में लाइव-स्ट्रीम की गई, जिसमें छात्रों ने भाग लिया। अभियान के परिणामस्वरूप, विकसित भारत @2047 के विज्ञान के लिए देश के युवाओं से 15 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए।





### वॉल ऑफ फ़ेम का लांच

नीति आयोग में एडीपी रैंकिंग के आधार पर शीर्ष रैंकिंग वाले जिलों और उनकी पहलों को प्रदर्शित करते हुए वॉल ऑफ फेम को डिजाइन और लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य एडीपी के तहत जिलों की सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है।



NITI - G20 THINK TANK WORKSHOP SERIES			
THEME	TITLE	DATE	VENUE
G20 to G21	India - AU cooperation for a better inclusive world	01 November 2023	Hall - Mumtaz Hotel Taj Palace, SP Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, New Delhi
Data for Development	Harnessing Data for Development	03 November 2023	Hall - Jehangir Hotel Taj Palace, SP Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, New Delhi
Tourism	Implementing the Goa Roadmap for Tourism	04 November 2023	Hall - Desire Hotel Le Meridien Windsor Pl, Connaught Place, New Delhi - 110001
Digital Public Infrastructure	Transformative Technology - Promoting Development, Growth and Innovation	05 November 2023	Hall - Inspire Hotel Le Meridien Windsor Pl, Connaught Place, New Delhi
SDG	Accelerating Progress on Sustainable Development Goals	06 November 2023	Conference Room No. 2 Dr. Ambedkar International Centre, New Delhi
Trade and GCVs	Inclusive Trade for prosperity	06 November 2023	Hall-Aftab Mahtab Hotel Taj Mahal, No.1, Man Singh Road New Delhi
Indian Development Model	Indian Development Model	07 November 2023	Hall - Desire Hotel Le Meridien Windsor Pl, Connaught Place, New Delhi - 110001
Women Led Development	NariShakti - Towards Women Led Development	08 November 2023	Hall-Yantra Hotel The Park Hotel, 15, Hanuman Road Area, Connaught Place, New Delhi
Reforming MDBs and Climate Finance	Accessing MDB & Global Finance for Development & GreenGrowth	09 November 2023	Hall - Mumtaz Hotel Taj Palace, SP Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, New Delhi
Green Development	Green Development	09 November 2023	Hall - Desire Hotel Le Meridien Windsor Pl, Connaught Place, New Delhi - 110001

**By invitation only**

### जी-20 परिणाम श्रृंखला कार्यशाला:

संचार कक्ष ने 10वीं जी-20 परिणाम कार्यशालाओं के लिए सभी संपार्श्विक (विस्तृत और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री) को सफलतापूर्वक तैयार किया और समय पर वितरित किया, और इन आयोजनों की सफलता में योगदान दिया।

### सोशल मीडिया आउटरीच

संचार टीम ने एक संसक्तिशील सोशल मीडिया उपस्थिति विकसित की, जिसके परिणामस्वरूप फॉलोअर्स में 170K की उल्लेखनीय वृद्धि हुई 6 महीनों के भीतर, सभी प्लेटफार्मों पर कुल 1678 पोस्ट प्रदर्शित की गईं, जिससे 63.86 मिलियन का इंप्रेशन प्राप्त हुआ और कुल फॉलोअर्स की संख्या 5.31 मिलियन तक बढ़ गई।



### ‘नीति फॉर स्टेट्स’ व्हाट्सएप चैनल का शुभारंभ:

संचार कक्ष ने ‘नीति फॉर स्टेट्स’ व्हाट्सएप चैनल को विकसित और लॉन्च किया, जो समुदाय के साथ सीधे संपर्क का माध्यम बनेगा। दो महीने के भीतर, व्हाट्सएप चैनल के कुल फॉलोअर्स की संख्या 7000 तक पहुंच गई। संचार कक्ष आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर नीति वार्ता के तहत साक्षात्कार, प्रमुख सरकारी योजनाओं का प्रभाव, फोकस में नीति, एक मिनट में नीति आयोग की खबरें और फैक्ट फ्राइडे जैसे अधिक आकर्षक सामग्रियों को तैयार करने की योजना बना रहा है।

**NITI For States** ✓  
7,903 followers

Follow Forward Share

Official WhatsApp Channel of NITI Aayog for the NITI for States initiative.

For more information, visit [www.nitiforstates.gov.in](http://www.nitiforstates.gov.in)

X (Twitter): <https://twitter.com/NITIAayog>

Instagram: <https://www.instagram.com/niti.aayog>

Facebook: <https://www.facebook.com/NITIAayog/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/35688600/admin/feed/posts/>

## शासी परिषद सचिवालय एवं समन्वय, संसद

### शासी परिषद सचिवालय एवं समन्वय

शासी परिषद सचिवालय (जीसीएस) नीति आयोग के वर्टिकल/प्रभागों/यूनिटों की सभी गतिविधियों का समन्वय करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विभिन्न पत्राचारों को संबंधित वर्टिकल को परिचालित भी करता है। सचिवालय ने माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 27 मई, 2023 को आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक का समन्वय किया। सचिवालय ने शासी परिषद की 8वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट और शासी परिषद की 9वीं बैठक के लिए एजेंडा नोट्स तैयार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय किया। जीसीएस की आठवीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर आगे की कार्रवाई चल रही है।

समन्वय के फोकल बिंदु के रूप में सचिवालय ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की साप्ताहिक बैठकों (एसओएम), वरिष्ठ प्रबंधन परिषद (एसएमसी) का आयोजन किया। इसने नीति आयोग द्वारा आउटसोर्स किए जाने वाले अनुसंधान प्रस्तावों/परियोजनाओं/अध्ययनों पर विचार-विमर्श के अलावा, प्रमुख नीतियों और प्राथमिकताओं और उनके कार्यान्वयन के लिए क्रॉस-सेक्टरल रणनीतियों के सुझावों पर चर्चा को सुगम बनाया।

इसके अलावा, इसने विशेष रूप से पिछले 9 साल में नीति आयोग से संबंधित उपलब्धियों/नीतिगत निर्णयों के संबंध में पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय से प्राप्त संदर्भों, स्वतंत्रता दिवस भाषण से प्राप्त इनपुट और कार्रवाई बिंदुओं, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों आदि के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत से निकले कार्रवाई बिंदुओं के लिए संबंधित वर्टिकल/प्रभागों से जानकारी का समन्वय और मिलान किया।

### संसद अनुभाग

नीति आयोग में एक पूर्ण संसद अनुभाग है जो योजना मंत्रालय से संबंधित सभी संसदीय कार्यों को देखता है।

संसद अनुभाग संसद सत्र के दौरान संसदीय प्रश्न (पीक्यू) के समय पर निपटान के लिए नीति आयोग के भीतर विभिन्न वर्टिकल के साथ समन्वय करता है। इसमें उत्तर प्राप्त करने और माननीय योजना मंत्री से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संसद की वेबसाइट पर उत्तरों को अपलोड करने के लिए संबंधित वर्टिकल को संसदीय प्रश्नों को अग्रेषित करना शामिल है। विधिवत रूप से अनुमोदित उत्तरों को सदन के पटल पर रखने के लिए लोकसभा / राज्यसभा को भी प्रस्तुत किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, सलाहकार समिति, स्थायी समितियों और विभिन्न अन्य समितियों की बैठकों के दौरान उठाए गए मुद्दों पर इनपुट प्रदान करने से संबंधित कार्य भी समय पर प्रदान किए जाते हैं।

जहां तक संसदीय आश्वासनों का संबंध है, डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में, संसद अनुभाग योजना मंत्रालय के खिलाफ लंबित सरकारी कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ओएएमएस (ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली) की नियमित रूप से निगरानी करता है और लंबित संसदीय आश्वासनों के निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाता है। यह अनुभाग नीति आयोग के बजट को अंतिम रूप देने के लिए बजट सत्र के दौरान डीडीजी (अनुदान की मांग) की विभिन्न बैठकें आयोजित करने में भी सहायता करता है।



analytical report allows to estimate to the full a both in all company, and in its divisions separately. It will allow to predict more precisely immediate prospects of development of the company at the account of preservation of positive dynamics of growth.

As a result of investigation of period to do next: raise a break-even sales level, increase incomes of direct sales, reduce costs to transportation, strengthen sale divisions, carry out personnel training.

The given analytic... a current situation both in all... separately. It will allow to predict more... prospects of development of the company... preservation of positive dynamics of growth.

As a result of investigation of period to do next: raise a break-even sales level, increase incomes of direct sales, reduce costs to transportation, strengthen sale divisions, carry out personnel training.

essenti

demogra

offer to both

observers di

pothesis, esp

ractitioners ca

ma facie reas

and the exist

ets react to s

sis. For exam

re not instant

of prices over

ents, the efficie

verage the po

information ap

ot required tha

gents act coldly

to a short term

ily be taken

ious factor

and foll

reliably

inclu

nd

खंड

8

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र  
अनुसंधान और विकास  
संस्थान (निलडी)

## भूमिका

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (निलई) जो नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के लिए अधिदेशित संस्थान है। पिछले 60 वर्षों से, निलई ने मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक नीति और शासन आदि जैसे नए क्षेत्रों में विकसित हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, संस्थान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान आयोजित होने वाले हैं।

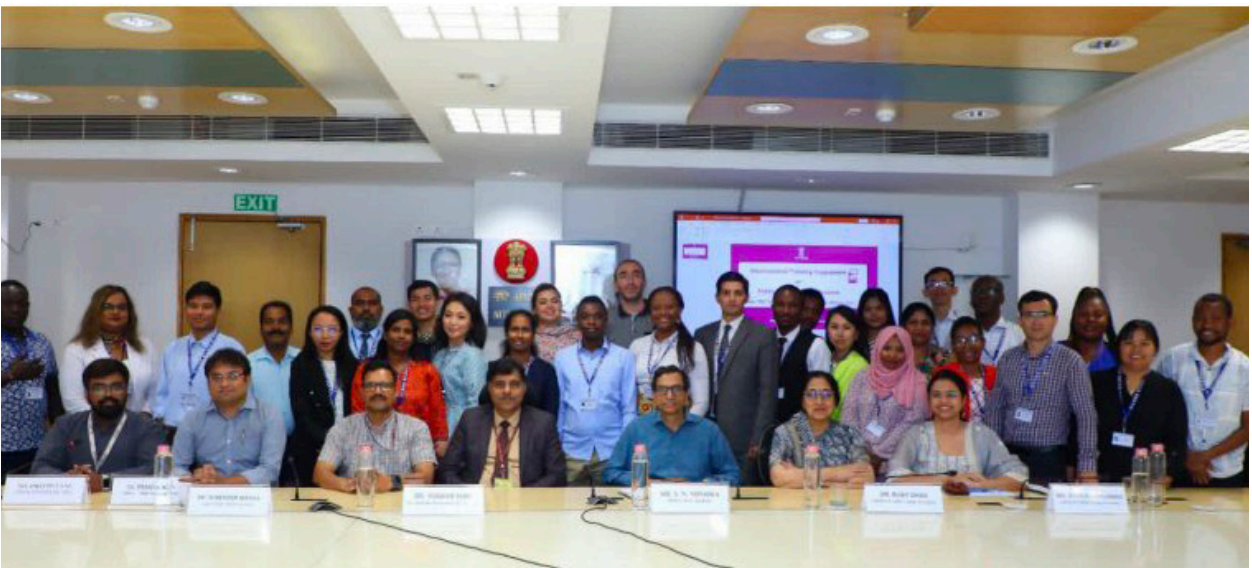
## 2023-24 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

क. **अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) (विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)** निलई विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रायोजित प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। ये कार्यक्रम सरकार/उद्योग/शिक्षा जगत के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों, विशेष रूप से विश्व भर के विकासशील देशों के अधिकारियों के लिए हैं। 2023-24 के दौरान अब तक, 40 से अधिक देशों के लगभग 200 प्रतिभागियों ने निलई के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। पहली बार, निलई ने स्पेनिश भाषा में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा बड़-चढ़ कर हिस्सा लिया गया।

आईटीईसी कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे:

### i. सार्वजनिक नीति और शासन (20 सितंबर - 10 अक्टूबर, 2023)

सार्वजनिक नीति और शासन पर तीन सप्ताह के आईटीपी में 18 देशों के 28 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने नीति आयोग, एमईआईटीवाई (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) और डीओसीए (उपभोक्ता मामले विभाग) का भी दौरा किया और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न नागरिक केंद्रित नीतिगत पहलों पर चर्चा की।



नीति आयोग में पीपीजी कार्यक्रम के प्रतिभागी



**ii सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) (स्पेनी भाषा में) (26 अक्टूबर – 8 नवम्बर 2023)**

स्पेनिश भाषा में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर दो सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निलर्ड द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें 6 लैटिन अमेरिकी देशों के 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। यह कार्यक्रम अद्वितीय था और अपनी तरह का पहला था, जिसे स्पेनिश भाषा में आयोजित किया जा रहा था। इसमें एसडीजी को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जा रहे दृष्टिकोण और रणनीतियों, एसडीजी के बजट, एसडीजी की प्राप्ति के लिए विश्वसनीय और सुलभ डेटा की आवश्यकता - राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एनआईएफ), एसडीजी स्थानीयकरण, एसडीजी लक्ष्य, एसडीजी संकेतक और सरकारी पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा, प्रतिभागियों ने अपने अध्ययन दौरे/फील्ड दौरे के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र के भारत में स्थित कार्यालय, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो और एक सामान्य सेवा केंद्र का भी दौरा किया।



संयुक्त राष्ट्र, भारत में प्रतिभागी

**iii विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी एवं मूल्यांकन (22 नवंबर से 12 दिसंबर, 2024)**

तीन सप्ताह का कार्यक्रम जिसका उद्देश्य, सार्वजनिक सेवा वितरण, मौजूदा उपकरणों, अवधारणाओं और तकनीकों के प्रयोग के प्रभावी डिजाइन और योजना के लिए एक मजबूत एम एंड ई प्रणाली की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 25 देशों के 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

**iv डिजिटलीकरण और मानव संसाधन प्रबंधन (17 जनवरी-6 फरवरी, 2024)**

तीन सप्ताह के कार्यक्रम में कार्यबल की बदलती प्रकृति के संबंध में विभिन्न एचआरएम गतिविधियों पर बदलती डिजिटल तकनीक के प्रभाव पर व्यावहारिक अभिविन्यास किया। पाठ्यक्रम में 30 देशों से 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

**v कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार (21 फरवरी, 12 मार्च, 2024)**

पाठ्यक्रम ने कौशल, उद्यमिता और नवाचार के लिए उत्तरदायी नीति, द्वितीय वास्तुकला, कार्यान्वयन और मूल्यांकन ढांचे को डिजाइन करने के लिए प्रतिभागियों की क्षमता निर्माण में सहायता की। इसने क्षेत्रीय स्तर पर सफल उद्यमिता, स्टार्ट-अप और इनोवेटर्स को एक्सपोजर दिया और जमीनी स्तर के नवाचार और सामाजिक नवाचार की भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम में 28 देशों से 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

**vi एसडीजी:- एक एकीकृत दृष्टिकोण (20 मार्च – 9 अप्रैल, 2024)**

कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को 17 एसडीजी की ओर उन्मुख किया; इसने भाग लेने वाले देशों के सामने आने वाली चुनौतियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों की विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में प्रभाव संबंधी जानकारी पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इसने प्रतिभागियों को विकास कार्यक्रमों के विभिन्न दिशानिर्देशों से भी परिचित कराया नए यंत्र और प्रौद्योगिकी के उपयोग को साझा किया और कैसे भारत इसे आगे लेकर जा रहा है, इसकी झलक भी प्रस्तुत की।



उद्घाटन समारोह की भागीदारी

**vii नागरिक केंद्रित शासन और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग (14 मार्च – 3 अप्रैल, 2024)**

प्रशिक्षण कार्यक्रम ने प्रतिभागियों की नागरिक केंद्रित शासन की अवधारणा और घटकों की समझने में सहायता की और उन्हें शासन में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की भारत की यात्रा से परिचित कराया। यह इस बात से परिचित हुआ कि कैसे शासन में सुधारों के कारण भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र में बदलाव आया हो। कार्यक्रम में 17 देशों के 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



नागरिक केंद्रित शासन संबंधी उद्घाटन कार्यक्रम और डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग

**viii वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन (27 मार्च – 16 अप्रैल, 2024)**

पाठ्यक्रम में विकासात्मक वित्त के क्षेत्र में बुनियादी और उन्नत मुद्दों और सुशासन वित्तीय समावेश के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग को शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम में 28 देशों के 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

**ix स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रम और ई-स्वास्थ्य पहल (26 फरवरी – 17 मार्च, 2024)**

प्रशिक्षण कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न प्रमुख पहलों, उनके कार्यान्वयन और निगरानी के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की। इसमें 8 देशों के 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



नीति आयोग में आयोजित समापन समारोह

**x आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निर्धारित चार अतिरिक्त आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक ऑनलाइन कार्यक्रम शामिल हैं:

- क. एसडीजी: एक एकीकृत दृष्टिकोण
- ख. कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार
- ग. डिजिटलीकरण और मानव संसाधन प्रबंधन
- घ. नागरिक केंद्रित शासन और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग
- ङ. प्रबंधन सूचना प्रणाली पर ऑनलाइन ई-आईटीईसी

**ख. घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रम**

ये कार्यक्रम विशेष रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों या मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण के लक्ष्य के साथ तैयार किए जाते हैं और अधिकारियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप कार्य के क्षेत्र में अपेक्षित ज्ञान, कौशल और व्यवहार संबंधी दक्षताएं प्राप्त करने में मदद करते हैं। 2023-24 के दौरान आयोजित पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

**i. निगरानी और मूल्यांकन पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 जनवरी - 6 जनवरी, 2024 और 8-13, जनवरी 2024**

यह पाठ्यक्रम जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया पाठ्यचर्या है। पहले बैच में योजना, निगरानी और मूल्यांकन विभाग, जम्मू के 22 पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का दूसरा बैच 8 जनवरी से 13 जनवरी, 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें कश्मीर के एक ही विभाग के 20 पदाधिकारियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा शुरू किया गया था।

**ii. सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम**

दिनांक 12-16 फरवरी, 2024 के दौरान आयोजित पाठ्यक्रम ने एसडीजी प्रेमवर्क, लक्ष्यों और संकतकों के बारे में समझ को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, वास्तविकता दी और अधिक विस्तृत तरीके से समझने, मौजूदा प्रयासों की जांच करने और सुधार करने के लिए कुछ लक्ष्यों पर गहराई से विचार करने और एसडीजी के संदर्भ में परिणामों को मापने निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपकरण तकनीकी पर विचार किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 18 राज्यों के 28 अधिकारियों ने भाग लिया।



नीति फॉर स्टेट्स पर विचार मंथन सत्र में नीति आयोग के अधिकारियों से बातचीत करते राज्य के अधिकारी

**iii. दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम, 2016 पर जागरूकता सृजन और संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम**

उपर्युक्त पाठ्यक्रम, जो 10 पाठ्यक्रमों में से अंतिम पाठ्यक्रम है तथा जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा शुरू किया गया है, में एमसीडी, डीजेबी, बैंकों आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के 43 कर्मचारियों ने भाग लिया था।

**iv. ज्ञान साझाकरण सम्मेलन**

निलई और नाबाई कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 2 दिवसीय ज्ञान साझाकरण सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

**ग. सहयोग**

- नीति आयोग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं जैसे अटल नवाचार मिशन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम और राज्य सहायता मिशन के लिए निलई को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नियुक्त किया गया है।
- निलई ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें सीएससी एसपीवी ग्राम स्तर के उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए निलई के बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा। शुरुआत में, जिला प्रबंधकों के लिए ऐसा एक प्रशिक्षण

कार्यक्रम सीएससी द्वारा 23-26 अप्रैल, 2023 के दौरान निलई परिसर में आयोजित किया गया था।

3. खरीद प्रथाओं को मजबूत करने के प्रयास में, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) और निलई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोग का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) के लिए सहयोगी कार्यशालाओं और विशेष प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से क्षमता निर्माण पहल को मजबूत करना है।

### **निलई की वार्षिक रिपोर्ट (2022-23) शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान संसद में प्रस्तुत की गई**

निलई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 अपने वार्षिक लेखापरीक्षित खातों के साथ 12 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में और 18 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में माननीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई।



# अनुलग्नक

---

## अनुलग्नक-1

01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 तक मूल्यांकित योजनाओं/परियोजनाओं का क्षेत्रवार वितरण

क्र.सं.	क्षेत्र	2023-24 (1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024)		
		संख्या	लागत (करोड़ रु. में)	%
1.	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	15	197117.07	6.62
2.	ऊर्जा	25	293446.96	9.86
3.	परिवहन	59	1154530.94	38.78
4.	उद्योग	23	636009.83	21.37
5.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	4	9880.69	0.33
6.	सामाजिक सेवाएं	23	100448.15	3.37
7.	संचार	7	244134.14	8.20
8.	अन्य	46	341296.08	11.46
	कुल	202	2976863.86	100.00

पीएफपीए में मूल्यांकित ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की क्षेत्रवार संख्या और लागत (1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक)

क्र.सं.	क्षेत्र	2023-24 (1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024)	
		संख्या	लागत (करोड़ रु. में)
	<b>कृषि</b>		
1.	कृषि एवं किसान कल्याण	10	162092.55
2.	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी	5	35024.52
	<b>ऊर्जा</b>		
3.	बिजली	7	59140.20
4.	कोयला	2	8962.32
5.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	10	131609.72
6.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	6	93734.72
	<b>परिवहन</b>		
7.	रेलवे	38	1035391.45
8.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	4	8320.63
9.	नागर विमानन	10	16973.46
10.	बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग	7	93845.40



	उद्योग		
11.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम	2	16035.33
12.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	5	52088.68
13.	इस्पात एवं खान		
14.	पेट्रो रसायन एवं उर्वरक	5	513280.88
15.	वस्त्र	1	4309.00
16.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1	7200.00
17.	वाणिज्य एवं उद्योग	9	43095.94
	<b>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी</b>		
18.	जैव-प्रौद्योगिकी		
19.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	4	9880.69
20.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान		
21.	महासागर विकास		
22.	पृथ्वी विज्ञान		
	<b>सामाजिक सेवाएं</b>		
23.	शिक्षा/मानव संसाधन विकास	10	24802.39
24.	संस्कृति		
25.	युवा मामले एवं खेल	1	3915.50
26.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2	17466.61
27.	आयुष	1	907.23
28.	महिला एवं बाल विकास		
29.	श्रम एवं रोजगार		
30.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1	835.00
31.	ग्रामीण विकास		
32.	अल्पसंख्यक कार्य		
33.	जनजातीय कार्य	2	30511.00
34.	पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता		
35.	उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण	6	22010.42
	<b>संचार</b>		
36.	सूचना एवं प्रसारण	1	494.45
37.	डाक		
38.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	3	16164.24
39.	डाक और संचार	3	227475.45
	<b>अन्य</b>		
40.	गृह मंत्रालय	8	53182.00
41.	पर्यटन	2	2298.00

42.	पर्यावरण एवं वन	1	722.24
43.	विधि एवं न्याय	3	4482.03
44.	जल शक्ति	3	38361.99
45.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (डोनर)		
46.	वित्त	9	10701.28
47.	कारपोरेट कार्य	1	978.53
48.	योजना आयोग/नीति आयोग	2	7130.40
49.	विदेशी मामले		
50.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन		
51.	संसदीय कार्य		
52.	पंचायती राज		
53.	आवासन एवं शहरी कार्य	12	218968.68
54.	कौशल विकास और उद्यमिता	1	1000.00
55.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन		
56.	सहकारिता	2	1715.00
57.	रक्षा	2	1755.93
	<b>कुल</b>	<b>202</b>	<b>2976863.86</b>

## अनुलग्नक- 2

**तालिका-2.1: 2023-24 के दौरान स्वीकृत नए शोध अध्ययनों की सूची (31 मार्च 2024 तक)**

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	संगठन का नाम
1.	भारत@2047 - समष्टि अर्थशास्त्र दृष्टिकोण	एनसीईआर, नई दिल्ली
2.	भारत के व्यापार पर वैश्विक मंदी का प्रभाव	डेलोइट एलएलपी
3.	मक्के से प्राप्त E20 इथेनॉल: खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव	आईसीएआर- भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, लुधियाना
4.	भारत में मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता (आशा) कार्यकर्ताओं का टाइम मोशन अध्ययन	पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई), गुरुग्राम
5.	परिभाषा, मापन और नीति: भारत में गरीबी उन्मूलन 2004/5 से 2021-22 तक	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बैंगलोर
6.	भारत के लिए 2047 तक समष्टि अर्थशास्त्र पूर्वानुमान रूपरेखा	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र, हरियाणा
7.	भारत के लिए 2047 तक समष्टि अर्थशास्त्र पूर्वानुमान रूपरेखा	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ह) यूनिवर्सिटी, पुणे

8.	भारत के लिए 2047 तक समष्टि अर्थशास्त्र पूर्वानुमान रूपरेखा	आईआईटी रोपड़, रुपनगर
9.	भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल प्रोफाइल की आवश्यकता	मानव विकास संस्थान (आईएचडी), नई दिल्ली
10.	भारतीय व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन	डेलोइट एलएलपी
11.	श्रम -प्रधान क्षेत्रों का तीव्र विकास (वस्त्र, चमड़ा, रत्न, आभूषण और खाद्य प्रसंस्करण)	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी), नई दिल्ली
12.	भारत में जलवायु वित्त का परिदृश्य: भारत के एनडीसी और नेट-शून्य लक्ष्यों के लिए वित्तपोषण मार्ग	जलवायु नीति पहल (सीपीआई), नई दिल्ली
13.	शिपिंग क्षमता पर गैर-प्रमुख बंदरगाहों का प्रभाव और भविष्य की नीति	उद्योग एवं आर्थिक बुनियादी सिद्धांत अनुसंधान ब्यूरो (बीआरआईएफ), नई दिल्ली

**तालिका-2.2: 2023-24 के दौरान पूर्ण किए गए अध्ययन (31 मार्च 2024 तक)**

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/शोधकर्ता
1.	महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना: चुनिंदा योजनाओं की समीक्षा	एमएससी इंडिया कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ
2.	एनिमेशन वर्चुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना	डेलोइट, गुरुग्राम
3.	सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में मधुमेह रेटिनोपैथी की जांच के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफॉर्म का एकीकरण	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
4.	जैव-उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन के लिए गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर), नई दिल्ली
5.	समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 3.0	डालबर्ग, नई दिल्ली
6.	भारत की जी-20 अध्यक्षता	ओलिवर वायमन, मुंबई
7.	भूमि मूल्य अधिग्रहण तंत्र को तेजी से अपनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तत्परता पर मूल्यांकन अध्ययन (देशव्यापी)	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद
8.	स्वतंत्रता-पूर्व कानून की समीक्षा	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली
9.	अटल टिंकरिंग लैब्स का मूल्यांकन	एथेना इन्फोर्नामिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
10.	प्रधानमंत्री योजना का प्रभाव आकलन	केपीएमजी, गुरुग्राम
11.	भारत@2047 - वृहद आर्थिक दृष्टिकोण	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर), नई दिल्ली

12.	सामाजिक लेखापरीक्षा सर्वेक्षण नमूनाकरण और विश्लेषण लागू करना	भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), कोलकाता
13.	स्पष्ट सब्सिडी का युक्तिकरण	राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली
14.	बाल विवाह निषेध (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 2016 का प्रभाव	राष्ट्रीय विधि विद्यालय (एनएलएस), बैंगलोर





सत्यमेव जयते

नीति आयोग